

आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

FOR MORE JOIN
MISSION SSC /
BANKING



सामान्य सचेतता

For **IBPS, SBI, RBI, LIC**
& Other Competitive Examinations



X-EEED PUBLICATION

FOR MORE JOIN
MISSION SSC / BANKING

विषय सूची

क्र.सं	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)	01-08
2.	भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)	09-11
3.	भारत में बैंको के विकास के चरण (Stages of Development of Banks in India)	12-34
4.	भारत में बैंकिंग प्रणाली का उन्नतिकरण (Updation of Banking System in India)	35-41
5.	मौद्रिक एवं साख निति (Monetary and Credit Policy)	42-44
6.	विभिन्न प्रकार के बैंकिंग अवयव (Different Kind of Banking Instruments)	45-48
7.	बेसल मानदंड (Basel Criterion)	49-51
8.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन (International Financial Organizations)	52-59
9.	भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार (Indian Financial and Capital Market)	60-63
10.	❖ विविध (Miscellaneous) 1. पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Yearly Plan) 2. बजट (Budget) 3. भारतीय कृषि (Indian Agriculture) 4. भारतीय के प्रमुख उद्योग (Main Industries Of India) 5. बेरोजगारी और निर्धनता (Unemployment And Poverty) 6. जनगणना (Census)- 2011	64-78
11.	बैंकिंग एवं वित्तीय शब्द संक्षेप (Banking and Financial Terminology)	79-89
12.	बैंकिंग एवं आर्थिक संक्षिप्तीकरण (Banking and Financial Abbreviation)	90-94
13.	वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)	95-111



भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

अर्थव्यवस्था: एक परिचय (Economy: An Introduction)

अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति 'अर्थ' एवं 'व्यवस्था' नामक दो शब्दों के संयुक्त होने से हुई है। अर्थ का तात्पर्य जहाँ 'मौद्रिक' से है वहीं व्यवस्था का तात्पर्य एक सुनिश्चित व संस्थापित प्रणाली से है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, (GDP के आधार पर) तथा क्रयशक्ति समता (Purchasing Power Parity) के आधार पर इसका स्थान तीसरा है, इसके अतिरिक्त भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े आयातकों व निर्यातकों में शामिल है।

वर्ष 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद आज अपनी विशाल जनशक्ति, विविध प्राकृतिक संसाधन व वृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों के कारण भारत विश्व की विशालतम व तीव्र गति से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में से एक के आधार पर दुनिया में जाना जा रहा है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार (Different Types of Economy)

अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में केन्द्रित होता है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)

आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें साधनों का आवंटन विनियोग की प्राथमिकताओं, उत्पादन के ढाँचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य के द्वारा हो तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बाजार तन्त्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है तथा दोनों एक इकाई के घटक के रूप में कार्य करते हैं अर्थात् यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, जिसमें पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का समन्वय होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त पर आधारित है।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics)

यह एक ऐसा अर्थशास्त्र है, जो माइक्रो अर्थशास्त्र (व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन) तकनीक को अच्छी आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सामान्य सन्तुलन के रूप में एक अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक दक्षता का विश्लेषण करता है। इसके परिणामस्वरूप आय से जुड़े सभी क्षेत्र का सामाजिक कल्याण का विश्लेषण होता है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने

लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का विकास किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of Economy)

सामान्यतः सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector)

इसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है।

- कृषि
- वानिकी
- मत्स्यन (मछली पकड़ना)
- खनन (ऊर्ध्वधर खुदाई) एवं उत्खनन (क्षैतिज)

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector)

इस क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है।

- निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसम्पत्ति का निर्माण किया जाए; जैसे- भवन।
- विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो; जैसे- कपड़ा, ब्रेड आदि।
- विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

तृतीयक या सेवा क्षेत्र (Tertiary Sector)

यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएँ प्रदान करता है, इसके अन्तर्गत निम्न क्षेत्र हैं

- परिवहन एवं संचार
- बैंकिंग
- बीमा
- भण्डारण
- व्यापार
- सामुदायिक सेवाएँ आदि।

कोर क्षेत्र (Core Sector)

भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 क्षेत्रों को कोर क्षेत्र अर्थात् अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संज्ञा दी गई है, जो आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

आठ कोर क्षेत्र इस प्रकार हैं-

- कोयला
- कच्चा क्षेत्र
- प्राकृतिक गैस
- रिफायनरी उत्पाद
- उर्वरक
- इस्पात
- सीमेण्ट
- विद्युत

विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण (Classification Of Economy By World Bank)



विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो निम्नलिखित हैं।

न्यूनतम आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 1035

मध्यम आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 1036-\$ 4085

उच्च आय अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय \$ 4086-\$ 12615

स्रोत वर्ष 2012-13 में विश्व बैंक के अनुसार

राष्ट्रीय आय (National Income)

किसी देश द्वारा एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अन्तर्गत उन सभी अन्तिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को शामिल करते हैं, जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित की गई हैं। इसमें देश के निवासियों द्वारा विदेशों में भी अर्जित आय को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय को 'राष्ट्रीय उत्पाद' के नाम से भी जाना जाता है।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आधार पर की जाती है।

राष्ट्रीय आय का मापन (Measurement of National Income)

राष्ट्रीय आय का मापन निम्न आधारों पर किया जाता है।

- राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा के रूप में होता है। राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत पुरानी वस्तुओं के मूल्य को मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।
- घरेलू सेवाएँ तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को (अंश-पत्र, ऋण-पत्र आदि का क्रय-विक्रय तथा हस्तान्तरण भुगतान, वजीफा, पेंशन भत्ता) राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता।
- देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तिम मूल्य को राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की गणना (Estimation of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः चालू तथा स्थिर दोनों मूल्यों पर की जाती है

- चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Price):** यह राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापने की विधि है, इसे **मौद्रिक आय** भी कहते हैं। कीमतों में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन हुए चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम या अधिक हो सकती है।
- स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Constant Price):** यह एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का वह मौद्रिक मूल्य है, जो किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' कहते हैं।

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित अवधारणाएँ

(Concepts of National Income)

राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में मूलतः दो अवधारणाओं- **राष्ट्रीय उत्पाद** तथा **घरेलू उत्पाद** को आधार स्वरूप लिया जाता है। शेष सभी धारणाएँ इन धारणाओं पर आधारित इनके प्रतिरूप स्वरूप हैं।

राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP)

एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा (निवासी/अनिवासी दोनों) की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसमें वे अनिवासी उद्यमी भी सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने देश के उत्पादन में योगदान दिया हो।

इसके अन्तर्गत देश की भौगोलिक सीमा के अन्दर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को निम्न सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है।

$$GDP = \text{उपभोग (C)} + \text{निवेश (I)} + \text{उपभोग व्यय (G)}$$

विभिन्न क्षेत्रों का जी डी पी में योगदान		
क्षेत्र	अंश में	कार्य बल में
उद्योग	26%	22%
सेवा	57%	27%
पर्यटन	6.23%	8.78%
कृषि	17%	51%

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product, GNP)

सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की अवधारणा की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़कर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) कहा जाता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) = जी डी पी + देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय (X) – विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय (M)

$$GNP = GDP + X - M$$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product, NNP)

जब GNP में से मूल्य हास (पूँजी स्टॉक की खपत) को घटाते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात होता है।

$$NNP = GNP - \text{पूँजी स्टॉक की खपत}$$

वैयक्तिक आय (Personal Income, PI)

घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही वैयक्तिक आय (Personal Income) कहते हैं। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। वैयक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा निगमों द्वारा अवितरित लाभांश एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए भुगतान को घटाने एवं सरकारी हस्तान्तरण



भुगतान, व्यापारिक हस्तान्तरण भुगतान एवं सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ने से प्राप्त होती है।

वैयक्तिक आय = राष्ट्रीय आय-निगम कर-निगमों का अवितरित लाभांश-सामाजिक सुरक्षा योजना का भुगतान + सरकारी हस्तान्तरण भुगतान + सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज

व्यय योग्य वैयक्तिक आय

(Disposable Personal Income, DPI)

राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसका योग अपनी इच्छा से जब चाहे खर्च कर सकते हैं, उसे व्यय योग्य वैयक्तिक आय (Disposable Personal Income, DPI) कहा जाता है। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है, उसको लोग अपनी इच्छानुसार व्यय कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं।

$$DPI = \text{उपभोग} + \text{बचत}$$

$$DPI = \text{व्यक्तिगत आय} - \text{प्रत्यक्ष कर} + \text{सब्सिडी}$$

वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income, RNI)

किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income) कहते हैं। इसे आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

निजी आय (Private Income, PI)

सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल आय को निजी आय (Private Income) कहते हैं। इसमें निजी निगम क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र दोनों शामिल किए जाते हैं।

साधन लागत एवं बाजार मूल्य (FC and MP)

साधन लागत (Factor Cost, FC) वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य (Input Cost, IC) होती है। सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो सब्सिडी दी जाती है अथवा इस पर कर लगाया जाता है। यदि कर लगाया जाता है, तो वस्तु का बाजार मूल्य (Market Price, MP) बढ़ जाती है। और यदि सब्सिडी दी जाती है, तो बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है।

राष्ट्रीय हरित आय

सकल राष्ट्रीय जो कि पर्यावरण हतल के मूल्य को घटाने के पश्चात शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, राष्ट्रीय हरित आय कहलाता है।

$$\text{राष्ट्रीय हरित आय} = \text{कुल वृद्धि} - \text{पर्यावरण ह्रास}$$

राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ

(Methods of Measuring National Income)

राष्ट्रीय आय साधन लागत पर आकलित निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। साइमन कुजनेट्स, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Income Accounting) के जन्मदाता हैं, ने राष्ट्रीय आय के मापन की निम्न तीन विधियाँ प्रस्तुत की हैं

1. उत्पाद पद्धति
2. आय पद्धति
3. व्यय पद्धति

उत्पाद पद्धति (Production Method)

कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया है। इस पद्धति के अन्तर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उसके योग को अन्तिम उपज योग (Final Product Total) कहा जाता है।

यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product, GDP) को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) की गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशों में अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है तथा मूल्य ह्रास को घटाया जाता है।

आय पद्धति (Income Method)

इस पद्धति के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है।

डॉ. बाउले तथा रॉटसन के अनुसार, आय गणना विधि के अन्तर्गत आयकर देने वाले तथा आयकर न देने वाले समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है।

व्यय पद्धति (Expenditure Method)

इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल बचतों का योग होती है। इस विधि से आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से सम्बन्धित आँकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन प्रणाली (Production Method) तथा आय प्रणाली (Income Method) का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है।

$$\text{राष्ट्रीय आय} = \text{कुल उपभोग व्यय} + \text{कुल बचत}$$

क्रय शक्ति समता विधि

(Purchasing Power Parity Method, PPP)

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न देशों के रहन-सहन स्तर के निर्धारण हेतु किया गया। इस विधि में किसी देश विशेष की सकल राष्ट्रीय आय को, देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना

(Estimation of National Income in India)

भारत में राष्ट्रीय आय एवं सम्बन्धित पक्षों की गणना का कार्य केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा किया जाता है।

भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में अनुमान 1868 ई. में दादाभाई नौरोजी द्वारा, उनकी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया' में व्यक्त किया गया। दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ₹ 20 बताई थी। वर्ष 1931-32 में डॉ. वी के आर वी राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की गणना की। वर्ष 1948-49 में प्रो. पी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति हुई, जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय सम्बन्धित लेखा प्रणाली का ढाँचा स्थापित हुआ तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1967 में पहली बार विदेशी व्यवहार को राष्ट्रीय आकलन में जोड़ा गया। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान वर्ष 1948-49 में वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा दिया गया।



भारत में राष्ट्रीय आय की गणना से सम्बन्धित प्रमुख संगठन

राष्ट्रीय-आय की गणना से सम्बन्धित प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(National Sample Survey Organisation, NSSO)

जनवरी, 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की स्थापना की गई। NSS अब NSSO का एक अंग बन गया तथा इसका कार्य सर्वेक्षण तक सीमित रहा। 12 जुलाई, 2006 को प्रो. सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्य शुरू करने के साथ NSSO अर्थहीन हो गया है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

(Central Statistical Organisation, CSO)

CSO की स्थापना मई, 1951 में की गई। CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय का एक भाग है। यह भारत में राष्ट्रीय आय तथा उससे सम्बन्धित सभी पक्षों की गणना का कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी औद्योगिक शाखा का मुख्यालय कोलकाता में है। यह अपना वार्षिक प्रकाशन 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' के नाम से प्रतिवर्ष जारी करता है।

CSO ने राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों की गणना के लिए वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया है।

CSO देश में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु उत्पादन एवं आय दोनों प्रणाली का प्रयोग करता है। CSO द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों तथा 14 उप-क्षेत्रों में (राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु) विभाजित किया गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

(National Statistical Organisation, NSC)

सी रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर 1 जून, 2005 को स्थायी सांख्यिकी आयोग गठित किया गया।

12 जुलाई, 2006 को प्रो. सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में इसने (NSC) कार्य प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, किन्तु NSSO द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य अब भी जारी है।

आर्थिक संवृद्धि (Economical Growth)

आर्थिक संवृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अथवा शुद्ध भौतिक उत्पाद में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संवृद्धि हो रही है। दूसरे शब्दों में साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक संवृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं।

आर्थिक संवृद्धि दर (Economic Growth Rate)

निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर 'आर्थिक संवृद्धि दर' (Economic Growth Rate) कहलाती है, इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है।

गतवर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एन एन पी

$$= \frac{\text{NNP में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)}}{\text{गत वर्ष का एन एन पी (NNP)}} \times 100$$

विकासशील देशों में आर्थिक संवृद्धि दर को विकास हेतु परिवर्तित करना अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है।

ट्रिकलडाउन इफैक्ट

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन **रोनाल्ड रीगन** ने वर्ष 1981 में किया, इसके अनुसार जब किसी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक संवृद्धि होती है तो उस संवृद्धि का लाभ अर्थव्यवस्था में रिस-रिस कर अर्थव्यवस्था के निचले स्तर तक जाता है, जिससे आर्थिक संवृद्धि का लाभ सभी को प्राप्त होता है।

आर्थिक विकास (Economic Development)

आर्थिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन-स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है अर्थात् इसमें आर्थिक एवं गैर-आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। आर्थिक संवृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक।

पहले का सम्बन्ध 'राष्ट्रीय आय' एवं 'प्रति व्यक्ति आय' की वृद्धि-दर से जुड़ा है, जबकि दूसरे का सम्बन्ध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढाँचे में परिवर्तन से होता है।

आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा, उद्योगों, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होता है। **आर्थिक संवृद्धि** राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि (यह एक परिमाणात्मक परिवर्तन है)। **आर्थिक विकास** राष्ट्रीय उत्पाद के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार (यह परिमाणात्मक के साथ एक गुणात्मक परिवर्तन भी है)।

आर्थिक विकास दर (Economic Development Rate)

सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर 'आर्थिक विकास दर' कहलाती है। गतवर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एन एन पी

$$\text{आर्थिक विकास दर} = \frac{\text{GDP में परिवर्तन (वृद्धि या कमी)}}{\text{गत वर्ष का एन एन पी (NNP)}} \times 100$$

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास

(Economical Growth Vs Development)

आर्थिक संवृद्धि बनाम आर्थिक विकास के मध्य अन्तर के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं

- आर्थिक संवृद्धि और विकास समान प्रतीत होने वाली अवधारणाएँ हैं, परन्तु तकनीकी दृष्टि से दोनों समान नहीं हैं।
- आर्थिक संवृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं प्रतिव्यक्ति आय में निरन्तर होने वाली वृद्धि से है अर्थात् आर्थिक संवृद्धि उत्पादन की वृद्धि से सम्बन्धित है।
- आर्थिक संवृद्धि में यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसे संवृद्धि की संज्ञा दी जाएगी।



- आर्थिक संवृद्धि से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है।
- आर्थिक विकास का सम्बन्ध लोगों के कल्याण से है, इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक संवृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है।

आर्थिक विकास का मापन

(Measurement of Economic Development)

विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के मापन तथा तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करने के निम्नलिखित दृष्टिकोण मिलते हैं

- क्रय-शक्ति क्षमता विधि
- मानव विकास सूचकांक
- ग्रीन जी एन पी
- आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम
- निवल आर्थिक कल्याण
- निर्धनता सूचकांक
- पोषण निवल राष्ट्रीय उत्पाद
- लिंग आधारित विकास सूचकांक
- जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
- राष्ट्रीय संवृद्धि सूचकांक

आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक

(Factors Determining Economic Growth)

आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले घटकों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

आर्थिक घटक (Economic Factor)

- प्राकृतिक संसाधन
- संगठन
- तकनीकी प्रगति
- पूँजी निर्माण
- विकासात्मक नियोजन
- पूँजी उत्पादन अनुपात
- श्रम-शक्ति एवं जनसंख्या
- वित्तीय स्थिरता
- आधारभूत संरचना

गैर-आर्थिक घटक (Non-Financial Component)

- सामाजिक घटक
- धार्मिक घटक
- राजनीतिक घटक

मूलभूत आवश्यक प्रत्यागम (Basic Necessity)

ये मानव विकास के मापन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले सामाजिक-सूचकांक हैं, जिसका प्रतिपादन **हिक्स व स्ट्रीटन** ने किया है, ये निम्नलिखित हैं

- प्राथमिक शिक्षा
- जीवन-प्रत्याशा
- प्रतिव्यक्ति-ऊर्जा उपभोग
- बाल मृत्यु-दर
- स्वच्छ जलापूर्ति
- आवास

महत्वपूर्ण विकास सूचकांक/ संकेतक (Important Growth Index/ Indicators)

विकास सूचकांक द्वारा विभिन्न देशों के जीवन स्तर, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को मापने का तुलनात्मक पैमाना है।

महत्वपूर्ण विकास सूचकांक निम्नलिखित हैं

1. मानव विकास सूचकांक
2. जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक
3. बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक
4. वैश्विक भुखमरी सूचकांक
5. लैंगिक विकास सूचकांक
6. मानव गरीबी सूचकांक
7. राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक

1. मानव विकास सूचकांक

(Human Development Index, HDI)

मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) से सम्बद्ध अर्थशास्त्रियों महबूब उल-हक, ए के सेन तथा सिंगर हंस ने किया था। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा व आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का सूचकांक है। HDI का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। एच डी आर वर्ष 2010 में, विषमता समायोजित एच डी आई बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (MPI) तथा जेण्डर इनइक्विटी इण्डेक्स (GII) की धारणा विकसित की गई है, जिसे यदि HDI में जोड़ दिया जाए तो आर्थिक विकास का अधिक स्पष्ट चित्र सामने आ सकता है।

मानव विकास सूचकांक की रचना तीन सूचकों के आधार पर होती है

- (i). जीवन-प्रत्याशा सूचकांक
- (ii). शिक्षा सूचकांक



(iii). जीवन-निर्वाह का स्तर जिसमें क्रय-शक्ति, समायोजित प्रति व्यक्ति आय (डॉलर में) व्यक्त करते हैं।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण	
वर्ग	एच डी आई का मान-विस्तार
अति उच्च	1.00-0.900
उच्च	0.899-0.800
मध्यम	0.799-0.500
निम्न	0.499-0.000

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

प्रतिवर्ष UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है।

शैक्षणिक उपलब्धि (Educational Achievement)

ज्ञान या शैक्षणिक उपलब्धि के मापन हेतु वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त नामांकन अनुपात (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नामांकन) का उपयोग किया जाता है। बालिग साक्षरता को दो-तिहाई वजन तथा संयुक्त नामांकन अनुपात को एक-तिहाई वजन दिया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)

इसे मापने हेतु प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद को आधार बनाया गया है, जिसमें जीवन-स्तर प्रभावित होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक तीन सूचकांकों- जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल राष्ट्रीय आय का औसत सूचकांक है। इस सूचकांक के लिए स्वास्थ्य स्तर का आकलन जीवन-प्रत्याशा (Expectancy of Life) के द्वारा, शैक्षणिक स्तर का प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पंजीकरण के आधार पर तथा रहन-सहन का स्तर का आकलन आय के स्तर एवं क्रय-शक्ति क्षमता के आधार पर किया जाता है।

सकल राष्ट्रीय खुशहाली (Gross National Happiness, GNH)

जी एन एच देश की गुणवत्ता को अधिक समग्र तरीके से मापता है और इसके तहत ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव समाज का विकास तब होता है, जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास साथ-साथ होते हैं और वे एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इसकी अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के नरेश जिग्मे सिंग्मे वांगचुक ने की थी। मेड जॉन के अनुसार, जी एन एच को मापने के लिए सात खुशी पर विचार किए जाते हैं

1. शीरीरिक
2. मानसिक
3. अच्छा शासन
4. सामाजिक
5. आर्थिक
6. कार्यस्थल
7. पारिस्थितिक जीवन शक्ति

भारत की मानव विकास रिपोर्ट (HDR, India)

सर्वप्रथम वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी बाद में कर्नाटक, गुजरात तथा राजस्थान द्वारा भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है।

भारत (UNDP) कण्ट्री प्रोग्राम दस्तावेज (2013-17)

नया कण्ट्री प्रोग्राम दस्तावेज (2013-17) सरकार द्वारा यू एन डी पी के कण्ट्री कार्यक्रम में तैयार किया गया। यह कार्यक्रम भारत संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढाँचे (2013-17) पर आधारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार मुख्य

बातों को समाहित किया गया है; समाविष्ट वृद्धि, गवर्नेंस, धारणीय विकास एवं लैंगिक समानता आदि।

2. जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक

(Physical Quality of Life Index, PQLI)

इस अवधारणा का विकास वर्ष 1979 में मौरिश डी मौरिश ने किया, इन्होंने विकास के प्रयासों के परिणामों को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत करने के लिए तीन संकेतकों का चुनाव किया, जो निम्नलिखित हैं

- (i). जीवन-प्रत्याशा (Life Expectancy)
- (ii). शिशु मृत्यु-दर (Infant Mortality Rate)
- (iii). मौलिक साक्षरता (Basic Literacy)

3. बहु आयामी निर्धनता सूचकांक

(Multi-dimensional Poverty Index, MPI)

बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक का विकास वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एवं ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास की पहल पर हुआ।

इस सूचकांक के निम्न तीन आयाम और 10 संकेतक हैं। इन सभी संकेतकों को समान महत्व प्राप्त है।

आयाम	संकेतक
स्वास्थ्य	शिशु मृत्यु-दर; पोषण
शिक्षा	विद्यालय अवधि; विद्यार्थी नामांकन
जीवन-स्तर	भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, पानी, विद्युत, शौचालय, आवास, सम्पत्ति

4. वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index, GHI)

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में एक बहु-आयामी सांख्यिकीय आँकड़ों का प्रयोग कर देश की भुखमरी के सन्दर्भ में स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस सूचकांक को इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 2006 में हुआ। यह सूचकांक प्रतिवर्ष निकाला जाता है। प्रत्येक वर्ष इस सूचकांक में किसी एक मुख्य मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जोकि भुखमरी को प्रभावित करता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक तीन मानकों के आधार पर निकाला जाता है।

- (i). अल्प पोषित लोगों का अनुपात।
- (ii). पाँच वर्ष से कम आयु के औसत से कम वजन के बच्चों का अनुपात।
- (iii). पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर।

5. लैंगिक विकास सूचकांक

(Gender Development Index, GDI)

इस सूचकांक को UNDP ने वर्ष 1995 में विकसित किया था। लैंगिक विकास सूचकांक (GDI) मानव विकास के तीन आयामों- जीवन-प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के सन्दर्भ में पुरुष जनसंख्या के सापेक्ष महिला जनसंख्या की उपलब्धि को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- मानव विकास सूचकांक का विचार सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने दिया था।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी।



- वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की उपलब्धि 21.3 है, जोकि काफी बुरी स्थिति की ओर इशारा करती है।

6. मानव गरीबी सूचकांक (Human Poverty Index, HPI)

इसमें अग्रलिखित सूचकांकों को शामिल किया जाता है जीवन-प्रत्याशा, साक्षरता, आय तथा सामाजिक वंचन। इसके आधार पर समाज की अभावग्रस्तता का पता लगाया जाता है। विकासशील और विकसित देशों के लिए अलग-अलग सूचकांकों की संकल्पना है। विकासशील देशों के लिए HPI-1 की संकल्पना एवं विकसित देशों के लिए HPI-2 की संकल्पना है।

विकासशील देशों के लिए HPI-1 की संकल्पना

- इस संकल्पना के अन्तर्गत जनसंख्या के उस भाग का पता लगाया जाता है, जिसकी जीवन-प्रत्याशा 40 वर्ष या उससे कम हो।
- प्रौढ़ शिक्षा दर 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले जनसंख्या के उस भाग का पता लगाया जाता है, जो निरक्षर है।
- स्वच्छ पेयजल से वंचित जनसंख्या का प्रतिशत।
- 5 वर्ष तक की आयु वाली जनसंख्या के उस भाग का प्रतिशत जिसका वजन औसत से कम है।

विकसित देशों के लिए HPI-2 की संकल्पना

- इसके अन्तर्गत जनसंख्या के उस अंश का पता लगाया जाता है, जिसकी जीवन-प्रत्याशा 60 वर्ष से कम है।

- श्रम शक्ति के उस अंश का पता लगाया जाता है, जो पिछले 12 महीने से बेरोजगार है और सामाजिक रूप से वंचित है, जिनकी आय मध्यम-आय के 50% से कम है। इस प्रकार HPI क्रय क्षमता पर आधारित आय और प्रति व्यक्ति आय को समाहित करता है।

7. राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक

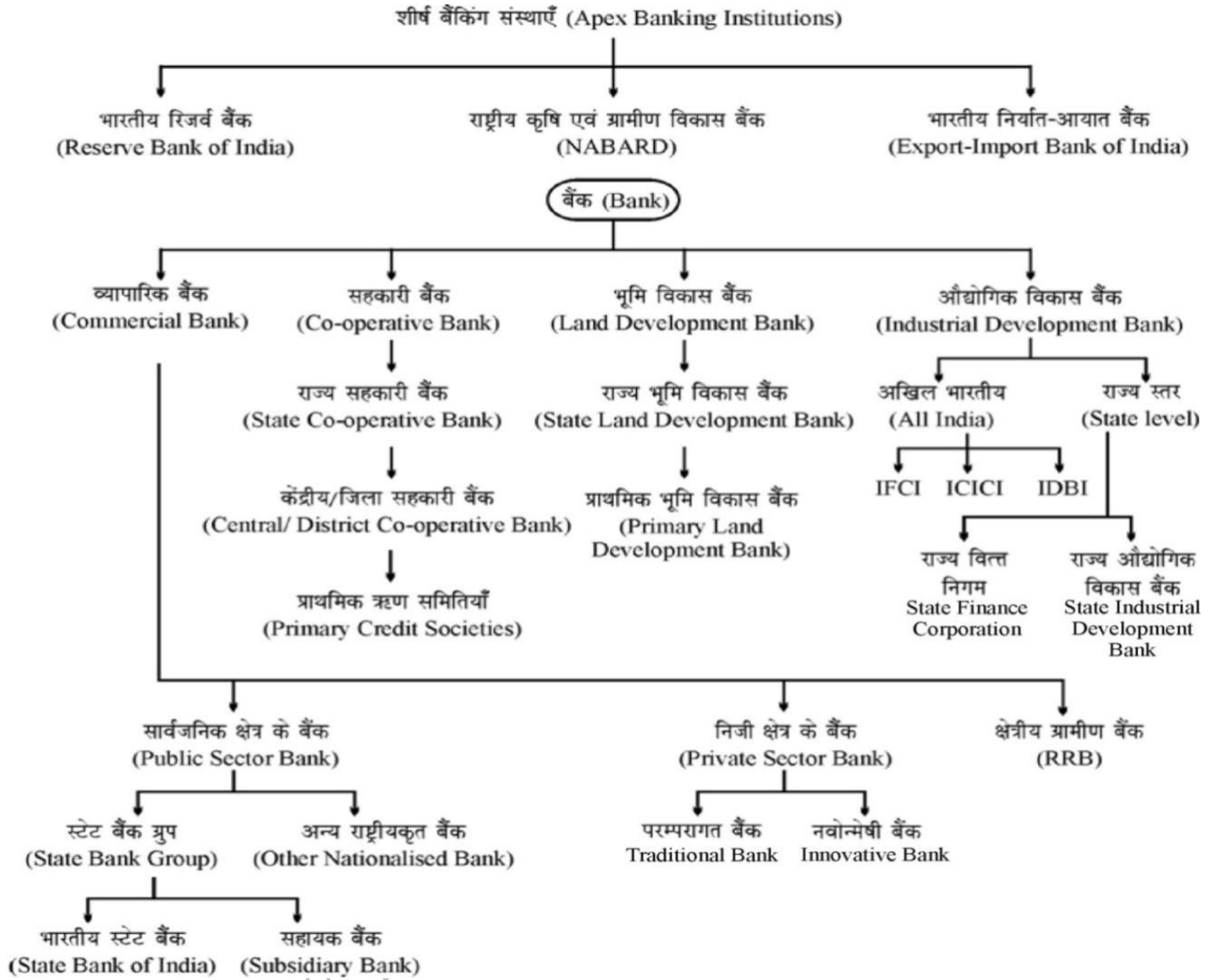
(National Prosperity Index, NPI)

सामाजिक-आर्थिक विकास के मापन को मानक सूचकांक, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक को माना जाता है। इसके तीन घटक हैं

- GDP की वृद्धि दर
 - जीवन की गुणवत्ता में सुधार (मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का)
 - अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित नैतिक मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना।
- उल्लेखनीय है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शुद्ध पेयजल, पोषण, आवासीय व्यवस्था, उचित सफाई, उत्तम स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा तथा रोजगार आदि सम्भाव्यताओं का फलन है। जबकि सांस्कृतिक विरासत, सामाजिकता, समन्वय, सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, सामाजिक विषमता का अभाव, सहभागिता, समरसता तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित करने पर निर्भर करती है।

बैंकिंग ज्ञान

भारतीय बैंकिंग संरचना



भारत में बैंकिंग का इतिहास (History of Banking in India)

भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास को निम्न छः चरणों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्रथम अवस्था (First Phase) (सन् 1806 तक)

17वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल के साथ ही भारतीय साहूकारी वित्त व्यवस्था को गम्भीर आघात लगा। इसका मुख्य कारण यह था कि साहूकार अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। अतः इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने मुम्बई तथा कोलकाता में कुछ एजेंसी गृहों (Agency Houses) की स्थापना की थी। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इन एजेंसी गृहों का वित्त पोषण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेंसी गृहों का मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूँजी के सहयोग से एलेक्जेंडर एण्ड कम्पनी द्वारा बैंक ऑफ हिन्दुस्तान के नाम से 1770 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, किन्तु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। इस प्रकार 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेंसी गृहों द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था।

2. द्वितीय अवस्था (Second Phase) (सन् 1806 से 1860 तक)

सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। यद्यपि यह तीनों बैंक निजी शेयरहोल्डरों (विशेष रूप से विदेशी व्यक्तियों) के बैंक थे तथापि इन तीनों बैंकों की शेयर पूँजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था। अतः सरकार इन तीनों बैंकों पर अपना नियन्त्रण रखती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया। सरकारी बैंक होने के कारण सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगाए गए थे। यह बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे तथा इनके द्वारा दिए गए ऋणों की समयावधि छः महीने से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों का क्रय-विक्रय करने का अधिकार भी नहीं था। आगे चलकर सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गई और 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रख दिया गया।

3. तृतीय अवस्था (Third Phase) (सन् 1860 से 1913 तक)

भारत सरकार द्वारा सन् 1860 में एक संयुक्त पूँजी कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इसके अन्तर्गत, बैंकों का सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर गठन किया जा सकता था। इस कानून के फलस्वरूप भारत में संयुक्त पूँजी वाले बैंकों की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक संयुक्त पूँजी बैंक स्थापित हो गए। उनमें प्रमुख बैंक थे-

इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), अवध कॉमर्शियल बैंक (1881), पंजाब नेशनल बैंक (1894), पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901)। सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक (सन् 1900 तक) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी, किन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ अर्थात् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। मुख्य रूप से उत्तरी भारत में नए बैंकों का जाल-सा बिछ गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ किया जाना था। इस आन्दोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार करके भारतीय बैंकों के साथ व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया था। इसी अवधि में देश के तत्कालीन चार बड़े बैंकों-बैंक ऑफ इण्डिया (1906) बैंक ऑफ बड़ौदा (1908) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1911) एवं बैंक ऑफ मैसूर (1913) की स्थापना की गई और अन्य छोटे बैंकों की संख्या 500 तक पहुँच गई।

4. चतुर्थ अवस्था (Fourth Phase) (सन् 1913 से 1939 तक)

1913 से 1917 का काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-18) के प्रारम्भ होने के साथ ही, भारतीय बैंकिंग की इस तीव्र वृद्धि का क्रम अवरूद्ध हो गया। सन् 1913 में अनेक भारतीय बैंक असफल हो गए। भारतीय बैंकों से जनविश्वास समाप्त होने की वजह से जमाकर्ताओं द्वारा अपने निक्षेप निकालने प्रारम्भ कर दिए गए तथा भारतीय मुद्रा बाजार में मुद्रा की बहुत कमी हो गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् देश में पुनः बैंकिंग विकास की दर तेज हुई। सन् 1917 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। बाद में सन् 1955 में उस बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का नाम दिया गया।

तीसा की विश्वव्यापी महान मंदी ने भी तत्कालीन भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, फिर भी विकास का क्रम जारी रहा। सन् 1930 में ही केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति का गठन किया गया। समिति का सुझाव था कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों के संगठन, प्रबन्ध, अंकेक्षण तथा समापन के लिए व्यापक व्यवस्था की जा सके। सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया तथा अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, किन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

5. पंचम अवस्था (Fifth Phase) (सन् 1939 से 1946 तक)



यह अवधि बैंकिंग विस्तार की अवधि कही जा सकती है। द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न मुद्रा प्रसार के कारण जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई फलतः सभी बैंकों के निक्षेप (Deposits) बढ़ गए।

युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नई-नई शाखाओं की स्थापना की तथा नए-नए बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना भी इसी काल में हुई थी। युद्धकाल में बैंकों की निवेश नीति (Investment policy) में कुछ आधारमूलक परिवर्तन हुए थे। बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना प्रारम्भ कर दिया था। युद्ध के पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54% सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61% कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय बैंकों ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोष (Cash Reserves) रखने प्रारम्भ कर दिए थे। युद्ध के पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग 11 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखा करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था।

6. षष्ठम् अवस्था (Sixth Phase) (सन् 1947 से अब तक)

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी, 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करने के लिए इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का नाम 1 जुलाई, 1955 को आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य 8 (जो वर्तमान में 5 हैं) बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया गया इसका नाम जिन्हें 'स्टेट बैंक समूह' के बैंक कहा जाता है।

ये बैंक निम्नलिखित हैं-

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर दोनों अलग-अलग थे। दोनों के कार्य क्षेत्रों में एकरूपता होने के कारण इन्हें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में बदल दिया गया।)

2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

5. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

7. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर

उपर्युक्त सात बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जुलाई 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का जून 2009 में SBI में विलय करने के निर्णय के फलस्वरूप SBI समूह में पाँच बैंक ही रह जाएँगे।

बैंकों को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से, देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रूपए से अधिक थीं। ये बैंक थे-

(1) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, (2) बैंक ऑफ इण्डिया, (3) पंजाब नेशनल बैंक, (4) केनरा बैंक, (5) यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, (6) सिंडीकेट बैंक, (7) बैंक ऑफ बड़ौदा, (8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, (9) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, (10) देना बैंक, (11) इलाहाबाद बैंक, (12) इण्डियन बैंक, (13) इण्डियन ओवरसीज बैंक, (14) बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

एक दशक पश्चात् 15 अप्रैल, 1980 को पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रूपए से अधिक थीं।

ये बैंक निम्नलिखित थे-

(1) आन्ध्रा बैंक, (2) पंजाब एण्ड सिंध बैंक, (3) न्यू बैंक ऑफ इण्डिया,

(4) विजया बैंक, (5) कॉर्पोरेशन बैंक, (6) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स।

4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटाकर 19 रह गई।

चरण	स्थापित बैंक	वर्ष
प्रथम चरण	बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
द्वितीय चरण	बैंक ऑफ बंगाल	1806
	बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
	बैंक ऑफ मद्रास	1843
तृतीय चरण	इलाहाबाद बैंक	1865
	एलाइंस बैंक ऑफ शिमला	1881
	अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
	पंजाब नेशनल बैंक	1894
	बैंक ऑफ इण्डिया	1906
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1908
	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1911
	बैंक ऑफ मैसूर	1913
चतुर्थ चरण	इम्पीरियल बैंक	1921
	भारतीय रिजर्व बैंक	1935
पाँचवां चरण	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	
	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	
षष्ठम चरण	भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी, 1949
	भारतीय स्टेट बैंक	1955
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1964
सप्तम चरण	आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक आदि	



भारतीय वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank of India)

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के पंजीकृत बैंकों को वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी गई। इन बैंकों को भारतीय बैंक विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शाखित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों से आशय उन बैंकों से है जो देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण**(Classification Of Commercial Banks):**

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित बैंक तथा गैर-अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है।

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank):

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त करने के लिए बैंको को निम्नवत् शर्तें पूरी करनी होती हैं-

- बैंक की प्रदत्त पूँजी तथा संचित राशि 5 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे जमाकर्ताओं का अहित हो।
- यह एक संयुक्त पूँजी कम्पनी होनी चाहिए न कि एकल व्यापारी अथवा साझा फर्म।

इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप से रखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर विवरण-पत्र भी भेजना पड़ता है।

अनुसूचित बैंक को निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं-

- (i) वह बैंक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- (ii) प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।
- (iii) ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक प्रथम श्रेणी के विनियम पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है, किन्तु इन सुविधाओं के बदले अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके (RBI) द्वारा निर्धारित औसत दैनिक नकद कोष रखना पड़ता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आवर्ती विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled Bank)

गैर-अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। परन्तु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन है और इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का अधिकार है। गैर-अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है।



भारत में बैंको के विकास के चरण (Stages of Development of Banks in India)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI) की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से हुई थी। यह 5 करोड़ रुपये की पूंजी 100 रुपये मूल्य के 5 लाख अंशों (Shares) में विभाजित थी। प्रारम्भ में लगभग समस्त अंश पूंजी का स्वामित्व गैर-सरकारी अंशधारियों के पास था, किन्तु अंशों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (Governor of RBI):

क्र.स.	गवर्नर	कार्यकाल
1.	सर ओसबोर्न स्मिथ (Sir Osborne Smith)	1-4-35 से 30-6-37
2.	सर जेम्स टेलर (Sir James Taylor)	1-7-37 से 17-2-43
3.	सर सी. डी. देशमुख	11-8-43 से 30-6-49
4.	सर बेनेगल रामाराउ	1-7-49 से 14-1-57
5.	के. जी. अंबेगांवकर	14-1-57 से 28-2-57
6.	एच. वी. आर. आयंगर	1-3-57 से 28-2-62
7.	पी.सी. भट्टाचार्य	1-3-62 से 30-6-67
8.	एल.के. झा	1-7-67 से 3-5-70
9.	बी. एन. अदरकर	4-5-70 से 15-6-70
10.	एस. जगन्नाथन	16-6-70 से 19-5-75
11.	एन. सी. सेनगुप्ता	19-5-75 से 19-8-75
12.	के. आर. पुरी	20-8-75 से 2-5-77
13.	एम. नरसिंहम	2-5-77 से 30-11-77
14.	आई. जी. पटेल	1-12-77 से 15-9-82
15.	डॉ. मनमोहन सिंह	16-9-82 से 14-1-85

16.	ए. घोष	15-1-85 से 4-2-85
17.	आर. एन. मन्होत्रा	4-2-85 से 22-12-90
18.	एस. वेंकटरमणन	22-12-90 से 21-12-90
19.	डॉ. सी. रंगराजन	22-12-92 से 21-11-97
20.	डॉ. बिमल जालान	22-12-97 से 6-9-03
21.	डॉ. वाई. वी. रेड्डी	6-9-03 से 5-9-08
22.	डी. सुब्बाराव	5-9-08 से 5-9-13
23.	डॉ. रघुरामराजन	5-9-13 से 4-9-16
24.	उर्जित पटेल	4-9-16 से अब तक

रिजर्व बैंक के कार्यालय (Office Of Reserve Bank):

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय अथवा मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के चार स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मद्रास तथा मुम्बई में हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, गौहाटी, जयपुर, मद्रास, हैदराबाद, मुम्बई, कानपुर, नागपुर तथा पटना में शाखा कार्यालय भी हैं। जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं हैं। वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय लन्दन में भी है जिसका कार्य अधिकता के कार्यों को करने के अतिरिक्त भारत के उच्च आयुक्त का हिसाब-किताब भी रखना है।

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना

(Structure/ Composition of RBI)

बैंक में सामान्य प्रबन्ध एवं निर्देशन का कार्य 21 सदस्यों पर आधारित केन्द्रीय निदेशक मण्डल को सौंपा गया। इसमें एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, दो वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित दस ऐसे निदेशक होते हैं, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार निदेशक स्थानीय बोर्डों (Local Boards) का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। स्थानीय बोर्डों के पाँच सदस्य होते हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रीय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है।

वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छानुसार बोर्ड (मण्डल) में बना रहता है।

रिजर्व बैंक के विभाग (Department of RBI)



रिजर्व बैंक के निम्नलिखित विभाग हैं

1. नोट जारी करने वाला विभाग (Note Issuing Department)

इस विभाग को नोट नासिक में स्थित इण्डियन सिक्क्योरिटी प्रेस (Indian Security Press) से प्राप्त होता है और यह विभिन्न टेजरी में वितरित करता है। नोट जारी करने के लिए सम्पूर्ण देश को सात क्षेत्रों (Circles) में विभाजित कर दिया गया है।

भारत में व्यापारिक दृष्टि से अक्टूबर-नवम्बर से अप्रैल-मई तक काल 'व्यस्त काल' (busy season) होता है, जिसमें मुद्रा तथा सरख में माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत, मई-जून से सितम्बर-अक्टूबर तक का काल 'शिथिल काल' (Slack season) कहलाता है जिसमें व्यापारी तथा उद्योगपति अपने ऋण लौटाने लगते हैं। प्रायः देखा गया है कि रिजर्व बैंक 'व्यस्त काल' में निर्गमित नोटों की मात्रा बढ़ाता है और 'शिथिल काल' में कम कर देता है।

2. बैंकिंग विभाग (Banking Department)

रिजर्व बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता है और यह बैंकों का बैंक भी है। यह विभाग चार विभागों में विभाजित है- राजकीय ऋण, राजकीय लेखा (Public Accounts), जमानत (Securities) तथा जमा-खाता (Deposit Accounts)

3. कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)

इस विभाग का काम कृषि-साख के विषय में छानबीन करना है। यह मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय दफ्तर में स्थित है। इस विभाग के चार हिस्से हैं

- वित्त तथा निरीक्षण (Finance and Inspection)
- योजना तथा व्यवस्था (Planning and Organisation)
- सहकारी प्रशिक्षण और प्रकाशन (Co-operative Training and Publication) तथा
- हथकरघा-वित्त (Handloom Finance)

4. विनियम-नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)

इस विभाग का निर्माण 1939 ई० में हुआ। इसका काम विदेशी विनियम पर नियन्त्रण रखना था। 1947 ई० के सन्निधिम ने विनियम-नियन्त्रण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को बहुत अधिकार दिए हैं, इसकी शाखाएँ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में स्थित हैं।

5. निरीक्षण विभाग (Inspection Division)

यह विभाग केन्द्रीय बैंक के विभिन्न ऑफिसों की समय-समय पर जाँच करता है।

रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य (Main Functions Of Reserve Bank)

भारत का केन्द्रीय बैंक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य काफी विस्तृत तथा विभिन्न प्रकार के हैं-

करेंसी नोटों का निर्गमन (Issue of Currency Notes)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, रिजर्व बैंक को एक रुपए के सिक्के/नोटों एवं छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग (Various Denomination) के करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। करेंसी नोटों के निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक अलग

नोट निर्गमन विभाग है। मूल्य अधिनियम के अनुसार नोट निर्गमन के पीछे स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूतियों का आनुपातिक कोष (Proportional Reserve) रखना पड़ता था। भारत में योजनाओं का युग प्रारम्भ होने पर मुद्रा प्रणाली में कुछ अधिक लोच लाने के लिए अक्टूबर, 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया तथा पत्र-मुद्रा निर्गमन की आनुपातिक कोषण प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपनाया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार विदेशी प्रतिभूतियाँ केवल 85 करोड़ रुपए रखना आवश्यक रह गया।

सरकारी बैंकर का काम करना (Work of Government Banker)

रिजर्व बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट तथा आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के नकद कोष रखने तथा सरकार के भुगतानों को स्वीकार करने का काम करता है, परन्तु वह इसके बदले में किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। रिजर्व बैंक सरकार की कर्तों से होने वाली आय को जमा करता है, सरकार के आदेशानुसार भुगतान करता है और सरकारी कोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित करता है। सार्वजनिक ऋण की सम्पूर्ण व्यवस्था करना, उनको जमा कराना तथा उनका भुगतान कराना रिजर्व बैंक का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के लिए ट्रेजरी बिलों का विक्रय, केन्द्र व राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराने (ऋण या तो माँग पर शोधनीय होने चाहिए अथवा अधिक से अधिक 90 दिन के भीतर शोधनीय कामचलाऊ अग्रिम होना चाहिए) आदि का काम भी करता है।

बैंकों के बैंक का कार्य (Work as Bankers of Banks)

देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से रिजर्व बैंक को मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों पर अधिकार प्राप्त है। बैंकिंग व्यवसाय से जुड़ी कोई भी कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपयों से अधिक हो, रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में शामिल कर ली जाती है और अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) कहलाती है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों की स्वीकृति बिलों की पुनर्कटौती (rediscounting) तथा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देकर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सहकारी तथा अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक प्रेषण (remittance) सुविधाएँ भी प्रदान करता है। यदि रिजर्व बैंक अनुभव करता है कि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उसका निस्तारण (Liquidation) जमाकर्ताओं तथा मुद्रा बाजार के हित में है तो रिजर्व बैंक उस बैंक विशेष को इस सम्बन्ध में आदेश देकर निस्तारण करवा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों की संख्या एवं नवीन शाखाओं पर नियन्त्रण रखना, विभिन्न बैंकिंग व्यवसाय सम्बन्धी विवरणों की प्राप्ति तथा निरीक्षण करना, बैंकों अथवा बैंक विशेष के किसी विशेष लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगाना, बैंक की साख निर्माण सम्बन्धी नीति को निर्धारित करना, प्रत्येक बैंक से वार्षिक स्थिति विवरण (Balance Sheet) तथा लेखा परीक्षक (auditor) की रिपोर्ट सहित अन्य लेखे प्राप्त करना तथा संकट काल में बैंकों को आवश्यक सलाह तथा आर्थिक सहायता देना, इत्यादि भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य विशेषाधिकार हैं।



विदेशी विनियम का नियन्त्रण

(Control Of Foreign Regulations)

रिजर्व बैंक देश के विदेशी विनियम भण्डार के परिरक्षक (Custodian) के रूप में कार्य करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक विदेशी विनियम दर के स्थिर रखने का काम करता है तथा इसके लिए प्रायः मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का सहारा लेता है। फरवरी, 1947 तक रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत विनियम नियन्त्रण करता था, लेकिन विदेशी विनियम नियमन अधिनियम, 1947 (FERA, 1947) के बन जाने से इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को स्वतन्त्र उत्तरदायित्व मिल गया। इस अधिनियम का स्थान बाद में विदेशी विनियम नियमन अधिनियम, 1973 ने ले लिया, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे। विदेशी विनियम नियमन अधिनियम (FERA) के स्थान पर अब विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम (FEMA) लागू कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of Reserve Bank)

केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य	सामान्य बैंकिंग के रूप में कार्य
नोट निर्गमित करना	जमा प्राप्त करना
सरकार का बैंकर	अल्पावधि ऋण देना
बैंको का बैंकर	अल्पावधि ऋण लेना
विनियम दर को स्थिर रखना	विपत्रों को भुनाना व क्रय-विक्रय
साख नियन्त्रण	कृषि विपत्रों का क्रय-विक्रय
समाशोधन गृह का कार्य	विदेशी विनियम विपत्रों का क्रय-विक्रय
कृषि साख की व्यवस्था	मूल्यवान धातुओं का क्रय-विक्रय
औद्योगिक वित्त व्यवस्था	बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना
बिल बाजार का विकास	विश्व बैंक में खाता खोलना
प्रशिक्षण व्यवस्था	अन्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों में खाता खोलना
आँकड़ों का संकलन व प्रकाशन	

प्रतिबन्धित कार्य जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता (Restricted Work Which Reserve Bank Can Not Perform)

रिजर्व बैंक अन्य बैंकों का प्रतियोगी (Competitor) न बन जाए, इसके लिए सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता।

- वह अचल सम्पत्ति के जमानत पर कर्ज नहीं दे सकता।
- ऐसी सम्पत्ति को अपने इस्तेमाल के लिए भी नहीं खरीद सकता।
- वह बिना जमानत लिए कर्ज (unsecured loan) नहीं दे सकता।

(iv) वह किसी कम्पनी या बैंक के अंशों को न तो स्वयं खरीद सकता है और न किसी जमानत पर कर्ज ही दे सकता है।

(v) वह केवल उन्हीं बिलों को जारी कर सकता है या भुना सकता है, जो माँग पर देय हों।

(vi) वह व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य में निश्चित काल के लिए भाग नहीं ले सकता।

➤ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

✍ सन् 1925-26 ई. में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने सरकार को बताया कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए।

✍ इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया जिसकी स्थापना सन् 1921 ई. में गयी थी, पूर्ण रूप से केन्द्रीय बैंक का कार्य नहीं कर रहा था। नोट छापने का अधिकार सरकार को था और बैंकों के बैंक (Banker's Bank) की हैसियत से इम्पीरियल बैंक ही कार्य करता था।

✍ इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता करता था। अतएव अन्य बैंकों को इस पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसे केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं था।

✍ इम्पीरियल बैंक के लिए सम्भव नहीं था कि वह केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के साथ-साथ साधारण बैंकिंग के कार्य भी कर सके। इसका संचालन-मण्डल यह मानने को तैयार नहीं था कि इम्पीरियल बैंक साधारण बैंकिंग कार्य को छोड़ दे।

✍ मुद्रा तथा साख पर सरकार एवं इम्पीरियल बैंक का दोहरा नियन्त्रण दोषपूर्ण था और इसके लिए केन्द्रीय बैंक का होना अत्यन्त आवश्यक था। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी अनुभव किया कि एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सन् 1934 ई. में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास किया गया और इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1935 ई. को रिजर्व बैंक ने अंशधारियों के बैंक के रूप में अपना कार्य शुरू किया।

✍ 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया।

✍ आर. बी. आई. की स्थापना 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ हुई। इसमें भारत सरकार का शेयर 5 प्रतिशत था और शेयर पूँजी 5 करोड़ (जोकि अब तक है) की थी।

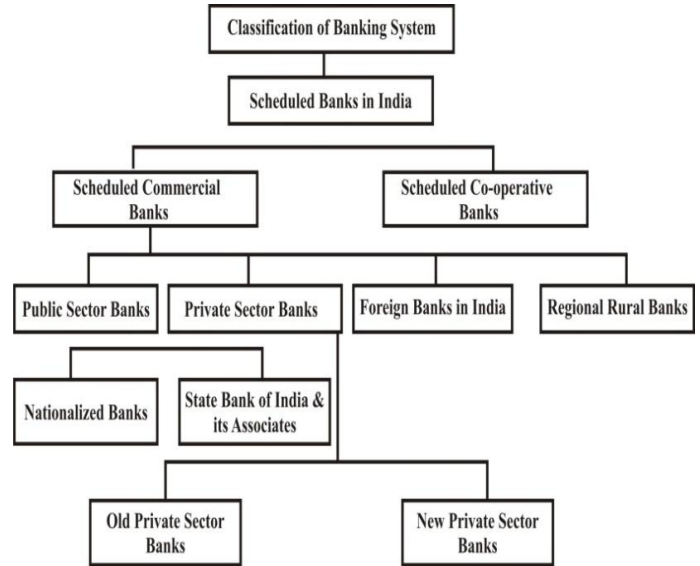
✍ यह बैंक वास्तविक तौर पर उस समय के बेहतर विदेशी केन्द्रीय बैंकों के मॉडल पर शेयर पूँजी 5 करोड़ रुपये का 100 रु-पये मूल्य के 5 लाख के शेयरों में बाँटा गया।

✍ प्रारम्भ में, केन्द्रीय सरकार को आवंटित 2,200 शेयरों को छोड़कर बाकी शेष सभी निजी शेयर धारकों के थे।



- ✍ फरवरी 1947 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप) अधिनियम 1948 के अनुसार सम्पूर्ण शेयर पूँजी केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित मान ली गयी।
- ✍ 1 जनवरी, 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र का संस्थान हो गया। 1948 का अधिनियम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनता के हित के लिए इस बैंक को निर्देश दे सकती है।
- ✍ भारत में अक्टूबर से मई तक का समय व्यापारिक दृष्टि से व्यस्त काल होता है और इस समय मुद्रा की माँग अधिक होती है। रिजर्व बैंक इस अवधि में मुद्रा के प्रचलन की मात्रा को बढ़ाता है। मई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी होती है, क्योंकि यह व्यापार में कमी का काल होता है। इस मंदी काल में रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा में कमी करता है।
- ✍ जून, 1948 तक RBI ने पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था।
- ✍ 14 जनवरी, 1935: भारतीय रिजर्व बैंक के सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की पहली बैठक कोलकाता में हुई।
- ✍ 1 अप्रैल 1935 : शेयर धारकों के बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ। सर ओसबोर्न एस. स्मिथ (Sir Osborne S. Smith) भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरम्भ में बैंक कुछ विभागों के साथ शुरू हुआ जैसे- नोटों का निर्गमन, बैंकिंग कृषि साख विभाग, लोक ऋण कार्यालय, जमा खाता और शेयर हस्तांतरण विभाग।
- ✍ 18 मार्च 1937: आर. बी. आई. ने बर्मा सरकार के बैंक के रूप में कार्य किया और 18 मार्च का बर्मा मौद्रिक प्रबन्ध आदेश 1937 के अनुसार बर्मा में नोट भी जारी किया।
- ✍ दिसम्बर 1937: रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय स्थायी रूप से कलकत्ता से बम्बई हस्तान्तरित किया गया।
- ✍ जनवरी 1938 : रिजर्व बैंक ने अपने करेंसी नोट जारी किये।
- ✍ 12 जनवरी, 1946 : ₹500, ₹1000 और ₹10,000 के बैंक नोट को demonetize किया गया।
- ✍ जनवरी 1947: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- ✍ मार्च 1947: विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट 1947 (Foreign Exchange Regulation Act, 1947) पास हुआ।
- ✍ 31 मार्च, 1947 : भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।

- ✍ RBI के निर्देशानुसार बैंकों को अपनी उधारियों का कम-से-कम 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है तथा इसमें से 18% भाग बैंकों से कृषि को उपलब्ध कराना होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं उनके विरुद्ध RBI उचित कार्यवाही भी कर सकता है। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 32% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक के उदय की शुरुआत उन्नीसवीं सदी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। तीन वर्ष बाद इस बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और उसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूँजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के उपरान्त बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई, 1843 को की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 27 जनवरी, 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का गठन किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक का उदय (Rise of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का अभ्युदय 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप हुआ। अगस्त 1955 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की अनुशंसा पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया।

1959 में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने पूर्ववर्ती राज्यों के सात सहयोगी बैंकों का अनुषंगी के रूप में अधिग्रहण किया। इस प्रकार भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव सामाजिक उद्देश्य के नए दायित्व के साथ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध किए गए 7 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक का अनुषंगी बैंक कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक निम्नवत् हैं-



बैंक का नाम	सहायक बैंक के रूप में कार्य आरम्भ करने की तिथि
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1 अक्टूबर, 1959
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ जयपुर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1 मई, 1960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1 अप्रैल, 1960
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1 मार्च, 1960
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1 जनवरी, 1960
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1 जनवरी, 1960

सहायक बैंकों के रूप में इन बैंकों का पृथक् अस्तित्व बनाये रखने का एकमात्र कारण 'अपने-अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति' ही था। 1 जनवरी, 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है। इस तिथि से स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की संख्या सात ही रह गई।

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन (Management Of State Bank Of India)

भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन एक 20 सदस्यीय केन्द्रीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। बैंक के केन्द्रीय संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष तथा 2 प्रबंध निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते हैं। इनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से करती है। केन्द्रीय संचालक मण्डल के 6 सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक के कार्य (Operations Perform By State Bank Of India)

स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. बैंकों के बैंक के रूप में कार्य- बैंकों के बैंक के रूप में स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य करता है-
 - (i) यह व्यापारिक बैंकों से जमाएँ स्वीकार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी देता है।
 - (ii) यह व्यापारिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
 - (iii) यह रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सभी व्यापारिक बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है।

2. रिजर्व बैंक का एजेंट (Agent of Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की अनुमति से स्टेट बैंक उसके एजेंट का कार्य कर सकता है। एजेंट के रूप में यह रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित कार्य करता है उसके लिए वह कमीशन भी प्राप्त करता है। यह उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक अपने स्थापना के वर्ष (1955) से ही रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य कर रहा है।

3. ऋण देना (Lending)

स्टेट बैंक का दूसरा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण देना है। ये ऋण सामान्यतः माल, सम्पत्तियों तथा प्रतिभूतियों की जमानत पर-नकद साख द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा तथा हुण्डियों द्वारा दिये जाते हैं।

4. जमाएँ स्वीकार करना (Accept Deposits)

स्टेट बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों की भाँति जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएँ स्वीकार करता है। अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक भी चालू खाता, स्थायी जमा खाता, संचिति खाता, बचत खाता आदि खाते खोलकर जनता की जमाओं को आकर्षित करता है। इनके द्वारा भी व्यापारिक बैंकों की भाँति ब्याज दिया जाता है।

5. ग्रामीण साख का विकास (Development of Rural Credit)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण साख के विभिन्न अंगों का विकास करना है। अतः यह बैंक सहकारी बिक्री और गोदाम व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

6. ग्रामीण बचत का संग्रह करना (Collecting Rural Savings)

स्टेट बैंक का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएँ खोलकर उनकी बचतों का संग्रह करना है तथा ग्रामीण जनता में बचत करने की भावना को प्रेरित करना है।

7. **अभिगोपन (Preferentiality)** स्टेट बैंक द्वारा अंशों, ऋण-पत्रों तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का अभिगोपन किया जा सकता है।

8. **सम्पत्ति की सुरक्षा (Security Of Assests)** स्टेट बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई मूल्यवान वस्तुएँ (अंश, ऋण-पत्र, सोना, जेवर आदि) सुरक्षा गृह में रखने की व्यवस्था कर सकता है।

9. ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य (Work as Customers Agent)

स्टेट बैंक अपने ग्राहक के एजेंट के रूप में धन का हस्तान्तरण, भुगतान प्राप्त करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, ग्राहकों के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करना, ट्रस्टी का कार्य करना, ग्राहकों को आर्थिक सलाह देना आदि अनेक कार्य करता है।

10. प्रतिभूतियों में विनियोजन (Appropriation in Securities)

अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह भारतीय स्टेट बैंक अपने कोष का सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेशन की प्रतिभूतियों तथा सरकारी ट्रेजरी में भी विनियोग करता है।

11. रकमों की वसूली (Recovery of Assests)

ग्राहकों द्वारा जमा किए गए प्रतिज्ञा-पत्र, ऋण-पत्र, अंश आदि की रकमें वसूल करके ग्राहकों के खातों में जमा करता है।

12. साख-पत्रों को जारी करना तथा धन स्थानान्तरण सुविधा (Issuance of Letter of Credit and Money Transfer Facility)

स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए देशी-विदेशी ड्राफ्ट, साख-पत्र आदि लिख सकता है और तार द्वारा रकमें भेजने का प्रबन्ध कर सकता है।



13. अन्य कार्य (Other Work)

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त स्टेट बैंक निम्नलिखित सामान्य बैंकिंग के कार्य भी करता है- (i) सोने व चाँदी का क्रय करना, (ii) बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना, (iii) यात्री चेक जारी करना (iv) लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को उदार शर्तों पर विशेष ऋण सुविधा देना, (v) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण देना, (vi) प्रत्यासी या ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, (vii) भारत के बाहर शोधनीय विनिमय-पत्र या लेटर ऑफ क्रेडिट लिखना आदि।

14. बिल (Bill)

स्टेट बैंक बिल लिखने, स्वीकार करने, खरीदने बेचने तथा कटौती करने का कार्य कर सकता है।

➤ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा (Life Insurance) कारोबार में पहले से ही संलग्न है। जीवन बीमा कारोबार के लिए फ्रांस की कार्डिफ एस. ए. (Cardif S.A.) के साथ गठबन्धन कर एसबी आई लाइफ (SBI Life) नाम से अपनी अनुषंगी कम्पनी का गठन 2001 में इसने किया था। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक था। स्टेट बैंक की एसबी आई लाइफ में 74 प्रतिशत शेयर-पूँजी है।
- वर्तमान में स्वयं सहायता समूह क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की अग्रणी भूमिका है। यह देश का पहला वाणिज्यिक बैंक है जिसे नाबार्ड (NABARD) ने स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आवास निर्माण की एक अभिनय योजना- 'सहयोग निवास' भारतीय स्टेट बैंक ने ही प्रारम्भ की है।
- ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जुलाई, 2010 को अपने स्थापना दिवस पर 'ग्रीन बैंकिंग चैनल' सुविधा अपनी चुनिंदा शाखाओं में शुरू की है। 'ग्रीन चैनल' काउण्टर पर बैंक के ग्राहक धन जमा करने (Deposits) एवं धन की निकासी (Withdrawals) की 'पेपरलेस' सुविधा उपलब्ध होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Banks)

➤ आईडीबीआई बैंक (IDBI BANK)



स्थापना वर्ष (Establishment Year) : जुलाई, 1964

मुख्यालय (The Headquarters) : मुम्बई

- आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो एक श्रेष्ठ कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहा है। यह बैंक देश भर के विभिन्न केन्द्रों में फैली अपनी कई शाखाओं और एटीएम के विशाल नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ तथा वित्तीय समाधान प्रदान करता है।

आईडीबीआई ने दुबई में भी अपनी विदेशी शाखा खोली है तथा वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए विदेश में और भी शाखाएँ खोलने की इसकी योजना है। इसका वित्तीय बाजारों का अनुभव इसे चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने और राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए भावी अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।

संकल्प (Oath)

- सभी अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करते हुए सबसे पसन्दीदा और विश्वसनीय बैंक बनना।

ध्येय (The Goal)

- अपनी उत्कृष्ट सेवा और बेहतरीन वित्तीय समाधानों की व्यापक शृंखला के साथ ग्राहकों को आनंदित करना।
- कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में उत्कृष्टता को बनाये रखते हुए रिटेल क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों के जीवन से जुड़ना।
- नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करते हुए कॉरपोरेट अभिशासन के लिए आदर्श मॉडल बनना।
- कारोबार कार्यकुशलता में सुधार लाने और ग्राहक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग करना।
- कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, विकसित करने और कर्मठ एवं प्रतिबद्ध मानव संसाधन तैयार करने के लिए सकारात्मक, सक्रिय एवं कार्य-निष्पादन आधारित कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- विश्व स्तर पर पहुँच को बढ़ाना।
- हस्त संरक्षी बनने के लिए निरंतर प्रयास करना।

आईडीबीआई के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

(Information Regarding IDBI Bank Formation)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank Of India): भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून, 1964 की अधिसूचना के द्वारा 01 जुलाई, 1964 से अस्तित्व में आया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4A के प्रावधानों के अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। सन् 2004 तक यानी, 40 वर्षों तक इसने वित्तीय संस्था के रूप में कार्य किया और 2004 में इसका रूपान्तरण एक बैंक के रूप में हो गया।

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (Industrial Development Bank Of India Ltd.):

आवश्यकता महसूस होने और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर आईडीबीआई को बैंक के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को निरस्त करते हुए इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (उपक्रम का अन्तरण व निरसन) अधिनियम, 2003 (निरसन अधिनियम) पारित किया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अधीन



27 सितम्बर, 2004 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से का उपक्रम आईबीआई (आईडीबीआई लि.) के नाम से एक नई कम्पनी सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित हुई। तत्पश्चात प्रभावी तारीख 01 अक्टूबर, 2004 से आईबीआई का उपक्रम के आईडीबीआई लि. में अंतरित व निहित कर दिया गया। निरसन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आईडीबीआई लि. वित्तीय संस्था की अपने पूर्ववर्ती भूमिका के अतिरिक्त बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of IDBI Bank Ltd. With IDBI Ltd.): बैंक की इनऑर्गेनिक वृद्धि के लक्ष्य को पाने के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A के प्रावधानों के तहत जिसमें दो बैंकिंग कम्पनियों के स्वैच्छिक समामेलन का प्रावधान है, आईडीबीआई लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था आईडीबीआई बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में समामेलन कर लिया गया। यह विलय 02 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हो गया।

यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. का आईडीबीआई लि. में विलय (Merger Of United Western Bank Ltd. With IDBI Ltd.): सतारा में केन्द्रित निजी क्षेत्र के बैंक-दि यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिस्थगन के अन्तर्गत रखा था। अपनी इनऑर्गेनिक वृद्धि में और तेजी लाने के मकसद से आईडीबीआई लि. द्वारा उक्त बैंक का अधिग्रहण करने की इच्छा प्रकट किये जाने पर, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने यूडब्ल्यूबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत आईडीबीआई लि. में समामेलित कर दिया। यह विलय 03 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी हुआ।

आईडीबीआई लि. का नाम आईडीबीआई बैंक लि. में परिवर्तित (IDBI Ltd's Name Changed to IDBI Bank Ltd.): इस उद्देश्य से कि बैंक के नाम से इसके द्वारा किये जा रहे कार्य स्पष्ट रूप से झलकें, बैंक का नाम बदल कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड कर दिया गया। यह नया नाम कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र द्वारा निगमन प्रमाणपत्र के जारी किये जाने के साथ ही 07 मई, 2008 से प्रभावी हो गया है। तदनुसार, बैंक अब आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मौजूदा नाम के साथ कार्य कर रहा है।

➤ ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(Oriental Bank of Commerce)

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943 (लाहौर में)

संस्थापक (Founded By): रामबहादुर लाल सोहनलाल

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- आरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है जिसे 19 फरवरी, 1943 को लाहौर में स्थापित किया गया।
- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देहरादून और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई



इस योजना में 75 (2 अमेरिकी डॉलर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है।

- ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएँ हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सकें। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।
- ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल, 1997 को पंजाब के तीन गाँवों) रुड़की कलान (जिला संगरूर), राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गाँवों-खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरम्भ की।
- पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गाँवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गाँवों में लागू है जिसमें 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है।
- इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केन्द्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गाँव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।
- बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्रीय कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया है।

14 अगस्त, 2004 को निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय किया है।

➤ कॉर्पोरेशन बैंक

(Corporation Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year):

12 मार्च, 1906

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड के नाम से उडुपि के मन्दिर-शहर में क्रांतदर्शियों के एक समूह के पुरोगामी प्रयत्नों से हुई। बैंक ने अपना प्रारम्भ 5000 से किया था तथा पहले दिन की समाप्ति पर संसाधन 38 रुपये 13 आना 2 पाई था।
- लोगों की दीर्घकालिक बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बचत की आदत भी डालने के लिए प्रतिबद्ध संस्थापक अध्यक्ष खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी कासिम साहेब बहादुर ने समाज में समृद्धि लाने वाली वित्तीय संस्था की संस्थापना पर अत्यधिक जोर दिया।
- बैंक की पहली शाखा कुंदापुर में 1923 में खोली गई, तत्पश्चात् मंगलूर में 1926 में दूसरी शाखा खोली गई।



- बैंक ने 1934 में मडिकेरी में अपनी सातवीं शाखा खोलते हुए तत्कालीन कूर्म राज्य में कदम रखा। बैंक को 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
- 1939 में बैंक का नाम केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन (उडुपि) लिमिटेड से 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में परिवर्तित किया गया तथा आदर्श-वाक्य 'सर्वे जना सुखिनो भवन्तु' जिसका अर्थ है 'सभी जन सुखी रहे' को अपने दर्शन के रूप में पेश किया गया।
- बैंक के नाम में दूसरा परिवर्तन 'केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' से जोड़ना 'कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड' 1972 में हुआ तथा 15 अप्रैल, 1980 को बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद 'कॉर्पोरेशन बैंक' हो गया।
- इन सब के बीच में वर्ष 1985 में बैंक ने 1000 करोड़ जमा का लक्ष्य पार किया तथा 1990 से नई प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त संवृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना प्रारम्भ किया।
- भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार के प्रथम चरण की समाप्ति में बैंक आस्ति, गुणवत्ता, पूँजी पर्याप्तता, परिचालनगत समक्षमता, सुविधिधकृत आय आधार, लाभप्रदता, उत्पादकता तथा सुदृढ़ तुलन-पत्र में अन्य बैंकों से आगे बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे नवोन्मेषी तथा सक्रिय बैंक के रूप में उभर रहा है।
- दुबई तथा हाँगकाँग में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं। संप्रति बैंक का देश भर में 1361 पूर्णतः स्वचालित सीबीएस शाखाओं, 1250 एटीएमों तथा 2500 शाखा रहित बैंकिंग इकाइयों का नेटवर्क है। बैंक ने अगले पाँच वर्षों में 700 नई शाखाएँ खोलने की योजना भी बनाई है। बैंक ने 2500 गाँवों में शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ प्रारम्भ की है तथा इन गाँवों के सभी खाताधारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किया है ताकि वे बैंक द्वारा नियुक्त कारोबार साथी के द्वारा अपनी दहलीज पर अपने खाते परिचालित कर सकें।

➤ विजया बैंक

(Vijaya Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year)

: 23 अक्टूबर, 1931

संस्थापक (Founded By): ए. बी. शेट्टी

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलुरु (कर्नाटक)

- स्वर्गीय ए.बी. शेट्टी और अन्य उद्यमशील किसानों ने 23 अक्टूबर, 1931 को कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर में विजया बैंक की नींव डाली। इसके संस्थापकों का मूल उद्देश्य था, कर्नाटक राज्य के दक्षिण में कन्नड़ जिले के किसान समुदाय में बैंकिंग की आदत डलवाना, मितव्ययिता का महत्व समझाना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। 1958 में विजया बैंक एक अनुसूचित बैंक बना।
- 1963-68 के दौरान नौ छोटे-छोटे बैंकों के विलयन के साथ विजया बैंक, धीरे-धीरे अखिल भारतीय स्तर के एक बहुत बड़े बैंक के रूप में उभरा।

विलय प्रक्रिया को सफलता से अमल में लाने और बैंकों को तरक्की के रास्ते पर लाने का श्रेय एम. सुंदर राम शेट्टी को मिलना चाहिए जो उस समय बैंक के मुख्य कार्यपालक थे। 15 अप्रैल, 1980 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।

- देश भर में बैंक के तमाम 28 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में तथा जुलाई 2007 को बैंक की 985 शाखाएं, 52 विस्तार काउंटर, 171 ए.टी.एम. हैं।

- बेंगलुरु में एटीएम की शुरुआत सर्वप्रथम विजया बैंक ने की थी।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक

➤ पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

(Punjab & Sind Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year):

: 1908

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

वर्ष 1908 में जब भाई वीर सिंह, सर सुन्दर सिंह मजीठिया तथा सरदार तिरलोचन सिंह जैसे दूरदर्शी तथा विद्वान व्यक्तियों के मन में देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर उठाने का विचार आया तब पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म हुआ। बैंक की स्थापना समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु सामाजिक बचनबद्धता के सिद्धान्तों पर की गई। 100 वर्ष बीत जाने पर भी आज पंजाब एण्ड सिंध बैंक अपने संस्थापकों की सामाजिक बचनबद्धता को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है।

➤ आन्धा बैंक (Andhra Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year):

20 नवम्बर, 1923

संस्थापक (Founded By): डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 15 अप्रैल, 1980

मुख्यालय (The Headquarters): हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

- आन्धा बैंक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉ. भोगराजु पट्टाभि सीतारमैय्या द्वारा स्थापित किया गया। बैंक को 20 नवम्बर, 1923 को पंजीकृत किया गया और 1.00 लाख की प्रदत्त पूँजी एवं 10.00 लाख की प्राधिकृत पूँजी के साथ 28 नवम्बर, 1923 को व्यापार प्रारम्भ किया गया।
- अनन्तता का सिम्बल यह सूचित करता है कि बैंक ग्राहकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शीर्ष का नीलासूचक बैंक के उस दर्शन का प्रतीक है जो सर्वदा विकास एवं नई दिखाओं की ओर बढ़ना चाहता है। कुंजीछिद्र निरापद तथा सुरक्षा का सूचक है। शृंखला मैत्री को इंगित करता है। लाल एवं नीला रंग गतिशीलता एवं सुदृढ़ता के मिश्रण को इंगित करता है,
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
- ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक



➤ बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(Bank of Maharashtra)



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक कुटुंब एक बैंक

स्थापना वर्ष (Establishment Year):

1935

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): पुणे (महाराष्ट्र)

- 1936 में पुणे में बैंक के परिचालन का प्रारम्भ हुआ। बैंक की दूसरी शाखा 1938 में फोर्ट, मुम्बई में खोली गई। 1940 में बैंक की तीसरी शाखा डेक्कन जिमखाना, पुणे में शुरू हुई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 1944 में अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ।
- 1964 में इसकी जमाशायियों ने एक करोड़ रूपए की सीमा पार की। पूरी तरह से अपने स्वामित्व में एक सहायक कम्पनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एण्ड ट्रस्टी कम्पनी गठित की। महाराष्ट्र के बाहर की पहली शाखा हुबली (मैसूर राज्य, अब कर्नाटक) में खोली गई।
- 1949 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश में विस्तार हुआ और हैदराबाद शाखा खोली गई। 1963 में गोवा में विस्तार के रूप में पणजी शाखा खोली गई। 1966 में मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ और इन्दौर शाखा खोली गई। इसके बाद बैंक का गुजरात में प्रवेश हुआ और बड़ोदरा शाखा खोली गई।
- 1969 में अन्य 13 बैंकों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1969 में ही करोल बाग शाखा खोलकर बैंक ने दिल्ली में प्रवेश किया। 1974 में इसकी जमाशायियों ने ₹100 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1976 में मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक के नाम से पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया। 1978 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसी वर्ष बैंक की जमाशायियों ने ₹500 करोड़ का लक्ष्य पार किया।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1979 में अनुसन्धान तथा विस्तृत कार्य शुरू करने एवं किसानों को अधिक विस्तृत सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'महाराष्ट्र कृषि अनुसन्धान और ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान' (महाबैंक एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड रूरल डवलपमेन्ट फाउण्डेशन) नामक सार्वजनिक न्यास स्थापित किया। इसके 6 साल बाद 1985 में महाराष्ट्र राज्य की 500वीं शाखा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में खोली गई।
- 1986 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ठाणे ग्रामीण बैंक को प्रयोजित किया। 1987 में पुणे में बैंक की 1000वीं शाखा इन्दिरा वसाहत, बिबवेवाडी में भारत के उप राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा के हाथों खोली गई। 1991 में सहाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, घरेलू क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया गया, मेन फ्रेम कम्प्यूटर स्थापित किया गया और एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. (स्विफ्ट) का सदस्य बन गया।
- 1995 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हीरक जयन्ती मनाई गई। इसी साल बैंक की जमाशायियों ने 5000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 1996 में बैंक ऑफ

महाराष्ट्र पहले की 'सी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में दाखिल हुआ और इसे स्वायत्तता प्राप्त हुई।

- 2000 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमाशायियों ने 10,000 करोड़ का लक्ष्य पार किया। 2004 में इसके शेयर्स का सार्वजनिक निर्गम किया गया। बी.एस.ई. और एन.एस.ई. में सूचीबद्ध हुए बैंक का सार्वजनिक निर्गम द्वारा 24% का स्वामित्व हस्तान्तरित किया गया।
- 2005 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंकाशुरेन्स और म्युचुअल फंड वितरण व्यवसाय शुरू किया। 2006 में इसके कुल व्यवसाय का स्तर 50,000 करोड़ पार कर गया। 2006 में ही बैंक में शाखा सीबीएस परियोजना प्रारम्भ की गई।
- 2009 में बैंक ने राष्ट्र की समर्पित सेवा के 75वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर एकीकृत सर्वांगीण विकास के लिए 75 अल्प विकसित देहातों को अंगीकृत किया गया। 2010 में 100 प्रतिशत सीबीएस शाखाओं का लक्ष्य हासिल किया गया। इसी साल बैंक के कुल व्यवसाय में एक लाख करोड़ रूपए का लक्ष्य पार किया। 2010 तक बैंक की कुल शाखा संख्या 1506 हो गई।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- वेनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

➤ इण्डियन ओवरसीज बैंक

(Indian Overseas Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1937

संस्थापक (Founded By): एम. चिदम्बरम चेटीयार

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

- इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की स्थापना श्री एम. सी. टी. एम. चिदम्बरम चेटीयार ने की जो बैंकिंग बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। बैंक की स्थापना उन्होंने दो उद्देश्यों से की थी- विदेशी विनिमय व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता।
- आई.ओ.बी. की यह एक अनोखी विशेषता थी कि 10 फरवरी 1937 (उद्घाटन दिवस को ही) को एक साथ 3 शाखाओं में व्यवसाय की शुरूआत की गई। भारत में कारैक्कुडि व चेन्नई में तथा बर्मा में रंगून में (जहाँ दूसरी शाखा पेनांग में खुली)। स्वतन्त्रता के समय आई.ओ.बी. की भारत में 38 शाखाएँ तथा विदेश में 7 शाखाएँ थीं। उस समय जमा रकम 3.23 करोड़ थी।

➤ पूर्व राष्ट्रीयकरण युग (Pre-Nationalization Era)

- इस अवधि के दौरान, आई.ओ.बी. ने अपने देशी गतिविधियों का विस्तार किया तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन को बढ़ाया। बैंक ने एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जो विकसित होकर चेन्नई में स्टाफ कॉलेज बना। इसके अतिरिक्त देश में 9 स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। आई.ओ.बी. उपभोक्ता ऋण शुरू करने वाला पहला बैंक था।



- बैंक कम्प्यूटरीकरण ने लोकप्रिय वैयक्तिक ऋण योजना 1964 में शुरू की तथा अन्तर-शाखा लेखा समाधान के क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण की 1968 में शुरूआत की। कृषकों की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिये आईओबी ने एक संपूर्ण विभाग की स्थापना की। राष्ट्रीयकरण (1969) के समय आई.ओ.बी. 14 बड़े बैंकों में एक था। 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय आई.ओ.बी. की भारत में 195 शाखाएँ तथा कुल जमा राशि 44.90 करोड़ थी।

➤ उत्तर-राष्ट्रीयकरण युग (Post-Nationalization Era)

- 1973 में, आई.ओ.बी. को अपनी पाँच मलेशियाई शाखाओं को बन्द करना पड़ा, क्योंकि मलेशिया का बैंकिंग कानून सरकारी बैंकों का निषेध करता है। इसके फलस्वरूप यूनाइटेड एशियन बैंक बरहद का निर्माण किया गया जिसमें आईओबी की 16.6% हिस्सेदारी है।
- इसी वर्ष भारत में भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड बना जिसमें थाइलैंड में स्थित बैंकाक शाखा की 30% इक्विटी भागीदारी थी।
- 1977 में, आई.ओ.बी. ने सियोल में अपनी शाखा खोली तथा 1979 में बैंक ने कोलम्बो में विदेशी मुद्रा बैंकिंग यूनिट खोली।
- बैंक ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-पुरी ग्राम्य बैंक, पांडियन ग्राम बैंक तथा ढेंकानाल ग्राम्य बैंक को प्रायोजित किया।
- अपना सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने तथा इस क्षेत्र में स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बैंक के अलग से कम्प्यूटर नीति व प्रायोजना विभाग (सीपीपीडी) की स्थापना की।
- फरवरी 1997 में आई.ओ.बी. ने वेबसाइट में प्रवेश किया। 1997-98 के दौरान आई.ओ.बी. ने स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया। सितम्बर 1999 में डेट नौसके वेरिटस (डीएनवी), नीदरलैंड्स से अपने प्रायोजना विभाग हेतु ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला आई. ओ. बी. ने पूरे बैंकिंग उद्योग में पहला बैंक बनने की विशिष्टता प्राप्त की।
- विकास, कार्यान्वयन तथा बैंक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण, टर्न-की परियोजनाओं की प्राप्ति व निष्पादन के लिए यह प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- नीलाचल ग्रामीण बैंक
- पांडयन ग्रामीण बैंक

➤ इण्डियन बैंक

(Indian Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1907

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969

मुख्यालय (The Headquarters): चेन्नई (तमिलनाडु)

- स्वदेशी आन्दोलन के अंश के रूप में इंडियन बैंक की स्थापना की गई। इस समय 19300 से अधिक समर्पित कर्मचारियों के दल के साथ इंडियन बैंक देश की सेवा में तत्पर है।

31/03/2011 तक कुल कारोबार 1,81,530 करोड़ के पार।

31/03/2011 को परिचालन लाभ में 3291.68 करोड़ तक की वृद्धि।

31/03/2011 निवल लाभ में 1774.07 करोड़ तक की वृद्धि।

समस्त भारत में इंडियन बैंक की 1932 शाखाएँ हैं।

कोलम्बो में एक विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई सहित सिंगापुर तथा कोलम्बो में विदेशी शाखाएँ

इंडियन बैंक के 70 देशों में 240 विदेशी सम्पर्क बैंक हैं।

■ 3 अनुषंगी कम्पनियाँ (Three Subsidiary Companies)

1. इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
2. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
3. इंडफंड मैनेजमेंट लिमिटेड

■ विशेषीकृत बैंकिंग में अग्रणी (Leading in Specialized Banking)

- विशेष रूप से निर्यात, आयात, विप्रेषण और अनिवासी भारतीय कारोबार से उत्पन्न होने वाले विदेशी विनिमय लेनदेनों का संचालन के लिए चेन्नई में स्थित 1 विशेषीकृत ओवरसीज शाखा सहित 97 विदेशी विनिमय हेतु प्राधिकृत शाखाएँ।
- विशेष रूप से लघु उद्योग इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए 62 विशेष लघु और मध्यम उद्यम शाखाएँ।

■ ग्रामीण विकास में नेतृत्व (Leadership in Rural Development)

- स्वयं सहायता समूहों तथा देश में वित्तीय समावेश परियोजना का आरम्भ करने के अग्रगामी।
- माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री से कृषि ऋण में श्रेष्ठता के लिए पुरस्कार विजेता।
- नाबार्ड से तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी में माइक्रो वित्त गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ कार्यनिष्पादक पुरस्कार।
- एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) जेएलजी (संयुक्त देयता समूह) संकल्पना के जरिए शहरी गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में 'माइक्रो सेट्स' नामक 7 विशेषीकृत अनन्य माइक्रो शाखाएँ स्थापित।
- ग्रामीण वित्त के लिए एक विशेष पटल 'माइक्रो क्रेडिट केन्द्र' 44 ग्रामीण अर्ध-शहरी शाखाओं में कार्यरत।
- ग्रामीण विकास तथा समावेशी बैंकिंग के लिए आईसीटी (सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी) का प्रयोग।
- कृषि परामर्शी एवं तकनीकी सेवाओं (एसीटीएस) के जरिए उद्यमियों को कृषि में तकनीकी सहायता व परियोजना रिपोर्ट से सहायता का प्रावधान

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- सप्तगिरी ग्रामीण बैंक
- पुडुवई भारतीहर ग्राम बैंक
- पल्लवन ग्राम बैंक



➤ इलाहाबाद बैंक



(Allahabad Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1865

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाता (पं. बंगाल)

- देश के प्राचीनतम संयुक्त स्टॉक बैंक को इलाहाबाद में यूरोपियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय संगठित उद्योग, व्यापार और बैंकिंग ने भारत में अपना आकार लेना प्रारम्भ किया था। इस प्रकार, बैंक का इतिहास तीन शताब्दियों-उन्नीसवीं, बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी तक फैला हुआ है।
- 24 अप्रैल, 1865 ₹30 लाख की अभिदत्त पूँजी से इलाहाबाद बैंक की स्थापना
- 1920 बैंक ₹436 प्रति शेयर के बिड मूल्य के साथ पी एंड ओ बैंकिंग कारपोरेशन समूह का हिस्सा बना।
- 1923 व्यावसायिक प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए बैंक का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में स्थानान्तरित किया गया।
- 19 जुलाई, 1969 13 अन्य बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत शाखाएँ, 151 जमाराशि, ₹119 करोड़ अग्रिम, रूपए 82 करोड़
- अक्टूबर 1989 यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि. का इलाहाबाद बैंक में विलय
- 1991 मर्चेन्ट बैंकिंग हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था आलबैंक फाइनेंस लि. की स्थापना
- प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- शारदा ग्रामीण बैंक
- लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

➤ देना बैंक (Dena Bank)



पुराना नाम : देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1938

संस्थापक (Founded By): प्राणलाल देवकरण नानजी

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- देना बैंक की स्थापना देवकरण नानजी के परिवार द्वारा 26 मई, 1938 को देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड के नाम से की गई थी। यह 1939 में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित हुआ और कालान्तर में इसका नाम बदल कर देना बैंक लिमिटेड हो गया।

वर्ष 1995 में वित्तीय क्षेत्र विकासपरक परियोजना के तहत द्विस्तरीय पूँजी बढ़ाने हेतु 723 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने हेतु विश्व बैंक द्वारा चुने गए छः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक।

प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले कुछेक बैंकों में से एक।

नवम्बर 1969 में 92.13 करोड़ का बॉण्ड निर्गम जारी किया।

नवम्बर 1996 में 180 करोड़ का एकमात्र सार्वजनिक निर्गम।

चुनिंदा महानगरीय केन्द्रों में टेली बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की।

निम्नलिखित की शुरुआत करने में देना बैंक सर्वप्रथम रहा।

नाबालिग बचत योजना।

ग्रामीण भारत में 'देना कृषि साख पत्र' (डीकेएपी) के नाम से विख्यात क्रेडिट कार्ड।

जुहू, मुम्बई में ड्राइव-इन-एटीएम काउन्टर।

मुम्बई की चुनिंदा शाखाओं में स्मार्ट कार्ड।

बैंक सेवाओं की रेटिंग करने हेतु ग्राहक रेटिंग प्रणाली

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- दुर्ग- राजनंदगाँव ग्रामीण बैंक
- देना गुजरात ग्रामीण बैंक

➤ यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

(Union Bank of India)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1919

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- बैंक में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 60.85%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुम्बई में हुई थी। बैंक के मुख्यालय भवन का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1921 में किया गया था।
- बैंक अब पूरे देश में 3000 से अधिक शाखाओं और विदेश में स्थित 6 शाखाओं/कार्यालयों के माध्यम से कारोबार कर रहा है।
- यूनियन बैंक ने भारत की आर्थिक संवृद्धि में एक अत्यन्त सक्रिय भूमिका निभाई है और इसने अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों (क्षेत्रों) की आवश्यकताओं के लिए खास सुविधाओं का विस्तार किया है।
- उद्योग, निर्यात, व्यापार, कृषि व संरचना और व्यक्तिगत संवर्ग ऐसे सेक्टर हैं, जिनमें बैंक ने आर्थिक संवृद्धि को प्रेरित करने और परिसंपत्तियों के एक सुविधीकृत पोर्टफोलियो से लाभार्जन के लिए साख सुविधाएं प्रदान की हैं। संसाधनों को चालू, बचत और मियादी जमाओं के जरिए और विदेशों से पुर्वनिर्गत तथा ऋणों के जरिए गतिशील बनाया गया है। बैंक का व्यापक ग्राहक आधार 24 मिलियन से भी अधिक है।



- तकनीकी मोर्चे पर बैंक ने आरंभ में ही पहल करते हुए अपनी शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया है। बैंक ने शाखाओं के बीच संपर्क सुविधा के साथ कोर बैंकिंग समाधान भी लागू किया है। बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग समाधान के अन्तर्गत होना, इसे तकनीकी समामेलन के मोर्चे पर समकक्षों के बीच अग्रणी बनाता है।
- जून 2011 के अंत में, बैंक ने कुल रूपए 3,44,745 करोड़ अर्थात् 77.12 बिलियन डॉलर का कारोबारी स्तर प्राप्त किया। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय कर्मचारियों की समर्पित टीम को जाता है, जो अपने संघटन में सचमुच विश्वस्तरीय विविधापूर्ण (कॉम्पोसॉलिटन) है। कर्मचारी सदस्यों की अनेक पीढ़ियों ने बैंक की सुदृढ़ छविनिर्मित करने में अमूल्य योगदान किया है।
- लगभग 29000 से अधिक कर्मचारी सदस्यों की वर्तमान टीम, अपनी ग्राहक केंद्रित सोच, सीखने की तत्परता और मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता के कारण स्वयं में विशिष्ट है, जो बैंक को एक सहृदय संगठन के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समर्थ बनाती है, जहां लोग अपने कार्य में और ग्राहकों के प्रति संबंधों में वास्तविक आनंद महसूस करते हैं।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- रीवा-सिद्धी ग्रामीण बैंक
- काशी-गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक
- **यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया**
(United Bank Of India)

पुराना नाम : यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1950

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाता (पं. बंगाल)

- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1950 में चार बैंकों का विलय करते हुए की गई थी। ये चार बैंक थे- कोमिल्लान बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1914), बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1918), कोमिल्लान यूनियन बैंक लिमिटेड (1922) और हुगली बैंक लिमिटेड (1932), जिनकी स्थापना कोष्ठक में दिए गए वर्षों में की गई थी।
- जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय बैंक की शाखाएँ 174 थीं, जमाराशि 147 करोड़ थी और अग्रिम 112 करोड़ थे। इनकी तुलना में आज की तारीख में 1600 से अधिक शाखाओं और कार्यालयों के साथ बैंक की सभी शाखाएँ सीबीएस में कार्य कर रही हैं और बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 1 लाख करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान में बैंक का संगठनात्मक ढांचा त्रिस्तरीय है, जिसमें प्रधान कार्यालय, 31 क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएँ आती हैं।
- राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक ने अपने नेटवर्क का व्यापक पैमाने पर विस्तार किया और विकासशील गतिविधियों में, विशेष रूप से राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के अनुरूप ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के सन्दर्भ में, सक्रिय सहभाग लिया। बैंक द्वारा अदा की गई भूमिका को ध्यान में लेते हुए बैंकों को अनेक जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया और वर्तमान में बैंक



पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के 30 जिलों में अग्रणी बैंक है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक भी है।

- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने देश के विभिन्न भागों, में विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में लक्षणीय भूमिका अदा की।
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया। इन चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर कुल 1000 शाखाएँ कार्यरत हैं। चार विभिन्न राज्यों के इन चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पूँजी में 35 प्रतिशत योगदान है। पश्चिम बंगाल के सुदरबन के दुर्गम इलाकों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने दो मोटर लांचों पर दो तैरती मोबाइल शाखाओं को कार्यान्वित किया, जो सप्ताह के विविध दिनों में एक-एक बोट में भ्रमण करती हैं। तैरती मोबाइल शाखाओं द्वारा जिन केन्द्रों को सेवाएँ दी जाती थीं, वहां पूरी-पूरी शाखाएँ स्थापित होने के बाद ये तैरती मोबाइल शाखाएँ बंद हुईं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को चाय (टी) बैंक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि चाय बागान को वित्त सहायता देने की इसकी पुरानी परम्परा रही है। यह चाय उद्योग को सर्वाधिक आर्थिक सहायता देने वाला बैंक है।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- असम ग्रामीण विकास बैंक
- मणिपुर ग्रामीण बैंक
- त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
- बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
- **बैंक ऑफ बड़ौदा**

(Bank Of Broda)



स्थापना (Establishment Year): 20 जुलाई, 1908

संस्थापक (Founded By): महाराजा सयाजीराव (तृतीय)

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): बड़ौदा (गुजरात)

- इस बैंक का लगभग एक शताब्दी का लम्बा घटना प्रधान इतिहास है जिसका विस्तार विश्व के 26 देशों में है। 1908 में बड़ौदा के एक छोटे से भवन से आरम्भ होकर आज यह मुम्बई में बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर स्थित अपने प्रतिष्ठित और उच्च तकनीक वाले भवन तक पहुँच गया है।
- इस बैंक का शुभारम्भ महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ की अलौकिक दूरदृष्टि एवं अपने राज्य में वाणिज्य एवं उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 20 जुलाई, 1908 को कम्पनी अधिनियम, 1897 के अन्तर्गत 10 लाख प्रदत्त पूँजी के साथ रोपा गया बैंक ऑफ बड़ौदा रूपी एक छोटा-सा पौधा आज का विश्वसनीय, शक्तिशाली, वित्तीय संस्था रूपी वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है।



- इसके संस्थापक महाराजा सयाजीराव की दूरदृष्टि ने यह भांप लिया था कि 'इस प्रकार का बैंक ऋण देने, जमाओं को स्वीकार करने तथा न केवल उनके राज्य वरन् निकटवर्ती राज्यों में भी कला, उद्योग एवं वाणिज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा'।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक
- झुबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा-राजस्थान ग्रामीण बैंक

➤ सिंडिकेट बैंक

(Syndicate Bank)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1925

संस्थापक (Founded By): यू. एस. पाई., वमन कुदवा, टी. एम. ए. पाई

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मणिपाल (कर्नाटक)

- सिंडिकेट बैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र 8000 रुपये की पूंजी से तीन दूरदर्शियों उपेन्द्र अनंत, श्री वामन कुदवा और डॉ. टी.एम.ए. पाई द्वारा की गई थी, जो क्रमशः व्यवसायी, इंजीनियर और डॉक्टर थे तथा समाज के कल्याण के प्रति उनमें अडिग आस्था थी। उनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुंचाना था क्योंकि हथकरघा उद्योग में संकट के कारण बुनकरों की स्थिति बदतर हो गई थी।
- बैंक सन् 1928 में शुरू की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर-घर पहुंच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है और बैंक इस योजना के अधीन प्रति दिन रूपए 2 करोड़ की राशि संग्रह कर रहा है।
- सिंडिकेट बैंक की प्रगति यात्रा भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपनी मार्गदर्शक की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 80 वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान बैंक ने अपने लिए दो या तीन पीढ़ी के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ ग्राहक आधार का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सृष्टि पकड़ और जमीनी हकीकत की व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भविष्य के भारत के बारे में एक दृष्टि है।
- बैंक और जनता, दोनों के परस्पर अविलंबन द्वारा प्रगति प्राप्त करने के उसके तत्वज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक आम आदमी के मामले में वैयक्तिक स्तर पर और ग्रामीण/अर्द्ध शहरी केंद्रों के संदर्भ में क्षेत्रीय स्तर पर देशभर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।
- बैंक सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतियोगिता के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए कटिबद्ध है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गई है और अपने सभी क्रियाकलापों के

क्षेत्रों में ग्राहक हर्षानुभूति को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है।

- बैंक ने केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान नामक एक महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी योजना का शुभारंभ किया है जिसके द्वारा इसकी प्रमुख 500 शाखाएं चार वर्षों की अवधि के दौरान अपने ए.टी.एम. सहित देशव्यापी नेटवर्क से जुड़ जाएंगी।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक
- नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक
- गुडगांव ग्रामीण बैंक
- प्रथमा बैंक
- कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

➤ यूको बैंक

(Uco Bank)



पूर्व का नाम : यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1943

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): कोलकाता (पं. बंगाल)

- सन् 1942 के ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' आंदोलन के बाद यथार्थ भारतीय बैंक की परिकल्पना भारतीय औद्योगिक पुनर्जागरण के प्रवर पुरोधा श्री धनश्याम दास बिड़ला ने की थी। शीघ्र ही इस नवोदित परिकल्पना को मूर्त रूप मिला और 6 जनवरी, 1943 को दि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका पंजीकृत और प्रधान कार्यालय कलकत्ता में खुला। प्रथम निदेशक मंडल में समाज के हर क्षेत्र से देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व था।
- बैंक ने अपनी इस अखिल भारतीय छवि को अक्षुण्ण रखा है- निदेशक मंडल के गठन के मामले में ही नहीं वरन् देश भर में तथा सिंगापुर एवं हांगकांग जैसे विदेशी केंद्रों में अपनी 1700 से अधिक शाखाओं के भौगोलिक विस्तार के मामले में भी।
- विस्तार और सुदृढ़ता के यात्रा क्रम में 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार की शत-प्रतिशत स्वामित्व के साथ यह बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से राष्ट्रीयकृत हुआ। इस ऐतिहासिक घटना ने बैंक की सोच और क्रियाकलापों में अमूल-चूल परिवर्तन किया।
- बैंक ने अब तक चली आ रही वर्ग बैंकिंग के स्थान पर सरकार की सार्वजनिक बैंकिंग की सामाजिक-राजनीतिक अवधारणा को अपनाया। शाखाओं का विस्तार, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत गति से हुआ तथा बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के क्षेत्र में एवं अन्यान्य सामाजिक उन्नयन प्रकल्पों के क्षेत्र में कई विशिष्टताएं हासिल कीं।
- विकास की पृष्ठभूमि में व्यावसायिक प्रगति के लिए सन 1972 में बैंक का सांठगठन पुनर्गठन हुआ। इसके फलस्वरूप कार्य-विशेषज्ञता, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, कार्मिक निपुणता और अभिवृत्ति विकसित हुई। साथ ही

सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अमल चलता रहा तथा बैंक के संयोजकत्व में वर्ष 1983 में तत्कालीन उड़ीसा एवं हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति की स्थापना हुई।

- 1985 में बैंक के इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब संसद के अधिनियम के तहत इसका नाम परिवर्तित कर यूको बैंक रखा गया।
- भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैंक ने ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सिटिजन चार्टर को भी शामिल किया गया था।
- अपने ग्राहकों को सतत बेहतर सेवा देने हेतु बैंक ने शाखाओं में सभी कार्य दिवसों में सार्वजनिक लेन-देन का समय समुचित रूप से बढ़ा दिया है। बैंक ने अनेक छुट्टी रहित शाखाओं की थी शुरुआत की है ये शाखाएँ वर्ष में 365 दिन खुली रहती हैं। अतिरिक्त अनेक शाखाओं में इसके प्रेस डीडी काउंटर हैं, जहाँ से मांग ड्राफ्ट इंतजार किए बिना खरीदे जा सकते हैं।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- जयपुर थार ग्रामीण बैंक
- महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक
- कलिंगा ग्राम्या बैंक

➤ केनरा बैंक (Canara Bank)

पूर्व का नाम : केनरा बैंक हिन्दू परमानेन्ट फण्ड



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 1906

संस्थापक (Founded By): ए. सुब्बाराव पाई

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): बंगलूरु (कर्नाटक)

- पिछले सौ वर्षों में बैंक ने अपनी प्रगति के पथ पर कई मंजिलें तय की हैं। केनरा बैंक का विकास आश्चर्यजनक था, विशेषकर 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद। भौगोलिक पहुँच और ग्राहक संवर्गों की दृष्टि से इस बैंक ने राष्ट्रीय स्तर की हैसियत प्राप्त की है। अस्सी के दशक में बैंक के व्यापार का विशाखन देखने को मिलता है। जून 2006 में बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक शताब्दी पूरी कर ली। आज केनरा बैंक भारतीय बैंकिंग की बिरादरी में एक अग्रणी स्थान प्राप्त किए हुए है और 2006-07 के लिए सकल व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक के रूप में उभरा। अपनी स्थापना से लेकर लाभ कमाने के कीर्तिमान सहित केनरा बैंक कई क्षेत्रों में अखिल आय आया है। इनमें कुछ हैं-

अन्तर-नगर एटीएम नेटवर्क का प्रारम्भ

एक शाखा के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करना

‘गुड बैंकिंग-बैंक की नागरिक संहिता’ की घोषणा

अनन्य रूप से महिलाओं के लिए महिला बैंकिंग शाखा का प्रारम्भ

सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श हेतु अलग से अनुषंगी की स्थापना किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत में पहला बैंक कृषि परामर्शी सेवा प्रदान करने वाला भारत में पहला बैंक

- कई वर्षों से बैंक भारत और विदेशों में अपनी नौ अनुषंगियों/ प्रायोजित संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों के साथ प्रमुख वित्तीय संकुल के रूप में उभरने के लिए बाजार में अपनी स्थिति में बढ़ोत्तरी करता आ रहा है।
- जैसे, दिसम्बर 2009 को बैंक ने देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त 3002 शाखाओं के साथ अपनी उपस्थिति में वृद्धि की है। ग्राहक सुविधा को प्राथमिकता देकर बैंक 723 केन्द्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक 2000 से अधिक एटीएम, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली 1918 शाखाएँ तथा ‘एनिवेयर बैंकिंग’ सेवाएँ प्रदान करने वाली 2086 शाखाओं सहित कई सारे वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को उपलब्ध करा रहा है। इस समय बैंक की कुल 3378 शाखाएँ कार्य कर रही हैं। उन्नत भुगतान और निपटान व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाओं को तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (एनईएफटी) सुविधा के लिए सक्षम बनाया गया है।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- प्रगति ग्रामीण बैंक
- साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक
- श्रेयस ग्रामीण बैंक

➤ पंजाब नेशनल बैंक



(Punjab National Bank)

स्थापना वर्ष (Establishment Year): 12 अप्रैल, 1895 (लाहौर में)

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): नई दिल्ली

- पंजाब का अंग्रेजों के अधीन तेजी से विकास हुआ और वर्ष 1849 में इसे साम्राज्य में मिला लिए जाने के बाद इसके विकास में और तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप एक नया शिक्षित वर्ग उत्पन्न हुआ जिसमें यह इच्छा भी पनप रही थी कि भारतीय पूँजी और ऐसे प्रबन्धन से एक स्वदेशी बैंक की स्थापना की जाए जो भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है।
- सर्वप्रथम यह विचार आर्य समाज के राय मूल राज जी को आया और जैसा कि लाला लाजपत राय जी ने बताया था कि उनके मन में यह इच्छा बहुत समय से थी कि भारतीयों का अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए। वे महसूस कर रहे थे कि ‘भारतीय पूँजी का इस्तेमाल अंग्रेजी बैंकों और कम्पनियों को चलाने में किया जा रहा था जिनसे होने वाला मुनाफा पूर्णतः अंग्रेजों को पहुँच रहा था और भारतीयों को अपनी पूँजी पर मिलने वाले थोड़े से ब्याज से सन्तुष्ट होना पड़ रहा था।’
- इनके ये प्रयास 23 मई, 1894 को कार्यान्वित हुए जब देश को सही अर्थ में एक राष्ट्रीय बैंक प्रदान करने के लिए उसके संस्थापक बोर्ड का गठन किया गया। इसमें भारत के अलग-अलग हिस्सों से विभिन्न धर्मों और



पृष्ठभूमि के ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनका एकमात्र उद्देश्य ऐसे बैंक की स्थापना करना था जो राष्ट्र के आर्थिक हितों को और आगे बढ़ाने वाला हो।

- यह बैंक कारोबार हेतु 12 अप्रैल, 1895 को खुल गया। इसके पहले निदेशक-मण्डल में 7 निदेशक थे। मात्र 7 माह के परिचालन के बाद ही 4 प्रतिशत के हिसाब से पहले लाभांश की घोषणा की गई। अनारकली, लाहौर के आर्य समाज मन्दिर के सामने स्थित इस बैंक में सर्वप्रथम लाल लाजपत राय जी ने खाता खोला और उनके छोटे भाई ने बैंक में प्रबन्धक के रूप में कार्यग्रहण किया। बैंक की प्राधिकृत कुल पूँजी 2 लाख और कार्यशील पूँजी 20000 थी। इसकी कुल कर्मचारी संख्या 9 और कुल मासिक वेतन 320 था।
- 31 मार्च, 1947 को बैंक के पदाधिकारियों ने बैंक के पंजीकृत कार्यालय को लाहौर से दिल्ली स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय से 20 जून, 1947 को अनुमति ले ली। वर्ष 1951 में बैंक ने भारत बैंक लि. की आस्तियों और देयताओं का अधिग्रहण किया और यह निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। वर्ष 1962 में इसने इंडो-कमर्शियल बैंक का अपने में विलय किया।
- वर्ष 1895 में भारतीय पूँजी से पहले स्वदेशी बैंक के रूप में अपनी छोटी-सी शुरुआत के बाद पीएनबी ने अपने कारोबार में काफी विकास किया है जो मार्च, 2010 के अन्त में 435931 करोड़ तक पहुँच गया। शाखा नेटवर्क, कारोबार और अन्य कई पैरामीटरों में पीएनबी भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।
- दिसम्बर 2008 से बैंक की सभी शाखाएँ कोर बैंकिंग सोल्युशन यानि सीबीएस के जरिए कार्य कर रही हैं। जिससे बैंक का 100 प्रतिशत कारोबार सीबीएस से हो रहा है और ये 3000 से ज्यादा ग्रामीण और अर्द्ध शहरी शाखाओं के ग्राहकों समेत अपने सभी ग्राहकों को 'किसी भी समय और कहीं भी' सुविधाएँ दे रही हैं।
- वर्ष 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में पहली बार एक राष्ट्रीयकृत बैंक यानि न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय हुआ।
- वर्ष 2003 में केरल में अवस्थित भूतपूर्व प्राइवेट नेडुन्गडी बैंक लि. का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ जोकि बैंक के 115 वर्ष से ज्यादा के इतिहास में बैंक में सातवाँ विलय था। बैसल II मानकों के लागू होने से भावी पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने मार्च, 2005 में बुक-बिलिंग के जरिए अपना एफपीओ जारी किया जिससे बैंक में सरकारी की शेयर-होल्डिंग घटकर 57.8 प्रतिशत रह गई।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
- पंजाब ग्रामीण बैंक
- हरियाणा ग्रामीण बैंक
- राजस्थान ग्रामीण बैंक
- हिमाचल ग्रामीण बैंक
- सर्व यूपी ग्रामीण बैंक

➤ बैंक ऑफ इंडिया

(Bank of India)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 7 दिसम्बर, 1906

संस्थापक (Founded By): मुम्बई के व्यापारियों का समूह

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई, 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- मुम्बई में एक कार्यालय के साथ आरम्भ हुए इस बैंक की प्रदत्त पूँजी 50.00 लाख थी तथा कर्मचारी 50 थे। इन वर्षों में बैंक तेजी से प्रगति कर पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत अस्तित्व में परिवर्तित हुआ है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच इसने प्रमुख स्थान पा लिया है।
- बैंक की भारत भर में सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कुल 3752 शाखाएँ हैं, इनमें से 141 विशेष शाखाएँ हैं। इन शाखाओं पर 50 आंचलिक कार्यालयों का नियन्त्रण है। विदेशों में बैंक की 29 शाखाएँ/कार्यालय हैं (इनमें पाँच प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं)।
- 1989 में अपनी महालक्ष्मी शाखा को पूर्णतः कम्प्यूटीकृत शाखा में परिवर्तित कर तथा एटीएम सुविधा प्रदान कर इस क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहल करने वाला यह बैंक है।
- यह बैंक भारत में स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य है। अपने ऋण संविभाग के मूल्यांकन/निर्धारण के लिए 1982 में स्वास्थ्य संहिता प्रणाली आरंभ कर इस क्षेत्र में भी बैंक अगुआ बना हुआ है।
- पूँजी बाजार के साथ बैंक का सहयोग काफी पहले, 1921 से रहा है, जब बैंक ने बीएसई समाशोधन गृह के प्रबन्धन के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ अनुबन्ध किया।
- यह सहयोग बाद में और विकसित होकर बीएसई के साथ एक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित हुआ, जिसका नाम था बीओआई शेयरहोल्डिंग कं. लि.। इसके जरिए स्टॉक ब्रोकिंग समुदाय को डिपॉजिटरी सेवाएँ प्रदान की जाने लगी।
- बैंक ऑफ इण्डिया पहला भारतीय बैंक था जिसने विदेश में (लन्दन में) 1946 में शाखा खोली, इतना ही नहीं यूरोप में भी पहली शाखा, पेरिस में बैंक ने ही 1974 में खोली। विदेशों में बैंक का काफी कारोबार है। महत्वपूर्ण बैंकिंग तथा वित्तीय केन्द्रों में, लन्दन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोकियो, हाँगकाँग एवं सिंगापुर में बैंक की 29 शाखाओं (इनमें पाँच प्रतिनिधि कार्यालय) के नेटवर्क के साथ प्रभावी उपस्थिति है।

■ प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)

- झारखण्ड ग्रामीण बैंक
- नर्मदा-मालवा ग्रामीण बैंक
- बैतरणी ग्रामीण बैंक
- आर्यव्रत ग्रामीण बैंक



➤ **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**

(Central Bank Of India)



स्थापना वर्ष (Establishment Year): 21 दिसम्बर, 1911

संस्थापक (Founded By): सोराबजी पोचखानवाला

राष्ट्रीयकरण (Nationalization): 19 जुलाई 1969

मुख्यालय (The Headquarters): मुम्बई (महाराष्ट्र)

- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबन्धन भारतीयों के हाथ में था। बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला ने इस बैंक की स्थापना करते हुए अपने स्वप्न को साकार किया। सही अर्थों में स्वदेशी बैंक के पहले अध्यक्ष सर फिरोजशह मेहता थे।
- वास्तव में सर सोराबजी पोचखानवाला इस बैंक की स्थापना से इतने गौरवान्वित हुए कि उन्होंने सैन्ट्रल बैंक को राष्ट्र की सम्पत्ति और देश की सम्पदा घोषित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्ट्रल बैंक जनता के विश्वास पर टिका है और यह जनता का अपना बैंक है।
- पिछले 100 वर्षों के इतिहास में बैंक ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। बैंक ने प्रत्येक आशंका को सफलतापूर्वक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया और बैंकिंग उद्योग में अपने समकक्षों से उत्कृष्ट रहा।
- सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने कई अभिनव और अनुपम बैंकिंग गतिविधियों का शुभारम्भ किया। ऐसी ही कुछ सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-
1921- समाज के सभी वर्गों में बचत/किफायत की आदत डालने के लिए घरेलू बचत सुरक्षित जमा योजना का प्रारम्भ
1924- बैंक की महिला ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट महिला विभाग की स्थापना
1926- सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा और रूपया यात्रा चेक
1929- निष्पादक एवं न्यासी विभाग की स्थापना
1932- जमा राशि बीमा सुविधा योजना
1962- आवर्ती जमा योजना
1976- मर्चेन्ट बैंकिंग कक्ष की स्थापना
1980- बैंक के क्रेडिट कार्ड 'सैन्ट्रल-कार्ड' का प्रारम्भ
1986- प्लैटिनम जुबली मनी बैंक जमा योजना
1994- बाहरी चेकों की शीघ्र वसूली के लिए त्वरित चेक वसूली सेवा (क्यू.सी.सी.) तथा तत्काल सेवा का शुभारम्भ
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है क्योंकि 29 में से 27 राज्यों में तथा 7 में से 3 केन्द्रशासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है।
- देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थित अपनी 3967 शाखाओं, 27 विस्तार पटलों के विस्तृत नेटवर्क के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सैन्ट्रल बैंक का एक अपना विशिष्ट स्थान है

■ **प्रायोजित ग्रामीण बैंक (Sponsored Rural Bank)**

- उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
- हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बलिया-इटवा ग्रामीण बैंक
- विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- उत्तर बंगा क्षेत्रीय-ग्रामीण बैंक

**राष्ट्रीयकृत बैंक, मुख्यालय एवं उनके स्लोगन
(Nationalized Bank, Headquarters And Their Slogan)**

बैंक	मुख्यालय	स्लोगन
इलाहाबाद बैंक	कोलकाता	"A Tradition of Trust"
आन्ध्रा बैंक	हैदराबाद	"For all your needs"
बैंक ऑफ बड़ौदा	मुम्बई	"India's international bank"
बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई	"Relationship beyond banking"
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पुणे	"One Family One Bank"
केनरा बैंक	बंगलूरु	"It's easy to change for those who you love. Together we can do"
देसा बैंक	मुम्बई	Trusted Family Bank
कॉरपोरेशन बैंक	बंगलूरु	A premier government of India
आईडीबीआई बैंक	मुम्बई	"Banking for all. Not just for big boys, "Aao Sochein Bada"
इण्डियन बैंक	चेन्नई	"Taking Banking Technology to the Common man"
इण्डियन ओवरसीज बैंक	चेन्नई	"Good people to grow with"
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	नई दिल्ली	Where every individual is committed"
पंजाब नेशनल बैंक	नई दिल्ली	"The name you can Bank upon"
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	नई दिल्ली	"Where service is a way fo..."
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई	"Pure Banking Nothing else"
सिंडिकेट बैंक	मणिपाल	"Your faithful & friendly Financial Partner"
यूको बैंक	कोलकाता	"Honours your Trust"
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	कोलकाता	"The Bank that begins with u"
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई	"Good people to Bank with"
विजया बैंक	बंगलूरु	"Friend you can bank on"



महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- ✍ प्रथम पूर्णतः भारतीय पूँजी से आरम्भ बैंक- **पंजाब नेशनल बैंक**
- ✍ भारत का सबसे पुराना, बड़ा और सफल व्यावसायिक बैंक - **भारतीय स्टेट बैंक**
- ✍ भारत का निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शिड्यूल्ड व्यावसायिक बैंक - **द फेडरल बैंक लिमिटेड**
- ✍ प्रथम बैंक जिसने भारत के बाहर लंदन में अपनी शाखा (1946 ई.) खोली - **बैंक ऑफ इंडिया**
- ✍ प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन का था - **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**
- ✍ भारत की प्रथम आई.एस.ओ. प्रमाण-पत्र बैंक - **केनरा बैंक**
- ✍ उत्तरी भारत के प्रथम आई.एस.ओ. 9002 प्रमाण-पत्र प्राप्त बैंक - **पंजाब एंड सिंध बैंक**

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक (Major Banks in Private Sector)

निजी क्षेत्र के बैंक	पंजीकृत कार्यालय	स्थापना वर्ष
इन्डस इंड बैंक	पुणे	1994
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	सिकन्दराबाद	1994
ICICI बैंक	बड़ौदा	1994
UTI बैंक *	अहमदाबाद	1994
टाइम्स बैंक	फरीदाबाद	1995
सेंचुरियन बैंक	पणजी	1995
बैंक ऑफ पंजाब	चण्डीगढ़	1995
HDFC बैंक	मुम्बई	1995
IDBI बैंक	इन्दौर	1995
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	मुम्बई	1995
Yes बैंक	मुम्बई	2004

*UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक लि. (Axis Bank Ltd.) कर दिया गया है। बैंक का यह नाम 30 जुलाई, 2007 से प्रभावी किया गया

विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय का विवरण (Details of Marger of Various Private Sector Banks in Public Sector Banks)

विगत वर्षों में अनेक अवसरों पर वित्तीय संकट में फँसे निजी क्षेत्र के बैंकों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर इनका विलय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किया गया है। निजी क्षेत्र के जिन अन्य बैंकों के कारोबार पर रोक लगाकर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया गया है; उनके नाम निम्नलिखित हैं-

बैंक	जिसमें विलय किया गया
बैंक ऑफ कोचीन	भारतीय स्टेट बैंक (1984-85)
लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक	केनरा बैंक (1984-85)
बैंक ऑफ बिहार	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (1969)
हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक (1986)
मिराज स्टेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (1985)
ट्रेडर्स बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (1988)
बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ तमिलनाडु	इण्डियन ओवरसीज बैंक
थंजावूर बैंक	इण्डियन बैंक (1989-90)
पारूर सेंट्रल बैंक	बैंक ऑफ इण्डिया (1989-90)
यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक	इलाहाबाद बैंक (1989-90)
पूर्वांचल बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1990-91)
बैंक ऑफ करनाल	बैंक ऑफ इण्डिया (1993-94)
बरेली कॉर्पोरेशन बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (1999)
सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (1999)
बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (2002)
पंजाब कोऑपरेटिव बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (1997)
नेदुत्तगड़ी बैंक	पंजाब नेशनल बैंक (2003)
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (2004)
नेशनल बैंक ऑफ लाहौर	भारतीय स्टेट बैंक (1970)
ईस्टर्न बैंक	चार्टर्ड बैंक (1971)
कृष्णाराम बलदेवों बैंक लि.	भारतीय स्टेट बैंक (1974)
बेलगाँव बैंक	यूनियन बैंक (1976)
न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	पंजाब नेशनल बैंक (1993-94)
काशीनाथ सेठ बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (1995-96)
बारी दोआब बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (1997)
टाइम्स बैंक	HDFC बैंक (1999)
ICICI	ICICI बैंक (2002)
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (2004)
भारत ओवरसीज बैंक	इण्डियन ओवरसीज बैंक (2006)
सांगली बैंक	ICICI बैंक (अप्रैल 2007)
लॉर्ड कृष्णा बैंक	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (अगस्त 2007)
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (मार्च 2008)
दी साउथ इण्डियन कोऑपरेटिव बैंक	सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक (सितम्बर, 2008)



स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	भारतीय स्टेट बैंक (जुलाई 2008)
बैंक ऑफ मद्रास	आईसीआईसीआई बैंक (1 मार्च, 2001)
बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (20 जून, 2002)
बैंक ऑफ पंजाब	सेंचुरियन बैंक (1 अक्टूबर, 2005)
लार्ड कृष्णा बैंक	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (19 अगस्त, 2006)
गणेश बैंक ऑफ कुरुदवाद	फेडरल बैंक (2 सितम्बर, 2006)
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	आईडीबीआई बैंक (27 सितम्बर, 2006)
सांगली बैंक	आईसीआईसीआई बैंक (दिसम्बर 2006)
सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (दिसम्बर 1999)

भारत में विदेशी वाणिज्य बैंक (Foreign Commercial Bank in India)

वित्त मन्त्रालय द्वारा लोक सभा में 2 सितम्बर, 2011 को दी गई एक जानकारी के अनुसार अगस्त 2011 के अन्त तक भारत में 38 विदेशी बैंक कार्यरत थे। देश में इन बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 321 होने की बात वित्त राज्य मंत्री ने सदन को बताई है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ किए गए वायदों के अनुरूप देश में विदेशी बैंकों की शाखाओं का विस्तार किया जा रहा। विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए वायदों के तहत विदेशी बैंकों की कम-से-कम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक को प्रदान करनी है।

नए प्रावधानों के तहत विदेशी बैंकों को भारत में अपनी शाखा खोलते समय केवल 10 मिलियन डॉलर की पूंजी साथ लेकर आनी होती है। दूसरी व तीसरी शाखा के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता क्रमशः 10 मिलियन डॉलर व 5 मिलियन डॉलर होगी। ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में अधिकतम शाखाएँ (81 शाखाएँ) है।

विदेशी बैंक (Foreign Bank)

- बैंक ऑफ अमेरिका
- मशरक बैंक
- ए. वी. एन. एमरो बैंक
- डच बैंक
- सोसिएट जनरल
- वी. एन. पी. परिव्राज
- आई. एन. जी. बैंक
- बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- चो हूंग बैंक

- एटवर्प डायमंड बैंक
- मिजूहो कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड
- ओमान इंटरनेशनल बैंक
- अबूधावी कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड
- अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
- चाइना ट्रस्ट कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड
- सुमितमो मित्सू बैंकिंग कॉर्पोरेशन
- बैंक ऑफ टोकियो मित्सूबिशी लिमिटेड
- स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लिमिटेड
- बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत
- बैंक ऑफ नोवा स्टाकिया
- सिटी बैंक
- एच. एस. बी. सी. लिमिटेड
- सोनाली बैंक
- वाक्लेज बैंक
- डी. वी. एस. बैंक लिमिटेड
- अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ सिलौन
- क्रूंग थाई बैंक
- जेपी मॉर्गन चेज बैंक
- यू. एफ. जे. बैंक लिमिटेड
- कैलियोन बैंक

विदेशी बैंकों के स्लोगन (Slogan of Foreign Banks)

बैंक	स्लोगन
एबीएन एमरो	"Making more possible"
बारक्लेज	"Now there's thought"
बैंक ऑफ अमेरिका	"Think what we can do for you"
ड्यूच बैंक	"Deutsche Bank : A passion to perform"
गोल्डमेन सेक्स	"Our client's interest always come first"
एचएसबीसी बैंक	"HSBC-The world's local bank"
जेपी मॉर्गन चैस	"Chase what matters"
मॉर्गन स्टेनले	"World wise"
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	"Leading the way Asia, Africa and the Middle East"



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की घोषणा की।

देश में 2 अक्टूबर, 1975 को भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एवं युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये-

- मुगादाबाद (उत्तर प्रदेश)- सिंडीकेट बैंक
- गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- भिवानी (हरियाणा)- पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया
- जयपुर (राजस्थान)- युनाइटेड कमर्शियल बैंक
- माल्दा (पं. बंगाल)- युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया

प्रत्येक RRB की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1 करोड़ रुपये तथा जारी और चुकता पूँजी (Issued and Paid up Capital) 25 लाख रुपये थी। RRB की हिस्सा पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा लीड बैंक द्वारा 35% का योगदान दिया जाता है।

वाणिज्य बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अन्तर

(Difference Between Commercial Bank And Regional Rural Bank)

एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि वह शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला पृथक निगमित निकाय (a separate body corporate with perpetual succession and common seal) होते हुए भी उस वाणिज्यिक बैंक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है जो उसकी स्थापना के प्रस्ताव को प्रायोजक होता है। वाणिज्यिक बैंक के आवेदन करने पर जब केंद्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन स्थानीय सीमाओं का भी उल्लेख करती है जिनके भीतर उस ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है।

भारतीय सहकारी बैंक (Indian Co-Operative Bank)

सहकारी बैंक वे बैंक हैं जिनकी स्थापना सदस्यों द्वारा अपने पारस्परिक लाभ के लिए की जाती है और जिन पर सहकारिता अधिनियम लागू होता है।

सहकारी बैंक की विशेषताएँ

(Features Of Co-Operative Bank)

- इसका उद्देश्य सदस्यों से थोड़ी-थोड़ी राशि अंश पूँजी के रूप में अथवा जमा राशि के रूप में लेना तथा उसमें से समय-समय पर उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देकर उसकी सहायता करना है।
- यह सीमित साधनों वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का ऐच्छिक संगठन है।
- सहकारी बैंकों का संचालन प्रायः सहकारी समिति कानून द्वारा होता है।

(iv). इसमें सभी सदस्यों का अधिकार व दर्जा समान होता है।

(v). इनका उद्देश्य सदस्यों में आत्म-निर्भरता और परस्पर सहयोग की भावना पैदा करना भी होता है।

सहकारी बैंक व वाणिज्य बैंक में अन्तर (Difference Between Co-Operative Bank and Commercial Bank)

सहकारी बैंक व वाणिज्य बैंक में अन्तर को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है-

- सहकारी बैंक आधारभूत रूप से ही ग्राम उन्मुखी (Rural-oriented) रहे हैं और कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ही वित्त सुलभ कराते हैं जबकि सन् 1969 तक वाणिज्यिक बैंक केवल नगर-उन्मुखी (Urban-oriented) रहे और व्यापार तथा उद्योगों को वित्त की सुविधाएँ देते रहे। भारत में सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों वाला (Three Tier Setup) है। राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है, जोकि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
- सहकारी बैंक केवल निर्धारित क्षेत्र में अपना काम-काज कर सकता है लेकिन अधिकांश वाणिज्य बैंकों की शाखाएँ अनेक राज्यों और देश के विभिन्न भागों में फैली हुई हैं।
- सहकारी बैंकों का गठन तीन स्तरों (Three Tier Set-up) वाला है, जबकि सहकारी बैंक अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गए हैं।
- सहकारी बैंक अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाये गए सहकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गए हैं जबकि वाणिज्य बैंक कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत संयुक्त पूँजीवादी कम्पनियों के रूप में गठित किये गए हैं।
- सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धान्तों पर चलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तों (Sound Business Principles) का अनुगमन करते हैं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता देता है।
- बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की सभी धाराएँ लागू हैं, जबकि सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ ही धाराएँ लागू हैं। इस तरह सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण केवल आंशिक है।

भारत में सहकारी बैंक संरचना (Co-Operative Bank Structure in India)

प्राथमिक साख समितियाँ (Primary Credit Society): इनकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की गई है। एक गाँव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम-से-कम दस व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। ये समितियाँ प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भी कहलाती हैं तथा सामान्यतः यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन (एक वर्ष के लिए) ऋण देती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।



राज्य सहकारी बैंक (State Co-Operative Bank): इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक (Apex Co-operative Bank) भी कहते हैं। यह बैंक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देता है और उनके कार्यों का नियन्त्रण करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। इस प्रकार यह बैंक रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का कार्य सम्पन्न करता है।

राज्य सहकारी बैंक अपनी चालू पूँजी अंश बेचकर तथा ऋण लेकर प्राप्त करता है। रिजर्व बैंक से इसे प्रायः बैंक दर से एक या 2 प्रतिशत कम पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार यह बैंक भी 2 प्रतिशत सीमान्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-Operative Bank): इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। इसका कार्य क्षेत्र एक जिले तक ही सीमित रहता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- (1) सहकारी बैंकिंग संघ, तथा
- (2) मिश्रित केन्द्रीय सहकारी बैंक

सहकारी बैंकिंग संघों की सदस्यता सिर्फ सहकारी समितियों को ही प्राप्त होती है, जबकि मिश्रित सहकारी बैंकों के सदस्य सहकारी समितियाँ तथा व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं। भारत के समस्त राज्यों में प्रायः मिश्रित सदस्यता वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। यह बैंक सहकारी साख समितियों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कि ये समितियाँ कृषकों तथा अन्य सदस्यों को समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा सकें।

केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूँजी में राज्य सहकारी बैंक (State co-operative Bank) से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं तथा सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। इनके ऋण की अवधि भी एक वर्ष से तीन वर्ष तक की हो सकती है। इस प्रकार अधिकांश केन्द्रीय बैंक राज्य सहकारी बैंक तथा प्राथमिक ऋण समितियों के मध्य अन्तर्वर्ती का कार्य करते हैं। मार्च 2001 के अन्त में देश में 367 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे। इनमें से 245 लाभ में तथा 112 हानि में चल रहे थे।

इस्लामिक बैंक (Islamic Bank)

3 फरवरी, 2011 ई. को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग से संविधान के मूल ढाँचे को कोई खतरा नहीं है। इस्लामिक वित्तीय संस्थान को सहप्रायोजित करने के केरल सरकार के निर्णय को जायत ठहराते हुए न्यायालय ने देश में इस्लामिक बैंकिंग पर लम्बे समय से चल रही बहस को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। गौरतलब है कि केरल औद्योगिक विकास निगम (जो एक सरकारी एजेन्सी है) ने अल-बरकाह वित्तीय सेवा कम्पनी में 11 फीसदी इक्विटी निवेश करने की घोषणा की थी। जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ बताते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। रिजर्व बैंक व अर्थशास्त्रियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं और लम्बी सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्वामी की याचिका खारिज करके इस्लामिक बैंकिंग का रास्ता साफ कर दिया।

इस्लाम धर्म में रीबा यानी ब्याज लेने को पाप माना जाता है और ब्याज लेने व देने वाले, दोनों ही इस्लाम की नजर में गुनहगार हैं। इसी विश्वास के चलते एक बड़ी आबादी बैंकिंग सुविधाओं से महरूम है और विकास की दौड़ में भागीदार नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग की अवधारणा इसी विश्वास पर काम करती है और यह बैंक इस्लामिक कानूनों (शरिया) के अनुसार लेन-देन करते हैं। परम्परागत बैंकों के विपरीत इस्लामिक बैंकों में ब्याज नहीं लिया जाता है और कर्ज लेने के लिए सम्पत्ति भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। सवाल उठता है कि ऐसे में इन बैंकों का परिचालन खर्च कैसे निकलता है और क्या इनके असफल होने की सम्भावना नहीं है। इस्लामिक बैंक कर्जदार को होने वाले मुनाफे से एक छोटी रकम लेते हैं जो इनके परिचालन खर्च में काम आती हैं। परिचालन खर्च से ज्यादा पैसा आने पर वह रकम बैंक के हिस्सेदारों में बाँट दी जाती है और कर्जदारों से ली जाने वाली रकम कम कर दी जाती है। इस्लामिक बैंकों के मुनाफा कमाने का दूसरा तरीका यह है कि बैंक की रकम का इन्श्योरेन्स, म्यूचुअल फण्ड, आधारभूत ढाँचे, विनिर्माण जैसे विकासात्मक कार्यों में निवेश किया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग के इस ब्याज रहित कारोबार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अनिश्चित व जोखिमपूर्ण जगहों पर पैसा नहीं लगाया जाता है और शरिया में वर्जित गतिविधियों मसलन जुआ, माँस-शराब का कारोबार व पोर्नोग्राफी के लिए भी धन मुहैया नहीं करवाया जाता है। सम्बन्धित देश के केन्द्रीय विनियामक बैंकों के अलावा इस्लामी धार्मिक स्कॉलरों का समूह इन बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है।

2006 में रिजर्व बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आनन्द सिन्हा की अगुवाई में एक समिति गठित की थी, जिसने मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था। कुछ समय बाद इस मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अपनी मलेशिया यात्रा के समय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह इस्लामिक बैंकिंग से प्रभावित हुए। इसके बाद फिर इस्लामिक बैंकिंग पर हलचल हुई और वित्त मन्त्रालय के कहने पर योजना आयोग द्वारा गठित रघुराम राजन समिति की सिफारिशों पर भी गौर नहीं किया गया, लेकिन अब केरल हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने नई उम्मीद जगाई है।

अन्य वित्तीय संस्थाएँ (Other Financial Institutions)

भूमि विकास बैंक (Land Development Banks)

इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं।

इन बैंकों का ढाँचा दो स्तर वाला है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला अथवा तालुक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों, में, जैसे-जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह ढाँचा ऐकिक (Unitary) है, अर्थात् वहाँ पर शीर्षस्थ (Apex) भूमि विकास बैंक है, जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियाँ सम्पन्न करते हैं।



भारत में भूमि बंधक बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों का वास्तविक प्रारम्भ मद्रास में हुआ, जबकि इस राज्य ने अपने राज्य के प्राथमिक बैंकों को समन्वित करने के लिए 1929 में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Bank) की स्थापना की इसके बाद देश के अनेक राज्यों में इनकी स्थापना की गई।

देश में भूमि विकास बैंकों की पूँजी के मुख्य स्रोत हैं- (1) अंश पूँजी, (2) सुरक्षित कोष, (3) जमा राशि, (4) ऋणपत्र तथा (5) ऋण। इनमें से ऋणपत्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ऋणपत्रों से ही केन्द्रीय भूमि विकास बैंक अपनी अधिकांश कार्यशील पूँजी एकत्रित करते हैं। इन बैंकों के ऋणपत्रों में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारें निवेश करती हैं। यह ऋणपत्र दीर्घकालीन अवधि (25 वर्ष तक) के होते हैं।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) (National Bank for Agriculture and Rural Development)

यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाला शीर्ष संस्था है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई थी। नाबार्ड की चुकता पूँजी (PAID UP CAPITAL) 100 करोड़ में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर (50:50) का योगदान था। वर्ष 1996-97 में इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपए कर दिया गया था जिसमें RBI का योगदान 800 करोड़ रूपए तथा केन्द्र सरकार का 200 करोड़ रूपए था। 31 मार्च, 2010 को नाबार्ड की 2000 करोड़ रूपए की चुकता पूँजी थी जिसमें 72.5% हिस्सेदारी RBI की है। RBI ने NABARD की इक्विटी में अपनी लगभग सारी हिस्सेदारी सरकार को अक्टूबर 2010 में बेच दी है। 13 अक्टूबर, 2010 को किए गए इक्विटी हस्तान्तरण के तहत RBI ने NABARD की केवल 1% हिस्सेदारी अपने पास रखी है अतः अब नाबार्ड की इक्विटी में केन्द्र सरकार व RBI की हिस्सेदारी क्रमशः 99% व 1% रह गई है।

कृषि ऋणों को बढ़ावा देने के लिए 'नाबार्ड' की चुकता पूँजी (Paid up Capital) में चरणबद्ध तरीके से 3000 करोड़ रूपए की वृद्धि की घोषणा 2011-12 के बजट प्रस्तावों के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई है। इसके फलस्वरूप नाबार्ड की चुकता पूँजी 5000 करोड़ रूपए की हो जाएगी।

नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढाँचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं (राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को पुनर्वित्त सुविधाएँ प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं।

अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से राशियाँ प्राप्त करता है। यह केन्द्र सरकार की गारण्टी प्राप्त बॉण्ड तथा ऋणपत्र जारी करके भी संसाधन जुटा सकता है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण साख (स्थिरीकरण) निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank-NHB)

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी। यह बैंक देश में आवास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिए शीर्षस्थ बैंक है। यह बैंक भूमि एवं भवन निर्माण सामग्री एवं संघटकों जैसे वास्तविक संसाधनों की आपूर्ति के संवर्द्धन के लिए भी प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक बॉण्डों तथा ऋण-पत्रों को जारी करके अपने संसाधन जुटाता है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(Export-Import Bank of India-EXIM BANK)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी, 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना से पूर्व IDBI का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग निर्यात तथा आयात की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अब एक्जिम बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसे उन सभी वित्तीय संस्थाओं के काम का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त जुटाते हैं।

यह बैंक न केवल भारत, अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए भी वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबन्ध करता है।

भारत के एक्जिम बैंक के विदेशों में कार्यालय वाशिंगटन डी.सी., सिंगापुर, आबिदजान (आइवरी कोस्ट) तथा बुडापेस्ट (हंगरी) में स्थापित किए गए हैं। इसका प्रधान कार्यालय मुम्बई (महाराष्ट्र) में है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust of India-UTI)

1964 में सार्वजनिक क्षेत्र में गठित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की एक कम्पनी हो गया है।

2001 में यू.एस.-64 के धराशायी होने के पश्चात् यूटीआई का विभाजन दो अलग-अलग कम्पनियों-यूटीआई-I व यूटीआई II (UTI-Asset Management Company UTI-AMC) में कर दिया गया था।

यूटीआई के शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य (Net Asset Value-NAV) आधारित सभी योजनाओं को यूटीआई-II (UTI-AMC) के अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसम्पत्तियों का परिचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा था। इन चारों ने अब सरकार को पूरा मूल्य चुका कर यूटीआई एएमसी (यूटीआई म्यूचुअल फंड) के प्रबन्धन के साथ-साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया है। इससे यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन चारों (जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा व पंजाब नेशनल बैंक) की हिस्सेदारी 25-25% हो गई है।

राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation)

देश में वित्त-पोषण करने वाली संस्थाओं की संरचना के विकास में राज्य वित्त निगम अभिन्न अंग हैं। वे अपने राज्यों में छोटे और मध्यम उद्यमों के उन्नयन के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि, अधिक निवेश, अधिक रोजगार और उद्योगों के व्यापक स्वामित्व में सहायक होते हैं।

इस समय 18 राज्य वित्त निगम हैं, जिनमें से 17 राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत गठित किए गए थे। राज्य वित्त निगम सावधि ऋणों,

इक्विटी/डिबेंचरों में प्रत्यक्ष अंशदान, एक्सचेंज बिलों की भुनाई और गारण्टियों के रूप में उद्योगों को सहायता प्रदान करते हैं।

किसी भी समय इन निगमों की कुल पूँजी में राज्य सरकार, सिडबी तथा अन्य सरकार नियन्त्रित संस्थाओं की भागीदारी मिलाकर 51% से कम नहीं हो सकती अर्थात् इन निगमों में निजी शेयरधारित 49 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड

(Industrial Investment Bank of India Ltd.- IIBIL)

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 20 मार्च, 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत, तत्कालीन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, देश में प्रधान ऋण तथा पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में रूग्ण तथा बन्द औद्योगिक एककों के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक औद्योगिक संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम देता है, स्टॉक, शेयरों बॉण्डों और डिबेंचरों की हामीदारी करता है और ऋणों तथा स्थगित अदायगियों की गारण्टी देता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (RBI) के स्थान पर एक पुनर्संचित नई कम्पनी स्थापित करने की सरकार की योजना है। इस सम्बंध में 6 मार्च, 1997 को लोक सभा ने एक विधेयक भी पारित किया है।

नई व्यवस्था के तहत IRBI एक नए नाम 'भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि0,' (Industrial Investment Bank of India Ltd.-IIBIL) से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी के रूप में कार्य करता है।

इसकी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1000 करोड़ रूपए है। इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। इस प्रकार यह IDBI, IFCI व ICICI की ही भाँति एक स्वतन्त्र विकास वित्त संस्था के रूप में कार्यशील हो गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड

(Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.-ICICIL)

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (ICICI) की स्थापना जनवरी 1955 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए की गई थी।

प्रारम्भ में इसकी समस्त पूँजी को कम्पनियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने निजी रूप से धारण कर रखा था, किन्तु वर्तमान में इसकी अधिकांश अंश पूँजी (Equity Capital) सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों जैसे- बैंकों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उसकी समानुषंगी कम्पनियों ने धारण कर रखी है।

निगम ऋणपत्रों के आधार पर दीर्घकालिक व मध्यकालिक ऋण देता है, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के अंशों में अभिदान करता है, उनके अंशों एवं ऋणपत्रों की नई शृंखला का अन्तर्लेखन (Underwriting) करता है, बॉण्डों एवं ऋणपत्रों का क्रय करता है तथा रूपए में भुगतान होने वाले ऋणों की गारण्टी देता है।

निगम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके द्वारा स्वीकृत ऋण राशि में विदेशी मुद्रा में मंजूर ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1973 के

बाद से निगम ने विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूँजी-बाजार में भी प्रवेश किया है।

मुम्बई उच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 1997 को विलय की मंजूरी देने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1996 से पूर्व प्रभावी तारीख से सरकार ने नौवहन उद्योग को वित्त उपलब्ध कराने वाली SCICI (शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी ऑफ इण्डिया) लि. का ICICI में विलय कर दिया।

वर्तमान में आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई बैंक में विलय किया जा चुका है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड

(Industrial Finance Corporation of India Ltd.-IFCI Ltd.)

औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के सुझाव पर एक विशेष अधिनियम द्वारा 1948 में हुई। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है।

निगम की अधिकृत पूँजी 10 करोड़ रूपए की थी, जो 5,000 रूपए के अंशों में बँटी हुई थी। बाद में यह बढ़ाकर 20 करोड़ रूपए कर दी गई।

अभी तक भारत सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा सहकारी समितियाँ इसके अंशधारियों में से थीं। साधारण व्यक्ति इसका अंशधारी नहीं था, किन्तु 1 जुलाई 1993 से इस निगम की प्रकृति में परिवर्तन करके इसे एक कम्पनी का रूप दे दिया, तदनुसार इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का स्तर प्रदान कर दिया गया। इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत किया जा चुका है।

देश के सबसे पुराने इस वित्तीय संस्थान को अब एक बैंकिंग संस्थान (PNB) में विलय करने का निर्णय सरकार ने कर्मचारियों के संगठन की माँग पर किया है। प्रस्तावित विलय को व्यावहारिक रूप देने के लिए बैंकिंग, विनियमन अधिनियम तथा NBFC अधिनियम में कुछ संशोधन भी सरकार को करने होंगे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

(Small Industries Development Bank of India-SIDBI)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण, विकास तथा ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है।

2 अप्रैल, 1990 से इसने कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय व 21 शाखा कार्यालय देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं।

इस बैंक की स्थापना हो जाने पर लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए जो कार्य आई.डी.बी.आई. करता था, वह सभी कार्य इस बैंक (सिडबी) को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं।

बैंक लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।



सिडबी द्वारा अपनी एकल खिड़की सेवा (Single Window Service) के तहत भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मुद्रा ऋण भी लघु उद्योगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्तमान में उसकी शत-प्रतिशत इक्विटी IDBI के पास है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड

(Industrial Development Bank of India Ltd.-IDBI)

देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया। 1976 तक यह बैंक रिजर्व बैंक का एक अनुषंगी बैंक (Subsidiary Bank) था। 1976 में इसे रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वर्तमान में IDBI में सरकार की हिस्सेदारी 58.47% है।

इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना है। यह बैंक बड़ी तथा मझोली औद्योगिक इकाइयों को सीधे ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि छोटी व मझोली इकाइयों को बैंकों तथा राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना के बाद इस बैंक के लघु तथा लघुतर इकाइयों को ऋण प्रदान करने सम्बन्धी सभी दायित्व अब लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को सौंप दिए गए हैं। सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थिति में सुधार के लिए 1 अक्टूबर, 2004 को इसका निगमीकरण (Corporatisation) कर इसे एक वाणिज्यिक बैंकिंग कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया था।

11 अक्टूबर, 2004 को RBI द्वारा एक अधिसूचना जारी करके IDBI को RBI अधिनियम 1934 के तहत एक अनुसूचित बैंक बना दिया। IDBI में भारत सरकार की अंशधारित 53% है।

भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन (Printing of Securities and Minting in India)

भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है-

छापेखाने (Printing Press)

इण्डिया सिक्क्योरिटी प्रेस, नासिक (महाराष्ट्र)- नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (India Security Press) में डाक सम्बन्धी लेखन सामग्री डाक एवं डाकभित्र टिकटों, अदालती एवं गैर-अदालती स्टाम्पों, बैंकों (RBI तथा SBI) के चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है।

सिक्क्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद- सिक्क्योरिटी प्रिन्टिंग प्रेस, हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई

थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके।

करेन्सी प्रेस नोट, नासिक (महाराष्ट्र)- नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, तथा 1000 रुपये के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है।

बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश)- देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है।

शाहबनी (पं. बंगाल) तथा मैसूर (कर्नाटक) के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड- दो नए एवं अत्याधुनिक करेन्सी नोट प्रेस मैसूर (कर्नाटक) तथा साल्बोनी (पं. बंगाल) में स्थापित किए गए हैं। यहाँ RBI के नियन्त्रण में करेन्सी नोट छापे जाते हैं। इन नए मुद्रणालयों में 1988-99 तक 10,000 मिलियन करेन्सी नोटों का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान था देवास तथा नासिक रोड स्थित करेन्सी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6,000 मिलियन करेन्सी नोटों का मुद्रण होता है।

सिक्क्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)- बैंक और करेन्सी नोट कागज तथा नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्क्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी।

टकसाल (Mints)

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की पाँच टकसालें मुम्बई, कोलकाता, चेलापल्ली, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता, की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गईं, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है।



भारत में बैंकिंग प्रणाली का उन्नतिकरण (Updation of Banking System in India)

भारत में सर्वाजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने विगत वर्षों में नवीन बैंकिंग शुरू की है।

लीजिंग (Leasing)

लीजिंग कम्पनी वित्त का ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ एक लीजिंग कम्पनी से अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी परिसम्पत्ति (अर्थात् कोई प्लांट, उपकरण, यातायात सुविधाएँ, भवन या कोई अन्य सेवाएँ) को किसी निश्चित अवधि के लिए किराए पर लेती हैं। लीजिंग कम्पनियाँ औद्योगिक इकाइयों को वित्त भी उपलब्ध कराती हैं। उपकरण अथवा संयन्त्र लीजिंग तथा वित्तीय लीजिंग का काम भारत में 1973 से निजी कम्पनियों के हाथ में है। अभी हाल ही में मर्चेण्ट बैंकिंग सहायक इकाइयों की स्थापना के बाद लीजिंग का काम सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक भी करने लगे हैं।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण (Computerization of Banks)

बैंकों में कम्प्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। धीरे-धीरे बैंक अपनी शाखाओं का पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण करते जा रहे हैं। बैंकों के लगभग 300 कार्यालय रिजर्व बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डाटा कम्प्यूनिकेशन नेटवर्क से मुम्बई कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद तथा नागपुर से जुड़े हैं। इसके साथ-साथ महानगरों में स्थित बैंकों की शाखाओं में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नीशन (एम.आई.सी.आर.) कूट अंक प्रणाली पर आधारित चैक बुक्स जारी करने को कहा गया। रिजर्व बैंक ने एम.आई.सी.आर. प्रणाली पर आधारित समाशोधन सुविधाएँ मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा नागपुर में उपलब्ध करवाई।

चल तथा संध्या बैंक (Walk and Evening Bank)

जनता में बैंकिंग आदतों का विकास करने के लिए कुछ बैंकों में चल बैंक (Mobile Bank) खोले हैं। ये बैंक मोटरगाड़ियों में होते हैं। ये बैंक निश्चित समय पर पहुँचते हैं। लोगों को इन बैंकों के साथ व्यवहार करना सरल हो गया है। इसी प्रकार संध्या बैंकों (Evening Bank) की स्थापना की गयी है। ये बैंक शाम को कार्य करते हैं जिससे नौकरी-पेशा लोग अपनी नौकरी के बाद इन बैंकों का लाभ उठा सकते हैं।

फैक्टरिंग सेवाएँ (Factoring Services)

लघु उद्योगों की ऋण वसूली की समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता से वाणिज्य बैंकों ने फैक्टरिंग सेवाएँ लागू की हैं। फैक्टरिंग के अन्तर्गत एक फैक्टरिंग संस्था अपने ग्राहक के द्वारा दी गयी साख का भुगतान स्वयं करके उसकी वसूली का कार्य करती है। इसके बदले में यह ग्राहक से कमीशन लेती है। फैक्टरिंग संस्था ऋण-वसूली से प्राप्त रकम को ग्राहक को वसूली की वास्तविक तिथि से पहले या वसूली के अन्त में दे देती है। इसके फलस्वरूप लघु उद्योगों को पूँजी का अभाव नहीं रहता। स्टेट बैंक ने फैक्टरिंग के लिए एस.बी.आई. फैक्टर्स एण्ड कॉमर्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (S.B.I. Factors and Commercial Services Pvt.Ltd) शुरू की है।

मर्चेण्ट बैंकिंग (Merchant Banking)

मर्चेण्ट बैंकिंग में कई सेवाएँ, जैसे शेयरों, डिबेंचरों आदि के जारी करने का प्रबन्धन, ऋण जुटाने का काम, वित्तीय एवं प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श, विलय तथा अधिग्रहण, अप्रवासी निवेशों का प्रबन्ध आदि आती हैं। भारत में मर्चेण्ट बैंकिंग की शुरुआत ग्रेंडले बैंक, सिटी बैंक जैसे विदेशी बैंकों ने की थी। आज भारत में कई वाणिज्यिक बैंक अपनी सहायक इकाइयों द्वारा ये सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (Electronic Banking)

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कराना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाता है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस समय बैंकिंग विकास का स्तम्भ माना जा रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बैंकिंग की भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रमुख संघटक

(Main Components Of Electronic Banking)

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-

- (i) **पी.सी. बैंकिंग या होम बैंकिंग (P.C. Banking or Home Banking):** इसके अन्तर्गत ग्राहक घर बैठे ही अपेक्षित राशि निकालने या जमा करने के लिए बैंक को ही कम्प्यूटर पर आदेश दे सकते हैं।
- (ii) **टेली बैंकिंग (Tele Banking):** इसमें ग्राहक का परिसर पी.एस.टी.एन. (Public Switched Telephone Network) लाइनों, नियमित टेलीफोन लाइनों और मॉडमों के जरिये शाखा से जुड़ा होता है। स्वयं अपने कार्यालय या डेस्क से ही सूचनाओं को प्राप्त करने की सामर्थ्य के कारण ग्राहक को भी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।
- (iii) **टेलीफोन द्वारा भुगतान (Payment by Telephone):** यह प्रणाली आपको अपनी वित्तीय संस्थाओं को टेलीफोन के जरिये आपके बिल के भुगतान व विभिन्न खातों में निधियों के अंतरण का अनुदेश देने की सुविधा देती है।
- (iv) **स्व-चालित टेलर मशीन (Automatic Teller Machine):** यह एक इलेक्ट्रॉनिक टेलर टर्मिनल है जो 24 घण्टे रूपया जमा करने या निकालने आदि की सेवा उपलब्ध करता है।
- (v) **डायरेक्ट क्रेडिट (Direct Credit):** इसमें ग्राहक सीधे पहले से धनराशि निकालने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सकते हैं ताकि आपने आवर्ती बिल, जैसे- बीमा किश्त आदि का स्वतः भुगतान होता रहे।
- (vi) **इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण प्रणाली (Electronic Money Transfer System):** इसके अन्तर्गत इस प्रकार की भुगतान प्रणालियों में लिखित चेक के बिना भी एक खाते से दूसरे खाते में धन अन्तरित किया जा सकता है।
- (vii) **डायरेक्ट जमा प्रणाली (Direct Deposit System):** इसके माध्यम से आप अपने विशेष जमा, जैसे- वेतन चेक, कमीशन, चेक, पेन्शन चैक आदि नियमित रूप से जमा कर सकते हैं।



- (viii) **इण्टरनेट बैंकिंग (Internet Banking):** इण्टरनेट बैंकिंग स्वयं एक लक्ष्य नहीं है परन्तु यह बैंकों के लिए ऑनलाइन लेन-देन सेवाएँ प्रदान करने तथा उनकी पूर्ति का एक साधन मात्र है। यह पारस्परिक बैंकिंग से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग विपणन का क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इण्टरनेट सुविधा होने से ऑनलाइन बैंकिंग अब भारत में भी होने लगी है।
- (ix) **स्मार्ट कार्ड व क्रेडिट कार्ड (Smart Card and Credit Card):** यह वास्तव में एक सूक्ष्म कम्प्यूटर होता है जो कार्ड के आकार का होता है। इसमें कार्डधारक के बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी रहती है। इसकी सहायता से कहीं भी लेन-देन किया जा सकता है अर्थात् यह एक इलेक्ट्रॉनिक पर्स है।
- (x) **रीयल टाइम ग्रास सेटलमेन्ट (R.T.G.S.):** इस प्रणाली में अनेक लेन-देन प्रारम्भ होते ही निपटान भी साथ-साथ होता जाता है बजाय इसके कि उसकी प्रोसेसिंग लेन-देन के समूह में हो।
- (xi) **इन.फाय.नेट (Indian Financial Network):** भारतीय वित्तीय नेटवर्क जो कि वृहद् सेटलाइट आधारित नेटवर्क है, वी सेट प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लाभ (Benefits of Electronic Banking)

ई-बैंकिंग प्रणाली से समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होता है।

- (i) **समाज को लाभ (Advantages to Society):** ई-बैंकिंग प्रणाली से राष्ट्रीय परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा में बदल जाएगी, निर्यात में वृद्धि होगी। व्यापार, उद्योग एवं बैंकिंग में लाभ होने से समाज में भी रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा। सरकार की कल्याणकारी समाज की स्थापना का प्रयास साकार होगा।
- (ii) **व्यापार एवं उद्योग को लाभ (Advantages to Trade and Industries):** ई-बैंकिंग प्रणाली से व्यापार व उद्योग से अत्यधिक वृद्धि होगी क्योंकि ग्राहकों की क्रय शक्ति क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि के प्रयोग से बँध जाएगी और व्यापार का स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो जाएगा।
- (iii) **बैंकों को लाभ (Advantages to Banks):** बैंक अब सीमित ग्राहक, सीमित सेवाओं की अवधारणाओं से निकलकर विस्तृत ग्राहक और विस्तृत सेवाओं के आधार पर कार्य करेंगे। फलतः बैंकों का व्यापार क्षेत्रीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हो जायेगा। इससे उनकी लाभप्रदता में वृद्धि होगी।
- (iv) **ग्राहकों को लाभ (Advantages to Customers):** ई-बैंकिंग प्रणाली से ग्राहक सभी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन बिना कहीं गये कर सकता है। इससे ग्राहकों को न केवल कम लागत पर चौबीसों घण्टे बैंकिंग सुविधाएँ प्राप्त होती हैं बल्कि यह सेवाएँ अत्यन्त सुरक्षित भी होती हैं।
- उपर्युक्त लाभों के होते हुए भी ई-बैंकिंग प्रणाली का बड़ी सतर्कता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर तो इसमें ग्राहकों के लिए पारदर्शिता में कमी आयेगी। इसमें अधिक पूँजी नियोजन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और दूसरी ओर विद्यमान बैंकिंग कर्मचारियों द्वारा छँटनी के भय से इसका विरोध किया जाएगा।

➤ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना एक करोड़ रूपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है।

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी, 2004 को लांच किया गया था। यह एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नोविगेशन कॉर्पोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। यह स्टीमर एर्नाकुलम जोड़ता है। और व्यपीन के बीच चलती है।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपान्तरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिन्द्रा फाइनेंस कम्पनी के रूप में कार्यरत था।
- निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटी.आई. बैंक ने 2 अप्रैल, 1994 से कार्य करना प्रारम्भ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए पूँजी पर्याप्तता मानक

(Capital Adequacy Standard For Financial Institutions)

वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ अपनी निधियों एवं प्राप्त निक्षेपों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऋण देती हैं या आस्तियों का सृजन करती हैं। इन ऋणों का पुनर्भुगतान न हो पाने या विलम्ब से हो पाने एवं ब्याज की प्राप्ति न हो पाने की जोखिम भी प्रायः बनी रहती है। पिछले वर्षों में भारत में बैंकों ने जिस प्रकार से पूँजी बाजार में ऋण वितरित किए और मन्दी की स्थिति में उन ऋणों की वसूली न हो पाने के कारण अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई। इसी प्रकार दक्षिण कोरिया में वर्ष 1997-98 में आए आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण भी यही था कि वहाँ के बैंकों ने जनता से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करके उससे सृजित निधियों के आधार पर घरेलू नागरिकों एवं कम्पनियों को दीर्घकालीन ऋण वितरित किए। इसके फलस्वरूप ये बैंक अपनी देनदारियों को समय से पूरा नहीं कर पाए और अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। 2008 में भी अमरीका सहित विश्व के अनेक देशों में यह संकट उत्पन्न हो गया। इस प्रकार के आर्थिक संकट को पैदा होने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर बैंक ऑफ इण्टरनेशनल सैटलमेन्ट द्वारा गठित वास्ले समिति ने सन् 1988 में सर्वप्रथम पूँजी पर्याप्तता मानक की अवधारणा को प्रस्तुत किया।

पूँजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूँजी से है जिसे उस कम्पनी द्वारा किसी व्यावसायिक आस्ति के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) व्यवसाय के उस स्तर को निर्धारित करता है जिसे कोई वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि पूँजी संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि पूँजी पर्याप्तता अनुपात 8% निर्धारित किया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि वित्तीय संस्थान को प्रत्येक एक सौ रूपए की व्यवसायिक आस्ति के लिए 8 रूपए की पूँजी अनिवार्य रूप से अपने पास रखनी चाहिए।

भारत में वास्ले समिति की सिफारिशों के अनुरूप समस्त बैंकों ने पूँजी पर्याप्तता मानक वर्ष 1992-93 से लागू करना प्रारम्भ कर दिया था। नरसिंहम समिति (II) की सिफारिशों के अनुसरण में CAR को चरणबद्ध रूप से वर्तमान 8% से बढ़ाकर 10% करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार RBI ने 31 मार्च, 2000 से CAR को बढ़ाकर 9% करने का निर्णय किया। ज्ञातव्य है कि विदेशी बैंकों और वैसे भारतीय बैंकों, जिनका परिचालन देश के बाहर भी है, को बेसल-2 मानकों को 31 मार्च, 2008 से लागू करना था, जबकि अन्य वाणिज्यिक बैंकों, स्थानीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, के लिए यह नियम 31 मार्च, 2009 से लागू किया जाना था।



माइक्रोफाइनेन्स (Microfinance)

लघुवित्त अथवा माइक्रोफाइनेन्स उन लोगों को ऋण मुहैया कराती है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण नहीं देते क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी या बन्धक के लिए कुछ भी नहीं होता।

ठेले पर सब्जी बेचने, पापड़-बढ़िया बनाने या सड़क किनारे पन्चर जोड़ने जैसे छोटे-छोटे कारोबार करने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि उनके पास बन्धक रखने को कुछ नहीं होता और बैंक इसके बगैर उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं होते। सामान्य स्थितियों में तो उनका धन्धा चलता रहता है लेकिन किसी हारी-बीमारी में, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाने पर, घर बनाने या शादी-ब्याह जैसे बड़े खर्च का बोझ उठाने के लिए वे साहूकार से बहुत ऊँची दर पर कर्ज लेते हैं और अक्सर ब्याज चुकाने में ही उम्र गंवा देते हैं। माइक्रोफाइनेन्स ऐसे ही लोगों को कर्ज देने का उपहार है।

जहाँ तक वंचित और गरीब लोगों का सवाल है, माइक्रोफाइनेन्स कम्पनियों की तरफ से इन गरीबों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा भी काफी कम रहती है और ज्यादातर उत्पादन काम में नहीं बल्कि उपभोग की मद में इस्तेमाल होता है। इसमें सूद की दर 20 से 40 फीसदी तक रहती है तथा कर्ज की वसूली 98% तक दिखाई जाती है। यह एक ऐसा वर्ग (तबका) है जो हमेशा ही सरकारी बैंकों और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा संचालित कर्ज की योजनाओं से बाहर रहा है।

**दामोदरन समिति के सुझाव
(Suggestion of Damodarn Committee)**

‘सेबी’ (SEBI) के पूर्व अध्यक्ष एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें अपनी रिपोर्ट में की हैं। यह रिपोर्ट भारतीय बैंक (RBI) की वेबसाइट पर अगस्त 2011 में जारी की गई थी तथा रिपोर्ट पर आम जनता की टिप्पणियाँ 27 अगस्त, 2011 तक रिजर्व बैंक द्वारा आमंत्रित की गई थी। इस समिति के प्रमुख सुझाव हैं-

- बचत खातों (Saving Accounts) में चेक बुक व एटीएम कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए खातों में ‘न्यूनतम बैलेंस’ का कोई बंधन नहीं हो।
- पासबुक भरने जैसी आवश्यक सेवाएँ खाताधारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ।
- न्यूनतम बैलेंस से कम बैलेंस होने की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला दंडात्मक शुल्क उतने ही अनुपात में ही हो, जिनती राशि से खाते में बैलेंस कम हुआ हो।
- सावधि जमाओं (Fixed Deposits) को खातेदार की लिखित अनुमति के बिना स्वतः ही ‘रिन्यू’ न किया जाए।
- बचत खातों में जमा राशि के लिए उपलब्ध बीमा सुरक्षा एक लाख रूपए की बजाय 5 लाख रूपए तक की जमाओं पर उपलब्ध कराई जाए।
- होम लोन अकाउंट समय पूर्व बंद कराने की स्थिति में कोई दंडात्मक शुल्क बैंक द्वारा वसूल नहीं किया जाए।
- होम लोन के नए ग्राहकों को रियायती ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध कराए जाने पर ऐसी रियायत पुराने ग्राहकों को भी उपलब्ध कराई जाए।
- होम लोन चुकता होने के पश्चात् संबंधित संपत्ति के कागजात उसके स्वामी को 15 दिन के भीतर बैंक द्वारा लौटाए जाएँ।
- बैंक ग्राहकों की बैंकिंग संबंधी शिकायतों व अन्य सुनवाईयों के लिए सभी बैंकों का एक ही कॉमन निःशुल्क कॉल सेंटर नंबर (फोन नंबर) हो।

- पहली बार 18 माह तक किश्त एवं ब्याज का भुगतान न करने पर सन्देशास्पद की संज्ञा प्रदान करना।
- अगली बार 12 माह तक किश्त एवं ब्याज का भुगतान न किए जाने पर घटिया परिसम्पत्ति की संज्ञा प्रदान करना।
- पहचान कर ली गई, परन्तु बट्टे खाते में न डाली गई परिसम्पत्ति को क्षतिवान परिसम्पत्ति की संज्ञा प्रदान करना।

- सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किए गए असुविधाजनक हो चुके ऋणों को गैर-निष्पादनीय आस्ति माना जाए।
- दो लाख रूपए से कम के ऋणों पर ब्याज निर्धारण का अधिकार बैंकों को दिया जाए।
- प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋणों में ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता अवयव को पूर्णतया समाप्त किया जाए।

भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के स्थापना वर्ष

(Establishment Year of India's Chief Financial Institutions)

संस्थान	स्थापना वर्ष
इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1 अप्रैल, 1935
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी, 1949
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)	1948
भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम (ICICI)	जनवरी, 1955
भारतीय स्टेट बैंक	1 जुलाई, 1955
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI)	1 फरवरी 1964
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)	जुलाई 1964
कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (NABARD)	12 जुलाई, 1982
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)	20 मार्च, 1985
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	1990
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)	1 जनवरी, 1982
राष्ट्रीय आवास बैंक	जुलाई 1988
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)	सितम्बर 1956
भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC)	नवम्बर 1972
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रारम्भ	2 अक्टूबर, 1975
जोखिम पूँजी एवं टेक्नोलॉजी निगम (Risk Capital and Technology Finance Corporation Ltd. RCTC)	मार्च 1975
भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कं. (Technology Development and Information Co. of India Ltd. TDICI)	1989
अधः संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लि. (Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd.)	1988
गृह विकास वित्त निगम लि. (Housing Development Finance Corporation Ltd. HDFC)	1977



विकास बैंक, व्यापारिक बैंक व विनियोग बैंक में अन्तर

(Difference in Development Bank, Business Bank and Appropriation Bank)

क्र.सं.	अन्तर का आधार	विकास बैंक	व्यापारिक व विनियोग बैंक
1.	उद्भव	इन बैंकों का उद्भव अन्तराल पूरकों (Gap Fillers) के रूप में हुआ है। जब औद्योगिक संस्थाओं को विशिष्ट या सामान्य स्रोत से वित्त की पूर्ति नहीं होती है तो विकास बैंकों की स्थापना करके इस कमी को पूरा किया जाता है।	इन बैंकों का प्रादुर्भाव प्रमुख रूप से बिखरी हुई बचतों को संग्रह करके लाभप्रद विनियोजन के लिए किया गया है।
2.	ऋण की प्रकृति	औद्योगिक उपक्रमिक्यों को मध्यम व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं।	व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध कराते हैं।
3.	वित्त प्रबन्धन की विधि	ये बैंक कम्पनियों से अंश खरीदकर उनके ऋण-पत्रों का रूप कर अथवा अंशों से ऋण-पत्रों के अभिगोपन द्वारा वित्तीय व्यवस्था करते हैं।	व्यापारिक बैंक ऋण देने वाले को ऋण की पूरी राशि नकद में नहीं देते बल्कि ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया निकालने का अधिकार दे देते हैं।
4.	ऋण के उद्देश्य	ये बैंक वास्तव में स्थिर सम्पत्तियों (Fixed Assets) में वास्तविक विनियोग के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं।	ये बैंक चालू पूँजी की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य बैंक की तरलता बनाये रखना होता है।
5.	वित्त के स्रोत	चूँकि ये बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं इसलिए उन्हें अधिकांश वित्त सरकार, केन्द्रीय बैंक और सार्वजनिक संस्थाओं से मिलता है। इनका बचतों के एकत्रीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता।	इनका प्रमुख वित्त का स्रोत बचतें ही हैं जिन्हें ये एकत्र करके उत्पादक कार्यों में लगाते हैं।
6.	कौशल निर्माण	ये बैंक कौशल निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।	ये यह कार्य नहीं करते हैं।
7.	सामाजिक लाभ	इन बैंकों का दृष्टिकोण विकासोन्मुख होता है। अतः इनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र औद्योगिक लक्ष्यों और योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करना होता है।	इनका दृष्टिकोण सेवा द्वारा लाभ कमाना होता है।
8.	विदेशी मुद्रा का अर्जन	ये बैंक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं और औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विदेशी कम्पनियों से प्राप्त किये गए ऋणों की गारण्टी देते हैं।	इन बैंकों की विदेशी मुद्रा का अर्जन और विदेशी ऋणों की गारण्टी की भूमिका नगण्य है।
9.	उपक्रमियों का विकास	ये बैंक देश में उद्यमशीलता के विकास में सक्रिय भूमिका का निर्माण कर रहे हैं।	ये यह कार्य नहीं करते हैं।
10.	तकनीकी सहायता	ये उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए उनके प्रवर्तन व प्रबन्ध में सहयोग देते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी एवं वित्तीय परामर्श भी देते हैं।	यद्यपि ये बैंक भी औद्योगिक परियोजनाओं के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं परन्तु इनका क्षेत्र व दृष्टिकोण संकुचित है।
11.	समन्वयात्मक कार्य	विकास बैंक एक सर्वोच्च संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त से सम्बन्धित विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करता है, ताकि सभी संस्थाएँ मिलकर समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर सकें।	इनकी इस प्रकार की कोई भूमिका नहीं है।
12.	नव-प्रवर्तन कार्य	विकास बैंक नव-प्रवर्तन के रूप में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे-नई-नई आकर्षक और उत्पादक बचत और विनियोग योजनाओं का निर्माण, आर्थिक विकास की नवीन संस्थाओं का सृजन आदि।	इन बैंकों में प्रायः नव-प्रवर्तन कार्यों का अभाव है।
13.	पूँजी बाजार का निर्माण	ये बैंक पूँजी बाजार को प्रोत्साहन देने और उनमें स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।	ये इस तरह के कार्य नहीं करते।



बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)

बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 14 जून, 1995 से देशभर में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लागू कर दी है इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी (Ombudsman) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति दिल्ली, भोपाल, बंगलौर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, मुम्बई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा त्रिवेन्द्रम में की गई है।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक ग्राहक प्रहरियों के दायरे में आते हैं, किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

कोई भी ग्राहक जिसकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा सन्तोषजनक तरीके से सम्बन्धित बैंक शाखा तथा उसके शीर्ष प्रबन्धन द्वारा 2 माह के भीतर नहीं किया जाता, बैंकिंग लोकपाल, के पास तक वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है। ये शिकायतें निम्नलिखित क्षेत्रों में की जा सकती हैं-

- चेकों, ड्रॉफ्टों, बिलों आदि के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलम्ब, करना,
- छोटे नोटों को बिना किसी उचित कारण बताए स्वीकार न करना,
- बैंक ड्रॉफ्ट निर्गत न करना
- बैंक द्वारा परिचालित किसी भी खाते के परिचालन से सम्बन्धी शिकायतें, विशेष रूप से ब्याज दरों से सम्बन्धित
- भारत में कार्यरत किसी भी बैंक से सम्बन्धित निर्यातकों तथा निवासी भारतीयों की शिकायतें

उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में लोकपाल, पहले प्रयास में शिकायतकर्ता तथा सम्बन्धित बैंक के मध्य समझौता कराने का प्रयास करता है, किन्तु इससे समाधान प्राप्त न होने पर वह शिकायतकर्ता को हुई हानि की राशि का (जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकती है) 'एवार्ड' घोषित कर सकता है। बैंक द्वारा एवार्ड का भुगतान न करने पर लोकपाल उसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी बैंकिंग व्यवहार अब शामिल किए हैं। क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित शिकायतों, वायदा की गई सुविधाएँ देने में विलम्ब, बैंकों के ब्रिकी ऐजेन्टों द्वारा किए गए वायदे पूरे नहीं करने तथा ग्राहकों पर पूर्व सूचना के बिना सेवा प्रभार लगाने आदि को भी अब इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। बैंक सेवाओं में विलम्ब, बैंकों द्वारा छोटे मूल्य वर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार नहीं करने अथवा इन पर कमीशन माँगने की शिकायतें भी बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती हैं।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non Performing Assets)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत के सर्वांगीण विकास में वाणिज्यिक बैंकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, लेकिन इसी के साथ-साथ विगत वर्षों में बैंकों की लाभप्रदता गिरी है। नीची लाभप्रदता का एक प्रमुख कारण बैंकों की गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non-Performing Assets) में भारी वृद्धि हो जाना है।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं, जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं पाती या बिलकुल नहीं हो पाती।

बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है। गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियों को पुनः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- घटिया परिसम्पत्तियाँ (Bad Assets):** बैंकों द्वारा वितरित ऋणों के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का पुनर्भुगतान जब दो वर्ष तक नहीं किया जाता, तो ऐसी परिसम्पत्तियों को घटिया या सब-स्टैंडर्ड परिसम्पत्तियों की संज्ञा दी जाती है। बैंकों द्वारा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान का नया शिड्यूल बनाया जाता है। ऐसे ऋणों को कम-से-कम एक वर्ष तक घटिया परिसम्पत्तियों के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
- सन्देहात्मक परिसम्पत्तियाँ (Suspicious assets):** ऐसे ऋण जो उपर्युक्तानुसार दो वर्षों तक गैर निष्पादनीय रहे हैं, परन्तु जिनके वसूल होने की सम्भावना है। अर्थात् जिन्हें क्षति परिसम्पत्तियाँ नहीं मान लिया गया है, सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इस वर्ग में अधिकांशतः ऐसी बीमार कम्पनियों द्वारा लिए गए ऋण आते हैं जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को सन्दर्भित कर दिया गया है और बोर्ड द्वारा उक्त कम्पनियों के पुनर्निर्माण का पैकेज अपेक्षित है।
- क्षति परिसम्पत्तियाँ (Damage Assets):** ऐसी परिसम्पत्ति जिसकी पहचान क्षति के रूप में कर ली गई है, परन्तु उसे अपलिखित नहीं किया गया है, क्षति परिसम्पत्ति कहलाती है। ये वे ऋण होते हैं, जो वसूल किए जाने की स्थिति में नहीं होते, तथापि इनका कुछ-नकुछ निस्तारण (Salvage) मूल्य अवश्य हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानक निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि बैंकों को ऋणों की वसूली न हो पाने से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में अपनी निधियों का एक भाग अलग से रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, घटिया या सब-स्टैंडर्ड परिसम्पत्ति के कुल अर्ध का 10 प्रतिशत, सन्देहात्मक परिसम्पत्तियों के अर्ध का 20 प्रतिशत तथा हानि परिसम्पत्तियों के अर्ध का 100 प्रतिशत प्रावधान राशि के रूप में रखना पड़ता है।

मानक परिसम्पत्तियाँ (Standard Assets)

बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण निष्पादनीय परिसम्पत्तियों माने जाते हैं, जिनका मूलधन एवं उस पर देय ब्याज समय से बैंक को प्राप्त होता रहता है। इसलिए इन्हें मानक परिसम्पत्तियों की संज्ञा दी जाती है। इसमें ऐसे ऋणों को भी शामिल किया जाता है जिनमें बकाया मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान क्रमशः 180 दिन तथा 365 दिन से अधिक समय तक किसी वित्तीय वर्ष में नहीं रोका जाता। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के लिए बैंकों को किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करना पड़ता।



गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ
(Non Banking Financial Companies)

NBFC प्रायः उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती है जहाँ ऋण अन्तराल विद्यमान है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और मोटरकारों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। NBFC के कारोबार में तीव्र वृद्धि ने निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। इसके लिए RBI ने NBFC की गतिविधियों की नियमित करना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 जनवरी, 2001 को जारी निजी क्षेत्र में नए बैंक के प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में अच्छे विगत रिकॉर्ड वाली NBFC को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक बनने की अनुमति दे दी गई है-

- NBFC की अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार कम-से-कम 200 करोड़ रूपए की निवल सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसे रूपान्तरण की तारीख से तीन वर्षों के भीतर 300 करोड़ रूपए तक बढ़ाया जाना होगा।
- NBFC को किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा प्रमोट किया हुआ नहीं होना चाहिए अथवा स्थानीय, राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार सहित, सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्वाधीन/ नियन्त्रणाधीन नहीं होना चाहिए।
- NBFC को पूर्व वर्ष AAA रेटिंग (अथवा इसके समकक्ष) से कमतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- NBFC का भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों/निर्देशों के अनुपालन और सार्वजनिक जमाओं की वापसी अदायगी में विगत रिकॉर्ड त्रुटिहीन होना चाहिए।
- NBFC के पास कम-से-कम 12% की पूँजी पर्याप्तता होनी चाहिए और इनकी निवल NPA 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- NBFCs के पास कम-से-कम 25 लाख रूपए का शुद्ध निजी कोष (Net Owned Fund) होना रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है। इस मानक को पूरा न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कारोबार करने से प्रतिबन्धित करने की घोषणा रिजर्व बैंक ने फरवरी 2003 में की थी।
- NBFCs द्वारा सार्वजनिक जमाओं (Deposits) पर अब अधिकतम 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज दिया जा सकेगा। अभी तक इसके लिए 12.5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित थी। ब्याज की नई उच्चतम सीमा 4 मार्च, 2003 से प्रभावी की गई थी। ब्याज दर की नई उच्चतम सीमा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था कि कम्पनियाँ (गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ) इससे कम ब्याज देने का स्वतन्त्र हैं।

बैंकिंग (संशोधन) अधिनियम, 2011
(Banking Reforms Act, 2011)

बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 22 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किया। Banking Laws (Amendment) Bill 2011 नाम के इस विधेयक में बैंकों को शेयर पूँजी जुटाने के मामले में अधिक आजादी प्रदान करने तथा बैंकिंग क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों के शेयरधारकों के लिए मताधिकार की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1% से बढ़ाकर 10% करने का प्रावधान जहाँ इस संशोधन विधेयक में किया गया है, वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के लिए मताधिकार की 10% सीमा को समाप्त करने का भी इसमें प्रावधान है। इस विधेयक के अधिनियमित होने से निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में शेयरधारकों का मताधिकार उनकी शेयर होल्डिंग के अनुरूप होगा।

इस विधेयक के जरिए Banking Regulation Act, 1949 तथा Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) 1970 व 1980 में संशोधन किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

यह देश के नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए उस देश की वित्तीय व्यवस्था का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। एवं वित्तीय व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब देश का एक-एक नागरिक वित्तीय प्रणाली से जुड़े वित्तीय समावेशन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

- लोगों की संस्थागत प्रणाली से जोड़ना जिसके माध्यम से लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया जा सके। साथ ही घरों में पड़े अधिशेष राशि को अर्थव्यवस्था में प्रवाहित किया जा सके।
- लोगों को संस्थागत ऋण की प्राप्ति कराना। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की निर्भरता साहूकारों पर कम हो सके एवं किसानों को भी सामान्य ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति हो सके।
- लोगों को मुफ्त वित्तीय परामर्श आवश्यकता पड़ने पर प्रदान किया जा सके।

वित्तीय समावेशन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आजादी के समय से ही आर.बी.आई. एवं भारत सरकार प्रयत्नशील रहे हैं। अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाये जा चुके हैं-

- 1955 से लेकर 1980 तक लगातार बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया जारी रही। यह मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए एवं बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के लिए किया गया।



- (ii) 1969 में अग्रणी बैंक (Lead Bank) की अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसके अंतर्गत वह बैंक जिसकी किसी भी जिले में सर्वाधिक शाखाएँ होंगी। उसे वह जिला वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से गोद लेना होगा।
- (iii) 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने का था।
- (iv) 1982 में NABARD की स्थापना की गई जोकि एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो उन बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आगे ऋण प्रदान करते हैं।
- (v) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण को भारतीय एवं विदेशी बैंकों के ऊपर अनिवार्य रूप से लागू किया गया ताकि समाज के उस वर्ग को भी संस्थागत ऋण की प्राप्ति हो सके जिसे बैंक आम तौर पर ऋण प्रदान नहीं करना चाहते।
- (vi) 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लागू की गयी जिसके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि के उद्देश्य से ऋण प्रदान किया जाता है।
- (vii) समाज के निम्न वर्ग को बैंक खाता प्रदान करने के उद्देश्य से No frills A/C / Bank account/ मौलिक खाता बैंकों ने खोलना प्रारम्भ किया। जिसके अन्तर्गत खाता शून्य जमा राशि पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
- (viii) बैंक मित्र/बैंक साथी की अवधारणा को लागू किया गया जिसके माध्यम से बैंकों को एवं बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया गया।
- (ix) खान समिति, रंग राजन समिति एवं नचिकेत मोर समिति की स्थापना की गयी। जिन्होंने समय-समय पर इस पूरी प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सुझाव दिये।
- (x) 28 अगस्त 14 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ।

नचिकेत मोर समिति रिपोर्ट (Nachiket More Committee Report)

वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. ने नीचकेत मोर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपने सुझाव 2014 में प्रस्तुत किये। इस समिति के अनुसार, आधार को बैंक खाता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य पहचान पत्र बनाया जाये। अगले 12 महीनों में देश की 50% आबादी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाये एवं उसके बाद के 12 महीनों में शत प्रतिशत आबादी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाये। इस समिति ने पेमेन्ट बैंक एवं स्माल फाइनैस एवं स्माल फाइनैस बैंक के रूप में वर्गीकृत बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने यह भी खुलासा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक शाखाओं की स्थापना की जाये। परन्तु समिति के अनुसार वित्तीय समावेशन के लिए ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाये जो देश के वित्तीय स्थायित्व के लिए खतरा है।

मौद्रिक एवं साख निति (Monetary and Credit Policy)

साख नियंत्रण (Credit Control)

रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है, जो साधारणतया किसी भी केन्द्रीय बैंक का प्रधान कार्य माना जाता है। वस्तुतः साख नियंत्रण के माध्यम से रिजर्व बैंक विनिमय, मूल्यों तथा अन्य गतिविधियों में स्थिरता बनाए रखता है। इसके लिए रिजर्व बैंक सभी वैधानिक उपायों जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाओं, वाणिज्यिक बैंकों के नकद कोषों के प्रतिशत में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, साख की राशनिंग, नैतिक प्रोत्साहन आदि का सहारा लेता है। रिजर्व बैंक 1956 के बाद से चयनात्मक साख नियंत्रण के उपायों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगा है। यह गुणात्मक तथा परिणामात्मक नियंत्रणों द्वारा भी बैंकों की साख क्रियाओं का नियंत्रण करता है।

साख नियंत्रण की विधि (Law of Control Credit)

साख मुद्रा का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के लिए परिमाणात्मक (Quantitative Method) तथा गुणात्मक (Qualitative Method) का प्रयोग करता है। परिमाणात्मक विधि के अन्तर्गत बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, परिवर्तनशील कोष अनुपात तथा तरलता कोष अनुपात तथा तरलता कोष अनुपात का प्रयोग किया जाता है जबकि गुणात्मक विधि के अन्तर्गत चयनित साख नियंत्रण, साख समायोजन, नैतिक अनुनय प्रचार तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधियों की संक्षिप्त विवेचना निम्नवत् है-

चयनात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Control)

चयनात्मक साख नियंत्रण का प्रयोग कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के विरुद्ध किया जाता है। ये वस्तुएँ हैं- खाद्यान्न, तिलहन, तेल, वनस्पति घी, कपास, खांडसारी, गुड़, चीनी, सूती कपड़ा एवं सूती धागा। भारत में इसके अन्तर्गत तीन उपाय किए जाते हैं-

- कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों या धरोहर के आधार पर ऋणों के लिए न्यूनतम मूल्यांतर (margin) निर्धारित करना,
- कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए ली जाने वाली उधार की राशि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना,
- कुछ विशेष प्रकार के अग्रिमों पर भेदमूलक ब्याज की दरें वसूल करना। 9 अक्टूबर, 1991 से रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख नियंत्रण के लिए तीन नए कदम उठाए हैं। ये हैं- (a) रूई और कपास को चयनात्मक साख नियंत्रण के अधीन लाया गया, (b) दालों की धरोहर पर चयनात्मक साख नियंत्रणों को और मजबूत बनाया गया, (c) गेहूँ पर अग्रिमों की साख सीमा किसी पार्टी द्वारा 1989-90 तक समाप्त तीन वर्षों में अधिकतम उपलब्ध साख की 85% निश्चित की गई।

परिमाणात्मक एवं गुणात्मक नियंत्रण (Quantitative and Qualitative Credit)

साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख (Credit) की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। केन्द्रीय बैंक के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य साख पर नियंत्रण करना होता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा सम्पन्न किया जाता है। साख नियंत्रण के उपायों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- (i) परिमाणात्मक उपाय तथा (ii) गुणात्मक (चयनात्मक) उपाय। परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में साख (उधारी) की कुल मात्रा पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। यह सभी प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों पर एकसमान लागू होता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रायः बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, सांविधिक तरलता, अनुपात तथा परिवर्तनीय नकद आरक्षण अनुपात का सहारा लिया जाता है, जबकि प्रचार, साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, नैतिक दबाव, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय हैं।

साख नियंत्रण के प्रमुख उपकरण (Main tools of Credit Control)

साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरण निम्नवत् हैं-

- CFR - परिवर्तन कोष अनुपात
(A) CRR - नगद आरक्षी अनुपात
(B) SLR - वैधानिक तरलता अनुपात
- Bank Rate - बैंक दर
- Repo Rate - रेपो दर
- Reverse Repo Rate - रिवर्स रेपो दर
- Open Market Operation - खुली बाजार की प्रक्रिया
- MSF - सीमांत स्थाई सुविधा

परिवर्तन कोष अनुपात (Change Fund Ratio)

भारतीय रिजर्व बैंक तरल कोष अनुपात में परिवर्तन के द्वारा भी साख नियंत्रण करता है। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा उतना ही कम साख सृजन होगा। परिवर्तनीय कोष अनुपात के दो घटक नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio, S.L.R.) हैं।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस अंश का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सामान्यतः यह 3% से 15% के मध्य होता है। नकद आरक्षित अनुपात जितना ही अधिक होगा, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता उतना ही कम होगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा प्रसार करना होता है तो नकद आरक्षित अनुपात में कमी कर देता है। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी संपत्ति का कम-से-कम 25% भारतीय रिजर्व बैंक के पास C.R.R. के अन्तर्गत रखे गए नकद के अतिरिक्त नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा की स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। यही वैधानिक तरलता अनुपात है। केन्द्रीय बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि किए जाने



पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम मात्रा में साख सृजन होता है। वैधानिक तरलता अनुपात में कमी होने पर साख सृजन अधिक होता है। C.R.R. पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर पर बैंकों को ब्याज देता है पर ऐसी कोई स्थिर या निश्चित दर नहीं है प्रतिशत की दर धारित प्रतिभूतियों की प्रतिशत की दर पर निर्भर करती है।

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है अथवा प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती या पुनर्बट्टा (Retscount) करता है। बैंक दर की नीति इस बात पर निर्भर करती है कि देश में वाणिज्यिक बैंक किस सीमा तक ऋण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय बैंक पर आश्रित है। अन्य शब्दों में यदि केन्द्रीय बैंक देश की वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो बैंक दर की नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होगी। यदि केन्द्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना चाहता है तो बैंक दर को कम कर देता है। बैंक दर को कम करने पर वाणिज्यिक बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इससे वाणिज्यिक बैंक औद्योगिक क्षेत्र या अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध करा सकेंगे फलतः आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

रेपो दर (Repo Rate)

रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉण्डों एवं प्रतिभूतियों (पुनर्खरीद समझौतों के अन्तर्गत) पर दी जाने वाली ब्याज की दर रेपो दर कहलाती है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

यह रेपो दर से उल्टी होती है। बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं।

➤ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- 3 मई, 2011 को 2011-12 की मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा के समय रिवर्स रेपो दर को रेपो दर के साथ सम्बद्ध करते हुए रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि आगे से इनमें से केवल एक (रेपो दर) सन्दर्भ दर रहेगी तथा रिवर्स रेपो दर इससे एक प्रतिशत बिन्दु नीचे बनी रहेगी। इसी के साथ यह घोषणा भी रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी कि बैंकों के लिए नई शुरु की गई सीमान्त स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility) के लिए ब्याज की दर रेपो दर से एक प्रतिशत बिन्दु अधिक रहेगी।

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Actions)

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब मुद्रा बाजार में सरकारी हुंडियों के क्रय-विक्रय के द्वारा देश में मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियन्त्रण करती है/किया जाता है, तो इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जब बाजार में व्याप्त मुद्रा को निकालना या कम करना होता है तो वह हुंडियों एवं प्रतिभूतियों का क्रय करने लगती है। अन्य शब्दों में जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तब बाजार में तरलता की कमी हो जाती है। इसके विपरीत जब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से प्रतिभूतियाँ या हुंडियों का क्रय करती है तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है अर्थात् बाजार में मुद्रा की पूर्ति

बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय करने पर साख सृजन कम होता है तथा प्रतिभूतियों के क्रय करने पर साख सृजन अधिक होता है। खुले बाजार की क्रिया का प्रयोग केवल साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसे सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के माध्यम या राजकोषीय यन्त्र के रूप में भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय करना (सामान्यतया अल्पावधि की) तथा दूसरी प्रतिभूतियों का उसके स्थान पर विक्रय करने की (लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों का) क्रिया जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि लम्बी हो सकें, को स्विच ऑपरेशन की संज्ञा दी जाती है।

सीमांत स्थाई सुविधा (Marginal Standing Facility-MSF)

इस उपकरण को भारत में 9 मई 2011 को लागू किया गया था। यह सुविधा मात्र वाणिज्यिक बैंकों को ही प्राप्त है। इसका लाभ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक नहीं उठा सकते इसके अंतर्गत यदि किसी बैंक को मात्र घंटों के लिए ऋण की आवश्यकता हो तो वह RBI से प्राप्त कर सकती है। परन्तु इस प्रक्रिया में वार्षिक ब्याज दर हमेशा रेपो दर से 1% ज्यादा होगी। अतः वर्तमान में MSF की दर 7% है। इस सुविधा के अंतर्गत कोई भी बैंक अपने कुल जमा राशि के 2% से ज्यादा की राशि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती। MSF के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों को उतने ही मूल्य के बराबर या उसे ज्यादा की प्रतिभूतियाँ गिरवी रखनी होती है। परन्तु यहाँ बैंक उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकती है जो उसने SLR के रूप में खरीदा है।

जब मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI लगातार दरों में कटौती करती है तो इन नीतियों को सस्ती ऋण नीति कहते हैं। क्योंकि इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को सस्ते दर पर ऋण प्राप्त कराने का होता है जिससे उपभोग बढ़ता है एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इसके विपरीत यदि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI लगातार दरों में बढ़ोत्तरी करे, तो इन नीतियों को महंगी ऋण नीति कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऋण को मंहगा कर मुद्रास्फीति के निवारण के उद्देश्य से माँग को नीचे लाने का होता है। जब RBI मौद्रिक एवं साख नीतियों में परिवर्तन करती है, तो दरों में किये गये परिवर्तन के अनुसार बैंकों को अपनी आधार दर परिवर्तित करनी होती है। (आधार दर वह न्यूनतम, ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती) यदि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से RBI दरों को परिवर्तित करे परन्तु बैंक अपना आधार पर परिवर्तित न करे, तो ऐसे में मौद्रिक नीतियाँ विफल हो जाती है। ऐसी स्थिति में RBI गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करती हैं, जिसके अंतर्गत वह बैंको को उनकी नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है। अन्यथा चेतावनी देती है या उन पर हरजाना लागू करती है।

भारत में हाल में RBI ने लगातार दो बार परिवर्तन किया, परन्तु बैंक इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने में विफल रहे। बैंकों की मुख्य समस्या यह रही है कि महंगी ऋण नीति के दौर में जमाकर्ता को आकर्षित करने के उद्देश्य से बैंकों ने सावधी जमा राशियों पर लगातार ब्याज दर बढ़ाया था। जिसके कारण उनका व्यय प्राप्त जमा राशियों पर ब्याज भी जाता है ऐसे में यदि बैंक मौजूदा ग्राहकों के लिए ब्याज दर में कटौती करते हैं, तो उनका घाटा होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी ओर RBI का कहना है कि यदि दरों में की गई कटौती का लाभ बैंक ग्राहकों तक नहीं पहुंचाती है, तो भविष्य में दरों को कम करना संभव नहीं होगा।



संदर्भित दर (Referenced Rate)

संदर्भित दर मुद्रा उधारी बाजारों में मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में एक सीमा चिह्न (Bench Mark) का काम करती है। यह दर सभी प्रकार की उधारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देशक का कार्य करती है। यह दर न्यूनतम दर होती है जिस पर पूँजी बाजार में कोई उधार लिया तथा दिया जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर जिस पर सामान्यतया समझौता होता है वह संदर्भित दर से ऊँची होती है। इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाले परिवर्तन निर्देशित होते हैं। अधिकांश देशों ने अपनी संदर्भित दरें निश्चित की हैं। यू. एस. के लिए संदर्भित दर फेड्स फंड्स रेट (Feds Funds Rate), जर्मनी के लिए फ्रैंकफर्ट इंटर बैंक ऑफर्ड रेट (Frankfurt Interbank Offered Rate-FIBOR), जापान के लिए टोबा-टोकियो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (Tokyo Interbank Offered Rate-TIBOR), तथा यू.के के लिए संदर्भित या निर्देशक दर लन्दन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबर (London Interbank Offered Rate-TIBRO) है। 15 अप्रैल, 1997 में घोषित साखनीति के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले सामान्य पुनर्वित्त तथा विदेशी मुद्रा जमाओं के सम्बन्ध में संदर्भित दर का काम करेगी। इस प्रकार लिबर की तरह, रिजर्व बैंक भी बैंक दर को संदर्भित दर के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

प्राइम लैंडिंग रेट के स्थान पर नई 'बेस रेट' व्यवस्था**(New Base Rate System Instad Of Prime Landing Rate)**

बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधारियों पर ब्याज दरों के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्राइम लैंडिंग रेट (PLR) के स्थान पर नई बेस रेट व्यवस्था अपनाई जा रही है।

पूर्व प्रचलित 'प्राइम लैंडिंग रेट' बैंक की मुख्य ब्याज दर होती थी तथा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की वास्तविक दर पीएलआर से कुछ कम या अधिक भी हो सकती थी। नई लागू की जा रही 'बेस रेट' बैंक द्वारा घोषित वह दर होगी जिससे कम दर पर कोई भी ऋण बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा।

प्रधान उधारी दर (Prime Leading Rate)

किसी बैंक की प्रधान उधारी दर वह ब्याजदर है जिस पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिसके सम्बन्ध में जोखिम शून्य हो, उधार देने के लिए तैयार है। यह वह दर होती है जिस पर बैंक यह उम्मीद करता है उसकी सभी लागतें तथा व्यय पूरा करने के बाद पूँजी पर पर्याप्त प्रतिफल मिल जाएगा। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के सम्बन्ध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary policy committee)

2011 में गठित Financial Sector Legislative Reform Commirttee (FSLRC) ने यह सुझाव दिया था कि मौद्रिक एवं साख नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका हो एवं इस उद्देश्य से मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाये उर्जित पटेल समिति ने इसी सुझाव को दोहराया एवं इस समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी नयी भारतीय वित्त संहिता (Indian Financial Code) के अंतर्गत सरकार ने सात

सदस्य मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रस्ताव रखा जिसमें RBI के गवर्नर भी एक सदस्य होंगे एवं समिति का नेतृत्व भी वही करेंगे। इन सात सदस्यों में से चार का चयन सरकार करेगी एवं कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में RBI के गवर्नर के वीटो का अधिकार खत्म कर दिया जायेगा।

वर्तमान में मौद्रिक नीतियाँ RBI अपने Technical Advisory Committee (TAC) के सुझाव के आधार पर करती हैं परन्तु अंतिम निर्णय RBI के गवर्नर का होता है। अतः प्रस्तावित समिति के गठन के बाद इस पूरी प्रक्रिया में के गवर्नर की भूमिका कम हो जायेगी। साथ ही चूंकि चार सदस्य सरकार द्वारा चयनित होंगे इस समिति के निर्णय पर सरकार का प्रभाव ज्यादा होगा। अतः RBI इस समिति का विरोध कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस विवाद को खत्म करने के उद्देश्य से इस समिति को संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह समिति 6 सदस्यों की होगी एवं इसका नेतृत्व के RBI गवर्नर करेंगे जोकि सातवें सदस्य होंगे। मतदान का अधिकार केवल उन 6 सदस्यों का होगा एवं बहुमत के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जायेगा। यदि मतदान में बराबरी की स्थिति उत्पन्न हो जाये तभी RBI के गवर्नर मतदान करेंगे।

चूंकि मुद्रास्फीति का नियन्त्रण एवं आर्थिक संवृद्धि RBI तथा भारत सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। मौद्रिक नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका जायज है। साथ ही चूंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी भी भूमिका होनी चाहिए। परन्तु दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि विगत कई वर्षों तक RBI अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाते आयी है। ऐसे में इस समिति में सरकार की भूमिका एक हस्तक्षेप की तरह है एवं इससे इस प्रक्रिया का राजनीतिकरण की संभावना बढ़ जाती है।

RBI का राष्ट्रीयकरण	1 जनवरी 1949
प्रथम गवर्नर	Sir Osborne Smith
प्रथम भारतीय गवर्नर	C.D. Deshmukh

भारत में बैंकिंग प्रणाली में RBI का स्थान सर्वोच्च है। RBI की निम्नलिखित भूमिकाएँ हैं-

- यह भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के लिए बैंक का कार्य करती है। अतः भारत सरकार के लिए ऋण उठाने की प्रक्रिया भी RBI की ही जिम्मेदारी है।
- यह भारत में बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है। अर्थात बैंक अपनी अतिरिक्त राशि RBI के पास जमा कर सकते हैं एवं साथ ही आवश्यकता पड़ने पर RBI से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- RBI भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है एवं उसकी अनुमति के बिना अनुसूचित बैंकों की स्थापना नहीं हो सकती।
- RBI भारत में मौद्रिक एवं साख नीतियों के माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है एवं यह मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धि तथा मुद्रा के विनिमय दर का प्रबंधन करती है।
- RBI भारत में विदेशी मुद्राकोश का भण्डारण/सर्वेक्षण करती है।
- यह देश में ₹1 के ऊपर के नोट जारी करती है।



विभिन्न प्रकार के बैंकिंग अवयव (Different Kind of Banking Instruments)

ड्राफ्ट (Draft)

यह एक ऐसा साख प्रपत्र है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को पावक (Payee) के आदेशानुसार ड्राफ्ट में उल्लिखित धनराशि माँग पर भुगतान करने का आदेश होता है। ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है तथा जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसकी पहचान करने के बाद इसका भुगतान कर दिया जाता है। ड्राफ्ट भी चेक की भाँति रेखांकित अथवा अरेखांकित हो सकता है।

चेक (Cheque)

चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चेक में तीन पक्ष होते हैं: (i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता (Drawer), (ii) जिसका आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक (iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चेक का धारक (Payee)

चेक के प्रकार (Types of Check)

1. साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)
2. आदिष्ट चेक (Order Cheque)
3. रेखांकित चेक (Crossed Cheque)
4. पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

1. साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)

जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, धारक चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेक उसके नाम में हो अथवा नहीं। ऐसे चेक के भुगतान के लिए चेक जारी करने वाले (Drawer) के ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेक के धारक की ही दे दिया जाए।

2. आदिष्ट चेक (Order Cheque)

जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर Order लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान करता है। इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाता है।

3. रेखांकित चेक (Crossed Cheque)

जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समान्तर रेखाएँ बना दी जाती हैं, तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान किसी खाते में उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

4. पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

जब किसी चेक के प्रायः बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है, जिसके नाम वह चेक लिखा होता है। अर्थात् इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जब चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक विशिष्ट रेखांकित चेक बन जाता है तथा ऐसी स्थिति में उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

चेक और ड्राफ्ट में अन्तर (Difference Between Draft and Check)

चेक किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है, जबकि ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है। चेक का भुगतान प्राप्त करने में संदेह हो सकता है, परन्तु ड्राफ्ट के सम्बन्ध में ऐसी कोई आशंका नहीं रहती है। चेक का भुगतान करते समय देखा जाता है कि खाते में अपेक्षित धनराशि है या नहीं, परन्तु ड्राफ्ट तो बनाया ही तब जाता है, जब भुगतान करने वाला आवश्यक धनराशि बैंक को दे देता है।

बैंकर्स चेक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट में अन्तर (Difference in Bankers Checks and Demand Drafts)

बैंकर्स चेक किसी बैंक द्वारा किसी ग्राहक की माँग पर या किसी ग्राहक का खाता उसी शाखा में न होने पर जारी किया जाता है। इस प्रकार के चेकों का भुगतान सामान्यतौर पर एक ही शहर के भीतर हो जाता है। दूसरे शहर की शाखा में जमा करने पर यह कलेक्शन हेतु भेजा जाता है। यदि डिमाण्ड ड्राफ्ट रेखांकित या एकाउण्ट पेयी है, तो वह उसी दिन खाते में जमा कर दिया जाता है।

समाशोधन गृह (Clearing House)

समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है, जहाँ 3-4 अथवा उससे अधिक बैंक होते हैं। क्लीयरिंग हाउस वह स्थान है जहाँ विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि प्रतिदिन एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के मध्य चेकों का आदान-प्रदान तथा जमा-खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का लेन-देन बहुत ही सरलता से तथा थोड़े समय में ही सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाशोधन (Clearing) कहते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा है, वहाँ रिजर्व बैंक में ही समाशोधन गृह होता है। जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में समाशोधन गृह होता है।

चेक कलेक्शन (Cheque Collection)

जब चेक शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है, तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक से डाक-व्यय एवं कमीशन लेती है।



बॉण्ड (Bond) अथवा डिबेन्चर (Debenture)

बॉण्ड एवं डिबेन्चर का अर्थ ऋणपत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेन्चर जारी करती हैं। इन बॉण्डों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है। जो संस्था इन्हें जारी करती है, वे इन पर धारक को एक निश्चित दर से ब्याज भी देती हैं।

धारक बॉण्ड (Bearer Bond)

धारक बॉण्ड वे ऋणपत्र हैं, जिनका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खरीदार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तान्तरित करते समय इनकी पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया जाता है।

चेक के भुगतान न होने के कारण

(Reason For Non-Payment Of Checks)

(i) आगे तारीख होने से (ii) तीन माह पुराना होने से, (iii) यथेष्ट फण्ड नहीं होने की वजह से, (iv) टाइप होने के कारण, (v) नमूने के दस्तखत से दस्तखत न मिलने पर, (vi) चेक का बेचन या पृष्ठांकन अपूर्ण, अनियमित तथा अस्पष्ट होने की वजह से, (vii) चेक पर कोई संशोधन हो और दस्तखत न किया गया हो, (viii) रेखांकित चेक बैंक द्वारा न आया हो, और (ix) चेक फटा हो।

कब चेक का भुगतान तिरस्कृत होना आवश्यक है? (When Should Payment Of Check Be Required To Be Rejected?)

(i) ग्राहक के मना करने पर, (ii) अदालत की निषेध- आज्ञा प्राप्त होने पर, (iii) ग्राहक के दिवालिया होने पर, (vi) ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर, (v) ग्राहक के पागल हो जाने पर, (vi) धारक का स्वत्व दूषित होने पर और (vii) ग्राहक द्वारा खाता बन्द कर देने पर।

चेक भुगतान करते समय ध्यान देने योग्य बातें (Things To Pay When Making Check Payments)

(i) चेक रेखित है अथवा अरेखित, (ii) क्या चेक आहर्ता उस बैंक की वही शाखा है, जहाँ चेक भुगतान के लिए उपस्थित किया जा रहा है, (iii) चेक ठीक ढंग से लिखा गया है या नहीं, (vi) चेक पर कोई संशोधन तो नहीं किया गया है, (v) आहर्ता के हस्ताक्षर, (vi) पृष्ठांकन ठीक ढंग से किया गया है या नहीं, (vii) क्या आहर्ता के जमा खाते में चेक के भुगतान के लिए पर्याप्त रकम है और (viii) ग्राहक ने बैंक को भुगतान करने से मना नहीं कर दिया है।

रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेन्ट प्रणाली

(Real Time Grass Settlement System)

रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेन्ट प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत प्रत्येक लेन-देन प्रारम्भ होते ही निपटान प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो जाती है। निधियाँ भेजने वाले से प्रादक के खाते में तत्काल अन्तरित हो जाती हैं। इस प्रणाली में दूसरे पक्षकार द्वारा होने वाली चूक की जोखिम प्रायः नहीं होती। भारत में यह प्रणाली सर्वप्रथम 26 मार्च, 2004 को मुम्बई में प्रारम्भ की गयी।

मूल्य वर्द्धित सेवाएँ (Value Added Services)

वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को सामान्य बैंकिंग क्रियाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित मूल्य वर्द्धित सेवाएँ (Value Added Services) उपलब्ध कराते हैं-

1. लॉकर्स सुविधा
2. यात्री चेक जारी करना तथा भुगतान करना
3. ग्राहकों के अनुरोध पर उनके बीमा प्रीमियम, पानी-बिजली के बिलों का नियमित रूप से भुगतान करते रहना
4. ग्राहकों के पक्ष में गारन्टी पत्र
5. ई-बैंकिंग सुविधा
6. एनीहेयर बैंकिंग सुविधा
7. एटीएम सुविधा
8. क्रेडिट कार्ड सुविधा
9. एटीएम डेबिट कार्ड सुविधा

कुछ अन्य प्रकार के चेक (Some Other Types Of Checks)

1. यात्री चेक (Traveller's Cheque)

यात्री चेक किसी बैंक द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है जिसे जारी करते समय चेक के मुखपृष्ठ पर आवेदक (चेक प्राप्त करने वाला) के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस चेक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेक का भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय पुनः चेक के मुखपृष्ठ पर धारक के हस्ताक्षर कराती है। दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेक का भुगतान होता है। बैंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान भी यात्री चेक नकद मुद्रा की भाँति स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके दुप्लीकेट चेक प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. पूर्व दिनांकित चेक (Ante-dated Cheque)

यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Ante-dated) चेक कहा जाता है

3. गतावधि अथवा पुराना चेक (Stale Cheque)

यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अवधि (वर्तमान में तीन महीने) के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए, तो उसे गतावधि अर्थात् पुराना चेक कहा जाता है। बैंक ऐसे चेक का आहरणकर्ता द्वारा पुष्टि के बिना भुगतान नहीं करता।

4. उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated cheque)

यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय उस पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post Dated) चेक कहा जाता है। ऐसा चेक विधि-अमान्य तो नहीं होता, अपितु उस तारीख से प्रभावी होता है, जो उसमें लिखी गई है।



5. चेक (MICR)

MICR-Magnetic Ink Character Recognition चेक में बैण्ड कोड लाइन पर चेक संख्या के अतिरिक्त 9 अंकों की एक संख्या भी मुद्रित रहती है। जिसके प्रथम तीन अंक केन्द्र/शहर को इंगित करते हैं। MICR चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस को सम्भव बनाते हैं। यह पद्धति भारत में 1987 में लागू की गयी। 9 अंकीय संख्या में मध्य के तीन अंक बैंक तथा अन्तिम तीन अंक बैंक की शाखा के कोड को बताते हैं।

बैंक में खातों के प्रकार (Types Of Accounts In The Bank)

बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)

बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं। इस खाते में जमा राशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है। प्रत्येक कलेण्डर महीने के दसवें दिन के अन्त से लेकर उस महीने की अन्तिम तारीख तक की अवधि में जो भी न्यूनतम जमा बाकी रहती है, उसके आधार पर ब्याज दिया जाता है।

चालू खाता (Current Account)

यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस का अनेक बार कितनी भी राशि का लेन-देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन-देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service charge) खाताधारी से वसूल करते हैं।

नकद साख खाता (Cash Credit Account)

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रुपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है।

ई-बैंकिंग (E-Banking)

आजकल सभी बैंक अकाउण्ट खोलने के बाद इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं। यह सुविधा दो तरह की होती है- पहली यूजर आई डी द्वारा भुगतान और दूसरी अपने ही ए.टी.एम. कार्ड द्वारा भुगतान। नया अकाउण्ट खोलने पर या पुराने अकाउण्ट पर मांगे जाने पर बैंक द्वारा यूजर आई डी और 2 पासवर्ड (लॉग-इन पासवर्ड, ट्रांज़ेक्शन पासवर्ड) प्रदान किया जाता है। जुलाई 2009 के बाद से जारी होने वाले सभी ए.टी.एम. कार्ड पर स्पेशन CVV/CVV2 कोड होता है जो ऑनलाइन भुगतान में प्रयोग होता है। चूँकि यह सारा काम ऑनलाइन होता है तो भूल-चूक की सम्भावना न के बराबर होती है। फिर भी कुछ इन्टरनेट हैकर्स आपका नुकसान कर सकते हैं। आपकी एक छोटी-सी गलती आपका पूरा अकाउण्ट खाली कर सकती है।

ई-बैंकिंग-सावधानी व सुरक्षा के 10 उपाय (Ten Tips For E-Banking Caution and Safety)

1. बैंक द्वारा प्रदान किए गए पासवर्ड फर्स्ट यूज के बाद ऑनलाइन अकाउण्ट एक्टिव हो जाता है अतः नया पासवर्ड डाल लें। अपना पासवर्ड किसी को भी न बताएँ। यहाँ तक कि अपना पासवर्ड बैंक के कर्मचारी, मैनेजर या कस्टमर केयर आदि किसी को भी न बताएँ।
2. कोशिश यही करनी चाहिए कि -ई-बैंकिंग अपने पर्सनल कम्प्यूटर पर ही करें। साइबर कैफे या किसी भी परिचित के कम्प्यूटर का उपयोग न करें।
3. अपने कम्प्यूटर पर भी खास सावधानी की जरूरत है। फालतू के सॉफ्टवेयर लोड न करें क्योंकि इनके साथ वायरस के आने की सम्भावना रहती है।
4. यदि मजबूरी में साइबर कैफे या अन्य किसी का कम्प्यूटर उपयोग कर रहे हैं तो मोजिला फायरफॉक्स या इन्टरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन प्रयोग में लायें। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में प्राइवेट ब्राउसिंग का ऑप्शन होता है जो आपकी लॉग-इन डाटा को सेव रखता है।
5. ई-बैंकिंग का भुगतान जिस वेबसाइट को कर रहे हैं। वह सुरक्षित होनी चाहिए। अधिकार वेबसाइट किसी 128 bit SSL Gateway (or 256 bit) का प्रयोग करती हैं। इन Gateways को प्रमाणित करने हेतु सर्टिफिकेट पर विशेष ध्यान दें।
6. बैंक कभी भी अपने यूजर्स को लॉग-इन पासवर्ड या प्राइवेट जानकारी से सम्बन्धित ई-मेल नहीं भेजता है। यदि आपको कोई ऐसा मेल मिले जो आपकी ई-बैंकिंग जानकारी को पूछे तो आप तुरन्त उसे डिलीट कर दें। बैंक द्वारा समय-समय पर आपको ई-मेल के माध्यम से यही अवगत कराया जाता है कि कोई कितना भी पूछे आई डी या पासवर्ड किसी को न बताएँ।
7. जिस बैंक अकाउण्ट का प्रयोग ई-बैंकिंग के लिए किया जाए उसमें न्यूनतम भुगतान राशि ही रखनी चाहिए, ताकि कोई भी गड़बड़ होने पर नुकसान की सम्भावना कम-से-कम हो।
8. बच्चों को अपना ए.टी.एम. कार्ड न प्रयोग करने दें। उनके लिए अलग से अकाउण्ट खुलवाकर देना चाहिए।
9. ए.टी.एम. कार्ड पर 16 अंकों का एक कोड व अवधि आदि का उल्लेख होता है ए.टी.एम. कार्ड द्वारा भुगतान करने पर यही कोड व अवधि आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः अपने कार्ड को छिपाकर ही रखना बेहतर होता है।
10. ए.टी.एम. कार्ड का प्रयोग ए.टी.एम. सेन्टर पर बहुत सावधानीपूर्वक मुक्त रूप से करने हेतु केबिन होता है। अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। ए.टी.एम. सेन्टर से जो पर्ची निकलती है उसको फाड़ कर ही कूड़ेदान में डालना चाहिए क्योंकि उस पर कोड अंकित होता है।



बैंक के विभिन्न जमा-खातों में अन्तर (Difference in Various Bank Deposits)

बैंक के विभिन्न जमा खातों के प्रमुख अन्तर अग्रलिखित तालिका द्वारा अधिक स्पष्ट किये जा सकते हैं

क्र.सं.	अन्तर का आधार	चालू खाता (Current A/c)	बचत खाता (Saving A/c)	स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit A/c)
1.	जमा की अवधि	इसमें जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती।	इसमें भी जमा की कोई निश्चित अवधि नहीं होती।	इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा की जाती है।
2.	जमा पर प्रतिबन्ध	इस खाते में रकम जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।	इस खाते में भी रकम जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा निश्चित है।	इस खाते में रकम केवल एक ही बार में जमा की जा सकती है।
3.	रकम निकालना	इस खाते में से रकम निकालने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एक सप्ताह में ही दिन में कई बार रकम निकाली जा सकती है।	बैंक के नियमानुसार सप्ताह में केवल एक या दो बार रकम निकाली जा सकती है।	जमा की अवधि समाप्त होने पर ही रकम निकाली जा सकती है। अवधि के पहले रकम निकालने पर ब्याज नहीं मिलता है।
4.	ब्याज	इस खाते में जमा की गयी रकम पर बैंक ब्याज अधिक नहीं देता है	इस खाते में ब्याज की दर चालू खाते की दर से अधिक है, किन्तु सावधि जमा से नहीं।	इस खाते में ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है।
5.	चेक का प्रयोग	इस खाते में चेक का प्रयोग बहुत अधिक होता है।	चेक का प्रयोग साधारणतया कम होता है।	अब कुछ बैंकों ने इस खाते में भी चेक की सुविधा देना शुरू कर दिया है। फिर भी इस खाते में चेक का प्रयोग अभी सीमित ही है।
6.	उद्देश्य	इस खाते के उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की रकम जमा करने तथा निकालने की सुविधा प्रदान करना है।	इस खाते में लोगों में बचत करने की आदत बढ़ती है।	इसका उद्देश्य ब्याज कमाना है।

बेसल मानदंड (Basel Criterion)

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी (Basel Committee on Bank Supervision-BCBS) समझौतों का एक सेट जो पूंजीगत जोखिम, बाजार जोखिम तथा संचालकीय जोखिम के सन्दर्भ में बैंकिंग विनियामकों पर सिफारिशें देती हैं। मानदण्डों के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थान अपनी देयताओं व अप्रत्याशित घाटों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी अपने पास सुरक्षित रखें।

बेसल मानदण्ड की आवश्यकता (Basel Criteria required)

वर्ष 1980 के दशक में यह महसूस किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जोखिमों (कर्ज में डूबे देशों की संख्या में बढ़ोत्तरी के सन्दर्भ में) के समय मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों का पूंजी अनुपात चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया। 10 केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने अपनी बैंकिंग प्रणाली में पूंजी मानक के क्षरण को रोकने के लिए विचार-विमर्श किए। विचार-विमर्श का मुख्य विषय था बैंकों की बैलेंस सीट पर जोखिम। कमेटियों के सदस्यों में इस बात को लेकर सहमति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अभिसंविदा तैयार की जाये। इसी के मद्देनजर दिसम्बर 1987 में 'पूँजी मापन प्रणाली' पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे 'बेसल पूँजी अभिसंविदा (Basel Capital Accord)' भी कहा गया। इसे बेसल मानक भी कहा गया। अभी तक तीन बेसल मानक प्रकाशित किये गये हैं। अन्तिम मानक प्रथम दो का संशोधित, उन्नत व प्रासंगिक मानक है।

बेसल(Basel)-I

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा साख जोखिम को कम करने हेतु अपने पास रखे जाने वाली न्यूनतम पूंजी अनिवार्यता बेसल- I - मानदण्ड हैं। ये मानदण्ड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले वित्तीय संस्थानों को अपनी जोखिम भारांश संपदा (Risk Weighted Assets) के बराबर या न्यूनतम 8 प्रतिशत टीयर-1 व टीयर-2 पूंजी अपने पास रखना अनिवार्य किया गया। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बैंक की जोखिम भारांश संपदा 100 मिलियन डॉलर है तो उसे न्यूनतम 8 मिलियन डॉलर की पूंजी अपने पास रखनी होगी। इसका उद्देश्य मुख्यतः वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखना था।

बेसल- I के तहत बैंकों की संपदा को पाँच जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया गया था ये थे-

1. 0% जोखिम : नकदी, राष्ट्रों की केन्द्रीय बैंक व सरकारी ऋण तथा किसी ओईसीडी देशों का कर्ज
2. 0%, 10%, 20% या 50% : सार्वजनिक क्षेत्रक ऋण

3. 20% : विकास बैंक ऋण, ओईसीडी बैंक ऋण, ओईसीडी प्रतिभूति कम्पनी ऋण, गैर-ओईसीडी बैंक ऋण (एक वर्ष तक वाला) व गैर-ओईसीडी सार्वजनिक क्षेत्र ऋण
4. 50% : आवासीय ऋण (आवास गिरवी)
5. 100% : रियल इस्टेट, निजी क्षेत्र ऋण, गैर-ओईसीडी बैंक ऋण (एक वर्ष से ऊपर का)

बेसल(Basel)- II

बेसल- II बेसल मानदण्ड का दूसरा चरण है। यह 26 जून, 2004 को जारी किया गया और वर्ष 2006 से लागू करने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1990 के दशक की कुछ आर्थिक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि बैंकों के समक्ष जोखिम केवल साख या कर्ज से ही नहीं जुड़ा हुआ है वरन् संचालकीय जोखिम के अलावा मूल्यों, ब्याज दरों या विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुए घाटों से भी जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेसल दो मानदण्ड जारी किये गये। जहाँ बेसल एक साख जोखिम पर केन्द्रित था वहीं बेसल दो का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग रखे जानी वाली पूंजी के लिए मानक तैयार करना व उसका विनियमन करना था।

बैंकों को निवेश व कर्ज देने की अपनी गतिविधियों के साथ जुड़े जोखिमों के मद्देनजर पूंजी अलग रखना जरूरी होता है। बेसल-2 मानदण्ड मुख्यतः तीन कारकों पर प्रभाव डालता है। ये हैं- पूंजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षीय मूल्यांकन व बाजार अनुशासन। बेसल कमेटी इन तीनों कारकों को जोखिम प्रबन्धन के तीन स्तम्भ मानती है। बेसल-2 मानदण्ड की पूंजी पर्याप्तता स्तम्भ के तहत बैंकों के लिए 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) या जोखिम भारांश संपदा अनुपात (Capital to Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) बनाए रखना अनिवार्य है।

सामान्यतः बैंक तीन प्रकार की जोखिमों का सामना करते हैं; ऋण सम्बन्धी जोखिम, संचालकीय जोखिम व बाजार जोखिम। पर्यवेक्षीय मूल्यांकन (Supervisory Review) के तहत के बेसल-2 मानदण्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक न केवल अपने जोखिमों की भरपाई के लिए अपने पास पर्याप्त पूंजी रखे वरन् अपने जोखिमों की निगरानी व प्रबन्धन के क्रम में बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीक का उपयोग व विकास भी करे।

बाजार अनुशासन (Market Discipline) बैंकों पर अपनी बैंकिंग व्यवसाय को सुरक्षित, सुदृढ़ व प्रभावी तरीके से संचालन करने का निर्देश देता है। बैंकों के लिए अपनी पूंजी, जोखिम विवरण या एक्सपोजर देना अनिवार्य है ताकि बाजार के भागीदार उस बैंक की पूंजी पर्याप्तता का अनुमात लगा सके।

बेसल(Basel)- III



वर्ष 2008 की अमेरिकी सब प्राइम संकट व वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में बेसल 3 मानक तैयार किये गये। बेसल 2 में किसी खास बैंक के जोखिमों व विनियमनों को केन्द्र में रखा गया था पर आर्थिक संकट को देखते हुए पूरी आर्थिक व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर बेसल-3 मानक के केन्द्र में रखा गया है। इसके तहत बैंकों को जोखिम संपदा भारांश का 4.5 प्रतिशत कॉमन इक्विटी (बेसल-2 मानक में यह 2 प्रतिशत था) व 6 प्रतिशत टायर-1 पूँजी (बेसल-2 में यह 4 प्रतिशत था) अपने पास रखने होंगे। बैंकों को अपने पास 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त पूँजी बफर भी रखना होगा। जो बैंक इस बफर को नहीं रख पाएँगे उन्हें शेयर पुनर्खरीद, लाभांश व बोनस भुगतान पर प्रतिबंध सामना करना पड़ेगा।

हाल के संकट ने यह प्रदर्शित किया कि बैंकों को आर्थिक विकास के दौरान कैपिटल बफर्स बनाने चाहिये। यह बफर बैंकों को आर्थिक मंदी के दौरान अपने घाटों की भरपाई में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को 3 प्रतिशत का न्यूनतम लीवरेज अनुपात भी रखना होगा। साथ ही बैंकों को लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का भी पालन करना होगा, जिसके लिए उन्हें 30 दिन की कठिन अवधि का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियाँ बनाये रखने की जरूरत होगी। एक स्थिर कोष अनुपात जनवरी 2018 से अस्तित्व में आएगा जिसका मकसद बैंकों की बैलेंस शीट में नगदी से जुड़ी दीर्घकालीन एवं संरचनात्मक विसंगतियाँ दूर करने की जरूरत होगी।

बेसल-3 मानदण्ड एक जनवरी, 2013 से लागू हो जाएँगे और इन्हें 1 जनवरी, 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सफलता हेतु क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है

(Implementation is Important for Success)

वैसे बेसल-3 मानक के क्रियान्वयन के लिए बैंकों को दी जा रही लम्बी अवधि राष्ट्रीय विनियामकों के लिए सरदर्द के रूप में देखा जा रहा है। आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि क्या बेसल-3 मानक बैंकों की जोखिम को कम करने में अपने पहले मानक से अधिक सफल हो पाएगा?

बेसल-3 के निर्देश बेसल-2 की तुलना में अधिक कठिन हैं। बेसल-2 बैंकों को वर्ष 2008 की आर्थिक संकट से नहीं बचा पाया जो कि वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के बाद की सबसे बड़ी मंदी थी।

वैसे बेसल-3 बैंकों को अपने पास तीन गुना अधिक उच्च गुणवत्ता वाली पूँजी रखना अनिवार्य करता है, पर इसका समय व विषय वस्तु में अभी भी गहन कमियाँ हैं जो सुधारों की प्रभावशीलता को दबा सकती है।

बेसल-3 मानक के सभी मानदण्ड वर्ष 2019 तक पूरे किये जाने हैं जो पर्यवेक्षकों एवं उसके राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष बैंकिंग सेक्टर में पर्यवेक्षण का वही संवेग बनाये रखने पर चुनौती प्रस्तुत करेगा। संदेह यह भी है कि वैश्विक संकट की यादें धुंधली हो जाने पर बैंकिंग सेक्टर अत्यधिक रिटर्न प्राप्ति के लिए लामबंद हो सकते हैं जिससे बेसल-3 मानक का क्रियान्वयन खटाई में पड़ सकता है।

भारत में बेसल मानदण्डों का क्रियान्वयन

(Implementation of Basel Norms in India)

भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल कमेटी के द्वारा 1988 में आरम्भ किया गया पूँजी पर्याप्तता मापन से सम्बन्धित जोखिम संपदा अनुपात भारतीय बैंकों के लिए 1992 में शुरू किया। विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में भी बेसल-1 मानदण्डों को वर्ष 1999 में अपनाया गया। बेसल-1 मानदण्डों के अपनाने का प्रत्यक्ष असर भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर देखा गया। इन बैंकों की गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियाँ यानी एनपीए कुल साख का वर्ष 1997-98 के 8.1 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2003-04 में 2.9 प्रतिशत आ गया। यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में एनपीए में निरपेक्ष में गिरावट दर्ज की गई। बेसल-1 की सफलता से आशान्वित होकर ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल-2 मानक अपनाने पर बल दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंक बेसल-3 के अनुसार नए पूँजी नियमों को आसानी से लागू कर लेंगे। आरबीआई के मुताबिक भारतीय बैंकों में कुल पूँजी और जोखिम पूर्ण परिसम्पत्तियों का अनुपात 30 जून, 2010 को 11.7 प्रतिशत था जबकि बेसल-3 नियमों के अनुरूप इसे 10.5 प्रतिशत ही होना चाहिये। भारतीय बैंकों के पास टायर-1 पूँजी 9 प्रतिशत है जबकि बेसल-3 नियमों के मुताबिक 8.5 प्रतिशत आवश्यक है। हालांकि कुछ भारतीय बैंक बेसल-3 नियम के पालन के क्रम में पूँजी की कमी की स्थिति का सामना कर सकते हैं।

बेसल-3 दिशा-निर्देश में पूँजी पर्याप्तता प्रतिशत (Capital Adequacy Percentage) की गणना करते वक्त की जाने वाली कटौतियों (deductions) में बदलाव भी किये गये हैं। इस बदलाव से भी भारतीय बैंक प्रभावित हो सकते हैं। एक प्रस्तावित दिशा-निर्देश के मुताबिक कटौती योग्य कटौती तभी की जा सकती है जब वे समन्वित स्तर से मूल पूँजी से 15 प्रतिशत अधिक होते हैं या एकल स्तर पर 10 प्रतिशत से बढ़ जाते हैं। वैसे इससे भारतीय बैंकों के प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी अनुमान्य कटौतियाँ की जाती हैं।

बेसल-3 में मूल पूँजी (Core Capital) से 100 प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों; टायर-1 पूँजी से 50 प्रतिशत व टायर-2 पूँजी से 50 प्रतिशत कटौती से अधिक कड़ा प्रस्ताव है।

बेसल-3 मानकों के अनुपालन का मतलब है भारतीय बैंकों द्वारा विनियामकीय पूँजी अनिवार्यता में बढ़ोत्तरी। मानक के अनुसार न्यूनतम मूल पूँजी को बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत करना है। इसके अलावा 2.5 प्रतिशत की बफर पूँजी भी जरूरी है। इसका मतलब है कि बैंकों को 7 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत की पूँजी का भंडार हालांकि पहले से ही भारतीय बैंक 6 प्रतिशत की पूँजी पर्याप्तता अनुपात रखे हुये हैं। पर एक ओर जहाँ निजी व भारत में संचालित विदेश बैंकों का मूल पूँजी अनुपात 9 प्रतिशत के आपसपास है वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मूल पूँजी अनुपात इससे काफी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के ये बैंक जोकि बैंकिंग सेक्टर की संपदा में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं और जो उत्पादक क्षेत्रों के वित्तीयन के प्रमुख स्रोत हैं, वे बेसल-3 मानक के पालन के पश्चात् कुछ संयम का सामना करेंगे। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के इन बैंकों में सरकार की



हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे में बैंक बाजार से स्वतन्त्र रूप से पूँजी भी नहीं उठा सकते। कुछ बैंकों में तो सरकार की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकार के सामने एक विकल्प इन बैंकों का पुनर्पूँजीकरण है।

बेसल-3: आरबीआई द्वारा जारी किये दिशा-निर्देश (Basel-3: Guidelines Issued by RBI)

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 दिसम्बर, 2011 को भारत में बेसल-3 नॉर्म्स लागू करने हेतु प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किये। प्रारूप दिशा-निर्देशों पर 15 फरवरी, 2012 तक राय माँगी गई। प्रारूप के अनुसार यदि सब कुछ ठीक रहा तो, भारत में बैंकिंग नियमन से सम्बन्धित बेसल-3 मानक 1 जनवरी, 2013 से लागू होंगे जबकि इसका पूर्णतया क्रियान्वयन 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा। प्रारूप दिशा-निर्देश की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
- कॉमन इक्विटी टायर-1 पूँजी, जोखिम भारांश आस्तियों (Risk Weighted Assets-RWAs) का न्यूनतम 5.5% होना चाहिए।
- टायर-1 पूँजी जोखिम भारांश आस्तियों का कम से कम 7% होना चाहिए।
- कुल पूँजी जोखिम भारांश आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए।
- कॉमल इक्विटी के रूप में पूँजी संरक्षण बफर जोखिम भारांश आस्तियों का 2.5% होना चाहिए। इसे 31 मार्च, 2014 और 31 मार्च, 2017 के बीच लागू किया जाएगा।
- ऐसे साधन जो कि विनियामकीय पूँजी साधन के योग्य के बीच नहीं होंगे उन्हें 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2022 के बीच चरणबद्ध ढंग से हटा दिया जाएगा।

क्या है टायर-1 कैपिटल (What is Tier-1 Capital)

पूँजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? (What is Capital Adequacy Ratio)

इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के संरक्षण व विश्व भर की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता व दक्षता के संवर्द्धन के लिए किया जाता है।

टायर-1 कैपिटल (Tier-1 Capital)

इस शब्द का इस्तेमाल बैंकों की पूँजी पर्याप्तता को वर्णित के लिए किया जाता है। टायर-1 बैंकों की केन्द्रीय या मुख्य पूँजी होती है जिसमें शामिल है- इक्विटी कैपिटल व ज्ञात भण्डार (Disclosed reserves) इक्विटी कैपिटल वह निवेशित धन है जिसे सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में निवेशक को पुनर्भुगतान नहीं की जाती है। टायर-1 सर्वाधिक विश्वसनीय पूँजी मानी जाती है।

टायर-2 कैपिटल (Tier-2 Capital)

यह भी बैंकों की पूँजी पर्याप्तता का ही द्योतक है। यह बैंकों की

द्वितीयक पूँजी होती है जिसमें अप्रकटित भण्डार (Undisclosed reserves), पुनर्मूल्यित भण्डार सामान्य प्रावधान, हाइब्रिड इन्स्ट्रूमेंट, अधिनस्थ कर्ज इत्यादि आते हैं। अधिनस्थ कर्ज (Subordinate term debt) असुरक्षित कर्ज या वैसा कर्ज है जो अन्य कर्जों दावों की तुलना में कम प्राथमिकता वाला होता है। अप्रकटित भण्डार के तहत कोई बैंक लाभ अर्जित करता है पर वह उसको सामान्य लाभ के रूप में नहीं दर्शाता है। वैसे इन्स्ट्रूमेंट को हाइब्रिड इन्स्ट्रूमेंट कहा जाता है जिनमें कर्ज व शेयरहोल्डर्स इक्विटी, दोनों की विशेषताएँ निहित होती हैं।



अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन (International Financial Organizations)

विश्व बैंक (World Bank)

द्वितीय विश्व युद्ध से न केवल बहुमुखी व्यापार प्रभावित हुआ अपितु अनेक देशों की जीवन और सम्पत्ति को भी हानि पहुँची। विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि जर्जर अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की योजना स्वीकार की गई। इस बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी स्थापना भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही पूरक संस्था के रूप में हुई। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 ई. को हुई तथा इसने 25 जून, 1946 ई. से कार्य प्रारम्भ किया।

विश्व बैंक के उद्देश्य (Objectives of World Bank)

- सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास (Reconstruction And Development Of Member Nations)** विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध जर्जरित राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और अल्पविकसित देशों के आयोजित विकास में आर्थिक सहायता प्रदान करना था।
- पूँजी विनियोग को प्रोत्साहन (Incentive To Capital Appropriation)**- विश्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य निजी विनियोगकर्ताओं को उनकी पूँजी की गारन्टी देकर अथवा ऋणों में भाग लेकर उन्हें पिछड़े हुए देशों में उत्पादक विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- दीर्घकालीन सन्तुलित व्यापार को प्रोत्साहन देना (Promoting Long-Term Balanced Trade)**- इसका तीसरा उद्देश्य विदेशी व्यापार के दीर्घकालीन सन्तुलित विकास में सहायता प्रदान करना है और इस प्रकार उत्पादकता, रहन-सहन के स्तर और श्रमिक वर्ग की दशाओं के सुधार को प्रोत्साहित करना है।
- शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना (Establishment Of Peaceful Economy)** सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

विश्व बैंक की सदस्यता (World Bank Membership)

1944 ई. में जो देश मुद्रा कोष के प्रारम्भिक सदस्य बने, वे सब विश्व बैंक के भी सदस्य मान लिए गए थे। बाद में सदस्यों का प्रवेश तत्कालीन सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत से किया जाता रहा है।

मताधिकार (Franchise)

विश्व बैंक के सदस्य देशों की मताधिकार शक्ति उनके अंशदान पर निर्भर करती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के 250 मत होते हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख डालर के अंशदान पर एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। 1 मार्च, 1994 ई. में अमेरिका और भारत के मतों का कुल मतों का कुल मतों में प्रतिशत क्रमशः 17.03 और 3.10 था।

विश्व बैंक का संगठन (World Bank Organization)

विश्व बैंक के संगठन के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया जाता है-

- गवर्नर मण्डल (Governor's Board)**- इस मण्डल में प्रत्येक राष्ट्र एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बैंक के अंशधारियों के प्रतिनिधि होते हैं। और बैंक की समस्त शक्ति गवर्नर मण्डल में निहित होती है। इसकी प्रतिवर्ष एक साधारण सभा होती है।
- कार्यकारी संचालक मण्डल (Executive Board Of Directors)**- कार्यकारी संचालकों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। ये संचालक बैंक की सामान्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक नियुक्त संचालक अपने को नियुक्त करने वाले सदस्य राष्ट्र का मत डालता है।
- सलाहकार परिषद् (Advisory Council)**- 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद् गठित की गई है जिसमें बैंकिंग, व्यापार, उद्योग, श्रम तथा कृषि के विशेषज्ञ होते हैं।
- ऋण समितियाँ (Credit Societies)**- सदस्य देशों द्वारा माँगे गए ऋणों की उपयुक्त जाँच करने के लिए बैंक ऋण समितियाँ नियुक्त करता है जो यथा समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

विश्व बैंक के कार्य (Functions of World Bank)

विश्व बैंक मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है-

- ऋण प्रदान करना (Provide Credit)**- विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण देता है। इसकी अवधि 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की होती है। ऋणों को सदस्य देश के केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाता है। ऋणों की व्यवस्था सदस्य देश की सरकार या उस देश में रहने वाले निजी उद्यमकर्ताओं, दोनों के लिए की जा सकती है। निजी उद्योगों को दिए गए ऋणों के लिए सम्बन्धित देश की केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार की गारन्टी आवश्यक होती है। विश्व बैंक अन्तिम ऋणदाता के रूप में होता है। विश्व बैंक केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देता है। विश्व बैंक द्वारा प्रमुख रूप से बिजली, परिवहन, उद्योग, कृषि, शिक्षा, जलापूर्ति आदि कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं।
- ऋण तीन प्रकार के होते हैं-

- (i) **प्रत्यक्ष ऋण (Direct loan)**- प्रत्यक्ष ऋण अपने निजी साधनों से अथवा खुले बाजार में ऋणपत्र निर्गमित करके दिए जाते हैं।
- (ii) **गारन्टीयुक्त ऋण (Guaranteed loan)**- निजी विनियोगकर्ताओं को गारन्टी देकर ऋण दिलाए जाते हैं जो बहुधा विकास परियोजनाओं के लिए होते हैं।
- (iii) **संयुक्त ऋण (Joint loan)**- व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर भी बैंक ऋण देता है। इस समय अधिकांश ऋण संयुक्त प्रकार के ही होते हैं।
2. **तकनीकी सहायता (Technical Support)**- विश्व बैंक सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देकर उनके पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक ने सदस्य देशों के विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण कराए हैं ताकि इन देशों के प्राकृतिक स्रोतों, आर्थिक विकास की सम्भावनाओं आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
3. **प्रशिक्षण व्यवस्था (Training System)**- सदस्य देशों की विकास योजनाओं के सफल संचालन के लिए बैंक प्रशिक्षण सुविधाएँ भी देता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अविकसित देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों को आमन्त्रित करके उन्हें सार्वजनिक वित्त, साख व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, भुगतान सन्तुलन आदि के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना है जिससे वह अपने देश में उपरोक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं का सही समाधान कर सकें।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा (Settlement Of International Disputes)**- एक अन्तर्राष्ट्रीय निष्पक्ष संगठन होने के कारण विश्व बैंक एक ऐसी संस्था बन गई है, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का कार्य सौंपा जा सकता है। इस प्रकार बैंक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भाव बढ़ाने का एक बड़ा साधन है। 1956 ई. में ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण के विवाद का मध्यस्थता द्वारा निपटारा कराया गया। इसी प्रकार 1960 ई. में भारत- पाकिस्तान के सिन्धु नदी के जल बँटवारे के विवाद को समाप्त कराया गया।

विश्व बैंक और भारत (World Bank and India)

भारत के प्रारम्भिक विकास में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एशियाई राष्ट्रों में सर्वप्रथम 1949 में पहला ऋण विश्व बैंक द्वारा भारत को ही दिया गया। वर्तमान में विश्व बैंक में भारत का अभ्यांश 5404 मिलियन डॉलर है।

भारत के विश्व बैंक से जुड़े कुछ तथ्य-

1. **संस्थापक सदस्य (Founder Member)**- भारत IMF एवं विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना से ही भारत इसका सदस्य है।
2. **कार्यकारी निदेशक (Executive Director)**- 1970 ई. तक भारत सबसे बड़े पाँच अंशधारियों में से एक था और इसी कारण उसे बैंक के कार्यकारी निदेशक मण्डल में स्थायी स्थान प्राप्त था। अब इसका स्थान जापान ने ले लिया है।
3. **सभापतित्व (Chairmanship)**- सितम्बर 1951 ई. में भारत ने बैंक के वार्षिक अधिवेशन का सभापतित्व किया।

4. **बैंक सन्देश (Bank Message)**- जब से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं को आरम्भ किया है तभी से वह बैंक विशेषज्ञों को आमन्त्रित करता रहा है। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक का एक मिशन भारत आता है जो यहाँ की आर्थिक स्थिति का आकलन करता है तथा हमारी योजनाओं की क्षमता की जानकारी प्राप्त करता है।
5. **भारत सहायता क्लब (India Assistance Club)**- 1958 ई. में भारत सहायता क्लब की स्थापना विश्व बैंक ने की, जिसमें विश्व बैंक के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं दस राष्ट्र हैं। भारत को बराबर भारत सहायता क्लब से सहायता मिलती रही है।
6. **तकनीकी सहायता व परामर्श (Technical Support and Consulting)**- विश्व बैंक भारत को बराबर आर्थिक मुद्दों पर तकनीकी सहायता एवं परामर्श देता रहा है। देश की मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में भी वह परामर्श देता है।
7. **प्रशिक्षण सुविधाओं से लाभ (Benefits From Training Facilities)**- समय-समय पर भारत अधिकारियों को उच्च कोटि का प्राविधिक प्रशिक्षण लेने हेतु बैंक के आर्थिक विकास विद्यालय में भेजता रहता है।
8. **सिन्धु जल विवाद (Indus Water Dispute)**- पाकिस्तान के साथ सिन्धु नदी जल के बँटवारे सम्बन्धी विवाद का विश्व बैंक ने निपटारा किया था। अभी कुछ साल पहले कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बन रही जल विद्युत परियोजना बगलिहार विवाद का निपटारा भी विश्व बैंक ने किया है। इस प्रकार विश्व बैंक एक सच्चे मित्र, सहायक और मार्गदर्शक के रूप में भारत को आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग देता है।

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights or SDR)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक विचार मंथन के पश्चात् 1967 में रियो डि जेनेरो (ब्राजील) में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की वार्षिक सभा में 'विशेष आहरण अधिकार' योजना स्वीकार की गई। 1969 में वाशिंगटन में मुद्रा कोष ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए अंगीकृत कर लिया। विशेष आहरण अधिकार को **कागजी स्वर्ण** भी कहते हैं। यह आभासी मुद्रा है।

विशेष आहरण अधिकार की विशेषताएँ (Features of Special Drawing Rights or SDR):

1. यह एक ऐच्छिक योजना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य अपनी इच्छानुसार इसका सदस्य बन सकता है।
2. यह कोष रहित मात्र पुस्तक प्रविष्टि है।
3. इसकी मात्रा का विभाजन सदस्य देशों में उनके अभ्यांशों के अनुसार होता है।
4. एस.डी.आर. की इकाई का मूल्य स्वर्ण में रखा गया है।
5. यह कागजी स्वर्ण है। विदेशी भुगतानों में इसका प्रयोग स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं की तरह उनके स्थान पर किया जाता है।
6. एस.डी.आर. भुगतान सन्तुलन के माध्यम को स्थापित करने में काम आते हैं।
7. निर्धारित राशि से अधिक एस.डी.आर. कोष जमा होने पर ब्याज मिलता है।



8. प्रयोग करने वाले देशों से ब्याज लिया जाता है।
9. एस.डी.आर. का प्रयोग किसी मुद्रा के लेन-देन में ही किया जाता है।
10. इस योजना में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निरीक्षण रहता है तथा वह समय-समय पर निर्देश देता रहता है।

विशेष आहरण अधिकार के उद्देश्य

(Purpose of Special Drawing Rights or SDR)

1. IMF के साधनों में वृद्धि करना, इस योजना का प्रथम व महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस योजना द्वारा मुद्रा कोष के साधनों में वृद्धि हुई है।
2. इस योजना का प्रारुभाव की वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से हुआ था। इससे अन्तर्राष्ट्रीय निधियों का सृजन हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अभाव दूर हुआ है।
3. इस योजना के अन्य वे सभी उद्देश्य हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य हैं।

एस.डी.आर. की कीमत निर्धारण(Pricing of S.D.R.):

योजना के शुरू के समय आहरण अधिकार का मूल्य डॉलर के अनुरूप रखा गया था। यह व्यवस्था 1 जनवरी 1970 ई. से चालू हुई। थी। उस समय यू.एस. एक डॉलर के बराबर एक एस.डी.आर. रखा गया था। परन्तु दिसम्बर 1971 ई. में डॉलर के अवमूल्य से यह परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात् यू.एस. डॉलर से आहरण अधिकार को जोड़ने के तीव्र आलोचना की गई, जिसके कारण जुलाई 1974 ई. से मुद्रा कोष ने एक नई कार्य प्रणाली काम में ली जिसे 'स्टैंडर्ड बास्केट' बोलते हैं। स्टैंडर्ड बास्केट में कुल 16 मुद्राओं को रखा गया है जिनको विशेष वजन देते हुए इनके मूल्यों से अब विशेष आहरण अधिकार का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

1 जनवरी 1981 ई. में समूह बास्केट के अन्तर्गत सम्मिलित प्रमुख मुद्राओं की संख्या घटाकर 5 कर दी गई। 1 जनवरी 1991 ई. को एस.डी.आर. का मूल्य 5 मुद्राओं का योग है-

यू. एस. डॉलर (40%)

ड्यूशमार्क (21%)

जापानी येन (17%)

फ्रेंच फ्रैंक (11%)

पौण्ड स्टर्लिंग (11%)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund of IMF)

विश्व में स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर स्थायित्व के साथ स्वतः चलता रहता था परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसका स्वार्थी देशों द्वारा दुरुपयोग होना शुरू हो गया तथा यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्थिति और बिगड़ गई। अत्यधिक मुद्रा प्रसार के कारण भी देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।

अतः 1944 ई. में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मौद्रिक तथा आर्थिक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 44 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि सभी देशों के विकास के लिए दो वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की जाएँ-

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund or IMF)
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (International Reconstruction and Development Bank or IBRD)

अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन जुड़वाँ संस्थाओं में से एक है जिनको स्थापित करने के निर्णय 1944 ई. में ब्रेटन वुड्स में लिया गया था।

मुद्रा कोष के उद्देश्य (Objectives of Monetary Fund)

कोष की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई-

1. **विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व (Stability In Foreign Exchange Rates):-** सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को स्थायी बनाए रखना और इसके लिए किसी भी सदस्य को उसकी मुद्रा के बदले अन्य सदस्य देशों की मुद्राएँ बेचना।
2. **बहुपक्षीय भुगतान की पद्धति स्थापित करना (Setting up a System of Multilateral Payment):-** मुद्रा कोष एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयत्न करेगा। जिसमें सदस्य देश एक-दूसरे की मुद्रा को निःसंकोच भुगतान में स्वीकार कर सकें।
3. **विनिमय नियन्त्रण को हटाना (Exchange Control):-** विदेशी व्यापार में कड़ी कठिनाई न रहे इसके लिए कोष की यह भी प्रयत्न करना था कि धीरे-धीरे विनिमय सम्बन्धी सभी नियन्त्रण समाप्त हो सकें।
4. **भुगतान विषमता दूर करना (Remove Payment Inequality):-** सदस्य देश ऐसा कार्य न करें जो विदेशी व्यापार में रूकावट उत्पन्न करे।
5. **अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के असन्तुलन को कम करना (To Reduce The Imbalance Of International Payments):-** मुद्रा कोष का उद्देश्य ऐसे प्रयत्न भी करना है जिससे विदेशी भुगतान का असन्तुलन अल्प समय में कम किया जा सके। इसके लिए मुद्रा कोष अपने पास से सदस्यों को विदेशी मुद्रा भी उधार दे सकता है।
6. **विदेशी व्यापार को बढ़ावा (Promoting Foreign Trade):-** मुद्रा कोष द्वारा ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जिनसे विदेशी व्यापार का सन्तुलित विकास व विस्तार हो सके, साथ ही सदस्य देशों को आर्थिक विकास करने में पर्याप्त सुविधा मिल सके।

मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना है और इसके लिए वह सदस्य देशों की विनिमय दरों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने का अधिकार रखता है। भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने कोष से चालू भुगतान के लिए किसी भी सदस्य देश को अन्य सदस्य देशों की मुद्राएँ बेचता है अथवा उधार देता है। यह उधार केवल अल्पकाल के लिए ही दिया जाता है।

मुद्रा कोष की सदस्यता (Membership of Monetary Fund)

मुद्रा कोष की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है, परन्तु सदस्य देशों के लिए कोष के उद्देश्यों तथा शर्तों का पालन करना आवश्यक है। जो देश कोष का सदस्य न रहना चाहे, वह सूचना मात्र से ऐसा कर सकता है। यदि कोई सदस्य देश मुद्रा कोष के समझौते पत्र की किसी धारा की अवहेलना करता है, तो उसे सदस्यता से पृथक किया जा सकता है। कोष की स्थापना के समय इसके 40 देश सदस्य थे। वर्तमान में यह संख्या 188 है।



मुद्रा कोष का संगठन एवं प्रबन्ध

(Organization and Management of Fund)

- गवर्नर मण्डल (Governor's Board)**- यह सर्वोच्च संस्था है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। गवर्नर मण्डल की वर्ष में एक बार सभा बुलानी आवश्यक होती है जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। गवर्नर मण्डल का मुख्य कार्य नीतियों का निर्धारण करना, सदस्य देशों के कोटे में संशोधन करना, नये सदस्य देशों, को प्रवेश देना, संचालक चुनना आदि निर्णय लेना है।
- कार्यकारी संचालक मण्डल (Executive board of directors)**- कार्यकारी संचालक मण्डल मुद्रा कोष की सामान्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुद्रा कोष में कम से कम 12 संचालक होने आवश्यक हैं। पाँच संचालन उन पाँच राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिनका मुद्रा कोष में सर्वाधिक अभ्यंश है। अन्य संचालकों का चुनाव किया जाता है।
- मताधिकार (Franchise)**- मुद्रा कोष के अधिकार सामान्य निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। बहुमत सदस्य संख्या द्वारा न होकर कुल मताधिकार द्वारा होता है। प्रत्येक सदस्य को 250 + 1 मत प्रति लाख एस.डी.आर. (अभ्यंश) का मताधिकार होता है।
- कार्यालय (Office)**- मुद्रा कोष का केन्द्रीय कार्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है, यानि सबसे अधिक कोटे वाले देश अमेरिका में है। अन्य सदस्य देशों में कोष की शाखाएँ अथवा एजेन्सी कार्यालय हैं।

मुद्रा कोष के आर्थिक साधन (Financial Instruments Of Monetary Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आर्थिक साधनों में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य देशों के लिए निर्धारित अभ्यंश है। जब कोई देश मुद्रा कोष का सदस्य बनता है, तो उसका अभ्यंश निर्धारित कर दिया जाता है। ये अभ्यंश देश की राष्ट्रीय आय, मुद्रा रक्षित, निधि, व्यापार शेष तथा अन्य आर्थिक निर्देशकों के आधार पर तय किए जाते हैं। किसी भी देश की अभ्यंश राशि उसकी सहमति के बिना बदलने की व्यवस्था नहीं है।

1 जनवरी 1981 ई. से एस.डी.आर. का मूल्य 5 मुख्य मुद्राओं के आधार पर निश्चित किया गया। 1 जनवरी 1991 ई. को एस.डी.आर. का मूल्य निम्न मुद्राओं का योग था- यू.एस. डालर (40%), ड्यूशमार्क (21%) जापानी कामा येन (17%), फ्रेंच फ्रैंक (11%) और पौण्ड स्टर्लिंग (11%)।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का संस्थापक सदस्य है। वित्त मन्त्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेस का पदेन गवर्नर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत का वैकल्पिक गवर्नर है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है जो अन्य देशों- बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है।

मुद्रा कोष में सदस्य देशों की हिस्सेदारी (अंश)- भारत का कोटा IMF में 1.91% से बढ़कर 2.44% हो गया है। भारत का मतदान में अधिकार 1.88% से बढ़कर 2.34% हो गया है। लेकिन मतों में हिस्सेदारी

के आधार पर भारत (बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ) 24 निर्वाचन संघों में 21वें स्थान पर है।

नगरानी- IMF के अनुबन्ध के भाग 4 के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए अनिवार्य हिस्से के रूप में IMF हर वर्ष अपने सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है। इससे सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। भाग 4 के परामर्श अभ्यास के दौरान आईएमएफ मिशन RBI और केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालय/विभागों के साथ चर्चा करता है।

➤ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)

- ✍ SDR में भारत का कोटा 4158.2 मिलियन SDR से बढ़ाकर 5821.5 मिलियन SDR हो गया है।

मुद्रा कोष के कार्य (Functions of Monetary Fund)

1. मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करना (Receiving Loans From Monetary Fund)- सदस्य देश मुद्रा कोष से ऋण की सुविधा ले सकते हैं। जब किसी देश में भुगतान सन्तुलन में अस्थायी रूप से विषमता उत्पन्न हो जाती है, तो वह कोष से धन उधार ले सकता है। वर्तमान में सभी सदस्य देशों की मुद्राएँ स्वतन्त्र हैं और उनकी विनिमय दरों में बाजार भाव से उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। मुद्रा कोष के द्वारा ऋण देने का कार्य केन्द्रीय बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। मुद्राकोष सदस्य देशों को उनके आर्थिक संकट से छुटकारा दिलाने के लिए सहायता देता है, इसीलिए कोष की तुलना आग बुझाने वाली दमकल से की जाती है, जो आर्थिक संकटों की आग बुझाने के लिए सहायता रूपी जल उपलब्ध कराता है। इस सन्दर्भ में कोष के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक जैकोब्सन ने कहा था, “मुद्रा कोष आग बुझाने वाले इन्जन की तरह है जिसका प्रयोग संकट काल में किया जाना चाहिए।” वास्तव में मुद्रा कोष एक गतिशील कोष है और इसकी पूँजी एक स्थान पर स्थिर नहीं रखी जा सकती। मुद्रा कोष मुख्य रूप से निम्न प्रकार की सहायता देता है-

- क्षतिपूरक वित्तीय सहायता (Compensatory Financial Assistance)**- इस योजना के अन्तर्गत उन देशों को सामान्य व्यवस्था से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो मुख्य रूप से प्राथमिक पदार्थों का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं।
- तेल के लिए सुविधा (Providing Facility for Oil)**- वे देश जो खनिज तेल कीमतों द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, उनको ऋण दिया जा सकता है।
- पूरक वित्त सुविधा (Supplementary Finance Facility)** - मुद्राकोष देशों को पूरक वित्त सहायता दे सकता है जिनकी आवश्यकता उनके साधारण कोटे से अधिक है और जो भुगतान शेष की असहाय कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
- संरचनात्मक समायोजन सुविधा (Structural Adjustment Facility)**- इसका उद्देश्य ऐसे सदस्य देशों को, जो भुगतान शेष की गम्भीर स्थिति से गुजर रहे हों और जिन्हें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की अत्यन्त आवश्यकता है; रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।



2. **दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency)**- जिन देशों की मुद्रा की माँग अधिक हो जाती है, मुद्रा कोष उन्हें 'दुर्लभ कोष' घोषित कर सकता है। मुद्रा कोष मुद्राओं को सदस्य देशों में उनकी आवश्यकतानुसार बाँट देता है।
3. **पुनर्क्रय (Repurchase)**- जब कोई देश मुद्रा कोष से उधार लेता है, तो अपनी मुद्रा देता है और दूसरे देश की मुद्रा को खरीदता है। इस प्रकार ऋणी देश के मौद्रिक भण्डार कोष के पास बढ़ जाते हैं। इन ऋणों को चुकाना पुनर्क्रय कहलाता है क्योंकि ऋणी देश के लिए आवश्यक है कि वह अपनी बेची मुद्रा को 5 वर्ष के भीतर पुनः खरीद ले।
4. **तकनीकी सहायता (Technical Assistance)**- वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कोष अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इस कार्य के लिए वह विभिन्न देशों में विशेषज्ञ दल भेजता है। तकनीकी सहायता, विनिमय तथा प्रशुल्क नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन, केन्द्रीय बैंकिंग विधान के निर्माण, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, वित्तीय तथा भुगतान सन्तुलन आदि विषयों में सम्बन्धित रहती है।

मुद्रा कोष के वर्जित कार्य (Prohibited Work Of Monetary Fund)- मुद्रा कोष निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता-

1. मुद्रा कोष निजी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता।
2. मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की भीतरी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल आवश्यक परामर्श दे सकता है।

वित्तीय प्रबन्ध (Financial Management)- वित्तीय प्रबन्ध, प्रबन्ध की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत संस्था के वित्तीय कार्य का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियन्त्रण किया जाता है जिससे कि वित्तीय कार्यों का कुशल एवं प्रभावी संचालन किया जा सके।

वेस्टन तथा ब्रीघम के शब्दों में, "वित्तीय प्रबन्ध निर्णय लेने का वह क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा उपक्रम के लक्ष्यों में एकरूपता स्थापित करता है।

वित्तीय नियोजन (Financial Planning)- वित्तीय नियोजन से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के लिए पूँजी की कुल राशि का पूर्वानुमान लगाना एवं उसके स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। इसका दूसरा नाम 'वित्तीय आयोजन' है। **जे.एच.बोनविले** के अनुसार, "निगम की वित्तीय योजना के दो पहलू होते हैं। यह न केवल निगम की पूँजी संरचना की ओर संकेत करती है बल्कि यह निगम द्वारा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को भी स्पष्ट करती है।"

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation or IFC)

विश्व बैंक द्वारा अल्पविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई, किन्तु इसमें दो मुख्य कमियाँ थीं-

1. विश्व बैंक केवल ऋण देता है, पूँजी के अंश नहीं खरीदता।
2. वह केवल सरकार को या सरकार की गारन्टी पर ही ऋण देता है। अनेक उद्योगपति सरकारी गारन्टी युक्त ऋण लेना पसन्द नहीं करते क्योंकि ऋण लेने से सरकार उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने लगती है। इन्हीं दोनों कमियों को दूर करने तथा विश्व बैंक के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत एवं

प्रभावी बनाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना का विचार 1952 ई. में आया तथा 21 जुलाई, 1956 ई. को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की विधिवत् स्थापना की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य (Objectives of IFC)

1. **निजी साहस को प्रोत्साहन (Promotion Of Personal Courage)**- यह निगम बिना सरकारी गारन्टी के ऋण देता है और अन्य स्रोतों से भी पूँजी दिलाने का प्रयत्न करता है।
2. **पूँजी तथा प्रबन्ध समन्वय (Capital And Managerial Coordination)**- इसका एक बड़ा उद्देश्य देशी और विदेशी पूँजी में सहयोग स्थापित कर उसे अनुभवी प्रबन्ध से संयोजित करना है। अर्थात् यह कुशल प्रबन्धन के लिए पूँजी की व्यवस्था करता है और किसी के पास पर्याप्त पूँजी हो, तो उसके लिए कुशल प्रबन्धन की व्यवस्था करता है।
3. **विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन (Incentive To Foreign Capital)**- निगम का एक प्रशंसनीय उद्देश्य अतिरिक्त पूँजी वाले देशों को अभाव वाले देशों में पूँजी लगाने को प्रोत्साहित करना है।

वित्त निगम की सदस्यता (Membership Of Finance Corporation)

विश्व बैंक के सदस्य ही वित्त निगम के सदस्य बन सकते हैं। निगम से कोई भी सदस्य देश किसी भी समय सदस्यता से अलग हो सकता है। यदि विश्व बैंक किसी सदस्य देश की सदस्यता समाप्त कर दे, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम में उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।

वित्त निगम का प्रबन्ध (Management of Finance Corporation)

इसकी प्रबन्ध व्यवस्था भी विश्व बैंक के समान ही है। विश्व बैंक का प्रशासन मण्डल ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रशासन मण्डल के रूप में कार्य करता है। विश्व बैंक का कार्यकारी संचालक मण्डल ही निगम के कार्यकारी संचालक मण्डल का कार्य करता है निगम का प्रधान कार्यालय **वाशिंगटन डी.सी.** में स्थित है। निगम सदस्य देशों में भी अन्य कार्यालय स्थापित कर सकता है। इस समय इनके अन्य कार्यालय, लन्दन, पेरिस और न्यूयॉर्क में हैं।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Economic Cooperations and Development Organization)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना के लिए 1948 ई. में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्ताविक योजना के प्रत्युत्तर में पेरिस में यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया गया तथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) बनाया गया। 30 सितम्बर 1961 ई. को इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) कर दिया गया।

इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का समन्वय करना तथा इसके सदस्यों को विकासशील देशों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

इसके 30 सदस्य हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक (Czech Republic), हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जेंबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए.। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।



अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association or IDA)

यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे 'विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की' या 'उदार ऋणी खिड़की' भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 ई. को की गई थी। इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 159 हो गई है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 ई. (जून-जुलाई) के दौरान IDA से सहायता पाने वाले देशों में भारत का पहला स्थान रहा था। इसके साधनों में मुख्यतः सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत पूँजी (Subscribed Capital), विकसित राष्ट्रों द्वारा किया गया अंशदान (General replenishments), विशिष्ट योगदान तथा IBRD द्वारा हस्तान्तरित शुद्ध आय आदि आते हैं।

यूरो जोन (Euro Zone)

विश्व के पटल पर बढ़ते आर्थिक एकीकरण अभियानों-नाफ्टा (उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता), साफ्टा (दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता), आसियान (दक्षिण-पूर्वी-एशियाई राष्ट्रों का संघ), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) आदि अनेक के प्रयासों ने क्षेत्रीय आर्थिक गुट की रणनीति को बढ़ावा दिया और इसी कड़ी में जुड़ गया एक और नाम-मास्ट्रिच संधि (Maastricht Treaty)।

9-10 दिसम्बर, 1991 ई. को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने मास्ट्रिच (नीदरलैंड) में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण हेतु एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए और यही मास्ट्रिच सन्धि यूरो करेन्सी के उदय की बुनियाद बनी।

1 नवम्बर 1993 ई. से लागू इस सन्धि ने राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय संघ (European Union) को जन्म दिया। मास्ट्रिच सन्धि एवं यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए **याक डेलोर्स** की योजना के परिणाम के रूप में ही आज विश्व पटल पर यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' ने दस्तक दी है।

यूरो जोन में भागीदारी : प्रमुख शर्तें (Participation in Euro Zone: Main Conditions)

मास्ट्रिच सन्धि के दस्तावेजों में यूरोप में मौद्रिक एवं आर्थिक एकीकरण एवं साझी मुद्रा 'यूरो' के प्रचलन के लिए चार प्रमुख शर्तों का उल्लेख किया गया-

- मुद्रास्फीति की दर पर नियन्त्रण (उत्तम निष्पादन करने वाले पहले तीन देशों में प्रचलित मुद्रास्फीति दर से मुद्रास्फीति की दर का 1.5% से अधिक न होना)।
- निम्न ब्याज दर (उत्तम निष्पादन करने वाले प्रथम तीन देशों की ब्याज दर की तुलना में 2% से अधिक न होना)।
- सरकारी ऋण का GDP के 60% से अधिक न होना।
- वार्षिक बजट घाटा GDP के 3% से अधिक न होना।

मास्ट्रिच सन्धि में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के देशों से उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे यूरोप की साझी मुद्रा 'यूरो' में अपनी भागीदारी दर्ज कर सकें। यूरोप के अब तक 15 राष्ट्रों ने यूरो में भागीदारी हेतु सभी आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा कर लिया है।

पूर्व में यूरोपीय संघ (EU) के 12 राष्ट्रों में एकीकृत मुद्रा 'यूरो' (Euro) का चलन 1 जनवरी 2002 ई. से प्रारम्भ हो गया था। इन राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस (यूनान) आयरलैंड, इटली, लक्जेंबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल व स्पेन शामिल हैं। यूरो चलन वाले राष्ट्रों के लगभग 30 करोड़ जनसंख्या वाले इस क्षेत्र को यूरो जोन (Euro zone) कहा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या : यूरो एक सम्भावित समाधान

(International Liquidity Problem: Euro is a Potential Salution)

विश्व पटल पर दिन-प्रतिदिन विषम होती अन्तर्राष्ट्रीय सरलता (International Liquidity) की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विविध विस्तार में अवरोध बनकर सामने आती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के परिमाणत्मक पहलू के साथ-साथ इस समस्या का गुणात्मक पहलू भी विश्व मौद्रिक बाजार में एक अवरोधक घटक रहा है। इस गुणात्मक पहलू का सम्बन्ध रिजर्व के रूप में अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पौण्ड स्टर्लिंग के प्रयोग से है, क्योंकि ये दोनों विश्व पटल पर लम्बे समय तक आधार मुद्राएँ रही हैं, यद्यपि यह स्थिति विगत कुछ समय से जापानी येन तथा जर्मन मार्क को भी प्राप्त हो गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के कुछ विशिष्ट देशों की मुद्रा के साथ बंधे रहने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय व्यवस्था में एकाधिकारी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। इसी समस्या के सम्यक् समाधान की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1971 ई. से विशेष आहरण अधिकार (SDR) की योजना, जिसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) के नाम से भी जाना जाता है, आरम्भ की गई। SDR के मूल्य निर्धारण में वर्ष 1991 ई. के दौरान मुद्राओं की पिटारी (Basket of currencies) में अमेरिकी डॉलर (भार 40%) जर्मन मार्क (भार 21%), जापानी येन (भार 17%), ब्रिटिश पौण्ड (भार 11%) तथा फ्रांसीसी फ्रैंक (भार 11%) को सम्मिलित किया गया।

अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व विशेष आहरण अधिकार (SDR) पर भी हावी है और इसी का परिणाम है वर्तमान में अमेरिका का IMF के पास सर्वाधिक कोटा। अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजारों में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व और अन्य मुद्राओं की सापेक्षिक उपेक्षा ने यूरोप में मौद्रिक एकीकरण की प्रक्रिया को गति दी और यूरोप के देश चल पड़े आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकृत मुद्रा 'यूरो' को अपनाने के लिए और वह भी इस आशा के साथ कि यूरो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में डॉलर की सम्प्रभुता को चुनौती देगा और अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा।

यूरो और भारत (Euro and India)

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर में आगे बढ़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में यूरो का उदय भारतीय व्यापार को निःसन्देह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2004-05 के दौरान यूरोपीय संघ के देशों को '77489 करोड़ (17246 मिलियन डॉलर) का भारत से निर्यात किया गया जो



कुल निर्यातों का 22% था। इसी प्रकार इसी वर्ष 2004-05 में यूरोपीय संघ के देशों को भारत से '81105 करोड़ (18051 मिलियन डॉलर) का आयात किया गया जो कुल आयातों का 16.86% था।

इसके अतिरिक्त एकल साझी मुद्रा यूरो के साथ भारत के रूपए की विनिमय दर में अब पहले की तुलना में विनिमय स्थिरता आ रही है जिससे यूरोलैण्ड के साथ भारत का विदेशी व्यापार सहज एवं विस्तृत होगा। यूरोलैण्ड के साथ 'यूरो' में किया गया भारतीय व्यापार भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को घटा रहा है और साथ ही यूरोलैण्ड के साथ विनिमय स्थिरता के कारण भारतीय उत्पाद यूरोलैण्ड में अधिक सस्ते पड़े रहे हैं। यह बिन्दु निःसन्देह भारतीय निर्यातों को बढ़ाने का एक प्रमुख मार्ग खोलेगा।

इस प्रकार निःसन्देह यूरो का उदय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank)

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 ई. में की गई थी। 1 जनवरी 1967 ई. को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है।

इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। वर्तमान में जापान के हारुहिको कुरोडा ADB के चेयरमैन हैं। उल्लेखनीय है कि ADB का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है, जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमेरिका का, एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में ADB की सदस्य संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

ADB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. विकास परियोजनाएँ और कार्यक्रम तथा परामर्श सेवाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
2. विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाही करना।
3. अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और ईक्विटी निवेश उपलब्ध कराना।
4. समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों के सहायता अनुरोधों पर कार्यवाही करना।

31 दिसम्बर, 2004 ई. तक बैंक के पूँजी स्टॉक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के अंशदान का 6.424 प्रतिशत था।

भारत बैंक के निदेशक मण्डल का कार्यकारी निदेशक है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओस पीडीआर और तजाकिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर हैं और सचिव (विदेश विभाग) इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं। इस समय भारत में एशियाई विकास बैंक की सहायता वाली 27 परियोजनाएँ तथा 49 तकनीकी परियोजनाएँ चल रही हैं। ADB ने भारत में ग्रामीण साख व्यवस्था के सृद्धीकरण हेतु 1 अरब डॉलर का ऋण दिसम्बर 2006 ई. में प्रदान किया था।

विश्व बैंक द्वारा गरीबी की रेखा के मानक में परिवर्तन (Changes In The Standard Of Poverty Line By The World Bank)

गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के आकलन हेतु विश्व बैंक द्वारा अभी तक एक डॉलर प्रतिदिन की आय को आधार माना जाता था। इस मानक में सुधार करते हुए विश्व बैंक ने इसे अब 1.25 डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। इससे भारत व अनेक अन्य देशों में गरीबी की रेखा के नीचे (Below Poverty Line or BPL) के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक द्वारा 26 अगस्त, 2008 ई. को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1981 ई. में भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 42.1 करोड़ थी, जो बढ़कर 2005 ई. में 45.6 करोड़ रही है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में वृद्धि को विश्व बैंक ने देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताया है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)

न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किए गए एक नए विकास बैंक का आधिकारिक नाम है। 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में 100 अरब डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय किया गया।

न्यू डेवलपमेंट बैंक पांच उभरते बाजारों के बीच अधिक से अधिक वित्तीय और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। साथ में, 2014 की गणनानुसार चार मूल। ब्रिक्स देशों में 3 अरब लोग या दुनिया की आबादी का 41.4 प्रतिशत शामिल है, तीनों महाद्वीप दुनिया की भूमि क्षेत्र के एक चौथाई से अधिक को घेरते हैं, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी है। बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। विश्व बैंक के विपरीत यह पूंजी शेयर के आधार पर वोट प्रदान करता है। ब्रिक्स बैंक में प्रत्येक भागीदार देश को एक वोट आवंटित किया गया है। और भागीदार देशों में से किसी के पास वीटो का अधिकार नहीं होगा।

ब्रिक्स (Bricks)

ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेज़ी नाम के प्रथमाक्षरों B, R, I, C व S से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे 'ब्रिक' के नाम से जाना जाता था। रूस को छोड़कर, ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। ये राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वर्ष 2013 तक, पाँचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया के लगभग 3 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक अनुमान के अनुसार ये राष्ट्र संयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। इन राष्ट्रों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 15 खरब अमेरिकी डॉलर का है। वर्तमान में, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts About International Organizations)

संगठन	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन डी.सी.	188
विश्व बैंक (पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) तथा बहुपक्षीय निवेश गारन्टी एजेंसी (MIGA) विश्व बैंक से ही सम्बद्ध संस्थाएँ हैं। मूलतः स्थापित संस्था IBRD है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। IFC की स्थापना 1956 में व IDA की स्थापना 1960 में हुई,)	1945	वाशिंगटन डी.सी.	188
एशियाई विकास बैंक	1966	मनीला	67
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जेनेवा	155
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ (ASEAN)	1967	जकार्ता	10 (इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कम्बोडिया)
नाफ्टा (NAFTA)	1992		3 (अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको)
एपेक (APEC)	1989		21 (ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, चीन, मेक्सिको, हांगकांग, ताइवान, द. कोरिया, जापान, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, पपुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम)
यूरोपियन संघ	1958 में स्थापित EEC का परिवर्तित रूप	ब्रूसेल्स	27 (फ्रांस, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैण्ड, हॉलैण्ड, इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड, स्वीडन, पोलैण्ड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, चैक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, साइप्रस, माल्टा, बुल्गारिया तथा रोमानिया)
मर्कोसुर (Mercosur)	1995		5 (ब्राजील, अर्जेन्टीना, पाराग्वे, उरूग्वे व वेनेजुएला)
ओपेक (OPEC)	1960	वियना (ऑस्ट्रिया)	11 (ईरान, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कतर, लीबिया, इक्वेडोर, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया व नाइजीरिया)
दक्षेस (SAARC)	1985	काठमाण्डू	8 (भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान)
जी-15 (19 विकासशील देशों का संगठन)	1989	जेनेवा	19 (भारत, मेक्सिको, जर्मनी, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली कीनिया, श्रीलंका कोलम्बिया व ईरान)
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)	1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का परिवर्तित रूप	पेरिस (फ्रांस)	30 (ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक, हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, स्लोवाकिया, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विजरलैण्ड, टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए.)
एसेम (ASEM)	1996		45 (यूरोपीय संघ के 27 व आसियान के 10 तथा 8 अन्य देशों को शामिल करते हुए एशिया के 18 देश)
एशियाई क्लियरिंग यूनियन (ACU)	1975	तेहरान	8 (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान व म्यांमार)
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	1945	न्यूयॉर्क	193

भारतीय वित्तीय एवं पूँजी बाजार (Indian Financial and Capital Market)

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market)

- शेयरों और अंश पत्रों का क्रय-विक्रय जिस बाजार में होता है उसे शेयर बाजार कहा जाता है।
- ये शेयर बाजार कुछ निश्चित एवं नियत स्थानों पर ही होते हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है।
- पब्लिक इश्यू जारी करके संसाधन एकत्रित करने वाली कंपनियों को यहाँ पंजीकरण कराना होता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) की स्थापना 12 अप्रैल, 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत पूँजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी, 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, किन्तु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। SEBI का प्रबन्ध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित होता है।
- 1988 में सेबी की प्रारम्भिक पूँजी 7.5 करोड़ रूपए थी जो कि प्रवर्तक कंपनियों (IDBI, ICICI तथा IFCI) द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन-प्रतिदिन के कार्य सम्पन्न होते हैं।
- भारतीय पूँजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेबी को ही प्राप्त हैं।
- नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार (Stock Exchange) को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैंक में मताधिकार के सम्बन्ध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है।
- सेबी (संशोधन) विधेयक 2002 के तहत 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के लिए 25 करोड़ रूपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में एक लाख रूपए प्रतिदिन की दर से एक करोड़ रूपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

भारत के प्रमुख शेयर बाजार

(India's Leading Stock Exchange)

1. **राष्ट्रीय शेयर बाजार (National Stock Exchange) :** राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992

में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) को इस बाजार (exchange) की स्थापना का कार्य सौंपा IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) की प्रारम्भिक अधिकृत पूँजी 25 करोड़ रूपए है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुम्बई में वर्ली में है।

2. **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) :** इसकी स्थापना 1875 ई. में स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे के नाम से किया गया था जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) कर दिया गया। 19 अगस्त, 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपान्तरित हो गया है। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियाँ पंजीकृत हैं।

3. **ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (OTCEI) :** इसकी स्थापना नवम्बर, 1992 में मुम्बई में की गई। यह भारत में सर्वप्रथम ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा सम्पन्न कम्प्यूटराइज्ड एक्सचेंज 'नैस्डेक' के आधार पर की गई है। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी पूँजी का स्तर 30 लाख रूपए से 25 करोड़ रूपए तक हो।

विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था।

- स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश (FII) हो सकता है।

- न्यूयॉर्क एटॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की आठ कंपनियाँ हैं-

(i) डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज (ii) HDFC (iii) ICICI (iv) MTNL (v) सत्यम कम्प्यूटर्स (vi) विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) (vii) विप्रो (WIPRO) (viii) टाटा मोटर्स।

- भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कंपनी को पूँजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूँजी अंश पूँजी या शेयर कहलाती है।

- शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं।

विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार (World Famous Stock Market)

शेयर मूल्य सूचकांक	स्टॉक एक्सचेंज
डो जोन्स (Dow Jones)	न्यूयॉर्क
निक्की (Nikkei)	टोकियो
मिड डेक्स (MID DAX)	फैंकफर्ट
हांग सेंग (HANG SENG)	हांगकांग
सिमेक्स (SIMEX)	सिंगापुर



कोस्पी (KOSPI)	कोरिया
सेट (SET)	थाइलैंड
तेन (TAIEN)	ताइवान
शंघाई कॉक (SHANGHAI COM)	चीन
नैसडैक (NASDAQ)	USA
एम. एण्ड पी. (S. & P.)	कनाडा
बोवेस्पा	ब्राजील
मिब्टेल	इटली
आई पी सी (I.P.C.)	मैक्सिको
जकार्ता कम्पोजिट	इण्डोनेशिया
KLSE कम्पोजिट	मलेशिया
सियोल कम्पोजिट	दक्षिण कोरिया
FTSE-100	लंदन

भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक (India's Main Stock Price Index)

1. **BSE SENSEX** : यह मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (The Stock Exchange Mumbai) का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 ई. है।
2. **BSE 200** : यह मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ई. है।
3. **NSE-50** : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दिल्ली से सम्बन्धित इस सूचकांक का नाम बदलकर S & P CNX Nifty रखा गया है।

बीमा उद्योग (Insurance Industry)

- भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएण्टल सोसाइटी (1818) थी।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को हुई थी।
- इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं जबकि इसका केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है।
- भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) ने 1 जनवरी, 1973 से काम करना प्रारम्भ किया। इसकी चार सहायक कंपनियाँ हैं:
 1. नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि.
 2. न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लि.
 3. ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि.
 4. यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी लि.
- बीमा क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मुद्रा बैंक (Mudra Bank)

Micro Units Development and Re-finance Agency

मुद्रा बैंक की स्थापना 8 अप्रैल 2015 को हो गयी। यह वास्तव में एक बैंक नहीं बल्कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होगी। यह उपभोक्ता एवं निवेशकों को प्रत्यक्ष तौर पर ऋण नहीं प्रदान करेगी। यह उन सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करेगी जो कुटीन उद्योगों को ऋण प्रदान करेंगे। अतः इससे सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की निर्भरता खत्म हो जायेगी एवं उन्हें कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण की प्राप्ति होगी। प्रारम्भ में मुद्रा बैंक सिडबी (SIDBI- Small Industries Development Bank of India) के रूप में करेगी। भविष्य में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का नियन्त्रण मुद्रा बैंक के अधीन कर दिया जायेगा।

कुटीर उद्योगों की स्थापना, आकार एवं विस्तार में आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा- शिशु, किशोर एवं तरुण। जो कुटीर उद्योग अभी स्थापित ही हो रहे हैं वो शिशु की श्रेणी में आये एवं उन्हें ₹ 50,000 हजार तक के ऋण की प्राप्ति होगी। किशोर, अवस्था में जो कुटीर उद्योग होंगे उन्हें ₹ 5 लाख तक के ऋण की प्राप्ति होगी एवं बूढ़े कुटीर उद्योग जो विस्तार कर रहे होंगे। तरुण अवस्था में कहलायेंगे एवं उन्हें ₹ 10 लाख तक के ऋण की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में मुद्रा बैंक की भूमिका देश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में अत्यधिक हो जायेगी। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पूंजी के अभाव से ग्रसित हैं। अतः यदि उन्हें उचित मात्रा में सहयोग प्राप्त हो तो गरीबी एवं बेरोजगारी दोनों का निवारण हो सकता है और साथ ही ये देश की आर्थिक समृद्धि में भी योगदान करेंगे।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

- विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 1.4% है।
- भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अभियान्त्रिकीय वस्तुओं (इन्जीनियरिंग गुड्स) का सर्वाधिक भाग (33%) है।
- भारत के आयात में सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थों का है।
- देश का पहला निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क सीतापुर में स्थापित किया गया है।
- एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र काण्डला में (1965) स्थापित किया गया था।

भारत का प्रमुख क्षेत्रों के साथ निर्यात (Export with major areas of India)

1. विकासशील देश	44%
2. OECD देश	34%
3. एशियन देश	31%
4. OPEC देश	21%
5. यूरोपियन देश	18%



भारत के प्रमुख देशों के साथ निर्यात (Export With Major Countries of India)

1. संयुक्त अरब अमीरात	11.6%
2. अमेरिका	10.4%
3. सिंगापुर	8.0%
4. चीन	5.1%
5. इण्डोनेशिया	3.0%

भारत के प्रमुख निर्यातक राज्य (India's Leading Exporter State)

1. महाराष्ट्र	24%
2. गुजरात	22%
3. तमिलनाडु	9%
4. कर्नाटक	5.1%
5. आन्ध्र प्रदेश	4.8%

विदेश व्यापार : दस स्वायत्तशासी निकाय (Foreign Trade : Ten Autonomous Body)

- कॉफी बोर्ड
- रबर बोर्ड
- चाय बोर्ड
- तम्बाकू बोर्ड
- मसाला बोर्ड
- निर्यात निरीक्षण परिषद्
- भारत विदेश व्यापार संस्थान
- भारतीय पैकेजिंग संस्थान
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

भारत का प्रमुख देशों एवं समूहों के साथ आयात (अप्रैल-सितम्बर 2011)

(Import With Major Countries And Groups of India)

1. OPEC	35%
2. विकासशील देश	32%
3. OECD	31%
4. एशिया	26%
5. यूरोपिय संघ	12%
• वर्ष 2001 में भारत का सर्वाधिक आयात (11.5%) चीन के साथ हुआ।	

भुगतान सन्तुलन (Balance Of Payments)

- एक वित्त वर्ष के दौरान विश्व के अन्य देशों के साथ किए जाने वाले लेन-देन को भुगतान सन्तुलन प्रदर्शित करता है।
- भुगतान सन्तुलन के अन्तर्गत चालू खाते व पूँजी खाते के लेन-देन शामिल किए जाते हैं।
- भुगतान सन्तुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त, 1944 को रूपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय (एस तारापोर समिति की सिफारिश पर) घोषित कर दिया गया।

- चालू खाते में आयात-निर्यात के साथ-साथ बीमा, पर्यटन, उपहार एवं परिवहन जैसी अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है।
- पूँजीगत खाते में ऋणों की प्राप्ति, अदायगियों, स्वर्ण करेंसी आदि के मामले शामिल किए जाते हैं।
- अप्रैल-सितम्बर 2011 में चालू खाते का घाटा 32.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि कुल जीडीपी का 3.6% था।
- भारत के विदेशी विनिमय के माध्यम निम्नलिखित हैं
 - (i) विदेशी मुद्रा विनिमय
 - (ii) विशेष आहरण अधिकार (SDRs)
 - (iii) सोना
 - (iv) रिजर्व ट्रेंच पोजीशन (RTP)
- भारत द्वारा अमेरिकी डॉलर एवं यूरो मुद्रा, निवेश की मुद्राओं के रूप में स्वीकृत हैं।
- विदेशी मुद्रा भण्डार की दृष्टि से भारत, चीन, जापान एवं रूस के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भण्डार वाला देश है।

➤ प्रमुख क्षेत्रीय संगठन (Major Regional Organizations)

संगठन/समझौता	उद्देश्य
भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग (1998)	भारत ने सर्वप्रथम श्रीलंका के साथ सीपा (CEPA) व्यापार समझौता किया
भारत-थाइलैण्ड आर्थिक समझौता (2001)	82 वस्तुओं पर टैरिफ को कम करना
भारत-सिंगापुर आर्थिक सहयोग (2005)	दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार स्थापित करना
भारत-यूरोपीय संघ समझौता (2007)	भारत एवं यूरोपियन संघ के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ाना
भारत-जापान आर्थिक समझौता (2007)	2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना
एशिया-पैसिफिक व्यापार समझौता (2007)	एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ आपसी व्यापार बढ़ाना
भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (2008)	सन् 2015 तक द्विपक्षीय व्यापार को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना
भारत-बिमस्टेक आर्थिक सहयोग (2008)	2012 से टैरिफ में छूट तथा बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाना
भारत-दक्षिण कोरिया आर्थिक समझौता (2009)	द्विपक्षीय व्यापार में ट्रिप्स टैरिफ सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करके व्यापार बढ़ाना
भारत-आसियान समूह समझौता (2009)	टैरिफ को 80% तक कम करके, व्यापार बढ़ाना



- विश्व बैंक की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 2012 के अनुसार 20 विकासशील देशों के समूह में चीन, रूस, ब्राजील एवं टर्की के बाद पाँचवाँ सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश भारत है।
- भारत का बाहरी ऋण कुल जीडीपी का 16.9% है, जबकि ऋण सेवा अनुपात 5.6% है। (2010-11)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone)

- एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र काण्डला में 1965 ई. में स्थापित किया गया था।
- पहली सेज (SEZ) नीति अप्रैल, 2000 में घोषित की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अधोसंरचना का विकास करके आर्थिक वृद्धि को गति देना है।
- सेज (SEZ) अधिनियम 2005 को 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया था।
- सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण केन्द्रों को सेज में बदल दिया गया है, जो निम्न है:
 - काण्डला (गुजरात)
 - सूरत (गुजरात)
 - सान्ताक्रुज (महाराष्ट्र)
 - कोचीन (केरल)
 - चेन्नई (तमिलनाडु)
 - विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)
 - फाल्टा (प. बंगाल)
 - नोएडा (उत्तर प्रदेश)

सेज (SEZ) अधिनियम 2005 के प्रावधान (Provision of SEZ Act 2005)

- सेज द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर 100% की कर छूट
- कर मुक्त आयात की स्वतन्त्रता
- केन्द्रीय व्यापार कर एवं सेवा कर में छूट
- एकल खिड़की योजना के तहत सेज स्थापित करने की नीति

भारत एवं विश्व व्यापार संगठन (India and World Trade Organization)

- दोहा समझौता (2001) विकासशील देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा।
- इस समझौते में दोहा विकास एजेण्डा पारित किया गया, जिससे विकासशील देशों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की गईं।
- दोहा विकास एजेण्डा में विकसित देशों द्वारा कृषि सब्सिडी को कम करना, ट्रिप्स समझौता तथा सर्वाजनिक सेवाओं के लिए विशेष अनुदानों पर विस्तृत विवेचना की गई थी।
- भारत का चार देशों- सिंगापुर, दक्षिण, कोरिया, जापान एवं मलेशिया-के साथ सिका (CECA) समझौता है।

भारत के अब तक के वित्त मंत्री (India's Finance Minister till Now)

वर्ष	वित्त मंत्री	वर्ष	वित्त मंत्री
1947-49	आर.के. षण्मुगम चेट्टी	1980-82	आर. वेंकटरमण
1949-51	जॉन मथाई	1982-85	प्रणव मुखर्जी
1951-57	सी.डी. देशमुख	1985-87	वी.पी. सिंह
1957-58	टी. टी. कृष्णामाचारी	1988-89	नारायण दत्त तिवारी
1958-59	जवाहर लाल नेहरू	1989-90	एस.बी. चह्माण
1959-64	मोरारजी देसाई	1990-91	मधु दण्डवते
1966-67	सर्चींद्र चौधरी	1990-91	यशवंत सिन्हा
1967-70	मोरारजी देसाई	1992-96	मनमोहन सिंह
1970-71	इन्दिरा गाँधी	1996-98	पी. चिदम्बरम
1971-75	यशवन्तराज बी. चह्माण	1998-2003	यशवन्त सिन्हा
1975-77	सी. सुब्रह्मण्यम	2003-2004	जसवन्त सिंह
1977-78	एच.एम. पटेल	2004-2008	पी. चिदम्बरम
1979-80	चरण सिंह	2009-2012	प्रणव मुखर्जी
		2012 से अब तक	पी. दिसम्बरम



विविध (Miscellaneous)

पंचवर्षीय योजना (Five Year Plane)

पहली पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan) 1951-1956

- इस योजना के लक्ष्य थे : शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम-से-कम सम्भव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करना। इसके साथ-साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan) 1956-1961

- प्रो. पी. सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात् लौह एवं इस्पात, अलौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन-निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan) 1961-66

- तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं-स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परन्तु इसके साथ-साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था।

तीन वार्षिक योजनाएँ (Three Year Schemes) 1966-67 से 1968-69

- वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, दो साल तक लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ बनायी गयीं। इस अवधि को 'योजना अवकाश' (Plan Holiday) कहा गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना (Fourth Five Year Plan) 1969-1974

- चौथी योजना के मूल उद्देश्य थे- स्थिरता से साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की 5.5% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और 'गरीबी हटाओ' जोड़ा गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan) 1974-1978

- इसमें दो मुख्य उद्देश्यो अर्थात् गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति

अपनाई गयी। मार्च, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने चार वर्षों के पश्चात ही पाँचवी योजना को समाप्त कर दिया।

छठीवीं पंचवर्षीय योजना (Sixth Five Year Plan) 1980-1985

- छठी योजना दो बार तैयार की गयी। जनता पार्टी द्वारा (1978-83 की अवधि हेतु) 'अनवरत योजना' बनायी गयी। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना, जन-उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। परन्तु जब कांग्रेस सरकार ने नयी छठी योजना (1980-85) तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (Seventh Five Year Plan) 1985-1990

- सातवीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (Eighth Five Year Plan) 1992-1997

- केन्द्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना दो वर्ष देर से प्रारम्भ हुई। आठवीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया, जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे- भुगतान संतुलन का संकट, बढ़ता हुआ ऋण भार, लगातार बढ़ता बजट-घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उद्योगों में प्रतिसार। नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नयी गति प्रदान की जा सके। आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (Ninth Five Year Plan) 1997-2002

- इसमें विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। नौवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य 'वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता' था। नौवीं योजना के विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-
नौवीं योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 प्रतिशत रही। अतः नौवीं योजना अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही।
नौवीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के 3.9 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1 प्रतिशत रही।
विनिर्माण क्षेत्र में भी उपलब्धि 3.9 प्रतिशत रही, जबकि इसका लक्ष्य 8.2 प्रतिशत था।
नौवीं योजना के 14.5 प्रतिशत के निर्यात लक्ष्य के विरुद्ध योजना के पाँच वर्षों के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही। इसी



प्रकार आयात के 12.2 प्रतिशत के विरुद्ध उपलब्धि केवल 6.6 प्रतिशत रही।

केवल निर्माण, सार्वजनिक, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (Tenth Five Year Plan) 2002-2007

लक्ष्य (Target)

- योजना काल के दौरान जी.डी.पी. में वृद्धि दर 8 प्रतिशत पहुँचाना।
- निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 20 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक कम करके 10 प्रतिशत तक लाना।
- वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को सर्वव्यापी बनाना।
- वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दसवर्षीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना।
- साक्षरता में वृद्धि कर इसे वर्ष 2007 तक 72 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत करना।
- वर्ष 2007 तक वनों से घिरे क्षेत्र को 25 प्रतिशत और वर्ष 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- वर्ष 2012 तक पीने योग्य की पहुँच सभी ग्रामों में कायम करना।
- सभी मुख्य नदियों को वर्ष 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को वर्ष 2012 तक साफ करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (Eleventh Five Year Plan) 2007-2012

लक्ष्य (Target)

- जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और इसे 12वीं योजना के दौरान 10% पर बरकरार रखना ताकि 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके।
- कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना।
- रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना।
- साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना।
- 2011-12 तक प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में 2003-04 के 52.2% के मुकाबले 20% की कमी करना।
- 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना।
- बाल मृत्युदर को घटाकर 28 प्रति 1000 व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना।
- प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना।
- 2009 तक सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (Twelfth Five Year Plan) 2012-2017

- राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 2012-17 तक चलने वाली 12वीं योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर को 57वीं एनडीसी की बैठक में यह योजना दी गई। इस योजना में वृद्धि का लक्ष्य 8.2 फीसदी से घटाकर 8.0 फीसदी किया गया है। योजना

के पांच साल में पांच करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। योजना दस्तावेज में कृषि, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। 12वीं योजना में केंद्र का सकल योजना आकार 43 लाख 33 हजार 739 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सकल योजना व्यय 37 लाख 16 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- इससे पहले 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9.0 फीसदी आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखने का सुझाव था। लेकिन, वैश्विक आर्थिक चिंताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था में गहराती सुस्ती के चलते सितंबर 2012 में इसे कम करके 8.2 फीसदी कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आर्थिक वृद्धि 5.7 से 5.9 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले एक दशक में यह सबसे कम आर्थिक वृद्धि होगा।
- मार्च 2011 में समाप्त हुई 11वीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि 7.9 फीसदी रही थी।

12वीं योजना के लक्ष्य (Goals of Twelfth Plan)

- सरकारी कामकाज के ढंग सुधारे जाएँगे इसके लिए नए सिरे से तय किए जाएँगे सरकारी कार्यक्रम
- शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य
- स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जाएगा फोकस, स्वास्थ्य पर खर्च को जीडीपी के 1.3 से बढ़ाकर किया जाएगा 2-2.5 फीसदी
- एफडीआई नीति के उदार बनाकर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति प्रदान करने पर जोर

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास

(Development In Five Year Plans)

कालावधि	लक्ष्य	वास्तविक
पहली योजना (1951-56)	2.1	3.61
दूसरी योजना (1956-61)	4.5	4.27
तीसरी योजना (1961-66)	5.6	2.84
चौथी योजना (1969-74)	5.7	3.30
पाँचवीं योजना (1974-78)	4.4	4.80
छठी योजना (1980-85)	5.2	5.66
सातवीं योजना (1985-90)	5.0	6.01
आठवीं योजना (1992-97)	5.6	6.50
नौवीं योजना (1997-2002)	6.5	5.40
दसवीं योजना (2002-2007)	8.0	7.2
ग्यारहवीं योजना (2007-2012)		



बजट (Budget)

परिणाम बजट एवं निष्पादन बजट

(Outcome Budget & Performance Budget)

इन दोनों को भारत में 2005 में लागू किया गया बजट तैयार कर इसे लागू करना जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उस बजट की समीक्षा है। बजट के माध्यम से तय किये गये लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं एवं साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित साधन एवं संसाधन पर्याप्त है या नहीं इनकी समीक्षा के उद्देश्य से बजट लागू होने के 6 महीने बाद परिणाम बजट तैयार किया जाता है एवं इसके आधार पर वांछनीय संशोधन किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में जब वर्तमान बजट की सफलता एवं असफलता की समीक्षा की जाती है तो इसे निष्पादन बजट कहते हैं। वह अगले वित्तीय वर्ष के बजट के लिए दिशा निर्देश का कार्य करती है।

शून्य आधार बजट (Zero Base budget)

इस प्रक्रिया को भारत में अमेरिका से अपनाया गया। प्रारम्भ से इसे रक्षा मंत्रालय में लागू किया गया (1984)। तत्पश्चात् 1987 में इसे हर सरकारी विभाग एवं मंत्रालयों में लागू कर दिया गया। यह सरकार के गैर-अनिवार्य खर्चों को कम करने का एक उपाय है। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी योजना अथवा परियोजना की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है। इस समीक्षा के दौरान यह देखा जाता है कि क्या यह परियोजना आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से भविष्य में उपयोगी होगी। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में इस परियोजना से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा तो उसी दिन से उस परियोजना अथवा योजना के राजस्व घाटे में से राज्यों को दिये गये अनुदान का यही हिस्सा, जिसे राज्य पूंजीगत निर्माण में प्रयोग कर लेते हैं, घटा दिया जाता है तो बचा हुआ राजस्व घाटा केन्द्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। इस FRBM Act - 2003 को संशोधित कर वित्तीय वर्ष 2011-12 में लागू किया गया।

राजकोषीय उत्तदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003

(Fiscal Responsibility and Budget Management Act - 2003)

➤ 1980 एवं 90 के दशक में सरकार का राजकोषीय स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। अतः घाटों को विधिवत रूप से निरंतर कम करने के उद्देश्य से विजय केलकर के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी इसी समिति ने राजकोषीय घाटे एवं राजस्व घाटों को कम करने के उद्देश्य से कुछ लक्ष्य प्रदान किये। इन लक्ष्यों को संसद में FRBM Act - 2003 के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न थे-

- सरकार अपने गैर-जिम्मेदाराना खर्चों को कम कर व्यय में कटौती करके इसके साथ-साथ कर के आधार को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्ति का प्रयास करे।
- वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को 5% की दर से कम किया जाये।
- 31 मार्च 2009 तक घाटे को घटा कर शून्य कर दिया जाये।

- वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष राजकोषीय घाटे को 0.3% के दर से कम किया जाये।
- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय को घटाकर GDP के 3% तक लाया जाये।
- विगत वर्ष के मुकाबले किसी भी वर्ष सरकार के ऋण में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी न हो।
- प्रत्येक तिमाही के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी संसद में प्रस्तुत की जाये।
- किसी आपात कालीन स्थिति में सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में चूक सकती है।

अर्थोपाय अग्रिम (WMA) (Wages and means Advantages)

जब देश में हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था लागू थी तब भारत सरकार ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. को प्रतिभूति जारी कर देती थी यदि वे प्रतिभूतियाँ खत्म हो जाती थी तो अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ (Ad-hoc treasury bills) जिनकी परिपक्वता की अवधि मात्र 91 दिनों की होती थी, जारी करके बेची जाती थी। यदि वे प्रतिभूतियाँ भी खत्म हो जाती थी अथवा बाजार से ऋण उठाना संभव नहीं रह जाता था तो आर.बी.आई. नये नोट जारी करती थी।

अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा के अंतर्गत ये अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ जारी करने की प्रक्रिया खत्म कर दी गयी। साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया कि सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए नये नोट जारी नहीं किये जायेंगे। इस सुविधा के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही, भारत सरकार एवं आर.बी.आई. यह सुनिश्चित कर लेती है कि घाटे की भरपाई के लिए अधिकतम कितनी प्रतिभूतियाँ जारी की जायेंगी। साथ ही एक राशि सुनिश्चित की जाती है जो प्रतिभूतियाँ को बेचने के उपरान्त अतिरिक्त रूप से आर.बी.आई. सरकार को प्रदान करने का आश्वासन देती है। यदि प्रतिभूतियों को बेचने के उपरान्त भी यदि घाटा-बरकरार रहे, तो आर.बी.आई. सरकार के खर्चों के लिए उसी पूर्व निर्धारित राशि में से अपने संसाधनों के माध्यम से 90 दिनों तक के लिए ऋण प्रदान करती है जिसकी ब्याज दर बैंक दर से 2 प्रतिशत ज्यादा होती है। इसी सुविधा को अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। यदि यह राशि भी खत्म हो जाये तो आर.बी.आई. सरकार को 10 दिनों के लिए अधिविकृष की सुविधा केन्द्र के अलावा आर.बी.आई. 23 अन्य राज्यों को भी प्राप्त कराती है। ये वो राज्य हैं जिनका खाता आर.बी.आई. के पास चलता है।

सरकार के विभिन्न प्रकार के घाटे

(Different Types Of Government Losses)

सरकार के आय और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए अलग-अलग उद्देश्य से अलग-अलग प्रकार के घाटों की गणना की जाती है। ये प्रमुख घाटे निम्नलिखित हैं-

- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
- प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
- मौद्रिक घाटा (Monetised Deficit)
- प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)



(i) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

यह सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। परन्तु इसकी गणना में लिये गये ऋण को आय का हिस्सा नहीं रखते। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सरकार का राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लिए गये कुल ऋण के बराबर होता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% रखा गया था जोकि वास्तव में मात्र 4% ही रहा। वित्तीय वर्ष 2015 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.9% का रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.5% एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3% का रखा गया है।

राजकोषीय घाटा आय में बढ़ोत्तरी के कारण तथा व्यय में कटौती के कारण भी कम होता है। यदि घाटा उतना ही रहे परन्तु सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी हो जाये तो प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घाटा कम दिखता है।

(ii) राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

यह सरकार के राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। यदि राजस्व व्यय अत्यधिक हो जिससे राजस्व घाटा बढ़ रहा हो तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अथवा सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा सूचक नहीं है। यह दर्शाता है कि देश में उपभोग के उद्देश्य से सरकार का व्यय ज्यादा है जिसके कारण सरकार के पास पूंजीगत निर्माण के लिए संसाधनों की कमी उत्पन्न हो सकती है।

(iii) प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

किसी भी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान सरकार के व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ब्याज का यह भुगतान विगत वर्षों में लिये गये ऋण के ऊपर होता है। अतः यह देखने के उद्देश्य से कि विगत वर्षों में लिये गये ऋण के ऊपर होता है। अतः यह देखने के उद्देश्य से कि विगत वर्षों में यदि ऋण न लिये गये होते एवं ब्याज का भुगतान का सरकार के व्यय में कोई भूमिका नहीं होती तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल घाटा कितना होता, प्राथमिक घाटे की गणना की जाती है। अतः प्राथमिक घाटे की गणना के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान वाला हिस्सा घटा देते हैं।

(iv) मौद्रिक घाटा (Monetised Deficit)

इसकी गणना 1997 के बाद से नहीं की जाती है। यह सरकार के घाटे का वह हिस्सा हुआ करता था जिसकी भरपाई आर.बी.आई. नये नोट जारी करके करती थी। चूंकि अब सरकार के घाटे की भरपाई के लिए नये नोट जारी नहीं किये जाते, मौद्रिक घाटे की गणना अब नहीं होती।

(v) प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)

सरकार के कुल व्यय में से राज्यों को दिया गया अनुदान केन्द्र के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। परन्तु प्राप्त किये गये इस अनुदान में से एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकारें पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से खर्च कर देती है।

राजकोषीय प्रणाली (FISCAL SYSTEM)

➤ यह सरकार की कुल आय एवं व्यय से सम्बन्धित है। सरकार की आय को बढ़ाने से एवं व्यय को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जो नीतियाँ बनायी

जाती हैं, उन्हें राजकोषीय नीति कहते हैं। यह नीतियाँ वित्तीय मंत्रालय की जिम्मेदारी होती हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के कुल आय एवं व्यय का सम्पूर्ण लेखा जोखा तथा आगामी वित्तीय वर्ष की कुल आय एवं व्यय का अनुमानित लेखा जोखा संसद में राष्ट्रपति के नाम पर बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- सरकार की आय को मुख्यतः दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है-
 - (i) राजस्व आय
 - (ii) पूंजीगत आय
- उसी प्रकार सरकार के व्यय को भी दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है-
 - (i) राजस्व व्यय
 - (ii) पूंजीगत व्यय

राजस्व आय (Revenue Receipt)

- ये सरकार की वैसी आय है जो न तो किसी परिसम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के रूप में होती है एवं न ही किसी सम्पत्ति की बिकवाली से प्राप्त की जाती है। इनमें निम्नलिखित आय सम्पत्ति है-
 - (i) कर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
 - (ii) ब्याज की प्राप्ति
 - (iii) सरकारी कम्पनियों से लाभांश की प्राप्ति
 - (iv) जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, यातायात, संचार इत्यादि जैसी सेवाओं से होने वाले राजस्व की प्राप्ति
 - (v) जुर्माना
 - (vi) किराये से होने वाला लाभ इत्यादि।

पूंजीगत आय (Capital Receipt)

- यह वैसी आय है जो कि किसी सम्पत्ति की बिकवाली से अथवा स्वयं किसी परिसम्पत्ति के रूप में होती है। इसमें निम्नलिखित आय सम्मिलित हैं-
 - (i) विनिवेश
 - (ii) निजीकरण
 - (iii) भूमि, कार्यालय, रक तदान, गृह इत्यादि जैसी सम्पत्तियों की बिकवाली
 - (iv) ऋण की प्राप्ति
 - (v) दिये गये ऋण के मूलधन की वसूली

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

- ये सरकार के वैसे व्यय हैं जिससे न तो किसी सम्पत्ति का निर्माण होता है और न किसी सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति के रूप में होते हैं। इसमें सरकार के निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं-
 - (i) लिए गये ऋण पर ब्याज का भुगतान
 - (ii) सरकार द्वारा प्रदान किये गये परिदान
 - (iii) सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान



- (iv) रक्षा के लिए किया गया व्यय
- (v) राज्यों को दिया गया वह अनुदान जिसकी नहीं की जा सकती
- (vi) कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशासन
- (vii) प्राकृतिक आपदाओं से पिटने के लिए किया गया व्यय
- (viii) समाजकल्याण से सम्बंधित योजनाएँ

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

- ये वैसे व्यय है जिनसे या तो सम्पत्ति का निर्माण होता है या वे स्वयं सम्पत्ति के रूप में अथवा परिसम्पत्ति के रूप में होते हैं। इसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है-
 - (i) बुनियादी निर्माण जैसे कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण इत्यादि।
 - (ii) सामाजिक बुनियादी निर्माण जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल इत्यादि का निर्माण।
 - (iii) कारखानों की स्थापना
 - (iv) भवन अथवा कार्यालयों का निर्माण, रेलवे स्टेशन बंदरगाह इत्यादि का निर्माण
 - (v) भूमि अधिग्रहण
 - (vi) सरकार द्वारा दिया गया ऋण
- राजस्व व्यय में ऐसे कई व्यय हैं जिससे पूंजी व्यय भी सम्मिलित होते हैं। अतः गणना के दौरान इन दोनों व्यय को अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रक्षा के क्षेत्र में लड़ाकू विमान, युद्ध पोत इत्यादि का अधिग्रहण पूंजीगत व्यय में आयेगा जबकि इनके परिचालन का व्यय राजस्व व्यय में आयेगा। इन सभी प्रकार के व्ययों में से जिन खर्चों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूर्व नियोजित किया जाता है। उन्हें नियोजित व्यय कहते हैं एवं अन्य सभी व्ययों को अनियोजित व्यय कहते हैं (राज्यों को दिये गये अनुदान के अलावा सरकार का सर्वाधिक व्यय व्याज के भुगतान में होता है।)

हीनार्थ प्रबंधन (Hinarth Management)

- यदि सरकार की आय उसके व्यय से कम रह जाये, तो सरकार घाटे में कहलाती है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार घरेलू बाजार से ऋण प्राप्त करती है। सरकार के घाटे की इस भरपाई के लिए बाजार से ऋण उठाने का कार्य आर.बी.आई. करती है। इस पूरी प्रक्रिया में आर.बी.आई. बाजार में बिल तथा बॉण्ड दोनों ही रूपों में प्रतिभूतियाँ बेचकर ऋण प्राप्त करती है।

राजकोषीय शुद्धिकरण (Fiscal Consolidation)

किसी भी देश में, उस देश के राजकोषीय स्वास्थ्य का उस देश की साख पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय घाटों के कारण साख पर नकारात्मक पड़ता है। ऐसे में उस देश में विदेशी निवेश तथा उस देश के लिए किसी अन्य विदेशी स्रोत से ऋण लेना कठिन हो जाता है।

भारत एक विकासशील देश है जिसमें सरकार की भूमिका अत्यधिक रही है। आजादी के समय से ही निजी निवेश के आभाव के कारण सरकार को औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भी निवेश करना पड़ा। इसके साथ-साथ अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण परियोजनाओं के माध्यम से अथवा समाज कल्याण योजनाओं के माध्यम से समाज के निम्न वर्ग को मुख्यधारा में लाने के प्रयास भी किया गया। सरकार की भूमिका आधारभूत बुनियादी निर्माण में भी रही। अतः सरकार के व्यय में बढ़ोत्तरी बरकरार रही, देश में बेरोजगारी एवं गरीबी के कारण राजस्व की प्राप्ति निम्न रही। जागरूकता की कमी के कारण कर की प्राप्ति में भी कमी देखी गयी ऐसे में राजकोषीय एवं राजस्व घाटे का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। अतः राजकोषीय शुद्धिकरण के उद्देश्य से सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है-

- (i) अधिकारी तन्त्र के आकार में कमी
- (ii) मंत्रालयों के आकार में कमी
- (iii) सरकार द्वारा प्रदान किये गये परिदान में कटौती
- (iv) गैर-अनिवार्य योजनाओं एवं परियोजनाओं की समाप्ति
- (v) धन के आवंटन से सम्बंधित भ्रष्टाचार एवं दुरुपयोग की रोकथाम
- (vi) सरकार द्वारा किये गये लाभ का उपभोगताओं तक प्रत्यक्ष हस्तान्तरण
- (vii) जन वितरण प्रणाली जैसे खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित व्यवस्था को दुरुस्त करना

राजकोषीय शुद्धिकरण राजकोषीय स्वास्थ्य को दुरुस्त करने की प्रक्रिया को सम्बोधित करता है। इस संदर्भ में जो सुनहरा नियम है वह यह प्रतिपादित करता है कि सरकार के राजस्व घाटे शून्य किये जाये एवं ऋण की प्राप्ति मात्र पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से ही की जाये।

भारतीय कृषि (Indian Agriculture)

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका (Role of Agriculture in the National Economy)

1. राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा (Share of Agriculture in National Income)

- वर्तमान में कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14% का योगदान करता है। 1950-51 में यह जी.डी.पी. का 55.4% था।
- राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सम्बद्ध उद्योगों का हिस्सा काफी अधिक है। हालांकि यह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

2. रोजगार का स्रोत (Source of Employment)

- भारत में श्रम शक्ति का लगभग 55% भाग कृषि से जीविका पाता है।
- यह बहुत निराशाजनक है कि 1951-2001 के दौरान, कृषि श्रमिकों का अनुपात 20% से बढ़कर 27% हो गया; जबकि कृषकों की मात्रा 50% से घटकर 32% हो गई।



3. औद्योगिक विकास का स्रोत (Source of Industrial Development)

- कृषि से प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। सूती और पटसन वस्त्र, उद्योग, चीनी, चाय, वनस्पति तथा बागान उद्योग, ये सब कृषि पर निर्भर है। हस्तकरघा बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल मिलता है।
- विनिर्माण-क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50% इस क्षेत्र से आता है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि की महत्ता (Importance of Agriculture in International Trade)

- भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कृषि वस्तुएँ हैं।
- मोटे तौर पर कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 10-15% है तथा कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% है।

5. आर्थिक आयोजन में कृषि की भूमिका (Role of Agriculture in Economic Planning)

- कृषि भारत की परिवहन-व्यवस्था का मुख्य अवलम्ब है क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना व ले जाना है।
- अन्तर्देशीय व्यापार की वस्तुएँ भी मुख्यतः कृषि वस्तुएँ ही हैं।
- अच्छी फसल होने पर किसानों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे उद्योग-निर्मित वस्तुओं की माँग और कीमतें बढ़ जाती हैं। परिणामतः उद्योगों की प्रगति होने लगती है।
- भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है।
- अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत सकल उर्वरक उपभोग में विश्व में चौथा स्थान रखता है।
- भारत में खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। वर्तमान में कृषि में प्रयुक्त भूमि का 65.8% भाग खाद्यान्न फसलों में तथा शेष 35.2% भाग व्यापारिक फसलों में प्रयोग किया जा रहा है।
- दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में 110.5 मिलियन मी. टन प्रति वर्ष से अधिक दुग्ध उत्पादन होता है।
- भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पाद का हिस्सा 26% है।
- हरित क्रान्ति का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से है। इस क्रान्ति का श्रेय अमेरिका के डॉ. नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को जाता है।
- दुध के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रान्ति का नाम दिया गया। श्वेत क्रान्ति गति को और तेज करने के उद्देश्य से 'आपरेशन फ्लड' नामक योजना आरम्भ की गयी। इस क्रान्ति का रेय भारत के डॉ. वर्गीस कुरियन को जाता है।

■ कृषि उत्पादक बोर्ड (Agriculture Producer Board)

बोर्ड	मुख्यालय
टी बोर्ड	कोलकाता
तम्बाकू बोर्ड	गुंटुर
मसाला बोर्ड	कोच्चि
कॉफी बोर्ड	बंगलौर
रबड़ बोर्ड	कोट्टायम
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	आनंद

■ उत्पादन सम्बन्धित क्रान्तियाँ (Production Related Revolution)

हरित	खाद्यान्न (अनाज-गेहूँ, चावल, मक्का आदि) उत्पादन
काली	पेट्रोलियम उत्पादन
नीली	मछली उत्पादन
भूरी	चमड़ा/गैर-परंपरागत ईंधन/ कोको उत्पादन
सुनहरी	बाग (उद्यान)/शहद उत्पादन
सुनहरा रेशा	जूट-उत्पादन
सलेटी	खाद (उर्वरक) उत्पादन
गुलाबी	प्याज/औषधि/झींगा उत्पादन
लाल	मॉस/टमाटर उत्पादन
वृत्ताकार	आलू उत्पादन
चमकीला रेशा	कपास उत्पादन
चमकीला	अंडा/कुक्कुट उत्पादन
श्वेत	दुग्ध उत्पादन
पीली	खाद्य तेल उत्पादन
सदाबहार	कृषि

भारतीय के प्रमुख उद्योग (Main Industries of India)

■ प्रमुख उद्योगों की स्थापना (Establishment of Main Industries)

उद्योग	आधुनिक तरीके के प्रथम कारखाने का स्थापना वर्ष एवं स्थान
सूती वस्त्र	1818, कोलकाता
जूट	1855, शिक्षा (प. बंगाल)
लोहा इस्पात	1870, कुल्टी (प. बंगाल)
चीनी उद्योग	1900, बिहार
सीमेण्ट	1904, चेन्नई (मद्रास)
साइकिल	1918, कोलकाता
कागज	1812, सेरामपुर (प. बंगाल)
उर्वरक	1906, तमिलनाडु



■ **सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने (Public Sector Steel Factories)**

स्थान	तथ्य
राउरकेला (उड़ीसा)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
भिलाई (मध्य प्रदेश)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
दुर्गापुर (प. बंगाल)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1962 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
बोकारो (झारखण्ड)	एशिया का सबसे बड़ा संयन्त्र। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1973 ई. में उत्पादन आरम्भ हुआ।
बर्नपुर (प. बंगाल)	निजी क्षेत्र संयन्त्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिगृहीत यह संयन्त्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ।
विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2256 करोड़ रुपये की सरकारी लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया।
सलेम (तमिलनाडु)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया।
भद्रावती (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया।
विजयनगर (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया।

■ **विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रमुख स्थान (Major Locations Associated With Different Industries)**

स्थान	महत्वपूर्ण उद्योग
असम घाटी	स्थानीय चाय, चावल, तिलहन का प्रसंस्करण
दार्जिलिंग क्षेत्र	स्थानीय चाय का प्रसंस्करण
उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से सटा उत्तर बिहार	स्थानीय गन्ने से चीनी का निर्माण
दिल्ली-मेरठ	स्थानीय गन्ने से चीनी का निर्माण, कुछ वस्त्र, रसायन एवं इंजीनियरिंग सामान

इन्दौर-उज्जैन	स्थानीय बाजार के लिए सूती वस्त्र, हस्तशिल्प
नागपुर-वर्धा	लघु कपास वस्त्र, लौह ढलाई खाना, रेलवे एवं सामान्य इंजीनियरिंग सामान, काँच एवं मिट्टी निर्माण
धारवाड़-बेलगाम	स्थानीय एवं अन्य बाजार के लिए सूती वस्त्र, रेलवे एवं सामान्य इंजीनियरिंग सामान
गोदावरी-कृष्णा डेल्टा	स्थानीय तम्बाकू, गन्ना, चावल एवं तेल, सीमेन्ट, लघु वस्त्र
कानपुर	वस्त्र एवं पोशाक, वृहद् आधुनिक चर्म उद्योग, चर्म कर्म, जूता निर्माण, सैनिकों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इन सभी की स्थापना की गई है।
चेन्नई	वस्त्र, हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएँ, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री
मालाबार-कोल्लम-त्रिचूर	काजू प्रसंस्करण, नारियल एवं तिलहन प्रसंस्करण, नारियल के छिलके से वस्तु निर्माण, साबुन, वस्त्र, विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प
शोलापुर वस्त्र निर्माण	स्थानीय मिट्टी से उत्पादित कपास पर आधारित महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग केन्द्र

■ **सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम (Public Sector Industrial Undertakings)**

नाम	स्थान
हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड	रसायनी (महाराष्ट्र)
■ एण्टीबायोटिक संयन्त्र (आई. डी. पी. एल.)	ऋषिकेश (उत्तराखंड)
■ संश्लेषित दवा परियोजना	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
■ सर्जरी उपकरण संयन्त्र	चेन्नई
हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक लिमिटेड	पिम्परी (महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	अवलाय (केरल) एवं दिल्ली
भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	नंगल (पंजाब), सिन्दरी (झारखण्ड), ट्राम्बे (महाराष्ट्र), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), नामरूप (असम), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)



भारी जल संयन्त्र	नेवेली, (तमिलनाडु), नाहरकटिया (असम), राउरकेला (ओडिशा), ट्राम्बे (महाराष्ट्र)
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	जलाहाली (कर्नाटक), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	रानीपुर (उत्तराखण्ड), रामचन्द्रपुर (आन्ध्र प्रदेश), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), भोपाल (मध्य प्रदेश)
भारत हैवी प्लेट एवं वैसेल्स लिमिटेड	विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश)
सेन्ट्रल मशीन टूल्स	बंगलौर
चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स	चितरंजन (पश्चिम बंगाल)
कोचीन शिपयार्ड	कोच्चि
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स	मरवाडीह, वाराणसी (उ. प्र.)
गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड	कोलकाता
हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बंगलौर
हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड	भोपाल
भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	राँची
भारी मशीन निर्माण संयन्त्र	राँची
भारी वाहन कारखाना	अवाड़ी (तमिलनाडु)
हिन्दुस्तान केबल्स कारखाना	रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल)
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	जलाहाली (कर्नाटक) बंगलौर के समीप, पिंजौर (हरियाणा), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), कलामसारी (केरल)
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	विशाखापट्टनम एवं कोच्चि
भारतीय टेलीफोन उद्योग	बंगलौर, नैनी (उत्तर प्रदेश), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), मानकपुर, गोंडा (उत्तर प्रदेश)
इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	कोटा (राजस्थान), पालक्कड़ (केरल)
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	पेरम्बूर (तमिलनाडु), कोटकपूरा (पंजाब)
भारतीय मशीन टूल निगम	अजमेर (राजस्थान)

मशीन टूल मॉडल कारखाना	अम्बरनाथ, मुम्बई
मझगाँव डॉक्स लिमिटेड	मुम्बई
खनन एवं सम्बद्ध उपकरण निगम लिमिटेड	दुर्गापुर
नाहन ढलाईखाना	सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
राष्ट्रीय उपकरण कारखाना	कोलकाता
प्राग टूल्स कापेरेशन	हैदराबाद निगम लिमिटेड
तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड	तुंगभद्रा (कर्नाटक)
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	हैदराबाद
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	उदयपुर (राजस्थान)
भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	कोरबा (मध्य प्रदेश), रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	अग्निगुडला (आन्ध्र प्रदेश), दारिबा (राजस्थान), मलाजखण्ड (मध्य प्रदेश), राखा (झारखण्ड)
भारत रसोई कोयला लिमिटेड	धनबाद (झारखण्ड)
भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	कोलार (कर्नाटक)
कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड	कोलकाता
नेवेली लिग्नाइट निगम	नेवेली (तमिलनाडु)
जस्ता प्रगलक	जवार (राजस्थान)
राष्ट्रीय अखबारी कागज कारखाना लिमिटेड	नेपानगर (मध्य प्रदेश)
भारतीय तेलशोधक लिमिटेड	बरौनी (बिहार)
	नूनमाटी (असम)
कोचीन तेलशोधक कारखाना	कोच्चि (केरल)
कोयली तेलशोधक कारखाना	कोयली (गुजरात)
भारतीय विस्फोटक कारखाना	गोमिया, हजारीबाग (झारखण्ड)
हिन्दुस्तान फोटोफिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड	ऊटकमण्ड, (तमिलनाडु)

नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित की संख्या 3 है- (i) परमाणु ऊर्जा (ii) रेल परिवहन एवं (iii) परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रीमण्डलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कम्पनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है।



- संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 से अपनाई गई है।
- 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति दी गई है।
- विनिवेश या अपनिवेश (disinvestment) का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है।
- सन् 1996 ई. में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जी. वी. रामकृष्ण थे।

औद्योगिक क्षेत्र	विदेशी निवेश की सीमा
सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र	49%
निजी बैंकिंग क्षेत्र	74%
गैर बैंकिंग वित्तीय कं.	100%
बन्दरगाह निर्माण	100%
विद्युत् एवं ऊर्जा (परमाणु ऊर्जा छोड़कर)	100%
पर्यटन	100%
दूरसंचार	74%
लघु उद्योग क्षेत्र	100%
पेट्रोलियम (रिफाइनिंग नई इकाईयाँ)	100%
दवा उद्योग	100%
नागरिक उड्डयन	49%
बीमा क्षेत्र	49%
कोयला खनन	100%
पेंशन	49%

■ निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ (Personalized Public Sector Companies)

सार्वजनिक कम्पनी	निजी क्षेत्र की कम्पनी, जिसे बेचा गया
मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
बाल्को	स्टारलाइट इंडस्ट्रीज
हिन्दू टेलीप्रिन्ट्स	एचएफसीएल
विदेश संचार निगम लिमिटेड	टाटा समूह की पैनाटोन फिनवैस्ट
सीएससी	टाटा संघ
पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	जुआरी मारोक फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड

आयल कॉर्पोरेशन (Oil Corporation)

1. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.)

- 1964 में इण्डियन रिफाइनरी लि. तथा इण्डियन ऑयल कं. को शामिल करके स्थापित की गई।

2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बी.पी.सी.)

- बर्मा शैल का अधिग्रहण करके 1976 में स्थापित की गई।

3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.)

- ई. एम.एस. ओ. तथा कालटैक्स को मिलाकर 1974 में स्थापित की गई।

प्रमुख तेल क्षेत्र (Main Oil Sector)

- गुजरात कैम्बे, अंकलेश्वर, अलपद, समन्द, कलोरी, विनाद
- असम डिग्बोई, रूद्रसागर तथा सिबसागर
- पंजाब-आदमपुर, जूनौरी तथा ज्वालामुखी

महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र (Important Oil Production Area)

- असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पं. बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, आन्ध्र प्रदेश तथा समुद्र की ओर बॉम्बे हाई, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गुजरात।

उद्योगों से जुड़े विभिन्न संगठन

(Different Organizations Related to Industries)

1. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.)

- यह भारतीय उद्योगों के उत्पादों के लिए मानक तैयार करने हेतु एक अर्द्ध सरकारी संस्था है। इसे वर्ष 1947 में स्थापित किया गया और यह विभिन्न उत्पादों पर गुणवत्ता चिह्न अर्थात् आई. एस. आई. चिह्न आवंटित करता है।

2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन.पी.सी.)

- यह एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1958 में उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी। यह उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन सम्बन्धी जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता के लिए एन.पी.सी. पुरस्कार दिए जाते हैं।

औद्योगिक रूग्णता (Industrial Sickness)

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक औद्योगिक इकाई उस स्थिति में रूग्ण (sick) मानी जाएगी जब इसे एक वर्ष नकद हानियाँ हो जाती हैं और आगामी दो वर्षों में भी नकद हानियाँ जारी रहने की सम्भावना होती है।



औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड**(Board for Industrial and Financial Reconstruction)**

- 1985 में औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार हेतु गठित तिवासी समिति की सिफारिशों के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम [Sick Industrial Companies (Special Provision) Act-SICA 1985] पारित किया गया।
- इसके बाद बृहत् और मध्यम क्षेत्र की बीमार और सम्भावित बीमार कम्पनियों के पुनरुत्थान, उधार उपचार, पुनर्संगठन, पुनर्स्थापन आदि के उद्देश्य से 12 जनवरी, 1987 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड (Board for Industrial and Financial Reconstruction) की स्थापना बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अन्तर्गत की गई।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान**(Main Institutions For Providing Industrial Finance)**

- स्वतन्त्रता के पश्चात् उद्योगों के विकास के लिए विकास बैंकों की स्थापना की गई। वर्तमान के उद्योगों के विकास के लिए छः विकास बैंक कार्यरत हैं। ये विकास बैंक निम्नलिखित हैं-
 - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
 - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
 - भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनियोग निगम (ICICI)
 - भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (IRCI)
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
 - भारतीय शिपिंग ऋण एवं निवेश कम्पनी (SCICI)

नवरत्न (Navratnas)

- विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले देश के कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने देश के 'नवरत्नों' के रूप में मान्यता दी है।
- इन्हें 1,000 करोड़ रुपये या अपनी नेटवर्थ के 15% तक के सौदे करने की स्वायत्तता सरकार द्वारा दी गई है-
 - नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
 - ऑयल इंडिया लिमिटेड
 - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
 - हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
 - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
 - नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO)
 - महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
 - भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BEL)
 - हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड (HAL)
 - पावर फाइनेंस लिमिटेड (PFC)
 - नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC)
 - पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 - रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- इसके अतिरिक्त 3 अक्टूबर, 1997 को सरकार ने लाभ में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 97 उपक्रमों को मिनी-रत्न अथवा लघु रत्न का दर्जा प्रदान किया। अब यह संख्या 62 हो गई है।

महारत्न (Maharatna)

- महारत्न योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े सरकारी उपक्रमों को शक्ति प्रदान करना है ताकि वे अपने परिचालन का विस्तार कर सकें और वैश्विक स्तर की प्रमुख कंपनियां बन सकें। महारत्न कंपनियों के निदेशक मंडल के पास नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीबीएसई) को मिली सभी शक्तियों के अलावा संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों में निवेश और निदेशक मंडल से नीचे के स्तर पर नए पदों के निर्माण का अधिकार होगा। महारत्न का दर्जा हासिल होने से कंपनी का निदेशक मंडल बिना सरकारी मंजूरी के 5,000 करोड़ रुपये तक के निवेश का फैसला ले सकेगा जबकि फिलहाल यह सीमा 1,000 करोड़ रुपये की है।
- महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कंपनी का पिछले तीन साल में सालाना शुद्ध मुनाफा 5,000 करोड़ रुपये होना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ और कारोबार 25,000 करोड़ रुपये का होना आवश्यक है। साथ ही कंपनी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध भी होनी चाहिए।
- निम्न कंपनियाँ सरकार द्वारा तय महारत्न की कसौटी पूरी करती हैं-
 - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
 - तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
 - भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम (SAIL)
 - भारतीय तेल निगम (IOC)
 - कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL)
 - भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
 - भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL)

**बेरोजगारी और निर्धनता
(Unemployment And Poverty)****बेरोजगारी (Unemployment)**

बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति की ओर इंगित करती है जिसमें किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता अर्थात् वह कोई ऐसी गतिविधि नहीं करता जिसके बदले उसे पैसे अथवा वस्तु के रूप में आमदनी हो, और वह ऐसी गतिविधि की तलाश में होता है।

बेरोजगारी के प्रकार (Types of Unemployment)

- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)**
सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप कुछ उद्योगों का विस्तार होता है, जबकि कुछ अन्य उद्योग शनैः-शनैः संकुचित होते जाते हैं। यदि भौगोलिक एवं तकनीकी दृष्टि से श्रम पूर्णतः गतिशील हो तो संकुचित होने वाले उद्योगों के श्रमिक नए उद्योगों में खपाए जा सकते हैं,



परन्तु वास्तव में श्रम इन दृष्टियों से पूर्णतः गतिशील नहीं होता, जिसके कारण कुछ बेरोजगारी उत्पन्न होती है। औद्योगिक जगत् में इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का है।

- **अल्प रोजगार (Under-employment)** : इसके अन्तर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किन्तु इनको अपनी क्षमतानुसार काम नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता। इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं, जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है।
- **छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment)** : इसके अन्तर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती अर्थात् यदि उन श्रमिकों को उस कार्य से निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इन श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है। कृषि में इस प्रकार की अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता है।
- **खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)** : इससे तात्पर्य उस बेरोजगारी से है, जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को बिना किसी कामकाज के रहना पड़ता है। उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता है। भारत में बहुत से श्रमिक गाँवों से शहरों की तरफ काम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, किन्तु काम उपलब्ध न होने के कारण वहाँ बेरोजगार पड़े रहते हैं। इसके अन्तर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण (अदक्ष) बेरोजगार श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है।
- **शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)** : शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उनकी कार्यकुशलता (क्षमता) भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किन्तु उनकी अपनी योग्यतानुसार कार्य नहीं मिलता तथा वे बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई है।
- **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)** : इसके अन्तर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि में सामान्यतः 7-8 माह ही काम चलता है तथा शेष महीनों में खेत में व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है।
- **शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)** : शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पायी जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है।
- **ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)** : इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के सही आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

निर्धनता (Poverty)

- देश में निर्धनता अनुपात व निर्धनों की संख्या के संबंध में ताजा आँकड़े योजना आयोग द्वारा 19 मार्च, 2012 को जारी किए गए हैं। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले के आधार पर 2009-10 के लिए यह आँकड़े जारी किए गए हैं। इससे पूर्व इस फॉर्मूले द्वारा निर्धनता संबंधी आँकड़े 2004-05 के लिए जारी किए गए थे। तेंदुलकर फॉर्मूले में निर्धनता रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के बजाए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग-अलग निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 672.8 रुपए प्रति माह व शहरी क्षेत्रों में 859.6 रुपए प्रति माह के उपभोग को जहाँ 2009-10 में निर्धनता रेखा की पहचान के लिए निर्धारित किया गया है, वहीं अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओडिशा में जहाँ यह 567.1 रुपए (न्यूनतम) है, वहीं बिहार में 655.6 रुपए, छत्तीसगढ़ में 617.3 रुपए, पंजाब में 830 रुपए तथा नागालैंड में यह सर्वोच्च 1016.8 रुपए है। शहरी क्षेत्रों में भी यह न्यूनतम ओडिशा में 736 रुपए है जबकि उत्तर प्रदेश में यह 799.9 रुपए, दिल्ली में 1040.3 रुपए तथा नागालैंड में यह सर्वोच्च 1147.6 रुपए निर्धारित किया गया है।

■ न्यूनतम निर्धनता अनुपात वाले राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र (State With Lowest Poverty Ratio/Union Territory)

राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र		निर्धनता अनुपात (% में)	
अंडमान निकोबार		0.4	
पुदुचेरी		1.2	
लक्षद्वीप		6.8	
गोवा		8.7	
चंडीगढ़		9.2	
जम्मू-कश्मीर		9.4	
हिमाचल प्रदेश		9.5	
सर्वोच्च निर्धनता अनुपात वाले राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र		निर्धनों का सर्वाधिक संख्या वाले राज्य	
राज्य/केंद्रशासित क्षेत्र	निर्धनता अनुपात (% में)	राज्य	निर्धनों की संख्या (लाख में)
बिहार	53.5	उत्तर प्रदेश	737.9
छत्तीसगढ़	48.7	बिहार	543.5
मणिपुर	47.1	महाराष्ट्र	270.8
झारखंड	39.1	मध्य प्रदेश	261.8
दादरा एवं नगर हवेली	39.1	पं. बंगाल	240.3



महत्त्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कार्यक्रम (Important Poverty Alleviation And Program)

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana)

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल, 1999 को प्रारम्भ की गई। इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नांकित 6 योजनाओं का विलय किया गया है- (1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP), (2) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), (3) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA), (4) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA), (5) गंगा कल्याण योजना (GKY) तथा (6) दस लाख कुआँ योजना (MWS)
- अब उपर्युक्त कार्यक्रम अलग से नहीं चल रहे हैं। इस योजना में पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों की शक्तियों और कमजोरियों का ध्यान रखा गया है।

2. प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (Prime Minister's Scheme)

- ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से वर्ष 2000-01 में प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना घोषित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे पाँच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है।
- प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) : वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या सहित सभी ग्रामवासियों को सभी मौसमों में अच्छी रहने वाली सड़कों के माध्यम से सड़क सम्पर्क सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई।
- प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) : ग्रामीण स्तर पर लोगों के स्थायी निवास को विकसित करने तथा ग्रामीण गरीबों की बढ़ती हुई आवास सम्बन्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 लाख आवासों का निर्माण करने की योजना।
- प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (पेयजल आपूर्ति परियोजना) : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटन का कम-से-कम 25 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मरू विकास कार्यक्रम/सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संरक्षण, जल प्रबन्धन, जल भराई तथा पेयजल संसाधनों को कायम रखने के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाना है।

3. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Grameen Rozgar Yojana)

- प्रधानमन्त्री द्वारा इस योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2001 को लाल किले की प्राचीर से की गई थी, किन्तु इसका शुभारम्भ प्रधानमन्त्री द्वारा 25 सितम्बर, 2001 को फरह (जिला-मथुरा) से किया गया जिसके लिए

रोजगार आश्वासन योजना (EAS) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) को एक में मिला दिया गया था। ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली 10 हजार करोड़ रुपये वार्षिक की केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी है।

4. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (Swaran Jayanti Shahari Rozgar Yojana-SJSRY)

- स्वतन्त्रता के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण की एक नई योजना प्रारम्भ की। स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना (SJSRY) नाम से प्रारम्भ यह योजना 1-12-1997 से लागू की गई। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पहले से क्रियान्वित की जा रही तीन योजनाओं-नेहरू रोजगार योजना (NRY), निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (Urban Basic Services for the Poor-UBSP) तथा प्रधानमन्त्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना (Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme-PMIUPEP) को इसी नई योजना में शामिल कर दिया गया है।

5. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)

- प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को अपने 76वें जन्मदिवस के अवसर पर दो नई योजनाओं का शुभारम्भ किया। इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना नाम से प्रारम्भ की गई। इसके तहत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 25 किग्रा खाद्यान्न 2 प्रति किग्रा गेहूँ तथा ₹3 प्रति किग्रा चावल उपलब्ध कराये जाएँगे।

6. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

- यह योजना 9 मार्च, 1999 को आरम्भ की गई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
- शुरूआत में इस योजना के अन्तर्गत केवल वे ही वरिष्ठ नागरिक आते थे जिन्हें योग्य होने के बावजूद किन्हीं कारणों से वृद्ध पेंशन नहीं मिल पाती थी। बाद में इस योजना में वृद्ध पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया।
- योजना के अन्तर्गत आने वाले नागरिकों को ₹2 प्रति किग्रा गेहूँ तथा ₹3 प्रति किग्रा चावल, की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग योजना (National Highway Scheme)

- प्रधानमन्त्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को घोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ-साथ बड़ी मात्रा में 'रोजगार के अवसर' भी उपलब्ध कराना है। यह योजना स्वतन्त्र भारत की एक अति महत्त्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना होगी, जिसमें लाखों मानव दिवसों का श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना पर 55 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जाएँगे।



8. प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना (Prime Minister's Rozgar Yojna)

- शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 अक्टूबर, 1993 से प्रारम्भ की गई प्रधानमन्त्री की रोजगार योजना (PMRY) के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान उद्योग सेवा तथा कारोबार में सात लाख लघुतर इकाइयाँ (Tiny Units) स्थापित करके लगभग 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

**राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (नरेगा)
(National Rural Guarantee Act)**

प्रारंभ : 2 फरवरी, 2006 (आन्ध्रप्रदेश के वान्दावाली जिले के अनन्तपुर गाँव से)

एक्ट : नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट गारंटी अधिनियम (सितम्बर, 2005)

नीति निर्माता : जीन ड्रेज (बेल्जियम के अर्थशास्त्री)

क्रियान्वयन : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

लागू : शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुई, अप्रैल, 2008 से यह 614 जिलों में लागू है।

विलय : सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना + काम के लिए अनाज योजना।

वित्तीय सहयोग : केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90 : 10 के अनुपात में दी जाती है।

योजना का प्रारूप : प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार। इसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी।

15 दिन का रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थाई अपंगता की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा 25000 रु. की राशि दी जाएगी।

कार्य की अवधि : 07 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल घर के 05km के भीतर हो। दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी।

नरेगा का नाम 2 अक्टूबर, 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा-महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है।

योजनाएँ : संक्षिप्त में (Schemes : In Short)

मनरेगा	2 फरवरी, 2006	ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार देना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1 अप्रैल, 1999	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2009-10	50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले ग्रामों का विकास
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1977-78	मरुभूमि क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2005	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	25 सितंबर, 2001	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	1 दिसंबर, 1997	शहरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2005-06	शहरी निर्धनों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना
प्रधानमंत्री रोजगार योजना	2 अक्टूबर, 1993	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
मिड डे मील योजना	15 अगस्त, 1995	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना
जनश्री बीमा योजना	10 अगस्त, 2000	बीमा सुविधा उपलब्ध कराना
पॉपुलेशन फर्स्ट योजना	2002	जनसंख्या वृद्धि को कम करना
निर्मल भारत योजना	2002	भारत को मलिन बस्ती से मुक्त करना
भारत निर्माण योजना	2005	ग्रामीण संरचना को मजबूत बनाना
इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना	2010	ग्रामीण इलाकों में जच्चा-बच्चा को सुविधा प्रदान करना
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2007	स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना

प्रधानमंत्री जनधन योजना (Prime Minister's Plan)

इसका शुभारंभ 28 अगस्त 14 को हुआ। यह वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। इसके अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 26 जनवरी 15 तक 7.5 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया एवं पहले ही दिन कुल 77 हजार शिविरों के माध्यम से 1.5 करोड़ बैंक खाते प्रदान किये गये जो कि एक कीर्तिमान है।

इस योजना के अंतर्गत पहचान पत्र से संबंधित नियमों को आसान बनाया गया (Know you customer Arm- KYC)। इसके अंतर्गत पारम्परिक पहचान पत्रों के साथ-साथ मनरेगा कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में वैध मान लिया गया। यदि यह भी उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा लिखित प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इस योजना के अंतर्गत उन ग्राहकों को जिनके पास अब तक बैंक खाता न हो No files A/C / मौलिक खाता प्रदान किया जायेगा।

रूपे Payment Getaway एक प्रदान करने वाली कम्पनी है जिसकी स्थापना National Payment Co-operation of India ने की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। यह खाता खाताधरक को शून्य जमा राशि पर प्रदान किया



जायेगा। खाताधारक के एक लाख रुपये तक की बीमा सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि खाता 26 जनवरी 2015 से पूर्व प्राप्त किया गया हो तो ₹ 30,000 का अतिरिक्त बीमा प्राप्त होगा। यदि खाता 6 महीनों तक जीवित रहे तथा यह आधार से जुड़ा हो तो खाताधारक को ₹ 5,000 तक की अधिविकर्ष सुविधा (Overdraft) प्राप्त होगी।

किसी भी योजना की तरह जन-धन योजना के कुछ नकारात्मक पक्ष एवं सकारात्मक पक्ष हैं। जन-धन योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रारम्भ में ऐसे लोगों ने भी खाता खुलवाया जिनके पास पहले से ही बैंक खाता उपलब्ध था। साथ ही कुल खातों का एक बहुत बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रह गया एवं उसमें किसी भी प्रकार की जमा राशि जमा नहीं हुई। ऐसे खातों से बैंकों के संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है एवं उनका व्यय बढ़ता है। साथ ही पहचान पत्रों के संबंधित नियमों को आसान बनाने से बैंकों के वित्तीय स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अधिविक के रूप में दी गयी राशि की वसूली से सम्बन्धित कोई भी अतिरिक्त प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं। ऐसे में बैंकों के गैर-निष्पादकारी परिसम्पत्तियों (NPA) के बढ़ने का खतरा है।

परन्तु इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष भी हैं। यह देश की वैसी आबादी को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सफल रही है जो अब तक बैंकों के सम्पर्क में नहीं थे। इससे बैंकों में पैसा जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा एवं घरों में रखा हुआ पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगा। यह बैंकों की निर्भरता आर.बी.आई. पर कम करेगी एवं आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बैंक खाता प्रदान करने के बाद भी परिदान का प्रत्यक्ष वितरण (Direct Benefit Transfer) जैसी सुविधाओं को प्रदान किया जा सकेगा। बैंक खातों के अभाव में देश के एक-एक नागरिक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को लागू करना असंभव होता। बैंक खातों के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत लाभ उन्हीं श्रमिकों तक प्रत्यक्ष रूप में पहुँच सकेगा जो इसके हकदार हैं।

भुगतान बैंक/ पेमेंट बैंक (Payment Bank / Payment Bank)

आर.बी.आई. ने पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से नवम्बर 2014 में दिशा निर्देश जारी किये। इसके आधार पर कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 11 को पेमेंट बैंक की स्थापना हेतु मंजूरी दी गयी। भुगतान बैंक की स्थापना मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकती है। इसकी स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश 100 करोड़ रुपये का होगा। प्रथम पाँच वर्षों में संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक लानी होगी एवं 12 वें वर्ष के अंत तक संस्थापक को अपनी हिस्सेदारी 26% तक लानी होगी पेमेंट बैंक मात्र बचत खातों के रूप में ही जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये बचत खाता भी मौलिक खाता (No Freels A/c) होगा। भुगतान बैंक उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं कर सकते। अतः ये बैंक डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं परन्तु यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। भुगतान बैंक अपनी कुल जमा राशि का 75% हिस्सा SLR के रूप में रखेंगे तब ये SLR मात्र सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ही रहेंगी इन बैंकों को CRR भी रखना अनिवार्य होगा। बची हुयी राशि ये बैंक किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में चालू खाता एवं सावधि

जमा राशि के रूप में रखेंगे। अतः इन बैंकों की आय का मुख्य स्रोत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश एवं अन्य बैंकों के साथ रखे गये सावधि जमा राशि राशि के रूप में होंगे।

स्माल फाइनेन्स बैंक (Small Finance Bank)

इनकी स्थापना भी नचीकेत मोर समिति के सुझावों के आधार पर ही की जा रही है। इनकी स्थापना के लिए कम से कम 100 करोड़ के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। संस्थापक को पहले पाँच वर्षों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक लानी होगी एवं 12 वें वर्ष के अंत तक संस्थापक को हिस्सेदारी 26% तक लानी होगी। ये ग्रामीण बैंक ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं। ये ग्राहकों से जमा राशि भी प्राप्त कर सकते हैं एवं उपभोक्ता को ऋण भी प्रदान कर सकते हैं। परन्तु ये बैंक खाता एक मौलिक खाता (No freels A/c) होगा। इन बैंकों द्वारा CRR एवं SLR के शर्त को भी पूरा किया जायेगा। इन बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाना चाहिए। दिये गये कुल ऋण में से 50% हिस्सा कुछ इस प्रकार ऋण के रूप में जाना चाहिए कि किसी भी एक ग्राहक को 25 लाख रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त न हो।

हालांकि ये वर्गीकृत बैंक लोगों से वित्तीय सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकते। इनके कार्य करने की प्रक्रिया कितनी सफल होगी यह भविष्य में ही तय हो पायेगा क्योंकि पेमेंट बैंक आप के स्रोत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य बैंकों के साथ रखे गये सावधि जमा राशि पर आश्रित होंगे इनका मुनाफा नगण्य होगा। साथ ही चूंकि ये ऋण प्रदान नहीं कर सकते। ये वित्तीय समावेशन के एक ही पक्ष को पूरा कर सकेंगे। स्माल फाइनेंस

बैंक की कार्य प्रणाली इसे वित्तीय रूप में कमजोर कर सकती है। दिये गये ऋण का 75% हिस्सा प्राथमिकता वाले दोगे में दिया जाना अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है। अतः इन बैंकों के असफल होने से देश में वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कुल जनसंख्या	1,21,01,93,422
■ पुरुष	62,37,24,248
■ स्त्रियाँ	58,64,69,174
दशकीय वृद्धि दर	17.64%
साक्षरता की दर	74.04%
■ पुरुष	82.14%
■ स्त्रियाँ	65.46%
औसत वार्षिक वृद्धि दर	1.64%
जनसंख्या (आयु वर्ग-0-6 वर्ष)	13.12%
जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी)	382
लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएँ)	940



जनगणना (Census)-2011

➤ जनगणना-2011: दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनघनत्व एवं साक्षरता दर

क्र. सं.	प्रदेश/केन्द्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2011	दशकीय वृद्धि दर		लिंगानुपात		जनघनत्व		साक्षरता दर-2011 (%)		
			1991-2001	2001-2011	2001	2011	2001	2011	योग	पुरुष	महिला
1.	जम्मू-कश्मीर	12,548,926	29.43	23.71	892	883	100	124	68.70	78.30	58.00
2.	हिमाचल प्रदेश	6,856,509	17.54	12.81	968	974	109	123	83.80	90.80	76.60
3.	पंजाब	27,704,236	20.10	13.73	876	893	484	550	76.70	81.50	71.30
4.	चंडीगढ़	1,054,686	40.28	17.10	777	818	7900	9,252	86.40	90.50	81.40
5.	उत्तराखंड	10,116,752	20.41	19.17	962	963	159	189	79.60	88.30	70.70
6.	हरियाणा	25,353,081	28.43	19.90	861	877	478	573	76.60	85.40	66.80
7.	दिल्ली	16,753,235	47.02	20.96	821	866	9340	11,297	86.30	91.00	80.90
8.	राजस्थान	68,621,012	28.41	21.44	921	926	165	201	67.10	80.50	52.70
9.	उत्तर प्रदेश	199,581,477	25.85	20.09	898	908	690	828	69.70	79.20	59.30
10.	बिहार	103,804,637	28.62	25.07	919	916	881	1,102	83.80	73.50	53.30
11.	सिक्किम	607,688	33.06	12.36	875	889	76	86	82.20	87.30	76.40
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,382,611	27.00	25.92	893	920	13	17	67.00	73.70	59.60
13.	नागालैंड	1,980,602	64.53	-0.47	900	931	120	119	80.10	83.30	76.70
14.	मणिपुर	2,721,756	29.86	18.65	978	987	103	122	79.80	86.50	73.20
15.	मिजोरम	1,091,014	28.82	22.78	935	975	42	52	91.60	93.70	89.40
16.	त्रिपुरा	3,671,032	16.03	14.75	948	961	305	350	87.80	92.20	83.10
17.	मेघालय	2,964,007	30.65	27.82	972	986	103	132	75.50	77.20	73.80
18.	असोम	31,169,272	18.92	16.93	935	954	340	397	73.20	78.80	67.30
19.	पश्चिम बंगाल	91,347,736	17.77	13.93	934	947	903	1,029	77.10	82.70	71.20
20.	झारखंड	32,966,238	23.36	22.34	941	947	338	414	67.60	78.50	56.20
21.	ओडिशा	41,947,358	16.25	13.97	972	978	236	269	73.50	82.40	64.40
22.	चंडीगढ़	25,540,196	18.27	22.59	989	991	154	186	71.00	81.50	60.60
23.	मध्य प्रदेश	72,597,565	24.26	20.30	919	930	196	236	70.60	80.50	60.00
24.	गुजरात	60,383,628	22.66	19.17	920	918	258	308	79.30	87.20	70.70
25.	दमन एवं दीव	242,911	55.73	53.54	710	618	1413	2,169	87.10	91.50	79.60
26.	दादरा और नगर हवेली	342,853	59.22	55.50	812	775	449	698	77.70	86.50	65.90
27.	महाराष्ट्र	112,372,972	22.73	15.99	922	925	315	365	82.90	89.80	75.50
28.	आंध्र प्रदेश	84,665,533	14.59	11.10	978	992	277	308	67.70	75.60	59.70
29.	कर्नाटक	61,130,704	17.51	15.67	965	968	276	319	75.60	82.80	68.10
30.	गोवा	1,457,723	15.21	8.17	961	968	364	394	87.40	92.80	81.80
31.	लक्षद्वीप	64,429	17.30	6.23	948	946	1895	2,013	92.30	96.10	88.20
32.	केरल	33,387,677	9.43	4.86	1058	1084	819	859	93.90	96.00	92.00
33.	तमिलनाडू	72,138,958	11.72	15.60	987	995	480	555	80.30	86.00	73.90
34.	पुदुचेरी	1,244,464	20.62	27.72	1001	1038	2030	2,598	86.50	92.10	81.20
35.	अंडमान एवं निकोबार	379,944	26.90	6.68	846	878	43	46	86.27	90.11	81.84
	भारत (कुल योग)	1,210,193,422	21.54	17.64	933	940	325	382	74.04	82.14	65.46

➤ भारत में जनसंख्या का विकास (Development of Population in India)

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि
1901	23,83,96,327	-
1911	25,20,93,390	5.75
1921	25,13,21,213	-0.31
1931	27,89,77,238	11.00

1941	31,86,60,580	14.22
1951	36,10,88,090	13.31
1961	43,92,34,771	21.64
1971	54,81,59,652	24.80
1981	68,63,29,097	24.66
1991	84,33,87,888	23.86
2001	102,70,15,247	21.54
2011	1,21,01,93,422	17.64



बैंकिंग एवं वित्तीय शब्द संक्षेप (Banking and Financial Terminology)

अवमूल्यन (Devaluation)

किन्हीं दो या दो अधिक देशों में प्रचलित मुद्रा के आधार पर समानता स्थापित की जाती है, उस निर्धारित समानता को जब कोई घटा देता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। जैसे भारत में प्रचलित रूपया नेपाल के दो रूपये के बराबर हो किन्तु इस मूल्यानुपात को घटा कर भारत सरकार अपने रूपए को नेपाली डेढ़ रूपये के बराबर मानने लगे तो इस रूपए का अवमूल्यन कहा जाएगा।

सामान्यतया कोई भी देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन नहीं करना चाहता लेकिन जब मुद्रा स्फीति, उत्पादन में कमी आदि के कारण अपने ही देश में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो दूसरे देश भी अधिक मूल्य देकर कम मूल्य लेकर विनिमय करना पसन्द नहीं करते। ऐसी स्थिति में जिस देश की मुद्रा का आन्तरिक मूल्य घट जाता है उस देश को विवश होकर अपनी मुद्रा का वैदेशिक मूल्य भी घटाना पड़ा जाता है। इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा करना आयात और निर्यात के लिए भी हो जाता है।

टकसाल (Mints)

सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चाँदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन के लिए भारत सरकार की चार टकसालें मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। मुम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों (मेडल) का भी उत्पादन किया जाता है। नोएडा की टकसाल में नवीनतम मशीनरी तथा उपकरण हैं परन्तु अन्य तीनों टकसालों की मशीनें काफी पुरानी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके रखरखाव पर काफी लागत आती है।

देशी बैंक व्यवस्था (Indigenous Banking)

भारत में देशी बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत सराफ, सेठ, साहूकार, महाजन, शेर्टी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो रूपया उधार देते हैं तथा हुण्डियों अथवा आन्तरिक विनिमय-पत्रों द्वारा वित्त प्रबन्ध करते हैं। देशी बैंकर अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से जमा भी स्वीकार करते हैं। ये रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते हैं।

मर्चेन्ट बैंकिंग (Merchant Banking)

वाणिज्यिक बैंकिंग के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों को विशिष्ट प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें परियोजना सम्बन्धी परामर्श (Project Counselling), व्यवहार्यता रिपोर्ट (Feasibility report) तैयार करना, प्रस्तावों पर सरकार की सहमति प्राप्त करना, नए निर्गमों (New issues) के प्रबन्धक के रूप में कार्य करना, कार्यशील पूँजी (Working capital) की व्यवस्था करना आदि बातें उल्लेखनीय हैं।

साख-पत्र (Letter of Credit)

साख-पत्र सामान्यतः एक बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम लिखा गया एक पत्र होता है जिसमें पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चेकों या उसके द्वारा स्वीकार किए गए विनिमय बिलों के भुगतान की गारण्टी प्रदान की जाती है। इस प्रकार के साख-पत्र निर्यात आयात व्यापार में बहुत उपयोगी होते हैं।

सुरक्षित तथा असुरक्षित अग्रिम (Secured and Unsecured Advances)

सुरक्षित ऋण या अग्रिम का अर्थ ऐसे ऋण या अग्रिम से है, जोकि ऐसी प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है जिनका बाजार मूल्य किसी भी समय ऐसे ऋण या अग्रिम की राशि से कम नहीं होता, जो ऋण इस प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें असुरक्षित ऋण या अग्रिम कहते हैं।

एसटीटी (सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स)

शेयर बाजार में प्रतिभूतियों (Securities) के खरीदने या बेचने पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता

(Foreign Currency (Non-Resident) Accounts)

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को 1 नवम्बर, 1975 से इस प्रकार के खाते खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार के जमा खाते कुछ चुनी हुई परिवर्तनशील मुद्राओं में खोले जाते हैं। नकद जमाओं के अलावा विदेशों में निवासी भारतीय ड्राफ्ट, मेल ट्रान्सफर, टेलीग्राफिक ट्रान्सफर या चेक के द्वारा धनराशि भेज सकते हैं। जिस (स्वीकृत) मुद्रा में खाता रखा जाता है, ब्याज उसी मुद्रा में अदा किया जाता है। ब्याज पर भारतीय आयकर नहीं लगता।

विनिमय साध्य विपत्र (Negotiable Instrument)

विनिमय-साध्य विपत्र एक लिखित प्रपत्र होता है, जो विधि अथवा व्यापारिक प्रथा के अन्तर्गत अन्तरित किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसा प्रपत्र सद्भाव से तथा मूल्य के बदले (in good faith and for value) प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को ऐसे प्रपत्र पर समुचित स्वामित्व रखने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है चाहे उसके अन्तरणकर्ता का उस विपत्र पर कोई स्वामित्व नहीं था अथवा दोषपूर्ण स्वामित्व था। वचन-पत्र (Promissory note), विनिमय-पत्र (Bill of exchange) तथा चेक (Cheque) की गणना विनिमय साध्य विपत्रों, के अन्तर्गत की जाती है। इन विपत्रों का नियमन 'विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम' (Negotiable Instruments Act) के द्वारा होते हैं।

कर, उपकर तथा अधिभार (Tax, Cess and Surcharge)

कर, उपकर तथा अधिकार कर की श्रेणी में आते हैं, किन्तु उपकर तथा अधिभार कर से भिन्न हैं। किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर नहीं लगाया जाता, जबकि उपकर तथा अधिभार दोनों ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्व की उगाही के लिए लगाए जाते हैं। उपकर कर के साथ कर आधार पर ही



किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर है, जबकि अधिभार कर के ऊपर कर है, जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है। सामान्यतया अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि उपकर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर दोनों पर लगाया जाता है। इस प्रकार सिद्धान्ततः उपकर कर आधार पर लगाया जाता है, जबकि कर भार कर दायित्व पर लगाया जाता है।

पुनः अधिभार तथा उपकर की प्राप्ति को राज्यों के वितरण योग्य पूल (Divisible Pool) में नहीं डाला जाता। इसके राजस्व को उन उद्देश्यों पर लगाया जाता है, जिनके लिए इन्हें लगाया जाता है।

समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security)

समपार्श्विक प्रतिभूति ऋण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋणी से प्राप्त की जाती है। यह प्रतिभूति तृतीय पक्षकार द्वारा उसकी जमानत (Guarantee) स्वरूप अथवा ऋणी द्वारा अन्य प्रतिभूतियाँ प्रदान करके उपलब्ध की जाती है।

बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)

बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचाकर रखना चाहते हैं। इस खाते में जमा राशि पर कुछ ब्याज भी दिया जाता है। प्रत्येक कलेण्डर महीने के दसवें दिन के अन्त से लेकर इस महीने की अन्तिम तारीख तक की अवधि में जो भी न्यूनतम जमा बाकी रहती है, उसके आधार पर ब्याज दिया जाता है।

लदान बिल (Bill of Lading)

लदान बिल अथवा लदान रसीद जहाज कम्पनी द्वारा माल प्राप्ति की रसीद होती है जिसमें माल का पूरा विवरण, लदान की तिथि, माल पहुँचने का स्थान आदि तथ्यों का विवरण होता है। बैंकों द्वारा इस प्रकार बिलों के प्रति ऋण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

चालू खाता (Current Account)

यह एक प्रकार का माँग जमा (Demand Deposit) खाता है जिसमें से किसी भी कार्य दिवस को अनेक बार कितनी भी राशि का लेन-देन किया जा सकता है। इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक लेन-देनों (Transactions) की संख्या के आधार पर कुछ सेवा शुल्क (Service charge) खाताधारी से वसूल करते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)

सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिज्ञा-पत्र (Government promissory notes), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र तथा राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बन्धक पत्र (Bearer bonds) आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बैंक इन प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा ये सुरक्षित समझी जाती हैं।

नकद साख खाता (Cash Credit Account)

यह एक ऋण खाता है। इस खाते के अन्तर्गत बैंक खाताधारी को एक निश्चित मात्रा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसी सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रूपया लेता है और जमा भी करता है। ब्याज उसी राशि पर वसूल किया जाता है, जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है।

करेंसी अथवा चलन मुद्रा तिजोरियाँ (Currency Chests)

करेंसी तिजोरियाँ ऐसे बॉक्स हैं जिनमें धात्विक सिक्कों के साथ-साथ नए या पुनः जारी कर सकने योग्य करेंसी नोटों का भण्डार रखा जाता है। ऐसी तिजोरियाँ रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी खजानों तथा उप खजानों (Government treasuries and sub-treasuries) द्वारा संचालित की जाती हैं। करेंसी तिजोरियों में इस तरह रखे जाने वाले नोटों का भण्डार सम्पूर्ण देश में फैला रहता है तथा अधिकांश मामलों में ये तिजोरियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही संचालित की जाती हैं।

स्मार्ट कार्ड (Smart Card)

डाक विभाग द्वारा चुनिंदा शहरों में प्रारम्भ की गई प्रीमियम बचत बैंक सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदार को एक 'स्मार्ट कार्ड' जारी किया जाएगा, जिससे वर्तमान कागज की पासबुक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से खातेदार किसी एक निश्चित डाकघर के स्थान पर विभिन्न डाकघरों में अपने खाते में धन जमा करा सकेंगे तथा निकाल सकेंगे।

सावधि जमा (Time Deposits)

सावधि जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए बैंक के पास जमा की जाती हैं। यह जमा राशि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने पर देय (Repayable) होती है। बैंक ऐसी जमा राशियों पर अपेक्षाकृत ऊँची दर से ब्याज देते हैं। इस प्रकार के जमा बैंकों द्वारा प्रायः सावधि जमा खाते (Fixed Deposit Account) तथा आवर्ती जमा खाते (Recurring Deposit Account) में स्वीकार किए जाते हैं।

अनिवासी (बाह्य) रूपया खाता (Non-Resident (External) Rupee Accounts)

इस प्रकार के खाते प्रमुख व्यापारिक बैंकों में अनिवासी भारतीयों के नाम में खोले जा सकते हैं। यह खाते भारतीय रूपयों में खोले जाते हैं। खातों का मूलधन तथा उस पर अर्जित ब्याज को बिना किसी कठिनाई के जमाकर्ता को उसके देश वापस कर दिया जाता है, परन्तु रूपयों को विदेशी मुद्रा में उस दर से परिवर्तित किया जाता है, जोकि धन भेजने की तारीख को लागू होती है। इन खातों पर दिया गया ब्याज कर मुक्त होता है। ऐसे खाते अनिवासी भारतीयों (NRIs) तथा भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा खोले जा सकते हैं। अन्य विदेशी लोगों को ऐसे खाते खोलने की अनुमति नहीं है।

माँग जमा (Demand Deposits)

माँग जमाओं के अन्तर्गत उन समस्त जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है, जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार चाहे जब वापस माँगी जा सकती हैं। बैंकों में चालू खाते (Current Account) तथा बचत खाते (Saving Account) में जमा राशियाँ माँग जमा के अन्तर्गत आती हैं।

प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)

जब वाणिज्यिक बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन बैंकों को नीति का अनुकरण करने के लिए बाध्य करने की विधि को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही कहा जाता है जैसे बैंकों को ही दी जाने वाली पुनः कटौती की सुविधा को बन्द कर देना, अतिरिक्त साख की स्वीकृति न देना आदि।



चेक कलेक्शन (Cheque Collection)

जब चेक शहर के शहर किसी अन्य स्थान पर भुगतान के लिए भेजा जाता है, तो इसे ही कलेक्शन कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक ग्राहक को डाक-व्यय एवं कमीशन लेती है।

म्यूचुअल फण्ड (Mutual Fund)

म्यूचुअल फण्ड के अन्तर्गत जन-साधारण के निवेश योग्य धन को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित करके विनियोग के बेहतर अवसरों में प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने वाली दक्ष वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक तथा जीवन बीमा निगम आदि ने इस प्रकार के म्यूचुअल फण्ड स्थापित किए हैं।

बॉण्ड (Bond) अथवा डिबेन्चर (Debenture)

बॉण्ड एवं डिबेन्चर का अर्थ ऋणपत्रों से होता है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिबेन्चर जारी करती हैं। इन बॉण्डों को हस्तान्तरित भी किया जा सकता है, जो संस्था इन्हें जारी करती हैं वे इन पर धारक को निश्चित दर से ब्याज भी देता है।

प्रतिभूति (Security)

प्रतिभूति एक व्यापक शब्द है। एक अर्थ में प्रतिभूति शब्द का प्रयोग प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा शेयर, डिबेन्चर व अन्य ऋणपत्रों आदि के लिए किया जाता है। बैंकिंग में ऋणों की जमानत के सन्दर्भ में भी 'प्रतिभूति' काफी प्रयुक्त होता है, जहाँ प्रतिभूति से अभिप्राय उस बीमित हित से होता है, जो ऋण के भुगतान न होने की स्थिति में उत्पन्न होता है अर्थात् प्रतिभूति ऋण का बीमा होती है। बैंकों द्वारा ऋणी की व्यक्तिगत अथवा दृश्य प्रतिभूति पर ऋण प्रदान किया जाता है।

धारक बॉण्ड (Bearer Bond)

धारक बॉण्ड वे ऋणपत्र हैं, जिनका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है। इन पर न तो खरीददार का नाम लिखा होता है और न ही हस्तान्तरित करते समय इनकी पीठ पर हस्ताक्षर ही करने होते हैं। प्रायः इनका उपयोग काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए किया जाता है।

व्यक्तिगत प्रतिभूति (Personal Security)

बैंक प्रायः छोटे-मोटे ऋणों के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति अथवा किसी तीसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभूति को ही स्वीकार कर लेती है। व्यक्तिगत प्रतिभूति में ऋणी का चरित्र, उसकी सम्पत्ति (Assets) तथा क्षमता (Capacity) को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए तथा उसकी बाजार में साख अच्छी होना चाहिए आदि।

सस्ती मुद्रा (Cheap Money)

वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर (Low interest rate) पर प्राप्त किया जा सकता है, सस्ती मुद्रा कहलाती है।

दृश्य अथवा मूर्त प्रतिभूति (Tangible Security)

दृश्य प्रतिभूति में ऋण की वसूली प्रतिभूति बेचकर की जा सकती है। दृश्य प्रतिभूति में अंश (Shares), ऋणपत्र (Debentures), सरकारी प्रतिभूति, माल (Goods) एवं जीवन बीमा पॉलिसी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती-दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।

प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security)

प्राथमिक प्रतिभूति से अभिप्राय उस प्रतिभूति से होता है, जो ऋण को मुख्यतः सुरक्षित करती है तथा यह प्रतिभूति ऋणी द्वारा प्रदत्त की जाती है।

खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

यह भी केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है, परन्तु संकीर्ण अर्थ में इससे अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है।

नो फ्रिल अकाउंट (No Fril Account)

यह एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जो बेहद बुनियादी बैंकिंग सुविधा है। इससे ग्राहक को कुछ बेहद जरूरी बैंकिंग सुविधा मिल जाती है। इसमें प्रीमियम सेविंग अकाउंट की सुविधा हासिल नहीं होती है। नो फ्रिल अकाउंट उन लोगों के लिए मुफीद है जो खाता खोलने के लिए बैंकिंग मानकों और जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते।

नो फ्रिल अकाउंट में कई न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं रखते। जबकि कुछ बैंकों में 500 रूपए का न्यूनतम बैलेंस जरूरी है। कुछ बैंक एटीएम की सुविधा देते हैं। कुछ बैंक चेकबुक और कुछ जरूरी सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। कुछ बैंक स्टेटमेंट के लिए शुल्क वसूलते हैं तो कुछ नहीं। समावेशी बैंकिंग के लिए देश में ज्यादा से ज्यादा नो फ्रिल अकाउंट खोले जाने चाहिए।

ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट (Global Depository Certificate)

किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक की ओर से विदेशी कंपनियों के शेयरों के बदले जो सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसे संक्षेप में जीडीआर कहा जाता है और यह एडीआर की ही तरह होते हैं। दरअसल जिस विदेशी कंपनी के शेयर एक साथ कई देशों में जारी होते हैं और इसके एवज में जमा रकम के बदले सर्टिफिकेट के समतुल्य शेयर उस बैंक की विदेशी शाखा के पास रखे जाते हैं।

थ्री-इन-वन अकाउंट (Three in One Account)

इस अकाउंट में आप तीन अकाउंट के काम कर सकते हैं। मतलब इस एक अकाउंट से सेविंग, ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट का काम हो सकता है। इसे ब्रोकरेज कंपनी या किसी भी बैंकिंग शाखा में खोला जा सकता है। इससे केवल



ऑन लाइन ट्रेड ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इससे सेविंग अकाउंट का काम भी लिया जा सकता है।

ऑन लाइन अकाउंट और ऑफ लाइन अकाउंट की तुलना में इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है मतलब यह है कि इसमें ज्यादा तेज गति से काम किया जा सकता है। इसकी मदद से सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में धन ट्रांसफर किया जा सकता है।

साथ ही इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसके अंतर्गत किया जाने वाला ट्रांजेक्शन काफी सुरक्षित होता है। उदाहरण के लिए मान लिया आपका कोई ऑन लाइन अकाउंट है और आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको दो पासवर्ड रखने होंगे। लेकिन श्री इन वन अकाउंट में ऐसा नहीं है और एक ही पासवर्ड से काम चल जाएगा।

साथ ही अगर आप ऑन लाइन अकाउंट से किसी ट्रेडिंग अकाउंट में धन ट्रांसफर करना चाहते लेकिन हो सकता है संबंधित बैंकिंग का सर्वर काम नहीं कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपका काम रूक जाएगा और तत्काल नहीं हो पाएगा लेकिन श्री इन वन अकाउंट में इस तरह की समस्या नहीं आती है।

रिवर्स मॉर्गेज (Reverse Mortgage)

रिवर्स मॉर्गेज अपने आप में एक ऐसी अवधारणा है जिसमें बैंक किस्त लेने के बजाय आपको किस्त देता है। दरअसल यह योजना विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए बनाई गई है।

मान लिया रिटायर होने के बाद आप नियमित रूप से आय चाहते हैं तो आपके लिए यह योजना बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। इसमें बैंक के पास संपत्ति गिरवी रखी जाती है और बैंक आपको आगे के जीवन के लिए नियमित रूप से ईएमआई जारी करता है।

मान लिया आप इस समय 60 साल के हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बैंक आपको मकान को गिरवी रख लेगा और उसके बदले में आपके नियमित रूप से किस्त का भुगतान करता रहेगा। जब आप नहीं रहेंगे तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेगा। इसमें यह व्यवस्था भी है कि अगर आपकी संपत्ति बैंक के कर्ज से ज्यादा है तो बकाया पैसा आपके वारिस को लौटा दिया जाएगा।

साथ ही इस योजना में इस बात की व्यवस्था भी की गई है कि अगर आपका वारिस चाहे तो बैंक के पैसे वापस लौटा कर अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। अगर आपकी संपत्ति की कीमत ज्यादा है तो यह कर्ज एक करोड़ रूपए से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि अगर कर्ज लेने वाला खुद चाहे तो अपना कर्ज चुकाकर अपनी संपत्ति को वापस ले सकता है। साथ ही इसमें कोई रिपेमेंट पेनाल्टी या फीस भी नहीं लगती है।

ईएमआई (EMI)

बैंक या वित्तीय संस्थाओं से जब आप कर्ज लेते हैं तो पैसे चुकाने के लिए वे आपको कर्ज पैसों को किस्तों में चुकाने की सुविधा देते हैं। इसके लिए एक राशि तय कर दी जाती है और एक अवधि भी। ईएमआई का पूरा फार्म होता है- इक्वेटेड मंथली इंस्टालमेंट। इसके तहत आपको एक राशि देनी होती है जिसमें मूल धन और ब्याज दोनों ही होते हैं। इसे एक तयशुदा अवधि में चुकाना होता है। लेकिन अगर इसी बीच ब्याज दर बढ़ जाती है तो अवधि भी बढ़ जाती है।

यानी आपको ज्यादा समय तक ईएमआई चुकाना पड़ता है। कर्ज चुकाने का यह सबसे सुविधाजनक तरीका है।

डिजिटल मनी (Digital Money)

आजकल हर ओर डिजिटल मनी के चर्चे हैं और इसके बढ़ते इस्तेमाल की बातें की जा रही हैं। दरअसल डिजिटल मनी कागजी मुद्रा से बिल्कुल अलग है और इसमें नकदी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। यह कंप्यूटर या स्मार्टफोन या फिर क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट के जरिये इधर से उधर होता है। यह नकदी में तभी बदलेगा जब कोई एटीएम या ऐसी मशीन का इस्तेमाल करेगा। डिजिटल मनी के ट्रांसफर या रखने-रखाने का काम वित्तीय सेवा कंपनियाँ करती हैं। वे इसे लेन देन का माध्यम बनती हैं। डिजिटल मनी के जरिये ऑनलाइन बैंकिंग आसानी से संभव है। इसमें नकदी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती तथा बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking)

मोबाइल बैंकिंग का सामान्य सा मतलब यह हुआ है आपका अकाउंट हमेशा आपके साथ-साथ गतिमान रहता है। आज की दौड़ती-भागती जिंदगी में मोबाइल बैंकिंग आपकी दिक्कतों को कम करने में मददगार साबित हो रही है। खासकर कारोबारियों के लिए तो यह बहुत जरूरी है। कारोबारियों को दिनभर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन की जरूरत पड़ती है।

अगर वह बैंक जाकर सारा कामकाज करना चाहे तब उसका आधा दिन यूँ ही खराब हो जाएगा। दिनभर के व्यस्त कार्यक्रम के दौरान आप कहीं भी खड़े होकर मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग का लाभ कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में और कभी भी उठा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपके मोबाइल के द्वारा एसएमएस या वेब के जरिये ऑपरेट होता है। मोबाइल बैंकिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा एसएमएस बैंकिंग है।

आजकल ज्यादातर खाताधारी जिन्होंने मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के विकल्प का आवेदन दिया होता है, उन्हें एटीएम या अकाउंट से किसी भी प्रकार के लेनदेन की सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिये उपलब्ध कराई जाती है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि आपके अकाउंट में कितनी रकम शेष है और कितना पैसा कहां किस मद में निष्कासित हो रहा है, आपको उसकी पल-पल जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में आज की तारीख में बहुत ज्यादा मांग वाली विषयवस्तु है। यह भविष्य में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के सिस्टम को हस्तान्तरित कर देगा। मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों में से 85-90 फीसदी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। यह ठीक-ठीक एटीएम की तरह ही होता है। यह इस्तेमाल करने में बेहद सुविधाजनक और सस्ता है।

एटीएम की तुलना में इससे बैंक के ऑपरेशनल खर्च में कमी आ जाती है। इसका लाभ बिल पैमेंट करने, फंड ट्रांसफर करने और बैलेंस चेक करने आदि में किया जाता है। कोरिया में मोबाइल फोन में दो सिम का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिम टेलीफोन के लिए दूसरा बैंकिंग के लिए। बैंकिंग अकाउंट डाटा स्मार्ट कार्ड चिप पर उपलब्ध होता है। वर्ष 2004 में बैंक ऑफ कोरिया में 33 लाख ट्रांजेक्शन मोबाइल बैंकिंग के जरिये हुआ था। जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ोत्तरी ही हुई होगी।



डीमैट अकाउंट (Demat Account)

डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरीलाइज्ड अकाउंट। इसके तहत कंपनियों के शेयरों को फिजिकल फॉर्म में रखने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। यानी कागज से छुटकारा।

डीमैट अकाउंट के लिए देश भर में कई संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। इनमें सरकारी और प्राइवेट बैंक भी हैं इन्हें डिपॉजिटरी कहते हैं। आपको वहां बैंक अकाउंट की तरह ही खाता खोलना पड़ता है। इसके बाद जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो वे आपके पास आने की बजाय उस डिपॉजिटरी में जमा हो जाएंगे। आपको बस डीमैट अकाउंट नंबर देना होगा। डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह काम करेगा और आपके आदेशानुसार आपके शेयरों की खरीद-बिक्री करेगा।

किसी भी व्यक्ति के लिए डीमैट अकाउंट खोलना बड़ा आसान है। उसे किसी डिपॉजिटरी में जाकर फार्म भरना होगा। इसके बाद उसका अकाउंट खुल जाएगा और उसे एक खाता नंबर और डीपी आई डी नंबर मिल जाएगा। ज्यादातर बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज ने डिपॉजिटरी खोल रखे हैं।

पॉइंट्स ऑफ सेल (Points of Cell)

‘पाइंट ऑफ सेल’ से तात्पर्य ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों एवं पेट्रोल पम्पों आदि से है जहाँ खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को ‘स्वाइप’ करके भुगतान करने की सुविधा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी दुकानों/प्रतिष्ठानों से एक दिन में अधिकतम एक हजार रूपए तक की नकद निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है।

‘पाइंट ऑफ सेल’ से नकद धन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी वर्ष 2010 में ही प्रदान कर दी थी तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या न कराना बैंकों के ऊपर छोड़ दिया था।

रेपो दर (Repo Rate)

अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु (ओवर-नाइट हेतु भी) जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, ‘रेपो दर’ कहलाती है।

रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)

अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है ‘रिवर्स रेपो दर’ कहलाती है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

बचत बैंक दर (Savings Bank Rate)

बैंक ग्राहकों की छोटी-छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को ‘बचत बैंक दर’ कहा जाता है।

जमा दर (Deposit Rate)

बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज की दर को ‘जमा दर’ कहा जाता है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, ‘नकद आरक्षित अनुपात’ कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊँची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)

किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह (प्रतिशत) भाग जो नकद स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)

वह न्यूनतम पूँजी जिसे एक बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को अपने पास रखना चाहिए, खासकर तब जब वह किसी व्यापारिक सम्पत्ति का सृजन करती हो, पूँजी पर्याप्तता कहलाती है, जबकि पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तियों के साथ पूँजी का अनुपात प्रदर्शित करता है।

माइकर कोड (Mikro Coad)

‘मैग्नेटिक ईक करेक्टर रिकॉग्नीशन’ कोड सामान्यतया 9 अंकों का कोड है, जो सभी बैंकों के चेक के निचले हिस्से में छपा रहता है। इसमें पहले 3 अंक बैंक शाखा के शहर के नाम, अगले 3 अंक बैंक के नाम तथा आखिरी 3 अंक बैंक ब्रांच की पहचान के लिए दिए रहते हैं।

IFSC कोड (IFSC Code)

‘इण्डियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड’ जो सामान्यतया 11 अंकों का प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा होता है। इसमें पहले 4 अक्षरों में बैंक का नाम, एक शून्य तथा अन्तिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से सम्बन्धित विवरण अन्तर्निहित होता है।

NEFT प्रणाली (NEFT System)

इंटरनेट के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर के द्वारा लिखित चेक के स्थान पर 1 लाख रूपए से कम धनराशि को एक बैंक से उसी तथा अन्य बैंक के खाते में खाताधारक द्वारा स्वयं ही स्थानान्तरित किया जा सकता है।

RTGS प्रणाली (RTGS System)

सामान्यतया 1 लाख रूपए से अधिक की धनराशि को खाता धारक द्वारा स्वयं इंटरनेट के माध्यम से रीयल टाइम ग्राँस सैटिलमेंट विधि से किसी भी खाताधारक के किसी भी बैंक के खाते में त्वरित रूप से भेजा जा सकता है।

ECS प्रणाली (ECS System)

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम योजना के माध्यम से बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उसके द्वारा आदेशित किसी भी संस्था/व्यक्ति के खाते में नियमित रूप से अन्तरित की जाने वाली धनराशि को बिना पेपर चेक काटे हुए स्वतः अन्तरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

नेट बैंकिंग (Net Banking)

इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे बैंकिंग के कार्यों का संचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को नेट बैंकिंग कहते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से



ग्राहक अपने कम्प्यूटर का उपयोग कर अपने बैंक नेटवर्क और वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। नेट बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी घर बैठे या ऑफिस से बैंक सर्विस का लाभ उठा सकता है।

तकनीकी दुरुपयोग के कारण नेट के जालसाज एकाउंट को हैक कर बैंक के ग्राहक को हानि पहुँचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि नेट बैंकिंग के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। नेट बैंकिंग की 50% वेबसाइट असुरक्षित होती है। अतः ग्राहक साइट खोलने से पहले यू आर एल और डोमेन का चेक करें और देखें कि यह उसी बैंक के यू आर एल और डोमेन की तरह हों। इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आप सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं।

यदि आप नेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफे का उपयोग कर रहे हों, तो अपने पासवर्ड को बदल लें। इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे। पासवर्ड को किसी पेपर पर न लिखें, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। अपनी सिस्टम पर स्क्रीन सेवर पासवर्ड डाल दें, जिससे आपके सिस्टम का उपयोग कोई अन्य नहीं कर सके।

चालू खाते पर बकाया (Balance on Current A/c)

किसी देश के भुगतान सन्तुलन के चालू खाते (आयात-निर्यात का पण्य व्यापार, जहाजरानी, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, अनिवासियों द्वारा विदेशी निधियों के अन्तरण) के लेन-देन का चालू खाते के बकाया पर नाम एवं जमा में दर्शाया जाता है।

संदर्भित दर तथा प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate-PLR)

संदर्भित, दर, पूँजी बाजार का निर्धारण करती है। यह दर न्यूनतम दर होती है, जिस पर पूँजी बाजार में उधार लिया या दिया जाता है। बाजार में प्रचलित ब्याज दर, जिस पर सामान्यतया समझौता होता है, संदर्भित दर से ऊँची होती है। इसके द्वारा ब्याज दर में होने वाला परिवर्तन निर्देशित होता है। विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से संदर्भित दरों को जाना जाता है। अमेरिका में Feds Funds Rate, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट इंटर बैंक ऑफर्ड रेट (FIBOR), जापान में टोकियो इंटर बैंक ऑफर्ड रेट (TIBOR), लन्दन में लन्दन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) इत्यादि।

प्रमुख उधारी दर (Prime Lending Rate-PLR) वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय (विश्वसनीय) ग्राहक को ऋण देता है। (विश्वसनीयता से तात्पर्य है जिसमें जोखिम शून्य हो) PLR एक प्रकार से आधार ब्याज दर की भूमिका अदा करता है। इसी PLR आधार पर अन्य उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है।

अदृश्य मदें (Invisible Items)

विदेशी लेन-देन के चालू खाते में निजी अन्तरण, सॉफ्टवेयर आयात-निर्यात से जुड़े लेन-देन, पर्यटन से जुड़े लेन-देन, निवेश भुगतान एवं विविध सेवाओं से जुड़े लेन-देन अदृश्य मदों के अन्तर्गत आते हैं।

पी.ए.एन. (Permanent Account Number-PAN)

परमानेंट एकाउण्ट नम्बर या स्थायी लेखा संख्या आयकर दाताओं को आवंटित एक ऐसी संख्या है जिससे उसके धारक द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त की गई आय एवं अन्य लेन-देन, जिनमें पी.ए.एन. का उल्लेख करना अनिवार्य है, का लेखा-जोखा रखा जाता है ताकि कर अपवंचन को रोका जा सके।

प्लास्टिक मना (Plastic Money)

प्लास्टिक मनी से तात्पर्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कम्पनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्डों से है, भारत के लगभग सभी महानगरों में क्रेडिट कार्डों का चलन बढ़ रहा है इनसे हवाई जहाज की टिकट, कपड़े, सामान आदि खरीदे जा सकते हैं। अब तो बाजार में पेट्रोल कार्ड तक आ गए हैं जिनसे ग्राहक पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ (Non-performing Assets)

गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्तियाँ बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित वे ऋण हैं जिनके मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती।

सामान्यतया बैंकों द्वारा वितरित ऐसे सभी ऋण और उस पर देय ब्याज गैर-निष्पादनीय परिसम्पत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनमें किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन तथा ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक दिनों तक रोक लिया जाता है।

ग्रामीण आधारिक अवसंरचना विकास निधि (RIDF)

ग्रामीण आधारिक अवसंरचना से सम्बन्धित चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व वाले निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने 1995-96 में ग्रामीण आधारिक अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की थी। अब तक इसकी 15 शृंखलाएँ (RIDF-XV) पूरी की जा चुकी हैं।

बजट (Budget)

किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय-व्यय का लेखा-जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय-व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का विवरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है।

बफर स्टॉक (Buffer Stock)

आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।

नेट एसेट वैल्यू (NAV)

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए 'एन.ए.वी.' शब्द एक पहेली की तरह है। इसका पूरा नाम 'नेट एसेट-वैल्यू' है। अगर फंड की कुल निवेश वैल्यू में कुल यूनिटों का भाग दे दिया जाए तो 'एसेट वैल्यू' निकलती है, मसलन किसी फंड में 1 लाख रूपए जमा हुए। इसमें से फंड हाउस ने 90 हजार निवेश किए। इस निवेश की वैल्यू रोज निकाली जाती है। अब मान लें इसकी वैल्यू 1,80,000 है। इसके अलावा 10 हजार रूपए फंड हाउस के पास नकद बचे हैं। यानि फंड की कुल वैल्यू हुई 1,90,000 अब देखा जाता है कि इस योजना की कितनी यूनिटें जारी हुई हैं। अगर योजना में 10 लोगों ने 10-10 हजार रूपए लगाए तो कुल 10 हजार यूनिटें जारी हुईं। मानकर चलते हैं कि यूनिटों की संख्या नहीं बदलती है, तो अब फंड की 'एनएवी' $190000/10000 = ₹19$ होगी।



डी-मैट अकाउंट (Demat Account)

यह एक प्रकार का बैंक खाता है जिसमें रूपयों की जगह शेयर व बॉण्ड रखे जाते हैं। इस खाते में रूपए का लेन-देन नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे डी-मैट खाता खुलवाना जरूरी है। 'सेबी' के नियमों के मुताबिक अगर आपको शेयर बाजार में खरीद-फरोख्त करनी हो, तो वह 'डी-मैट' खाते के जरिए ही हो सकती है। यही नहीं अगर किसी कंपनी के 'आईपीओ' में निवेश करना हो, तो भी डी-मैट खाता जरूरी है। डी-मैट खाता खुलवाने पर बैंक या ब्रोकर पैसा लेता है। यह खाता शेयर के न होने पर बन्द नहीं होता है। इसके लिए वार्षिक फीस चुकानी पड़ती है।

ग्रोथ, लाभांश तथा निवेश म्यूचुअल फंड (Growth Dividend and Investment Mutual Fund)

म्यूचुअल फंड कंपनियाँ आमतौर पर अपनी योजनाओं में निवेश के तीन विकल्प देती हैं। पहला है- 'ग्रोथ', इस विकल्प में पैसा लगातार निवेशित रहता है। निवेशक को जब जरूरत होती है वह अपनी यूनिट बेचकर पैसा निकाल सकता है। दूसरा विकल्प है- 'लाभांश', इस विकल्प में म्यूचुअल फंड योजनाएँ समय-समय पर लाभांश घोषित करती है यह लाभांश निवेशक को दिया जाता है। लेकिन जितना पैसा लाभांश, के रूप में दिया जाता है यूनिट का भाव उसी हिसाब से घट जाता है। तीसरा विकल्प होता है- 'लाभांश का पुनः निवेश'। इसमें जितना लाभांश बनता है उतने पैसे की यूनिट निवेशक को जारी की जाती है। ऐसे में फंड की 'एनएवी' (नेटएसैट वैल्यू) तो कम हो जाती है, लेकिन निवेशक की यूनिटें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार निवेशक का निवेश लगातार बढ़ता रहता है।

ओपन एंडेड फंड (Open Aided Fund)

इस फंड में निवेशक सीधे निवेश कर सकता है और जिस दिन चाहे अपने निवेश को निकाल भी सकता है। ऐसी योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका हो, तो निवेशक अपना निवेश निकाल सकता है। यही नहीं अगर जरूरत हो तो पूरा या आंशिक रूप से पैसे निकालने की इजाजत होती है।

क्लोज एंडेड फंड (Closed Aided Fund)

इस फंड में निवेश सिर्फ एनएफओ यानि इसकी शुरुआत में ही होता है। बाद में यह फंड निवेश के लिए बंद रहते हैं, लेकिन अगर निवेशक पैसा निकालना चाहता है, तो उसे कुछ विकल्प दिए जाते हैं। कई बार हफ्ते में एक बार तो कई बार महीने में एक बार पैसा निकालने की इजाजत होती है। इसके लिए दिन या तारीख निश्चित रहती है, अगर यह समय निकल जाता है तो अगली तारीख तक इंतजार करना पड़ता है।

ऑडिट अकाउंट (Adid Account)

'वार्षिक ऑडिट अकाउंट' किसी कंपनी के बारे में जानकारी एकत्र करने का सर्वोत्तम साधन है। किसी कंपनी के ऑडिट अकाउंट की जाँच-पड़ताल के बाद उसमें किया गया निवेश फायदेमंद होता है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनी अपना वार्षिक ऑडिट अकाउंट जारी करती है। यह निवेश के लिए कई जगहों पर उपलब्ध होता है जिससे निवेशक, निवेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर जानकारी ले सकता है।

साख संकुचन (Credit Squeeze)

इसका अर्थ है- कम मात्रा में ऋण वितरित करना। जब बैंकों द्वारा अधिक ऋण दे दिया जाता है, तो बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है। इससे वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसे रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा 'साख संकुचन' की विधि अपनाई जाती है।

फ्लोटिंग ऑफ करेन्सी (Floating of Currency)

किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड़ देना, ताकि माँग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके।

कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty)

इसे सीमा शुल्क कहते हैं। कस्टम्स ड्यूटी वह कर है, जो आयात व निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है।

एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty)

उस कर को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो देश के अन्दर निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन बन्दु पर ही लगाया जाता है। इसे 'उत्पाद शुल्क' कहते हैं।

अवमूल्यन (Devaluation)

यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है।

विमुद्रीकरण (Demonetization)

जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है, वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

मुद्रा संकुचन (Deflation)

जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था 'मुद्रा संकुचन' कहलाती है।

ऐस्टेट ड्यूटी (Estate Duty)

किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय जो कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है, उसे 'ऐस्टेट ड्यूटी' कहते हैं।

उपहार कर (Gift Tax)

किसी उपहार के देने पर जो कर लगाया जाता है वह 'उपहार कर' कहलाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है।

स्वर्णमान (Gold Standard)

जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को 'स्वर्णमान' कहते हैं। अब किसी देश में स्वर्णमान नहीं है।



हॉट मनी (Hot Money)

उस विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं, जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की सम्भावना होती है, वहीं यह स्थानान्तरित हो जाती है।

विधिग्राह्य मुद्रा (Legal Tender Money)

जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे 'विधिग्राह्य' मुद्रा कहते हैं। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा रूपया है।

सीमित कम्पनी (Limited Company)

उस कम्पनी को कहते हैं। जिसमें हर शेयर होल्डर का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है।

मोरेटोरियम (Moratorium)

उस अवधि को 'मोरेटोरियम' कहते हैं जिसमें कानून द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है।

रिबेट (Rebate)

किसी संस्थान को दिए जाने वाले धन में छूट के रूप में एक निश्चित भाग कम कर दिया जाना 'रिबेट' कहलाता है।

मुद्रा बाजार व पूँजी बाजार**(Money Market and Capital Market)**

जिस प्रकार अन्य वस्तुओं का बाजार होता है, उसी प्रकार मुद्रा का भी बाजार होता है जहाँ मुद्रा का लेन-देन किया जाता है। मुद्रा बाजार के अन्तर्गत उन समस्त व्यक्तियों व वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो अल्पकाल के लिए मुद्रा उपलब्ध कराते हैं। इसके विपरीत पूँजी बाजार में दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है।

ऋणशोधन निधि (Sinking Fund)

नियमित रूप से धनराशि जमा करके तैयार किया गया ऐसा कोष जिससे किसी ऋण का परिपक्वता पर आसानी से भुगतान किया जा सके, शोधन कोष कहलाता है।

प्राइमरी गोल्ड (Primary Gold)

24 केरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं।

रिफ्लेशन (Reflations)

रिसेशन अथवा मन्दी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की माँग बढ़े, इसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं।

सॉफ्ट करेन्सी (Soft Currency)

जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा की माँग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, तो ऐसी मुद्रा 'सॉफ्ट लोन' कहलाते हैं।

सॉफ्ट लोन (Soft Loan)

जिस ऋण को कम ब्याज और लम्बी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है, उसे 'सॉफ्ट करेन्सी' कहलाती है।

विक्रेता बाजार (Seller Market)

जब माँग अधिक होती है और पूर्ति कम, तब व्यापारी कमी का लाभ उठाकर वस्तुओं को मनमानी कीमतों पर बेचते हैं। ऐसे बाजार को 'विक्रेता बाजार' कहते हैं।

टैरिफ (Tariff)

किसी देश द्वारा आयतों पर लगाए गए कर को ही प्रायः 'टैरिफ' कहा जाता है।

सम्पत्ति कर (Wealth Tax)

किसी व्यक्ति द्वारा संचित सम्पत्ति के आधार पर लगने वाले कर को सम्पत्ति कर कहते हैं। यह एक प्रत्यक्ष कर है।

अधिविकर्ष (Overdraft)

बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपनी जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना 'अधिविकर्ष' कहलाता है।

विनिमय दर (Exchange Rate)

जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है, उसे 'विनिमय दर' कहते हैं।

विवेकीकरण (Rationaliation)

विवेक द्वारा उद्योगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना विवेकीकरण कहलाता है। इसके अन्तर्गत कार्य का पुनर्विभाजन करना, आधुनिक मशीनों का उपयोग करना तथा व्यर्थ बचे पदार्थों का उपयोग करना शामिल है।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

ग्रेशम के अनुसार यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हों, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन में बाहर कर देती है। इसे ही ग्रेशम के नियम के रूप में जाना जाता है।

आर्बिटेज (Arbitrage)

इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः विदेशी विनिमय के सन्दर्भ में किया जाता है। स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा बाजारों में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरन्त ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊँचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को 'आर्बिटेज' कहा जाता है।

अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)

पूँजी की वह अधिकतम मात्रा जिस सीमा तक कोई कम्पनी अपने शेयर जारी कर सकती है। यह आवश्यक नहीं कि कम्पनी द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य अधिकृत पूँजी के बराबर ही हो। यह अधिकृत पूँजी के बराबर या उससे कम हो सकता है, किन्तु अधिक नहीं।

बैड डैट (Bad Debt)

वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा सम्भव न हो।



बैलेंस शीट (Balance Sheet)

यह एक ऐसा लेखा-पत्र होता है जिसमें किसी व्यापारिक संस्थान के किसी निश्चित तिथि को समस्त आस्तियों व देनदारियों को दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के आधार पर फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

जन्म-दर (Birth Rate)

किसी क्षेत्र में किसी वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म-दर कहलाती है।

ब्लू चिप (Blue Chip)

यह शब्द प्रायः उन कम्पनियों के शेयरों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे शेयरों को खरीदने में हानि की सम्भावना बहुत कम होती है तथा जब चाहे, उचित मूल्य पर इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है।

मिश्रित माँग (Composite Demand)

जब कोई वस्तु एक से अधिक उपयोगों में प्रयोग की जाती है, तो ऐसी वस्तु की कुल माँग उसकी विविध उपयोगों हेतु माँग का योग होती है, यह मिश्रित माँग कहलाती है।

लागत प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost Push Inflation)

जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है एवं मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति लागत प्रेरित कही जाती है। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property)

बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) मानव की वह सम्पत्ति कहलाती है, जो उसकी स्वयं की बौद्धिक क्षमता एवं परिश्रम द्वारा तैयार की जाती है। कलात्मक रचनाएँ, वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्यिक और संगीतात्मक रचनाएँ, नवीन सिद्धान्त, सूत्र, उपकरण आदि सभी सृजन करने वाले व्यक्ति की बौद्धिक सम्पत्ति है। इस बौद्धिक सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति चुराकर कर स्वयं प्रयोग न करे इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पेटेंट' एवं समान रूप से अन्य कानून बनाए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (World Intellectual Property Organization) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पत्ति की सुरक्षा में सहायक होते हैं।

माइक्रो क्रेडिट (Micro Credit)

माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त छोटी-सी कर्ज राशि होती है, जो कि काफी करीब लोगों को दी जाती है, ताकि वे अपनी जीविका चलाने के लिए छोटा-मोटा काम शुरू कर सकें। सामान्य रूप से उनमें वे लोग शामिल होते हैं, जिनके पास बैंकों से ऋण पाने के बदले गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। वर्ष 2006 का नोबेल शान्ति पुरस्कार बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने वाले मुहम्मद यूनस और उनके ग्रामीण बैंक को प्रदान किया गया है।

मृत्यु दर (Death Duty)

यह एक प्रत्यक्ष कर है, जो मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति के हस्तांतरण से पूर्व उत्तराधिकारी को चुकाना होता है।

ऋण परिवर्तन (Debt Conversion)

किसी सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता पर यदि सरकार उसका वास्तविक भुगतान न करके उसके स्थान पर दूसरे नये ऋण पत्र जारी कर दे, तो यह प्रक्रिया 'ऋण परिवर्तन' कहलाती है।

मूल्य माँग (Price Demand)

किसी निश्चित मूल्य पर किसी समय में किसी वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा उस मूल्य पर वस्तु की माँग कहलाती है। इसे प्रायः माँग कहा जाता है।

मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति (Disinflation)

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं (जैसे साख-नियंत्रण आदि), उनके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य-स्तर गिरता है, तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है।

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक संसाधनों का पूर्व मूल्यांकन करके, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने हेतु संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लिया जाता है। तथा साधनों का आवंटन उसी के अनुसार किया जाता है।

विनिमय नियंत्रण (Exchange Control)

यह उस व्यवस्था का नाम है जिसके अन्तर्गत कोई देश विदेशी मुद्राओं के स्वतन्त्र बाजार पर नियंत्रण करके अपनी मुद्रा की विनिमय दर को उस दर से भिन्न रखने का प्रयास करता है, जो स्वतन्त्र बाजार में निर्धारित होती है।

गिफिन वस्तुएँ (Giffin Goods)

गिफिन वस्तुएँ कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर माँग का नियम लागू नहीं होता, बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी माँग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी से माँग भी कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास (Giffin's Paradox) कहा जाता है।

अल्पाधिकार (Oligopoly)

यदि किसी वस्तु के बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम (किन्तु दो से अधिक) होती है जिनके मध्य आपस में कोई समझौता सम्भव हो सकता हो, तो ऐसा बाजार अल्पाधिकार कहलाता है। इस प्रकार के बाजार में वस्तु एकसी भी हो सकती है तथा वस्तु में विभेद भी हो सकता है।

अनुसूचित व्यापारिक बैंक (Scheduled Commercial Banks)

अनुसूचित व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर दिया है। कुछ आवश्यक



शर्तें पूरी करने पर ही रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को इस अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है। जैसे बैंक की चुकता पूँजी तथा आरक्षित पूँजी का योग कम-से-कम 5 लाख रूपए होना चाहिए तथा बैंक का संचालन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जमाकर्ता के हित सुरक्षित हों।

प्रारम्भिक जमा तथा व्युत्पन्न जमा (Primary Deposits and Derivative Deposits)

प्रारम्भिक जमा से तात्पर्य उन जमा राशियों से है, जो नकदी अथवा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती हैं। इस प्रकार की नकद जमा का निर्माण बैंक नहीं करती, इन्हें निष्क्रिय जमा (Passive Deposits) अथवा प्रत्यक्ष जमा (Direct Deposits) भी कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई बैंक किसी को ऋण अथवा अग्रिम देता है, तो उस ऋण की राशि को उसके खाते में जमा कर दिया जाता है, इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जमा राशियाँ व्युत्पन्न जमा (Derivative Deposits) अथवा साख जमा अथवा गौण जमा (Secondary Deposits) कहलाती हैं। इन्हें सक्रिय जमा (Active Deposits) भी कहते हैं।

शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत किसी बैंक के एक प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएँ देशभर में फैली होती हैं और कभी-कभी कुछ शाखाएँ देश के बाहर भी होती हैं

इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

इसके अन्तर्गत एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि एक सीमित क्षेत्र में ये बैंक अपनी कुछ शाखाएँ भी स्थापित कर लेते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में अधिक लोकप्रिय रही है।

अग्रणी बैंक अथवा लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme)

यह योजना जिलों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 1969 में प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है। जिस बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है।

चेक (Cheque)

चेक एक प्रकार से विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange) होती है, जो एक निर्दिष्ट (विशिष्ट) बैंक के ऊपर आहरित होती है तथा माँग पर ही, जिसका भुगतान किया जाता है। चेक में तीन पक्ष होते हैं: (i) भुगतान का आदेश देने वाला, आहर्ता, (Drawer), (ii) जिसको आदेश दिया जाता है (Drawee) अर्थात् बैंक तथा (iii) जो भुगतान प्राप्त करता है अर्थात् चेक का धारक (Payee)।

विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुण्डी (Bill of Exchange)

यह एक ऐसा लिखित विपत्र है, जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को यह शर्तारहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विपत्र के वाहक को भुगतान कर दें। विनिमय हुण्डी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है अर्थात् इसका भुगतान केवल मुद्रा के रूप में ही होता है, किसी वस्तु जैसे कपड़ा, अनाज, सोना, चाँदी आदि के रूप में नहीं।

सामान्य हुण्डी एवं चेक (Hundi and Cheque)

चेक और हुण्डी में मुख्य अन्तर यह होता है कि चेक सदैव माँग पर ही देय होता है, जबकि कुछ हुण्डियाँ (दर्शनी) माँग पर देय होती हैं और कुछ निश्चित समय या अवधि के बाद।

साधारण या धारक चेक (Bearer Cheque)

जब तक संदेह करने के लिए कोई विशेष कारण न हो, धारक चेक का भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, भले ही वह चेक उसके नाम में हो अथवा नहीं। ऐसे चेक के भुगतान के लिए चेक जारी करने वाले (Drawer) के ऐसे ही निर्देश होते हैं कि भुगतान चेक के धारक को ही दे दिया जाए।

आदिष्ट चेक (Order Cheque)

जब किसी धारक चेक में से धारक (Bearer) शब्द को काट दिया जाए अथवा उस चेक पर आर्डर लिख दिया जाए, तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लने वाले व्यक्ति की पहचान करती है। इस औपचारिकता के बाद ही उस चेक का भुगतान किया जाता है।

रेखांकित चेक (Crossed Cheque)

जब चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर दो समानान्तर रेखाएँ बना दी जाती हैं, तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है। इस रेखांकित चेक का भुगतान बैंक काउंटर पर नकद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान किसी खाते में उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है।

पावक खाता चेक (Account Payee Cheque)

जब किसी चेक के प्रायः बाईं ओर ऊपर कोने में दो समानान्तर रेखाओं के मध्य 'Account Payee Only' लिख दिया जाता है, तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है, जिसके नाम वह चेक लिखा होता है अर्थात् इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

जब चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानान्तर रेखाओं के मध्य किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो यह चेक विशिष्ट रेखांकित चेक बन जाता है, तथा ऐसी



स्थिति में उस चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में जमा करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

यात्री चेक (Traveller's Cheque)

यात्री चेक किसी बैंक का द्वारा जारी किया गया ऐसा चेक होता है, जिसे जारी करते समय चेक के मुखपृष्ठ पर आवेदक (चेक प्राप्त करने वाला) के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इस चेक का भुगतान देशभर में सम्बन्धित बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। चेक भुगतान करने वाली शाखा भुगतान के समय पुनः चेक के मुखपृष्ठ पर धारक के हस्ताक्षर कराती है। दोनों हस्ताक्षर मिलने पर ही यात्री चेक का भुगतान होता है। बैंक द्वारा अधिकृत प्रमुख वाणिज्यिक संस्थान भी यात्री चेक नकद मुद्रा की भाँति स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के चेक यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि चेक खो जाने पर आवश्यक शर्तें पूरी करके डुप्लीकेट चेक प्राप्त किए जा सकते हैं।

पूर्व दिनांकित चेक (Ante-dated Cheque)

यदि आहरणकर्ता चेक लिखने की तारीख से पहले की कोई तारीख चेक पर लिखता है, तो ऐसे चेक को पूर्व दिनांकित (Ante dated) चेक कहा जाता है।

गतावधि अथवा पुराना चेक (Stale Cheque)

यदि चेक जारी करने की तारीख के बाद वह चेक समुचित अवधि (भारत में छः महीने) के अन्दर भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए, तो उसे गतावधि अर्थात् पुराना चेक कहा जाता है। बैंकर ऐसे चेक का आहरणकर्ता द्वारा पुष्टि के बिना भुगतान नहीं करता।

उत्तर दिनांकित चेक (Post-dated Cheque)

यदि किसी चेक का आहरणकर्ता चेक लिखते समय पर कोई आगामी तारीख लिख देता है, तो ऐसे चेक को उत्तर दिनांकित (Post-dated) चेक कहा जाता है। ऐसा चेक विधि-अमान्य तो नहीं होता, अपितु उस तारीख से प्रभावी होता है, जो उसमें लिखी गई है।

ड्राफ्ट (Draft)

यह एक ऐसा साख प्रपत्र है, जिसमें किसी बैंक द्वारा अपनी किसी अन्य शाखा को पावक (Draft) के आदेशानुसार ड्राफ्ट में उल्लिखित धनराशि माँग पर भुगतान करने का आदेश होता है। ड्राफ्ट किसी बैंक द्वारा पहले से भुगतान प्राप्त करके जारी किया जाता है तथा जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसकी पहचान करने के बाद इसका भुगतान कर दिया जाता है। ड्राफ्ट भी चेक की भाँति रेखांकित अथवा आरेखांकित हो सकता है।

समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस (Clearing House)

समाशोधन गृह अथवा क्लीयरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है, जहाँ 3-4 अथवा उससे अधिक बैंक होती हैं। क्लीयरिंग हाउस वह स्थान है जहाँ विभिन्न के प्रतिनिधि प्रतिदिन एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के

मध्य चेकों का आदान-प्रदान तथा जमा-खर्च होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का लेन-देन बहुत ही सरलता से तथा थोड़े समय में ही सम्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को समाशोधन (Clearing) कहते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा है, वहाँ रिजर्व बैंक में ही समाशोधन गृह होता है। जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में समाशोधन गृह होता है।

बैंकिंग एवं आर्थिक संक्षिप्तीकरण (Banking and Financial Abbreviation)

A			
A/C	अकाउंट	BRS	बेस रेट सिस्टम
ABO	एक्यूमुलेटेड बेनेफिट ऑब्लिगेशन	BCBS	बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन
ABP	ऑटोमैटिक बिल पेमेंट	BSR	बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स
ACF	ऑटो-कोरिलेशन फंक्शन	C	
ACH	ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस	CAD	कैपिटल अकाउंट डेफिसिट
AD	ऑथोराइज्ड डीलर	CAER	सेंटर फॉर असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च
ADB	एशियन डेवलपमेंट बैंक	CAG	कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
ADR	अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट	CBDT	सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज
AERA	एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेग्युलेटरी अथॉरिटी	CBS	कन्सोलिडेटेड बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स
AFPPD	एशियन फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट	CC	कैश क्रेडिट
AFS	एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट	CCB	क्रेडिट कार्ड बिजनेस
AFS	अवेलेबल फॉर सेल	CCG	क्रेडिट कार्ड ग्रीवेंसिज
AG	एकाउन्टेन्ट जनरल	CD	सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट
AGM	एन्युअल जनरल मीटिंग	CD Ratio	क्रेडिट डिपॉजिट रेश्यो
AIRCSC	ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी	CDBS	कमेटी ऑफ डायरेक्शन ऑन बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स
AITUC	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	CF	कंपनी फाइनेंस
ALM	असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट	CFRA	कंबाइंड फाइनेंस एंड रिवेल्यूशन अकाउंट
AO	एडिटिव आउटलॉयर्स	CGRA	करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूशन अकाउंट
APEC	एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन	CIBIL	क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
APR	एन्युअल पर्सेंटेज रेट	CII	कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
APY	एन्युअल पर्सेंटेज यील्ड	CO	कैपिटल आउटले
AR	ऑटो रिग्रेशन	CP	कॉमर्शियल पेपर
ARIMA	ऑटो रिग्रेशन इंटेग्रेटेड मूविंग एवरेज	CPI	कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स
ARM	ऐडजस्टेबल रेट मॉर्टगैज	CPI-IW	कन्ज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स
ASEAN	एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स	CR	कैपिटल रिसिप्ट
ASSOCHAM	एसोसियेटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	CRAR	कैपिटल टू रिक्स वेटेड असेट रेश्यो
ATM	एसिनक्रोनस ट्रांसफर मोड	CRISIL	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
ATM	ऑटोमेटेड टैलर मशीन	CRR	कैश रिजर्व रेश्यो
B		CSIR	काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
BER	बैंक एक्सचेंज रेट	CSO	सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन
BIFR	बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकन्स्ट्रक्शन (औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड)	CVC	सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
BIS	बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट्स	CVV	कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू
BIS	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स/ब्रिटिश इनफॉर्मेशन सर्विसेज	D	
BOP	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स	DAP	डेवलपमेंट एक्शन प्लान
BPMS	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैनुअल फिफ्थ एडिशन	DBOD	डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट
BPSD	बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिविजन, डीइएसएसीएसए, आरबीआई	DBS	डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, आरबीआई
		DCA	डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स
		DCB	डिमांट कलेक्शन एंड बैलेंस
		DCCB	डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
		DCM	डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट (आरबीआई)



DD	डीमांड ड्राफ्ट
DDS	डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स
DEIO	डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस
DESACS	डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर सर्विसिज
DGBA	डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, आरबीआई
DGCI&s	डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स
DI	डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
DICGC	डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
DID	डिस्चार्ज ऑफ इंटरनल डेट
DIN	डॉक्यूमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर
DMA	डिपार्टमेंट लाइज्ड मिनीस्ट्रीज अकाउंट
DRI	डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटररेस्ट स्कीम
DSBB	डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड बुलेटिन बोर्ड
DVP	डिलीवरी सर्विज पेमेंट
E	
ECB	यूरोपियन सेंट्रल बैंक
ECB	एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग
ECGC	एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन
ECS	इलैक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम
EDMU	एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट
EEA	एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट
EEC	यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी
EEC	यूरोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी
EEPC	एक्सचेंज अर्नर्स फॉरन करेंसी
EFR	एक्सचेंज फ्लकचुएशन रीजर्व
EMD	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट
EMI	इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट
EPF	एमप्लॉइज प्रोविडेंड फंड
EPPI	एक्सपोर्ट प्रोमोशन इंस्ट्रुमेंटल पार्क
EPZ	एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
EUR	यूरो
EWP	अर्ली विड्रॉल पेनल्टी
EXIM Bank	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया
F	
FAO	फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
FAT	फाइनेंशियल एक्टिविटीज टैक्स
FCA	फॉरन करेंसी असेट्स
FCCB	फॉरन करेंसी कंवर्टिबल बांड
FCNR(B)	फॉरन करेंसी नॉन रेजीडेंट (बैंक्स)
FCNRA	फॉरन करेंसी नॉन रेजीडेंट अकाउंट

FCNRD	फॉरन करेंसी नॉन रिपैरियेबल डिपॉजिट
FCS	फॉरन करेंसी सरचार्ज
FDI	फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
FEMA	फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
FERA	फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
FI	फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
FI	फाइनेंशियल इनक्लूजन
FICCI	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
FII	फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
FIIA	फॉरन इन्वेस्टमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑथोरिटी
FIMMDA	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरीवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
FIPB	फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड)
FISIM	फाइनेंशियल इंटरमिडिएशन सर्विसेज इन्डायरेक्टली मेजर्ड
FLAS	फॉरन लाइबिलिटीज एंड असेट्स सर्वे
FOF	फ्लो ऑफ फंड्स
FPI	फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट
FRA	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट
FRBM	फिस्कल रिस्पॉसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003
FRM	फिक्स्ड रेट मॉर्टगेज
FRN	फ्लोटिंग रेट नोट
FSS	फार्मर्स सर्विसेज सोसाइटीज
FWG	फर्स्ट वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाय
G	
GATT	जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड
GDP	ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट
GDR	ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट
GFD	ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट
GFS	गवर्नमेंट फाइनेंस स्टेटिस्टिक्स
GIC	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
GNP	ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
GPD	ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट
GPF	जनरल प्रॉविडेंड फण्ड
G-Sec	गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
H	
HDFC	हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन
HFT	हेल्ड फॉर ट्रेडिंग
HICP	हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसिस
HO	हेड ऑफिस
HUDCO	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
I	



IBPS	इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन
IBRD	इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट
IBS	इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
ICAR	इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
ICD	इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट
ICICI	इंस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
ICRA	इंडियास् क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
IDB	इंडिया डेवलपमेंट बैंड्स
IDBI	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
IDD	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
IFAD	इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट
IFC	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
IFC(W)	इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (वॉशिंगटन)
IFCI	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
IFR	इन्वेस्टमेंट फ्लकचुएशन रिजर्व अकाउंट
IFRS	इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड
IFS	इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स
IFSC	इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम कोड
IIBI	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया
IIP	इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
IIP/InIP	इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोलीशन
IMD	इंडिया मिलेनियम डिपॉजिटर्स
IMF	इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
IN	इंडिया
INR	इंडियन रुपी
IOTT	इनपुट-आउटपुट ट्रांजेक्शन टेबल
IP	इंटरनेट पेमेंट
IR	इंटरनेट रेट
IRBI	इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया
ISDA	इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन
ISIC	इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन
ISO	इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन
ITO	इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
ITPO	इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
ITRS	इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम
IWGDS	इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स
K	
KCC	किसान क्रेडिट कार्ड
KVIC	खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन
KYC	नो योर कस्टमर
L	
LAF	लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेसिलिटी
LAMPS	लार्ज-साइज आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटीज

LAS	लोन एंड एडवांसेज बाई स्टेट्स
LBD	लेंड डेवलपमेंट बैंक
LBS	लोकेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
LBS	लीड बैंक स्कीम
LC	लैटर ऑफ क्रेडिट/लाइन ऑफ क्रेडिट
LERMS	लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम
LIC	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
LTO	लॉग टर्म ऑपरेशन
M	
M1	नैरो मनी
M3	ब्रॉड मनी
MA	मूविंग एवरेज
MC	माइक्रो क्रेडिट
MCA	मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स
MFN	मोस्ट फेवर्ड नेशन
MICR	मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर
MIGA	मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी
MIS	मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम
MMSE	मिनिमम मीन स्क्वार्ड एरर्स
MODVAT	मोडीफाइड वैल्यू एडेड टैक्स
MoF	मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
MOF	मास्टर ऑफिस फाइल
MRM	मॉनीटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म
MSS	मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम
MT	मेल ट्रांसफर
MTM	मार्केट-टू-मार्केट
N	
NABARD	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
NAC(LTO)	नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (लॉग टर्म ऑपरेशन)
NAFTA	नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
NAIO	नॉन एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडेपेंडेंट ऑफिस
NAS	नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स
NASSCOM	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
NBC	नॉन बैंकिंग कंपनीज
NBFC	नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज
NEC	नॉट एल्सवेयर क्लासीफाइड
NEER	नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
NEFT	नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
NFA	नॉन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स
NFD	नॉन फिसकेल डेफिसिट
NGO	नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन
NHB	नेशनल हाउसिंग बैंक
NIC	नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन
NNML	नैट-नॉन मॉनेट्री लाइबिलिटीज
NOL	नैट ऑपरेटिंग लॉस



NPA	नॉन परफॉर्मिंग असेट्स
NPD	नैट प्राइमरी डेफिसिट
NPRB	नैट प्राइमरी रेवेन्यू बैलेंस
NPV	नैट प्रेजेंट वैल्यू
NR(E)RA	नॉन रेजीडेंट (एक्सटर्नल) रुपी अकाउंट
NR(NR)RA	नॉन रेजीडेंट (नॉन रिपैट्रियेबल) रुपी अकाउंट
NRE	नॉन रेजीडेंट एक्सटर्नल
NREP	नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम
NRG	नॉन रेजीडेंट गवर्नमेंट
NRI	नॉन रेजीडेंट इंडियन
NSC	नेशनल स्टेटिस्टिक्स कमीशन
NSSF	नेशनल स्मॉल सेविंग फंड
NSSO	नेशनल सेम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन
O	
OD	ओवर ड्राफ्ट
ODA	ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस
OECD	ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
OECD	ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक को-ऑपरेशन
OLTAS	ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम
OMO	ओपन मार्केट ऑपरेशंस
OPEC	ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज
OSCB	अदर इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक
P	
PAC	पब्लिक एकाउंट्स कमिटी/प्रोविन्शियल आम्ड कौन्सिलर (उत्तर प्रदेश)
PACF	पार्शियल ऑटो-कोरिलेशन फंक्शन
PACS	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी
PAN	परमानेंट एकाउंट नंबर
PCARDB	प्राइमरी को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
PD	प्राइमरी डेफिसिट
PDAI	प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
PDO	पब्लिक डेट ऑफिस
PDO-NDS	पब्लिक डेट ऑफिस-कम-नेगोशिएटिड डीलिंग सिस्टम
PDs	प्राइमरी डीलर्स
PES	पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे
PF	प्रोविडेंट फंड
PG	पेमेंट गेटवे
PIN	पोस्टल इन्डेक्स नंबर/पर्सनल आइडेंटिटी नंबर
PIO	पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन
PNB	पंजाब नेशनल बैंक
PO	प्रिंसिपल ऑफिस
PRAN	परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर

PRB	प्राइमरी रेवेन्यू बैलेंस
PSE	पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज
PSL	प्रायरीटी सेक्टर लेंडिंग
PUC	पेड अप केपिटल
Q	
QRR	क्विक रिव्यू रिपोर्ट
R	
RBI	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
RCBI	रूरल को-ऑपरेटिव बैंक इन इंडिया
RD	रेवेन्यू डेफिसिट
RDBMS	रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
RE	रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
REER	रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
RFC	रेजीडेंट्स फॉरन करेंसी
RIB	रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स
RIDF	रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
RLA	रिकवरी ऑफ लॉस एंड एडवांसेज
RLC	रिपेयरमेंट ऑफ लॉस टू सेन्टर
RLP	रिटेल लोन पोर्टफोलियो
RMB	रेनमिनबी (चीन की मुद्रा)
RNBC	रेजीड्यूरी नॉन-बैंकिंग कंपनीज
RO	रीजनल ऑफिस
RoCs	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
RPA	रुपी पेमेंट एरिया
RPCD	रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट (आरबीआई)
RR	रेवेन्यू रिसिट
RRB	रीजनल रूरल बैंक
RRR	रिवर्स रेपो रेट
RTGS	रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट
RTP	रिजर्व ट्रंच पोजीशन
RUCB	रेगुलेशन ऑफ अरबन को-ऑपरेटिव बैंक
RUF	रिवॉल्विंग अंडरराइटिंग फेसिलिटी
RWA	रिस्क वेटेड असेट
S	
SAM	सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स
SAS	स्टेटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम
SBI	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
SC	शेड्यूल कास्ट
SCARDB	स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
SCB	स्टेट-को ऑपरेटिव बैंक
SCB	शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक
SCS	साइज क्लास स्ट्राटा
SDDS	स्पेशल डेटा डेसिमिनेशन स्टैंडर्ड्स
SDR	स्पेशल ड्राइंग राइट
SEBI	सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया



SEBs	स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स
SFC	स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन
SGL	सब्सिडियरी जनरल लेजर
SGSY	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
SHGs	सेल्फ हेल्प ग्रुप
SIDBI	स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
SIDC	स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
SI-SPA	सिस्टम इंफ्रूवमेंट स्कीम अंडर स्पेशल प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर
SJSRY	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
SLR	स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेश्यो
SLRS	स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्केवेन्जर्स
SNA	सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स
SMG	स्टैंडिंग मॉनिटरिंग ग्रुप
SRWTO	स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन
SSI	स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
SSSBs	स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज
ST	शेड्यूल ट्राईब
SWG	सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई
T	
TBs	ट्रेजरी बिल्स
TFS	टेकआउट फाइनेंसिंग स्कीम
TT	टेलिग्राफिक ट्रांसफर
U	
UALM	अंडरस्टैंडिंग असैट लाइबिलिटी मिसमैच
UBB	यूनिफार्म बैलेंस बुक
UBD	अरबन बैंक्स डिपार्टमेंट
UCA	अंडरस्टैंडिंग कैपिटल एडीक्वेसी
UCB	अरबन को-ऑपरेटिव बैंक
UCN	यूनिफार्म कोड नंबर
UDI	अंडरस्टैंडिंग डिपॉजिट इश्योरेंस
UNCTAD	यूनाइटेड नेशन्स कार्नेक्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट
UNDP	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
UNIDO	यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
USD	यूएस डॉलर्स
UTI	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया
UUB	अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल बैंकिंग
V	
VAT	वैल्यू एडेड टैक्स
VBM	वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट
VC	वेंचर कैपिटल

W	
WEF	वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
WGMS	वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई एनालिटिक्स एंड मैथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन
WPI	होलसेल प्राइस इंडेक्स
WSS	वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट
WTO	वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (विश्व व्यापार संगठन)
Y	
YTM	यील्ड टू मैच्योरिटी
Z	
ZBA	जीरो बैलेंस अकाउंट
ZO	जोनल ऑफिस



वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Questions)

- निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक राज्य में बैंकिंग लोकायुक्त की नियुक्ति होती है?
 - भारत सरकार का समाज-कल्याण मंत्रालय
 - कम्पनियों के रजिस्ट्रार
 - भारतीय रिजर्व बैंक
 - इण्टरनल बैंकिंग
 - इनमें से कोई नहीं
- भारत के वित्त मंत्री और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में 'फाइनेन्सियल इनक्लूजन' पर जोर दिया है। 'फाइनेन्सियल इनक्लूजन' से इनका मतलब क्या है?
 - देश के सभी भागों में समाज के सभी वर्गों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना।
 - सामाजिक कल्याण के उपाय के रूप में बिना किसी लाभार्जन के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हर प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराना।
 - इसका अर्थ यह है कि अब से बैंकों को अपनी शाखाएँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोलनी चाहिए।
 - केवल (1) और (2)
 - केवल (2)
 - केवल (1) और (3)
 - केवल (1)
 - इनमें से कोई नहीं।
- 'JETRO' का पूरा रूप निम्नलिखित में से कौनसा है?
 - Joint External Trade Organization
 - Japan External Trade Organization
 - Japan Export and Trade Organization
 - Joint Export and Trade Organization
 - इनमें से कोई नहीं।
- भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पदों का प्रावधान है?
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - इनमें से कोई नहीं।
- झारखण्ड में स्थित झारखण्ड ग्रामीण बैंक निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा प्रायोजित है?
 - बैंक ऑफ इण्डिया
 - बैंक ऑफ बड़ौदा
 - इलाहाबाद बैंक
 - भारतीय स्टेट बैंक
 - इनमें से कोई नहीं।
- निम्नलिखित में से कौनसी कंपनी बीमा व्यवसाय में नहीं है?
 - ICICI प्रूडेंशियल
 - बजोज एलियांज
 - टाटा AIG
 - रॉयल ऑर्किड
 - इनमें से कोई नहीं।
- बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई कम्पनी सार्वजनिक निर्गम लाने की योजना बना रही है। इसका क्या अर्थ है?
 - कंपनी के शेयरों/बैंकों/केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों आदि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के जरिए ही जारी किए जाएंगे।
 - आम जनता को कंपनी के शेयर प्राथमिक बाजार लके जरिये ही जारी किए जाएंगे।
 - इसका अर्थ है कुछ हिस्सेदार/प्रवर्तक कम्पनी छोड़ने को तैयार हैं। इसलिए वे अपने शेयर आम जनता को बेचना चाहते हैं।
 - केवल 1
 - केवल 2
 - केवल 3
 - केवल 1, 2, व 3 सभी
 - इनमें से कोई नहीं।
- जब भी कोई व्यक्ति व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करना चाहे, उसे बैंक से अवश्य सम्पर्क करना पड़ता है। इस बारे में बैंक क्या सेवाएँ देते हैं?
 - चालू खातों को परिचालित करके, चेकों का भुगतान करके और उनके लिए भुगतान प्राप्त करके बैंक भुगतान एजेंट के रूप में काम करते हैं।
 - उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए लेखा बहियों का रखरखाव, ताकि उन्हें नियमित आधार पर लेखा/वित्त कर्मचारी नियुक्त न करना पड़े।
 - व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ओवरड्राफ्ट, किस्तों पर ऋण, कर्जा या अर्गिम के जरिए धन उधार देना।
 - केवल 1
 - केवल 2
 - केवल 3
 - केवल 1 व 2
 - इनमें से कोई नहीं।
- इन दिनों बैंक "शाखा रहित बैंकिंग" पर ज्यादा बल दे रहे हैं। वास्तव में इसका क्या अर्थ है?
 - पुराने अच्छे दिनों की तरह अब बैंकों की ज्यादा शाखाएँ नहीं होंगी, बल्कि शाखाओं की संख्या सीमित होगी और केवल विनिर्दिष्ट कोर बिजनेस ही करेंगी।
 - बैंक कई डिलिवरी चैनल आरम्भ करेंगे या चलाएंगे जैसे ATMs, मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग आदि ताकि लोगों को अपनी सामान्य बैंकिंग आदि ताकि लोगों को अपनी सामान्य बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए बैंक में न जान पड़े।
 - इसका अर्थ है कि रोजमर्रा के सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों के लिए बैंक केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। चेकों/नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
 - केवल 1
 - केवल 2
 - केवल 1 व 2
 - केवल 2 व 3
 - इनमें से कोई नहीं।
- निम्नलिखित में से कौनसा बैंक का कार्य नहीं है?
 - परियोजना वित्त देना
 - म्युचुअल फण्ड बेचना
 - CRR/रिपो दर/SLR आदि जैसी नीतिगत दरें तय करना
 - ग्राहकों की ओर से भुगतानों का निपटान
 - इनमें से कोई नहीं।
- भारत में निम्नलिखित में से कौनसा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है?
 - कृषि क्षेत्र
 - औद्योगिक क्षेत्र
 - परिवहन क्षेत्र
 - बैंकिंग क्षेत्र
 - इनमें से कोई नहीं।
- NIS का पूर्णरूप क्या है?
 - नेशनल इन्फेक्शियस डिजीजिज सेमीनार
 - नेशनल इरीगेशन शेड्यूल
 - नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
 - नेशनल इन्फोर्मेशन सेक्टर
 - इनमें से कोई नहीं।



13. दो देशों के बीच वस्तु-विनिमय (एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज) को क्या कहा जाता है?
 (A) व्यापार शेष (B) द्विपक्षीय व्यापार
 (C) व्यापार परिमाण (D) बहुपक्षीय व्यापार
 (E) इनमें से कोई नहीं।
14. विशेष आहरण अधिकार (SDR) निम्नलिखित में से किस संगठनों / एजेंसियों की आरक्षित परिसम्पत्तियों का मौद्रिक यूनिट है?
 (A) विश्व बैंक
 (B) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
 (C) एशियाई विकास बैंक (ADB)
 (D) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
15. वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त 'NBFC' का पूरा रूप क्या है?
 (A) New Banking Finance Company
 (B) National Banking & Finance Corporation
 (C) New Business Finance & Credit
 (D) All of the above
 (E) इनमें से कोई नहीं।
16. 'इंटानेट' क्या है?
 (A) सूचना को आन्तरिक रूप से अन्तरित करने के लिए प्रयुक्त आन्तरिक इंटरनेट
 (B) सूचना को बाहरी कम्पनी को अन्तरित करने के लिए प्रयुक्त आन्तरिक इंटरनेट
 (C) किसी एक संस्था की सूचना सम्बन्धी आन्तरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया आन्तरिक नेटवर्क
 (D) सूचनाओं को दो संस्थाओं के बीच अन्तरित करने के लिए डिजाइन किया गया आन्तरिक नेटवर्क
 (E) इनमें से कोई नहीं।
17. बैंकेश्युरन्स-----को बेची जा सकती है।
 (A) सभी बैंकों
 (B) सभी बीमा कंपनियों
 (C) बीमा एजेंटों
 (D) सभी मौजूदा और भावी बैंक ग्राहकों
 (E) इनमें से कोई नहीं।
18. SME ऋण का लक्ष्य समूह है-
 (A) सभी बिजनेसमैन (B) सभी प्रोफेशनल
 (C) सभी (D) उपर्युक्त सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
19. नाबार्ड (NABARD) है:
 (A) सार्वजनिक क्षेत्र की एक स्वायत्त संस्था
 (B) भारतीय स्टेट बैंक की एक सहायिका
 (C) सार्वजनिक क्षेत्र का एक राष्ट्रीयकृत बैंक
 (D) एक सर्वोच्च कृषि बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
20. निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की 'रियायती ऋण देने वाली खिड़की' (Soft Loan Window) के रूप में जाना जाता है?
 (A) आईडीए (IDA) (B) आईएफसी (IFC)
 (C) आईएमएफ (IMF) (D) आईबीआरडी (IBRD)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
21. निम्नलिखित में से कौनसी संस्था मूलतः वित्तीय/आर्थिक मामलों से संबंधित नहीं है?
 (A) WTO (B) WHO
 (C) IDA (D) IBRD
 (E) इनमें से कोई नहीं।
22. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
 (A) 1982 (B) 1983
 (C) 1984 (D) 1985
 (E) इनमें से कोई नहीं।
23. काले धन को बाहर निकालने के लिए भारत में 1000 रूपए के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था?
 (A) 1968 (B) 1978
 (C) 1988 (D) 1998
 (E) इनमें से कोई नहीं।
24. भारत में अग्रणी बैंक (Lead Bank) योजना की शुरुआत निम्नलिखित की अनुशंका पर की गई थी:
 (A) एम. नरसिम्हम (B) एफ.के.एफ. नरीमन
 (C) डी.टी. लकड़ावाला (D) वी.एम. दाण्डेकर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
25. वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है:
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (B) स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा
 (C) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा (D) वित्त मंत्रालय द्वारा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
26. सूक्ष्म-वित्त (Micro finance) के लिए भारत में शीर्षस्थ बैंक कौनसा है?
 (A) भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
 (B) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
 (C) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
 (D) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
27. लैफर वक्र निम्नलिखित के मध्य का सम्बन्ध प्रदर्शित करता है:
 (A) प्रति व्यक्ति आय तथा पर्यावरणीय प्रदूषण
 (B) बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर
 (C) कर की दर तथा कर राजस्व
 (D) आर्थिक संवृद्धि तथा आय विषमता
 (E) इनमें से कोई नहीं।
28. आधुनिक मुद्रा नहीं है:
 (A) सांकेतिक मुद्रा (Token Money)
 (B) अधिदेश मुद्रा (Fiat Money)
 (C) साख मुद्रा (Fiduciary Money)
 (D) पूर्णकाय मुद्रा (Full Bodied Money)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
29. एक नया आवास कीमत सूचकांक रेजीडेक्स (RESIDEX) निम्नलिखित ने जारी किया है:
 (A) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (B) योजना आयोग
 (C) आवास विकास वित्त निगम (D) राष्ट्रीय आवास बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
30. बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है:
 (A) OCR (B) MICR
 (C) OMR (D) PMR
 (E) इनमें से कोई नहीं।



31. नरसिंहम समिति का संबंध है:
 (A) उच्च शिक्षा सुधारों से (B) कर रचना सुधारों से
 (C) बैंकिंग संरचना सुधारों से (D) नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से
 (E) इनमें से कोई नहीं।
32. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए?
 (A) ₹ 85 करोड़ (B) ₹ 115 करोड़
 (C) ₹ 200 करोड़ (D) ₹ 250 करोड़
 (E) इनमें से कोई नहीं।
33. 'स्मार्ट मनी' शब्द का प्रयोग होता है:
 (A) इन्टरनेट बैंकिंग में (B) क्रेडिट कार्ड में
 (C) बैंक में बचत खाता में (D) बैंक में चालू खाता में
 (E) इनमें से कोई नहीं।
34. विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था:
 (A) समाज के कमजोर वर्ग के लिए
 (B) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए
 (C) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए
 (D) बड़े निर्यातकों के लिए
 (E) इनमें से कोई नहीं।
35. भारत में पूँजी निर्माण के आँकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है?
 (A) भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
 (B) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक
 (C) भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक
 (D) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
 (E) इनमें से कोई नहीं।
36. आर. बी. आई. के 'खुले बाजार संचालन' (ओपेन मार्केट ऑपरेशन) से आशय है:
 (A) शेयरों का क्रय और विक्रय (B) विदेशी मुद्रा की नीलामी
 (C) ऋण पत्रों में व्यवसाय (D) सोने का सौदा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
37. A.T.M. (Automated Teller Machine) जारी करने वाला पहला बैंक है:
 (A) अमरीकन बैंक (B) सीटी बैंक
 (C) बार्कलेज बैंक (D) एक्सिस बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
38. वर्ड बैंक द्वारा चलाया गया शिक्षा का वह अभिमान जो काफी सफल रहा:
 (A) सर्व शिक्षा अभियान (B) बालिका शिक्षा योजना
 (C) गोकुल शिक्षा योजना (D) सर्वधारा शिक्षा योजना
 (E) इनमें से कोई नहीं।
39. बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है:
 (A) ब्याज की बाजार दर (B) निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग
 (C) ऋण देने वाले बैंक (D) नकदी आरक्षण अनुपात
 (E) इनमें से कोई नहीं।
40. निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता?
 (A) राष्ट्रीय बचत पत्र (B) दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड
 (C) बीमा पॉलिसी (D) भविष्य निधि
 (E) इनमें से कोई नहीं।
41. जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र. देशान्तरण (Migration) की प्रवृत्ति हो, उसे कहते हैं:
 (A) दुर्लभ मुद्रा (Scarce currency)
 (B) सुलभ मुद्रा (Soft currency)
 (C) स्वर्ण मुद्रा (Gold currency)
 (D) गरम मुद्रा (Hot currency)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
42. साधारणतया नकदी-कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) निर्धारित होता है:
 (A) बाजार की शक्तियों के स्वतंत्र व्यवहार (Free Play) द्वारा
 (B) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
 (C) RBI द्वारा
 (D) तीनों द्वारा मिलकर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
43. निम्नलिखित में से कौनसा भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market) का अंग नहीं है?
 (A) BSE (B) NSE
 (C) SEBI (D) RBI
 (E) इनमें से कोई नहीं।
44. मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है?
 (A) कांडला (B) सांताक्रुज
 (C) नोएडा (D) फाहटा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
45. विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से एक आईसीबीसी किस देश का वाणिज्यिक बैंक है?
 (A) अमरीका (B) चीन
 (C) सऊदी अरब (D) स्विट्जरलैण्ड
 (E) इनमें से कोई नहीं।
46. निम्नलिखित में से कौन परिमाणमात्मक साख नियन्त्रण (Quantitative Credit control) का उपाय है?
 (A) नैतिक दबाव (Moral Suasion)
 (B) बैंक दर (Bank Rate)
 (C) उपभोक्ता साख का नियमन
 (D) विशिष्ट प्रतिभूतियों पर मार्जिन अनुपात का निर्धारण
 (E) इनमें से कोई नहीं।
47. आयोजन में 'कोर सेक्टर' का अर्थ है:
 (A) कृषि (B) चयनित आधारभूत उद्योग
 (C) रक्षा उद्योग (D) लोगा एवं इस्पात उद्योग
 (E) इनमें से कोई नहीं।
48. मुद्रा-स्फीति (Inflation) में किसे लाभ होता है?
 (A) बचत कर्ता (Saver) को (B) ऋणदाता (Creditor) को
 (C) ऋणी (Debtor) को (D) पेंशनधारी (Pensionholder) को
 (E) इनमें से कोई नहीं।
49. हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) का प्रत्यक्ष प्रभाव है:
 (A) अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगती हैं
 (B) अतिरिक्त मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, फलस्वरूप बाजार और अधिक स्पर्धात्मक हो जाता है
 (C) कीमत स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण होता है
 (D) मांग तथा पूर्ति दोनों में वृद्धि होती है



- (E) इनमें से कोई नहीं।
50. मुद्रा की पूर्ति की निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसे भारत में 'विस्तृत मुद्रा' (Broad Money) कहा जाता है?
 (A) M_1 (B) M_2
 (C) M_3 (D) M_4
 (E) इनमें से कोई नहीं।
51. अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) वह बैंक होता है जो:
 (A) राष्ट्रीयकृत (Nationalised) हो
 (B) अन्तराष्ट्रीयकृत (Not Nationalised) हो
 (C) विदेश में हो
 (D) आर. बी. आई. की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो
 (E) इनमें से कोई नहीं।
52. अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्रव्यता (लिक्विडिटी) बनाये रखने हेतु जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं?
 (A) ब्याज रेट (B) रेपो रेट
 (C) बैंक रेट (D) प्रतिवर्ती रेपो रेट
 (E) इनमें से कोई नहीं।
53. निम्नलिखित में से कौनसा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है?
 (A) राज्य सहकारी बैंक (B) व्यापारिक बैंक
 (C) प्राथमिक ऋण समितियाँ (D) भूमि विकास बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
54. भूमि विकास बैंक भाग है:
 (A) व्यापारिक बैंकों का (B) आई. डी. बी. आई. का
 (C) एफ. सी. आई. का (D) सहकारी साख संरचना का
 (E) इनमें से कोई नहीं।
55. आजकल हम वित्त जगत और मुद्रा बाजार में प्रयुक्त शब्द 'डेरिवेटिव' के बारे में समाचार पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौनसा कथन ठीक से बताता है कि डेरिवेटिव क्या है और मुद्रा/वित्त बाजार को कैसे प्रभावित करता है?
 (1) डेरिवेटिव व्यक्तियों और कम्पनियों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा पाने में समर्थ बनाते हैं।
 (2) डेरिवेटिव बैंक में सावधि जमा की तरह हैं और बैंक में बेकार पड़े पैसे को निवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका है?
 (3) डेरिवेटिव वित्तीय लिखते हैं, भारत में जिनका प्रयोग ब्रिटिश राज्य के दौरान भी होता था।
 (A) केवल 3 (B) केवल 2
 (C) केवल 1 (D) 1,2 और 3 सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
56. बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी अनुपात/दर में कुछ आधार बिन्दुओं का परिवर्तन या संशोधन किया है। आधार बिन्दु क्या होता है?
 (A) एक सौ बिन्दु का दस प्रतिशत
 (B) 1% का सौवाँ हिस्सा
 (C) 10% का सौवाँ हिस्सा
 (D) 1,000 का दस प्रतिशत
 (E) इनमें से कोई नहीं।
57. जिस बाजार में स्टॉक और बॉण्ड जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ बेची और खरीदी जाती हैं, उसे सामान्यतः ----- कहते हैं।
 (A) कमोडिटी एक्सचेंज (B) कैपिटल मार्केट
 (C) बुल मार्केट (D) बुलियन मार्केट
 (E) इनमें से कोई नहीं।
58. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया निम्न में से कौन-सा निर्णय देश में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बढ़ावा देगा?
 (A) कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कार्सपोंण्डेंट के रूप में नियुक्त करना
 (B) सेवा देने के लिए ग्राहक से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रभार वसूल करना
 (C) बिना सेवा वाले क्षेत्रों में रोजाना कम-से-कम 50 नए खाते खोलने के लिए बैंकों को कहना
 (D) B और C दोनों
 (E) इनमें से कोई नहीं।
59. कॉरपोरेट गवर्नेंस से सम्बन्धित मुद्दों पर N.R. नारायण मूर्ति समिति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी?
 (A) सेबी
 (B) RBI
 (C) CII
 (D) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
 (E) इनमें से कोई नहीं।
60. निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन/एजेंसी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) को संकलित और जारी करती है?
 (A) कम्पनी रजिस्ट्रार (B) भारतीय उद्योग परिसंघ
 (C) भारतीय रिजर्व बैंक (D) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
 (E) इनमें से कोई नहीं।
61. अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी/कुछ बैंक/बैंकों को उनके द्वारा दी गई राशि 'राइट ऑफ़' करनी पड़ती है। बैंकिंग शब्दावली में पद 'राइट ऑफ़' का अर्थ क्या है?
 (A) कागज पर मंजूर ऋण, किन्तु बैंक को इनका प्रावधान अभी करना है ताकि उधारकर्ता धन का आहरण कर सकें
 (B) बड़े कॉर्पोरेट ऋण, जिनके लिए बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेना पड़ता है
 (C) ऐसे ऋण जिसके लिए दस्तावेजीकरण अभी पूरा करना बाकी है
 (D) अशोध्य/अवसूलीयोग्य ऋण
 (E) इनमें से कोई नहीं।
62. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित बेंचमार्क मूल उधार दर (BPLR) सम्बन्धी कार्य-दल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था?
 (A) डॉ. के. सी. चक्रवर्ती (B) श्री दीपक मोहंती
 (C) श्री आर. भास्करन (D) श्री ओ. पी. भट्ट
 (E) इनमें से कोई नहीं।
63. सामान्यतः बैंक को निम्नलिखित में से सम्बन्धित मसलों ----- से निपटना नहीं पड़ता है।
 (A) भुगतान व निपटान प्रणाली
 (B) लेनदारों के संविदात्मक अधिकार
 (C) बौद्धिक सम्पदा अधिकार
 (D) दिवालियापन के मामले
 (E) इनमें से कोई नहीं।
64. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (CFSA) ने निम्नलिखित में से भारत में विद्यमान किस कानून में भी कुछ सुधारों की सिफारिश की है?
 (A) कराधान कानून (B) वाणिज्यिक कानून
 (C) बैंककारी विनियमन कानून (D) सम्पत्ति कानून



- (E) इनमें से कोई नहीं।
65. राष्ट्रीय शेयर बाजार पर शुरू किए गए नए म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध पहला म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से कौनसा था?
 (A) UTI म्यूचुअल फंड (B) SBI म्यूचुअल फंड
 (C) LIC म्यूचुअल फंड (D) बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड
 (E) इनमें से कोई नहीं।
66. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार रूपए की पूर्णतः परिवर्तनीयता के लिए भारत की आर्थिक स्थिति उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में रूपया निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय है?
 (1) पूँजी खाते में पूर्णतः (2) चालू खाते में पूर्णतः
 (3) व्यापार खाते में अंशतः
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) केवल 1 और 3
 (E) इनमें से कोई नहीं
67. बैंकों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 'तृतीय पक्ष ATM उपयोग' अब केवल कुछ एक आहरणों और सीमाओं तक सीमित रहेगा। वास्तव में इसका अर्थ क्या है?
 1. अब ATM कार्ड धारक किसी भी स्थिति में अन्य बैंकों के ATMs आहरण नहीं कर पाएंगे
 2. एक बैंक के ग्राहक दूसरे बैंकों के ATMs से अब एक सीमित राशि ही निकाल पाएंगे
 3. बार-बार दूसरे बैंकों के ATMs से पैसे निकालने पर ATM कार्डधारकों को शुल्क अदा करना होगा।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) केवल 2 और 3 सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
68. बैंकों द्वारा अपने मुख्य/प्रमुख और प्रतिष्ठित ग्राहकों को प्रभासित ब्याज की दर ----- नाम से जानी जाती है।
 (A) जोखिम प्रीमियम (B) मूल उधार दर
 (C) रेपो दर (D) रिवर्स रेपो दर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
69. राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने हाल में ब्याज दर पयूचर (IRF) की शुरुआत की। वास्तव में (IRF) है:
 (A) विशेष रूप से SME क्षेत्र के लिए व्यापार का नया रूप
 (B) व्यापार का वित्तीय माध्यम
 (C) एक से दूसरे खाते में धन अंतरित करने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम
 (D) भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंजों में एक साथ व्यापार करने का सबसे सुरक्षित व सबसे तेज माध्यम
 (E) इनमें से कोई नहीं।
70. समाचारपत्रों में प्रायः दिखने वाले UNEP शब्द का पूर्ण रूप क्या है?
 (A) Universal Notification on Energy Protection
 (B) Universal New Education Project
 (C) Universal Natural Energy Project
 (D) United Nations Environment Programme
 (E) इनमें से कोई नहीं।
71. 'डब्लू ई एफ' (WEF) का पूर्ण विस्तार है:
 (A) Western Economic Front
 (B) Western Economic Forum
 (C) World Economic Forum
 (D) World Economic Front
 (E) इनमें से कोई नहीं।
72. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था/एजेंसी भारत के वित्तीय क्षेत्र की कार्यप्रणाली से सीधे सम्बन्धित नहीं है?
 (A) NABARD (B) ECGC
 (C) EXIM Bank (D) UGC
 (E) इनमें से कोई नहीं।
73. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
 (1) RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
 (2) RBI ऋण और मौद्रिक नीति की घोषणा करता है।
 (3) RBI देश के विदेशी मुद्रा भण्डार का अभिरक्षक है।
 (4) केन्द्र सरकार का वित्त सचिव RBI के गवर्नर का पदभार सँभालता है।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) केवल 4
 (E) इनमें से कोई नहीं।
74. यूरो मुद्रा ----- की आधिकारिक मुद्रा है।
 (A) SAFTA (B) NATO
 (C) यूरोपियन यूनियन (D) OPEC
 (E) इनमें से कोई नहीं।
75. वित्तीय समाचार-पत्रों में बहुत बार हम 'IPO' शब्द पढ़ते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या है?
 (A) Initial Public Office (B) Indian Public Offer
 (C) Initial Public Offer (D) Initial purchase Offer
 (E) इनमें से कोई नहीं।
76. आयकर निर्धारितियों को एक मल्टी डिजिट अल्फा न्यूमरिक नम्बर लेना पड़ता है, जो प्रत्येक करदाता के लिए विशिष्ट होता है। इस नम्बर को ----- कहते हैं।
 (A) PIN (B) ATM
 (C) VAT (D) PAN
 (E) इनमें से कोई नहीं।
77. बैंकिंग/वित्तीय संव्यवहारों में हम अक्सर पद 'TDS' देखते हैं। इसका पूरा रूप क्या है?
 (A) Total Discount Subtracted
 (B) Time, Duration, Sequence
 (C) Tax During Service
 (D) Tax Deducted at Source
 (E) इनमें से कोई नहीं।
78. नाबार्ड का मुख्यालय (Head Quarter) स्थित है:
 (A) नई दिल्ली (B) मुम्बई
 (C) लखनऊ (D) कोलकाता
 (E) इनमें से कोई नहीं।
79. निम्नलिखित में से कौनसा शब्द सामान्यतः बैंकिंग और वित्तीय लेन-देनों में प्रयोग में नहीं आता है?
 (A) लिक्विडिटी पोजीशन (B) M 3 ग्रोथ
 (C) रिपो दर (D) कोल्ड वार
 (E) इनमें से कोई नहीं।
80. निम्नलिखित में से कौन-सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है?
 (A) HDFC (B) IDBI
 (C) YES (D) SEBI
 (E) इनमें से कोई नहीं।
81. निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं?
 (A) नई दिल्ली (B) मुम्बई



- (C) कोलकाता (D) अहमदाबाद
(E) इनमें से कोई नहीं।
82. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना ---- की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में हुई थी।
(A) ECGC (B) RBI
(C) NABARD (D) IDBI
(E) इनमें से कोई नहीं।
83. निम्नलिखित में सकल देशी पूँजी निर्माण (GDCF) का/के घटक कौन-सा/कौन-से हैं?
1 सकल देशी बचत
2 शुद्ध पूँजी अन्तर्वाह
3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1 और 2 दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
84. अनुमान तैयार करते समय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित करने की प्रथा है। निम्नलिखित में से किसे/किन्हें इन क्षेत्रों का/के अंश माना जाता है?
1. घरेलू क्षेत्र
2. कॉर्पोरेट क्षेत्र
3. सरकारी क्षेत्र
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1 और 2 दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
85. बहुत बार हम वित्तीय समाचार-पत्रों में 'PPP' शब्द पढ़ते हैं। वित्तीय जगत में प्रयुक्त इस शब्द का पूर्ण रूप क्या है?
(A) Public per Capita Power
(B) Per Capita Potential Purchases
(C) Purchasing Power Parity
(D) Present Purchasing Power
(E) इनमें से कोई नहीं।
86. शब्द OECD का पूर्ण रूप लिखिए:
(A) Organization for Economic Co-operation and Development
(B) Organization for Economic Co-ordination and Development
(C) Organization for Exporters' Co-ordination and Development
(D) Organization for Exporters' Co-ordination and Development
(E) इनमें से कोई नहीं।
87. बैंक निम्नलिखित में से किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमीट्रिक ऑटोमेटिड टेलर मशीनें लगाने की योजना बना रहे हैं?
(A) छात्र (B) शिक्षा संस्थान
(C) शहरी ग्राहक (D) ग्रामीण ग्राहक
(E) इनमें से कोई नहीं।
88. बैंकों ने हाल ही में 'नो फ्रिल' खाते खोलना शुरू किया है। ये खाते ग्राहकों के किस वर्ग के सहायतार्थ हैं?
(A) समाज के कमजोर वर्ग
(B) सम्पन्न ग्राहक
(C) छात्र
(D) ऋण चाहने वाले, जो अपने पहले लिए गए ऋण चुका नहीं सके
(E) इनमें से कोई नहीं।
89. जैसा कि हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक भारत का शीर्ष बैंक है, वैसे ही अमरीका के शीर्ष बैंक का नाम ----- है।
(A) फेडरल रिजर्व
(B) दि सेंट्रल बैंक ऑफ USA
(C) बैंक ऑफ अमरीका
(D) सेंट्रल नेशनल बैंक ऑफ USA
(E) इनमें से कोई नहीं।
90. बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौनसे मानदण्ड/प्रथाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए अपनायी गई हैं, कि अवैध गतिविधियों/स्रोतों से धन बैंक में न आए ताकि राष्ट्र का आर्थिक स्वास्थ्य प्रभावित न हो?
1. अपने ग्राहक को जानिए
2. वित्तीय समावेशन
3. शाखारहित बैंकिंग
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1 और 2
(E) इनमें से कोई नहीं।
91. प्रथानुसार, वर्तमान में सभी बैंक अपनी कर पूर्व की आय से कुछ राशि काट कर अशोध्य होने की सम्भावना वाले ऋणों के लिए कुशन तैयार करने हेतु एक अलग खाते में रखते हैं। इसे ----- कहते हैं।
(A) CRR (B) SLR
(C) प्रावधानीकरण (D) PLR
(E) इनमें से कोई नहीं।
92. जैसा कि हम जानते हैं बहुत से भारतीय बैंक आजकल विदेशों में अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं। आपकी राय में किस/किन कारण/कारणों से ये बैंक विदेशों में शाखाएँ खोलना चाहते हैं?
1. विश्व में भारत की बैंक की शाखाओं का नेटवर्क सबसे बड़ा है। अतः दूसरे राष्ट्र भी उनकी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं।
2. भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा निधियाँ जुटाने का अवसर मिलता है और बहुराष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों के निधीयन का अनुभव भी मिलता है। इससे उन्हें विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलने की प्रेरणा मिलती है।
3. भारत में बहुत से विदेशी बैंक कार्यरत हैं, इसी प्रकार विदेशों में समान संख्या में भारतीय बैंकों की शाखाएँ खोलना अपेक्षित है।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) केवल 1 और 2
(E) इनमें से कोई नहीं।
93. बांग्लादेश जाने वाले व्यक्ति को अपने सारे भुगतान निम्न में से किस मुद्रा में करने होंगे?
(A) रियाल (B) दिनार
(C) टका (D) रूपया
(E) इनमें से कोई नहीं।
94. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्न में से किस कदम को मुद्रा-स्फीति को रोकने वाला कदम नहीं कहा जा सकता है?
(A) कुछ वस्तुओं पर से सीमा-शुल्क में कमी
(B) मिल्क पाउडर के आयात पर प्रतिबन्ध
(C) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 'रेपो एण्ड रिवर्स रेपो' दरों में संशोधन
(D) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन
(E) इनमें से कोई नहीं।



- (E) इनमें से कोई नहीं।
95. भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर/सूचकांक का निर्धारण नहीं करता है?
 (A) बैंक दर (B) रेपो दर
 (C) CRR (D) SENSEX
 (E) इनमें से कोई नहीं।
96. निम्नलिखित में कौन-सा पद बैंकिंग/वित्त जगत् से सम्बन्धित नहीं है?
 (A) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)
 (B) रीयल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट (RTGS)
 (C) एकजम्प्लीग्रशिआ (e.g.)
 (D) प्रबंधाधीन आस्तियाँ (AUM)
 (E) इनमें से कोई नहीं।
97. भारत में किसी बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कार्ड जारी नहीं किया जाता है?
 (A) क्रेडिट कार्ड (B) डेबिट कार्ड
 (C) ATM (D) PAN
 (E) इनमें से कोई नहीं।
98. भारत में विदेशी मुद्रा संव्यवहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अधिनियम से शासित होते हैं?
 (A) SEZ (B) MRTPA
 (C) POTA (D) FEMA
 (E) इनमें से कोई नहीं।
99. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में कार्यरत किसी बैंक के नाम के एक भाग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है?
 (A) YES (B) ICICI
 (C) ITC (D) SBI
 (E) इनमें से कोई नहीं।
100. निम्नलिखित में से किस एजेंसी/संस्था ने प्रारम्भिक सार्वजनिक
 (A) RBI (B) SEBI
 (C) BSE (D) AMFI
 (E) इनमें से कोई नहीं।
101. बैंकों ने आजकल कई नई सेवाएँ/कारोबार शुरू कर दिये हैं। बैंक निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं करते हैं?
 (A) बीमा पॉलिसियों की बिक्री
 (B) विदेशी मुद्रा को संभालना
 (C) संपत्ति के क्रय/विक्रय में सहायता
 (D) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (NSCs) और किसान विकास पत्र (KVP) की बिक्री
 (E) इनमें से कोई नहीं।
102. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं:
 1. सभी नोट व सिक्के जारी करना
 2. सभी नोट व सिक्के वितरित करना
 3. मौद्रिक नीति का निर्धारण करना
 4. भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अन्तर्गत सरकारी-एजेन्ट की भूमिका निभाना
- कूटः**
 (A) 1, 3 व 4 (B) 2 व 3
 (C) 2, 3 व 4 (D) 1, 2, 3 व 4
 (E) इनमें से कोई नहीं।
103. मुद्रा स्फीति के कारणों की सूची में से हैं:
 1. कृषि निर्गतों में धीमी वृद्धि
 2. सरकार का बढ़ता गैर-विकासोन्मुख खर्च
 3. जनसंख्या की तीव्र वृद्धि
 4. मंहँगे आयात में तीव्र वृद्धि
 (A) केवल 1 व 2 (B) केवल 2 व 3
 (C) 1, 2, 3 व 4 सभी (D) केवल 1 व 4
 (E) इनमें से कोई नहीं।
104. कार्पाट (CAPART) का मुख्यालय कहाँ है?
 (A) मुम्बई (B) नई दिल्ली
 (C) बंगलौर (D) हैदराबाद
 (E) इनमें से कोई नहीं।
105. 'एकल खिड़की ऋण योजना' किस क्षेत्र के लिए बनाई गई है?
 (A) कृषि (B) सहकारिता
 (C) बड़े उद्योग (D) लघु व कुटीर इकाइयाँ
 (E) इनमें से कोई नहीं।
106. 'मॉडवैट' (MODVAT) का सम्बन्ध किस कर से है?
 (A) बिक्री कर (B) सेवा कर
 (C) उत्पाद शुल्क (D) सीमा शुल्क
 (E) इनमें से कोई नहीं।
107. 'सेंसेक्स' (SENSEX) में तेजी प्रत्यक्षतः किस स्थिति का परिचालक है?
 (A) मुद्रा स्फीति में वृद्धि
 (B) विदेशी निवेश में वृद्धि
 (C) निर्यातों में वृद्धि
 (D) शेयर मूल्यों में वृद्धि
 (E) इनमें से कोई नहीं।
108. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) कहाँ स्थित है?
 (A) नई दिल्ली (B) मुम्बई
 (C) बंगलौर (D) हैदराबाद
 (E) इनमें से कोई नहीं।
109. 'निफ्टी' (Nifty) निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है?
 (A) न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
 (B) नई दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज
 (C) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज
 (D) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
 (E) इनमें से कोई नहीं।
110. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक किस देश का बैंक है?
 (A) अमरीका (B) ब्रिटेन
 (C) नीदरलैंड्स (D) इटली
 (E) इनमें से कोई नहीं।
111. निम्नलिखित में से कौनसा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाए गए उपायों में से नहीं है?
 (A) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (B) नगद आरक्षण अनुपात
 (C) वैधानिक तरलता अनुपात (D) नगद जमा अनुपात
 (E) इनमें से कोई नहीं।
112. भारत में उद्योगों तथा विदेशी मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से कुछ अधिनियमों पर विचार करें;
 1. विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (FEMA)



2. औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम (IDRA)
 3. एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP)
 4. विदेशी मुद्रा एवं विनियमन अधिनियम (FERA)
 उपरिलिखित अधिनियमों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
 कोड :
 (A) 3, 2, 4 तथा 1 (B) 2, 3, 4 तथा 1
 (C) 2, 4, 3 तथा 1 (D) 1, 4, 2 तथा 3
 (E) इनमें से कोई नहीं।
113. निम्नलिखित में से किस समिति ने सबसे पहले पूँजी खाता परिवर्तनीयता की जाँच की?
 (A) मेहरोत्रा समिति (B) रंगराजन समिति
 (C) तारापोर समिति (D) चैलैया समिति
 (E) इनमें से कोई नहीं।
114. विदेशी मुद्रा बाजार में सुरक्षा (हेजिंग) किसे इंगित करता है?
 (A) अवमूल्यन करना
 (B) भविष्य में विदेशी मुद्रा के जोखिम से रक्षा नहीं करना
 (C) भविष्य में विदेशी मुद्रा के जोखिम से रक्षा करना
 (D) मुद्रा स्फीति
 (E) इनमें से कोई नहीं।
115. भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है:
 (A) दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में
 (B) दिल्ली, कोलकाता तथा हैदराबाद में
 (C) मुम्बई, दिल्ली तथा बंगलुरु में
 (D) मुम्बई, कोलकाता तथा हैदराबाद में
 (E) इनमें से कोई नहीं।
116. भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है?
 (A) क्रिसिल (B) केयर
 (C) इक्रा (D) ये सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
117. 'निककी' (Nikkei) क्या है?
 (A) जापान का विदेशी विनिमय बाजार
 (B) देश के योजना आयोग का जापानी नाम
 (C) जापान के केन्द्रीय बैंक का नाम
 (D) टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
118. बैंक दर, ब्याज की वह दर है जिस पर:
 (A) एक बैंक सामान्य जनता को उधार देता है
 (B) भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य जनता को ऋण देता है
 (C) भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है
 (D) भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती (Rediscount) करता है
 (E) इनमें से कोई नहीं।
119. आधुनिकतम वैश्विक मंदी और वित्तीय संकट के बाद, डॉलर हेजेमनी पर बहस जारी है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सरल शब्दों में:
 1. यह विश्वभर में प्रचलित व्यापार प्रथा है जिसमें यू. एस. ए. डॉलर उपलब्ध कराता है और शेष विश्व उन वस्तुओं का विनिर्माण करता है जिन्हें डॉलर खरीद सकते हैं।
 2. यह वह स्थिति है जिसमें सभी राष्ट्रों को मजबूरन अपनी स्थानीय मुद्रा का डॉलर के मूल्य के सामने मूल्यांकन करना पड़ता है। अतः वैश्विक

- बाजार में सुरक्षापूर्वक ऑपरेट के लिए उन्हें रख सके उतने डॉलर मजबूरन रखने पड़ते हैं।
3. जब विश्वभर के अर्थशास्त्री इस डॉलर जाल से बाहर आने के लिए हल ढूँढ़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह हेजेमनी निर्यातकर्ता राष्ट्रों को यू. एस. ए. से अर्जित डॉलरों का घरेलू खर्च के लिए उपयोग करने से रोकती है।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
120. विदेश में आरम्भ या निगमित वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा भारत में किसी भारतीय उद्यम में किए गए निवेशों को सामान्यतः ----- कहते हैं।
 (A) पेटेंट मनी (B) प्राइवेट ईक्विटी
 (C) विदेशी संस्थागत निवेश (D) चालू खाता मुद्रा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
121. जैसाकि हम सब जानते हैं भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है/हैं?
 1. मुद्रास्फीति (अपस्फीति) का अभाव आवश्यकता सदैव एक अच्छी चीज नहीं होता है।
 2. मुद्रास्फीति माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में एक वृद्धि है।
 3. मुद्रास्फीति के बढ़ने पर धन की क्रय शक्ति भी बढ़ती है।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 1 और 2 (D) केवल 1 और 3
 (E) इनमें से कोई नहीं।
122. बहुत से बैंक अब बीमा के कारोबार में प्रवेश कर रहे हैं। बैंक इस क्षेत्र में क्यों प्रवेश कर रहे हैं, विशेषकर तब जब पहले से भारत में बहुत सी बीमा कंपनियाँ हैं?
 1. बीमा उत्पाद उपलब्ध करा कर बैंक फीस/कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय कमाता है।
 2. बैंक अपने विशाल ग्राहक बेस से, ग्राहकों को पालिसीधारक बनाने के लिए अपने वर्तमान सम्बन्धों का फायदा उठाते हैं।
 3. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की वृद्धि के साथ, हर कोई चाहे जितना बड़ा या छोटा बीमा कवर चाहता है। बैंक बहुत से आकर्षक प्रस्तावों सहित आगे आ रहे हैं जो आम लोगों की पहुँच के भीतर है।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) केवल 1 और 2
 (E) इनमें से कोई नहीं।
123. जैसा कि हम जानते हैं कभी-कभी भारतीय निर्यात आयात बैंक, IDEAS नामक द्विपक्षीय आर्थिक सहकार कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के आदेश और सहायता से विकासशील देशों को ऋण व्यवस्था देता है। IDEAS का पूरा रूप क्या है?
 (A) Indian Development and Economic Assistance Scheme
 (B) Industrial Designing and Exemplary Assistance Scheme
 (C) International division of Export Accounts and Services
 (D) Integrated Development of European and Asian Societies



- (E) इनमें से कोई नहीं।
124. सुदृढ़ विकास को प्रेरणा देने वाला एक प्रमुख कारक है - **ब्याज दरें**। ब्याज दरें किस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देती हैं विशेषकर तब जब इन्हें कम किया जाता है?
1. इससे निगमों को अधिक लागत के ऋण का समय पूर्व भुगतान करने और उन्हें कम दरों पर जुटाई गई निधियों से प्रतिस्थापित करने का अवसर मिलता है।
 2. बैंक अपने ट्रेजरी परिचालनों से अधिकतम लाभार्जन के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं और इस अधिक लाभ का उपयोग NPAs या अशोध्य ऋणों के लिए अधिक प्रावधान कर उनके तुलनपत्र के परिमार्जन के लिए किया जाता है।
 3. सरकार को भी इससे लाभ होता है क्योंकि वह खुले बाजार से कम ब्याज दरों पर निधियाँ उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति कर सकती है।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
125. बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त 'BRA' का पूरा रूप निम्नलिखित में से कौनसा है?
- (A) Brazilian and Russian Association
(B) Banking Restructuring Act
(C) Banking Resources for Agriculture
(D) Banking Regulation Act
(E) इनमें से कोई नहीं।
126. भारत में विशेष रूप से विकसित आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में देश के कुछ आर्थिक कानूनों और प्रतिबन्धों में निवेशकों को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से ढील दी जाती है, उन्हें ----- कहते हैं।
- (A) अधिमानी क्षेत्र (B) आर्थिक कारिडोर
(C) औद्योगिक पार्क (D) विशेष आर्थिक क्षेत्र
(E) इनमें से कोई नहीं।
127. शेयर बाजार सूचकांक पारम्परिक रूप से निवेशकों/प्रवर्तकों के निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोर्टफोलियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए बेंचमार्क का काम करते हैं?
- (A) ईक्विटी पोर्टफोलियो (B) कर बचत लिखतें
(C) म्यूचुअल फण्ड (D) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
(E) इनमें से कोई नहीं।
128. उस करार को क्या कहते हैं जो वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों और अल्पावधि खजाना बिलों की भावी तारीखों में खरीद और बिक्री के लिए एक संविदा है और जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर भी निर्दिष्ट करता है -----
- (A) रेपो दर (B) बैंक दर
(C) रिवर्स रेपो दर (D) मूल उधार दर
(E) इनमें से कोई नहीं।
129. निम्नलिखित में से भारत का निजी क्षेत्र का बैंक कौनसा है?
- (A) भारतीय स्टेट बैंक (B) बैंक ऑफ बड़ौदा
(C) पंजाब नेशनल बैंक (D) HDFC बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
130. बैंकिंग में प्रायः इस्तेमाल होने वाले शब्द संक्षेप सीबीएस (CBS) का पूर्ण विस्तार क्या है?
- (A) कोर बैंकिंग सॉल्यूशियन (B) कोर बैंकिंग सर्विसेज (C) कैरियर बैंकिंग सर्विसेज (D) कैरियर बेस्ड सिस्टम
(E) इनमें से कोई नहीं।
131. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की 'पुरा' (PURA) अवधारणा मूलतः किसने प्रस्तुत की थी?
- (A) डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (B) डॉ. मनमोहन सिंह
(C) प्रतिभा पाटिल (D) इन्द्र कुमार गुजराल
(E) इनमें से कोई नहीं।
132. निम्नलिखित में से वाणिज्यिक पत्र की सही परिभाषा कौनसी है?
1. यह और कुछ नहीं वित्तीय लेन-देनों का रजिस्टरी करने के लिए प्रयुक्त न्यायिक स्टाम्प पेपर का लोकप्रिय नाम है।
 2. यह एक लिखत है जिसके जरिए कम्पनियाँ बाजार से कर्ज जुटाती हैं।
 3. यह बैंकों द्वारा अपने खुदरा ग्राहकों को दिए गए जमा प्रमाण-पत्र का नाम है।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 एवं 3 तीनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
133. बैंकों ने इन दिनों 'रिवर्स मॉर्टगेज' नाम की नई योजना उत्पाद आरम्भ किया है। यह योजना निम्नलिखित में से समाज के किस समूह को ध्यान में रखकर बनाई गई है?
- (A) युवक, जिन्होंने बस अभी कमाना शुरू किया है
(B) रक्षा कार्मिक, जिनके जीवन को हमेशा भारी जोखिम रहता है
(C) वरिष्ठ नागरिक
(D) महिलाएं जिनका आय का स्वतन्त्र स्रोत नहीं है
(E) इनमें से कोई नहीं।
134. अखबारों में अक्सर 'हॉट मनी' शब्द पढ़ने को मिलता है। निम्नलिखित में से हॉट मनी की सही परिभाषा कौनसी है?
1. यह एक ऐसी निधि है जिसे अनुकूल ब्याज दर का लाभ उठाने के लिए किसी देश में डम्प कर दिया जाता है इसलिए इससे अधिक लाभ मिलता है।
 2. यह एक ऐसी निधि है जिसे कोई बैंक कम नोटिस पर और बहुत ऊँची ब्याज दर पर और लम्बी चुकौती अवधि के लिए अमरीकी डॉलर में देता है।
 3. यह एक ऐसी निधि है जिसे हवाला या ऐसे ही किसी गैर-कानूनी तरीके से बाजार में धकेल दिया जाता है और कभी-कभी इसे काला धन भी कहते हैं।
- (A) केवल 1 सही है (B) 1 और 2 दोनों सही हैं
(C) केवल 3 सही है (D) केवल 2 सही है
(E) इनमें से कोई नहीं।
135. वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण कभी-कभी निवेशकों के वास्तविक लाभ में कमी आ जाती है। वित्तीय बाजार में इस परिघटना को कहते हैं।
- (A) बाजार जोखिम (B) मुद्रास्फीति जोखिम
(C) ऋण जोखिम (D) निधियों का विशाखीकरण
(E) इनमें से कोई नहीं।



136. मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह से बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किन/किन मुख्य कारण/णों से इसमें अचानक परिवर्तन आता है?
1. उच्च GDP वृद्धि।
 2. लगातार विदेशी मुद्रा का प्रवाह।
 3. विदेशी मुद्रा रिजर्व की अधिक मात्रा।
 4. USA में मंदी।
- (A) केवल 1 एवं 2 (B) केवल 2 एवं 3
(C) केवल 3 और 4 (D) केवल 2
(E) इनमें से कोई नहीं।
137. यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात (CRR) में कमी की जाती है तो इसका साख-सृजन पर प्रभाव होगा:
- (A) वृद्धि (Increase) (B) कमी (Decrease)
(C) कोई प्रभाव (No Impact) (D) कोई अन्य नहीं
(E) इनमें से कोई नहीं।
138. भारतीय विकास फोरम (IDF) पहले जाना जाता था:
- (A) भारत सहायता क्लब (B) भारत सहायता बैंक
(C) विश्व बैंक (D) भारत विकास बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
139. एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है:
- (A) वित्त-मंत्रालय के सचिव का (B) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का
(C) वित्तमंत्री का (D) राज्य वित्तमंत्री का
(E) इनमें से कोई नहीं।
140. वह फोरम क्या है जहाँ व्यक्ति एवं व्यवसाय माल और सेवाओं के बदले धन का आदान-प्रदान करते हैं?
- (A) राजनीतिक-तंत्र (B) मार्केट प्लेस
(C) स्टॉक एक्सचेंज (D) कमोडिटी-एक्सचेंज
(E) इनमें से कोई नहीं।
141. कौनसी मार्केट फिलॉसफी अबंधता (Laissez faire) को सबसे अच्छी तरह अभिव्यक्त करती है?
- (A) वित्तीय प्रतिबन्ध (B) पम्प अपक्रामण
(C) कैविएट एम्पटर (D) आपूर्ति और माँग
(E) इनमें से कोई नहीं।
142. किसी ऋण का जिम्मा लेती संपत्ति क्या कही जाती है।
- (A) कॉलेटरल (B) ब्याज
(C) स्टॉक (D) बॉण्ड
(E) इनमें से कोई नहीं।
143. सप्लायर्स क्रेताओं को किसके रूप में वित्त प्रबन्ध प्रदान करेंगे?
- (A) सिक्यूरिटी क्रेडिट (B) रिवाँल्विंग क्रेडिट
(C) ट्रेड क्रेडिट (D) मॉर्गिज क्रेडिट
(E) इनमें से कोई नहीं।
144. वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो घर पर बने रहते हैं और अपना कार्य अपनी कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से भेजते हैं?
- (A) टेलिकम्प्यूटर (B) कम्प्यूटर इंटरफेसर
(C) कम्प्यूटर (D) बेरोजगार
(E) इनमें से कोई नहीं।
145. केन्द्र सरकार ने दीपक पारिख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किस सम्बन्ध में समीक्षा के लिए किया था?
- (A) आधारिक संरचना वित्तीयन (B) दूरसंचार सुधार
- (C) बैंकिंग सुधार (D) शेयर आवंटन प्रणाली में सुधार
(E) इनमें से कोई नहीं।
146. विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष (Accounting Year) किस तिथि से शुरू होता है?
- (A) 1 जनवरी (B) 1 अप्रैल
(C) 1 जून (D) 1 जुलाई
(E) इनमें से कोई नहीं।
147. अक्सर हम अखबारों में GM फसलों के बारे में पढ़ते हैं। 'GM' का पूरा रूप क्या है?
- (A) Generally Marketed (B) Genetically Modified
(C) Green & Moisturising (D) Globally Marketed
(E) इनमें से कोई नहीं।
148. भारतीय स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय ----- में स्थित है।
- (A) कोलकाता (B) नई दिल्ली
(C) पुणे (D) मुम्बई
(E) इनमें से कोई नहीं।
149. निम्नलिखित में से कौनसा विश्व के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक का नाम नहीं है?
- (A) नासडाक (B) निक्की
(C) कोस्पी (D) कॉम्बिक्स
(E) इनमें से कोई नहीं।
150. आर्थिक समाचार-पत्रों में हम बहुत बार 'ECB' शब्द पढ़ते हैं। ECB का पूर्ण रूप क्या है?
- (A) Essential Commercial Borrowing
(B) Essential Credit & Borrowing
(C) External Credit & Business
(D) External Commercial Borrowing
(E) इनमें से कोई नहीं।
151. बैंक की नई शाखा खोलने से पहले बैंकों के लिए, ----- से अनिवार्यतः अनुमति/लाइसेंस लेना जरूरी होता है।
- (A) राज्य सरकार
(B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
(D) भारतीय बैंक संघ
(E) इनमें से कोई नहीं।
152. केन्द्रीय बजट सदैव ----- में पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- (A) लोक सभा (B) राज्य सभा
(C) संसद के संयुक्त सत्र (D) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में
(E) इनमें से कोई नहीं।
153. HNI
- (A) Highly Negative Individual
(B) High Networth Individual
(C) High Neutral Individual
(D) Highly Necessary Individual
(E) इनमें से कोई नहीं।
154. डिजिटल बैंकिंग का अर्थ है-----(सही विकल्प का पता लगाइए)।
- (A) केलकुलेटर के साथ बैंकिंग
(B) डिजिटल उपकरणों के साथ बैंकिंग
(C) इंटरनेट बैंकिंग और टेलिबैंकिंग
(D) निर्यात वित्त
(E) इनमें से कोई नहीं।
155. आवास ऋण ----- को दिए जाते हैं।
- (A) व्यक्तियों (B) संस्थानों



- (C) बिल्डरों (D) उपर्युक्त सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
156. क्रेडिट कार्डों का प्रयोग ----- के लिए किया जाता है।
(A) नकदी निकालने
(B) हवाई जहाज के टिकट खरीदने
(C) खुदरा दुकानों से उपभोज्य वस्तुएं खरीदने
(D) उपर्युक्त सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
157. ATM क्या होते हैं?
(A) बैंकों की शाखाएं
(B) बैंकों के स्टाफ-युक्त काउंटर
(C) बिना स्टाफ के नकदी देने वाले
(D) उपर्युक्त सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
158. इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है?
(A) नेट पर बैंकों की बैठक
(B) नेट प्रैक्टिस
(C) इंटरनेट के जरिए बैंकिंग संव्यवहार
(D) विदेशों के साथ संव्यवहार
(E) इनमें से कोई नहीं।
159. विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के 'छोटे उधारकर्ता' अब भी अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक मार्ग पसन्द करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौनसा ऋण का 'अनौपचारिक मार्ग' है?
(A) क्रेडिट कार्ड
(B) वित्तीय संस्था से सोने के बदले ऋण
(C) डेबिट कार्ड
(D) साहूकार
(E) इनमें से कोई नहीं।
160. निम्नलिखित में से कौनसा पद बैंकिंग/वित्त से सम्बन्धित नहीं है?
(A) क्रेडिट रैप (B) EMI
(C) परिपक्वता तक धारित (D) डिफ्यूजन्
(E) इनमें से कोई नहीं।
161. ग्रामीण और अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के गरीबों को बहुत छोटी मात्रा में ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद देने के प्रावधान को ----- कहते हैं। इससे उनकी आय का स्तर और जीवन स्तर बढ़ता है।
(A) कॉर्पोरेट बैंकिंग (B) वैयक्तिक बैंकिंग
(C) माइक्रो क्रेडिट (D) गैर-बैंकिंग वित्त
(E) इनमें से कोई नहीं।
162. निम्नलिखित में से भारत के एक प्रमुख माइक्रो वित्त संस्थान का नाम क्या है?
(A) ग्रामीण (B) कम्पार्टमॉस
(C) ब्रैक (D) स्पंदन
(E) इनमें से कोई नहीं।
163. निम्नलिखित में से देश की अर्थव्यवस्था का वार्षिक सूचक किसे माना जाता है?
1. वास्तविक वर्षा 2. जनसंख्या 3. थोक मूल्य सूचकांक
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 एवं 3 तीनों
- (E) इनमें से कोई नहीं।
164. ग्रामीण लोगों को वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देने वाली गैर-सरकारी संस्था (NGO) का संक्षिप्त नाम निम्नलिखित में से कौनसा है?
(A) SEWA (B) AMUL
(C) CRY (D) A और B दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
165. वित्तीय अखबारों में हम औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के प्रयोजन के लिए औद्योगिक क्षेत्र से कौन-कौनसे क्रियाकलाप सम्बद्ध हैं?
1. खनन 2. विनिर्माण 3. निर्माण
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
166. अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि रूपए का अधिमूल्यम हो रहा है। जब हम क्रय शक्ति-समता (PPP) के परिप्रेक्ष्य में रूपया-डॉलर विनिमय दर के बारे में विचार करते हैं तो हम जानते हैं कि इन दो करेंसियों की विनिमय दर-----
(A) दोनों देशों में मूल्य स्तरों के अनुपात के समान होनी चाहिए
(B) दोनों देशों में मूल्य स्तरों के अनुपात के समान नहीं होनी चाहिए
(C) तीसरी प्रमुख करेंसी अर्थात् यूरो या येन के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए
(D) दोनों करेंसियों के लिए आवश्यकतः अलग-अलग होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तियों के अलग-अलग सेटों द्वारा संचालित होती हैं और इसका PPP से कोई सम्बन्ध नहीं है
(E) इनमें से कोई नहीं।
167. अक्सर हम वित्तीय अखबारों/पत्रिकाओं के बड़े कॉरपोरेटों द्वारा किए गए 'शेयर स्वैप' के बारे में पढ़ते हैं। यह क्या होता है।
1. कारोबार अधिग्रहण जिसमें अर्जनरता कम्पनी अर्जित कम्पनी के लिए भुगतान करने हेतु अपने स्वयं के स्टॉक का उपयोग करती है।
2. जब कोई कम्पनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के कुछ अल्पावधि ऋण पाने के लिए अपने स्वयं के शेयरों का उपयोग करती है, तो इसे शेयर स्वैप कहते हैं।
3. अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए पूँजी अर्जन हेतु जब कम्पनियों को नया निर्गम जारी करना पड़ता है, प्रत्येक शेयरधारक को कुछ अतिरिक्त अधिमान शेयर मिलते हैं। अधिमान शेयर के आवंटन की प्रक्रिया शेयर स्वैप कहलाती है।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) केवल 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
168. निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सबसे बड़ी चेक ट्रंक्शन सुविधा है?
(A) चीन (B) भारत
(C) श्रीलंका (D) म्यांमार
(E) इनमें से कोई नहीं।
169. भारत में विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापित परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी का नाम निम्नलिखित में से क्या है?
(A) AMFI (B) ARCIL
(C) SEBI (D) HCR



- (E) इनमें से कोई नहीं।
170. अक्सर हम विभिन्न समाचार-पत्रों में मुद्रा बाजार की गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा बाजार की मुख्य गतिविधियाँ क्या हैं?
1. यह सरकार और सरकारी क्षेत्र के संगठनों को अल्पावधि निधियाँ उपलब्ध कराता है।
 2. कार्यशील पूँजी की अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यापारियों और अन्यो को अल्पावधि निधियाँ प्राप्त होती हैं।
 3. मुद्रा बाजार और कुछ नहीं, किन्तु विदेशी मुद्रा बाजार का दूसरा नाम है। यहाँ केवल विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय है।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) केवल 1 और 2
(E) इनमें से कोई नहीं।
171. जैसा कि हम वित्तीय अखबारों और आर्थिक जर्नलों/पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, वित्तीय क्षेत्र में एक ऐसा समय आता है जब बैंक अधिक ऋण नहीं दे सकते हैं, वास्तव में वे पुराने ऋण वापस माँगने लगते हैं और ब्याज दर भी बढ़ा देते हैं। इससे व्यापारी समुदाय को क्या संदेश मिलता है?
1. इससे ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें कॉरपोरेट अपना स्टॉक धारण कम करने लगते हैं और विनिर्माताओं के पास लम्बित अनिष्पादित ऑर्डर रद्द कर देते हैं।
 2. विनिर्माता अपने परिचालनों की मात्रा कम करने लगते हैं और कामगारों को रोजगार से मुक्त कर देते हैं।
 3. कामगार अपना व्यय कम करने लगते हैं और वस्तुओं, माल/सेवाओं की माँग कम हो जाती है क्योंकि लोग कम खरीदी करते हैं।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) केवल 1 और 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
172. अक्सर हम वित्तीय अखबारों/पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि सरकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इससे भारत सरकार किस लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास कर रही है?
1. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अवांछनीय उतार-चढ़ाव टालना।
 2. विकास की वहनीय (Sustainable) तेज दर सुनिश्चित करना।
 3. यह सुनिश्चित करना कि लोगों को लाभकारी रोजगार प्राप्त हो।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
173. अक्सर हम वित्तीय अखबारों/पत्रिकाओं और जर्नलों में पढ़ते हैं कि सरकार लोगों में बचत की आदत डालने के लिए प्रयत्न कर रही है। 'बचत' की सही परिभाषा क्या है?
1. यह व्यक्ति की कुल आय और सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए सभी करों और देयों के बीच का अंतर है।
 2. यह व्यक्ति की सकल आय और सकल उपभोग के बीच का अंतर है।
 3. यह वह राशि है, जो प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम शेष के रूप में अपने बैंक खाते में रखनी पड़ती है।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1 और 3 दोनों
(E) इनमें से कोई नहीं।
174. बहुत बार हम अखबारों में माइक्रो वित्त (Micro Finance) के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज माइक्रो वित्त सर्वाधिक वरीयता प्राप्त रूट है?
- (A) उच्च मूल्य के व्यक्तिगत ग्राहक
(B) बड़े कारपोरेट गृह
(C) 50 करोड़ रूपए तक के निवेश वाले औद्योगिक यूनिट
(D) समाज के गरीब और कमजोर वर्ग
(E) इनमें से कोई नहीं।
175. हर बार जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक और ऋण नीति की समीक्षा करता है या उसमें कुछ सुधार/समायोजन करता है, तब बैंक भी सामान्यतः अपनी ब्याज दरें बढ़ा या घटाकर उनमें संशोधन करते हैं। ब्याज दरें थोड़ी घटाई जाएँ तो समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है?
1. इससे कॉरपोरेटों पर ब्याज का बोझ कम हो जाएगा।
 2. पूँजी की लागत भी कम हो जाती है।
 3. इससे औद्योगिक विकास और निवेश में तेजी आएगी।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) सभी 1, 2 और 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
176. अक्सर हम बैंकों द्वारा प्रभाषित 'प्राइम लेंडिंग रेट' (PLR) के बारे में पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या है ?
1. वह दर जिस पर बैंक सामान्यतः अपने अत्यधिक प्रतिष्ठित ग्राहकों को ऋण देते हैं।
 2. वह दर जिस पर बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से धन प्राप्त होता है।
 3. वह दर जो बैंक उनके पास रखी गई 5 वर्ष या अधिक अवधि की सावधि जमाओं पर सामान्यतः अदा करता है।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
177. जैसा कि हम जानते हैं आजकल बैंकों ने बैंकिंग के अतिरिक्त कई नई सेवाएं आरम्भ की हैं। निम्नलिखित में से कौनसी आजकल बैंकों द्वारा दी जा रही नई सेवा/सेवाएं हैं?
1. यूटिलिटी सेवाओं के लिए बिल भुगतान सेवा
 2. बैंक इश्योरेंस
 3. विभिन्न करारों के लिए स्टाम्प पेपरों का फ्रैंकिंग
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
178. ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधाजनक बनाने के लिए हाल ही में बैंकों ने बहुत से नए डिजिटल चैनल्स आरम्भ किए हैं। निम्नलिखित में से बैंकों द्वारा अपनाया/विकसित किया गया डिजिटल चैनल कौनसा नहीं है?
- (A) आटोमेटेड टेलर मशीन (ATMs)
(B) टेली बैंकिंग
(C) इंटरनेट बैंकिंग
(D) ओपरेशनल बैंकिंग
(E) इनमें से कोई नहीं।



179. जैसाकि हम सब जानते हैं कि विश्वभर में बैंकिंग में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें भारत भी अपवाद नहीं है। भारतीय बैंकिंग के परिदृश्य में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख घटना/घटनाएं निम्नलिखित में से कौनसी है/हैं?
1. वित्तीय क्षेत्र के सुधार
 2. भूमंडलीकरण
 3. वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की कार्यवाही
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
180. 'मुक्त व्यापार' (Free Trade) का अभिप्राय है:
- (A) एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचलन
(B) माल का निःशुल्क संचलन
(C) माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान-प्रदान
(D) निः शुल्क व्यापार
(E) इनमें से कोई नहीं।
181. भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन-देन नहीं करता?
- (A) नागालैंड (B) जम्मू और कश्मीर
(C) पंजाब (D) असम
(E) इनमें से कोई नहीं।
182. शब्द 'अहस्तक्षेप' (Laissez faire) अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ सम्बन्धित है?
- (A) पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (B) समाजवादी अर्थव्यवस्था
(C) मिश्रित अर्थव्यवस्था (D) निर्देशित अर्थव्यवस्था
(E) इनमें से कोई नहीं।
183. भारत सरकार के बजट आँकड़ों में ब्याज का भुगतान, पेंशन, सामाजिक सेवाएँ आदि किसका अंग है?
- (A) योजना व्यय का
(B) राज्य सरकार के व्यय का
(C) पूँजीगत व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण का
(D) योजनेतर व्यय का
(E) इनमें से कोई नहीं।
184. 'ग्रीन अकाउंटिंग' का अर्थ है, ----- के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना।
- (A) देश के कुल वन क्षेत्र
(B) देश के वन अच्छादन के विनाश
(C) प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति
(D) उद्धार की गई परती भूमि के क्षेत्रफल
(E) इनमें से कोई नहीं।
185. बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चैक काटने के लिए दी गई अनुमति को कहते हैं:
- (A) निजी ऋण
(B) साधारण ऋण
(C) हुंडी को बट्टे पर देना
(D) ओवरड्राफ्ट
(E) इनमें से कोई नहीं।
186. 'नाबार्ड' (NABARD) का सम्बन्ध किसके विकास के साथ है?
- (A) कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके

- (B) भारी उद्योग
(C) बैंकिंग क्षेत्र
(D) स्थावर संपदा
(E) इनमें से कोई नहीं।
187. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'वृद्धि की हिन्दू दर' पद किसने बनाया था?
- (A) ए. के. सेन
(B) किरीट एस पारिख
(C) राजकृष्ण
(D) मोन्टेक सिंह अहलूवालिया
(E) इनमें से कोई नहीं।
188. 'विश्व बैंक' का एक अन्य नाम है:
- (A) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक
(B) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक
(C) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक
(D) अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
189. मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति (Inflation) को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है?
- (A) लागताधिक्य स्फीति (Costpush inflation)
(B) माँगाधिक्य स्फीति (Demandpull inflation)
(C) विस्फीति (Disinflation)
(D) प्रत्यवस्फीति (Reflation)
(E) इनमें से कोई नहीं।
190. पूँजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या:
- (A) नोट जारी करके
(B) सरकार से ऋण लेकर
(C) प्रतिभूतियाँ जारी करके
(D) विदेशी संस्थाओं से ऋण लेकर
(E) इनमें से कोई नहीं।
191. समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, बैंक, विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं के गुणात्मक निर्धारण के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ निम्नलिखित में से कौनसी हैं?
1. CARE
 2. CRISIL
 3. ULIP
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2 (D) केवल 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
192. समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 'प्लास्टिक के मुद्रा नोट' जारी करना आरम्भ करने वाला है। 'प्लास्टिक नोटों' का/के लाभ क्या है/हैं?
1. उनका जीवनकाल अधिक होगा।
 2. ये प्लास्टिक मनी या क्रेडिट, डेबिट कार्ड को प्रस्थापित करेगी, जिनके परिणामस्वरूप बहुतसी कपट प्रथाएं अस्तित्व में आने लगी हैं।
 3. इनका मुद्रण सस्ता होता।
- (A) केवल 1 (B) केवल 2



- (C) केवल 3 (D) 1, 2 और 3 सभी
(E) इनमें से कोई नहीं।
193. 'सब प्राइम ऋण' पद निम्नलिखित को दिए गए ऋणों के लिए लागू होता है।
(A) ऐसे उधारकर्ता जिनकी साख पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है
(B) वे जो मूर्त अस्तियों के बंधक पर ऋण लेना चाहते हैं
(C) जिनकी साख पृष्ठभूमि अच्छी है और जिन्हें बैंक 10 वर्ष से जानता है
(D) वे उधारकर्ता जो बैंक के सर्वाधिक तरजीह प्राप्त ग्राहक हैं
(E) इनमें से कोई नहीं।
194. बेसल-II मानदण्ड (Basel-II Norms) बैंकिंग उद्योग के निम्नलिखित में से किस पहलू से सम्बद्ध हैं?
(A) जोखिम प्रबंधन
(B) मानवशक्ति आयोजन
(C) कर्मचारियों के लिए निवृत्ति लाभ
(D) कार्पोरेट शासन
(E) इनमें से कोई नहीं।
195. वित्तीय क्षेत्र में बार-बार प्रयुक्त पद 'Underwriting' का अर्थ है:
(A) आस्तियों का अल्प मूल्यांकन
(B) शुल्क प्राप्ति के लिए जोखिम उठाने की क्रिया
(C) यह गारंटी देना कि ऋण अशोध्य नहीं होगा
(D) IPO फ्लोट करने के लिए अनुमति की क्रिया
(E) इनमें से कोई नहीं।
196. भारतीय मूल के बहुत से बैंक विदेशों में कार्यालय/शाखाएं खोल रहे हैं। यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से क्यों उभर रही है?
1. ये बैंक विदेशियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से देशों में प्रचुर मात्रा में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। भारत इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।
2. ये बैंक भारतीय फर्मों को स्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय दरों से निधियां जुटाने में सहायता करना चाहते हैं।
3. ये बैंक भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 3 (D) केवल 2 और 3
(E) इनमें से कोई नहीं।
197. भारत में बहुत से अर्थशास्त्री, बैंकर और शोधकर्ता अक्सर सिफारिश करते हैं कि बैंकों को नई चुनौतियों के लिए स्वयं को सुसज्जित करना चाहिए। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित में से किस रूप में हैं?
1. भारतीय अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ अधिकाधिक जुड़ती जा रही है। इसलिए कॉर्पोरेट बैंकिंग की माँग आकार, सेवाओं के संयोजन और गुणवत्ता की भी दृष्टि से परिवर्तित होने की सम्भावना है।
2. भारत में बढ़ते हुए विदेशी व्यापार को स्थानीय बैंकों द्वारा वित्त पोषित करना होगा।
3. विदेशी लोग प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध आराम के आदि हो गए हैं। इस दिशा में भारत को बहुत कुछ करना है।
(A) केवल 1 सही हैं (B) केवल 2 सही हैं
(C) केवल 3 सही हैं (D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं
(E) इनमें से कोई नहीं।
198. निम्नलिखित में से कौन सा पद बैंकिंग/वित्त से सम्बन्धित नहीं है?
(A) क्रेडिट रैप (B) IMI
(C) परिपक्वता तक धारित (D) डिफ्यूज
(E) इनमें से कोई नहीं।
199. 'नास्कोम' (NASSCOM) क्या है:
(A) भारत का एक शेयर बाजार
(B) अमरीका का एक शेयर बाजार
(C) भारत का एक कमोडिटी बाजार
(D) भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों का संगठन
(E) इनमें से कोई नहीं।
200. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन कर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के लिए दो अलग-अलग 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड' (CBDT) व 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) कब गठित किए गए थे?
(A) 1950 में (B) 1963 में
(C) 1973 में (D) 1993 में
(E) इनमें से कोई नहीं।
201. वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) क्या है?
(A) राज्यों द्वारा लगाये करों जैसे सरचार्ज, टर्नओवर आदि के स्थान पर लगाया गया एक अकेला कर
(B) उपभोक्ताओं पर लगाया गया एक सरल, पारदर्शी तथा आसानी से देने वाला कर
(C) उच्च आय वालों के कर भार में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक नया कदम
(D) पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादकों पर लगाया गया एक नया कर
(E) इनमें से कोई नहीं।
202. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी?
(A) चौथी (B) पाँचवीं
(C) छठवीं (D) आठवीं
(E) इनमें से कोई नहीं।
203. अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है?
(A) 6 माह तथा उससे कम (B) 1 वर्ष तक की अवधि
(C) 3 वर्ष तक की अवधि (D) 5 वर्ष तक की अवधि
(E) इनमें से कोई नहीं।
204. निवेश (Investment) की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है?
(A) चाय (B) सीमेंट
(C) इस्पात (D) पटसन
(E) इनमें से कोई नहीं।
205. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने रियल एस्टेट के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के आकलन हेतु एक नया सूचकांक रेसीडेक्स (RESIDEX) कब जारी किया है?
(A) जुलाई 2007 में (B) जून 2008 में
(C) मार्च 2009 में (D) अप्रैल 2010 में



- (E) इनमें से कोई नहीं।
206. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी?
- (A) शिवारमन समिति (B) भावे समिति
(C) गुप्त समिति (D) माली समिति
(E) इनमें से कोई नहीं।
207. भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है?
- (A) केन्द्र सरकार (B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) स्टेट बैंक के 6 सहायक बैंक (D) निजी निवेशक
(E) इनमें से कोई नहीं।
208. निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई थी?
- (A) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(B) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
(C) एशियाई विकास बैंक (ADB)
(D) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(E) इनमें से कोई नहीं।
209. भारतीय रूपए के पहचान चिह्न ₹ की रचना किसने की?
- (A) डी. उदय कुमार (B) राममनोहर लाल
(C) डी. आनंद कुमार (D) मोहन दास गुप्ता
(E) इनमें से कोई नहीं।
210. रूपए को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया:
- (A) अप्रैल 1993 में (B) जुलाई 1995 में
(C) अगस्त 1994 में (D) अप्रैल 1996 में
(E) इनमें से कोई नहीं।
211. 'रेपो दर' है:
- (A) शेयर दलाली दर (B) अल्पकालिक ब्याज दर
(C) बॉण्ड कटौती दर
(D) विदेशी मुद्रा क्रय व विक्रय कीमतों के मध्य का अन्तराल
(E) इनमें से कोई नहीं।
212. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
- (A) जनवरी 1949 में (B) अप्रैल 1935 में
(C) अक्टूबर 1956 में (D) मार्च 1951 में
(E) इनमें से कोई नहीं।
213. निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है?
- (A) नाबार्ड (B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(C) वाणिज्यिक बैंक (D) सहकारी बैंक
(E) इनमें से कोई नहीं।
214. साख एवं विनियोग नियंत्रण हेतु केन्द्रीय बैंक को करनी चाहिए:
- (A) नकद आरक्षित अनुपात में बढ़ोत्तरी और बैंक दर में बढ़ोत्तरी
(B) नकद आरक्षित अनुपात में बढ़ोत्तरी और बैंक दर में कमी
(C) नकद आरक्षित अनुपात में कमी और बैंक दर में कमी
(D) नकद आरक्षित अनुपात में कमी और बैंक दर में बढ़ोत्तरी
(E) इनमें से कोई नहीं।
215. 'स्टैगफ्लेशन' वह स्थिति है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती हैं:
- (A) विस्फीति एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी
(B) स्फीति एवं बढ़ता हुआ रोजगार
(C) सतत मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती बेरोजगारी
(D) स्थिर रोजगार एवं विस्फीति
(E) इनमें से कोई नहीं।
216. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM BANK) की स्थापना हुई थी वर्ष:
- (A) 1982 में (B) 1960 में
(C) 1991 में (D) 1995 में
(E) इनमें से कोई नहीं।
217. 'सेन्सेक्स' (SENSEX) निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का सूचकांक है?
- (A) न्यूयार्क शेयर बाजार (B) कोलकाता शेयर बाजार
(C) राष्ट्रीय शेयर बाजार (भारत) (D) हांगकांग शेयर बाजार
(E) इनमें से कोई नहीं।
218. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से कौनसी दर निर्धारित नहीं की जाती है?
- (A) रेपो दर (B) आरक्षित नकदी निधि अनुपात
(C) लाभ एवं हानि अनुपात (D) रिवर्स रेपो दर
(E) इनमें से कोई नहीं।
219. AWAN का पूरा रूप क्या है?
- (A) Army welfare Association of Nations
(B) Army Wide Area Network
(C) Asian Wing of Advanced Nations
(D) Armed Wing of Advanced Nations
(E) इनमें से कोई नहीं।
220. बैंकिंग संव्यवहारों के सन्दर्भ में बहुत बार पद MSS पढ़ते हैं। MSS का पूरा रूप क्या है?
- (A) Money Stabilization Scheme
(B) Market Stabilization Scheme
(C) Maturity and Standardization Service
(D) Money Stabilization Service
(E) इनमें से कोई नहीं।
221. 'WMD' का पूरा रूप निम्नलिखित में से कौन सा है?
- (A) World Meteorological Directory
(B) World Market Debt
(C) Weapons of Mass Destruction
(D) World Meteorological Day
(E) इनमें से कोई नहीं।
222. सॉफ्टवेयर और सेवा कम्पनियों का संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है?
- (A) NASDAQ (B) NCSA
(C) NASSCOM (D) NCAER
(E) इनमें से कोई नहीं।
223. Computer से सम्बन्धित शब्द CCDS का विस्तारित रूप है:
- (A) कैसेट कपल डिशेज (B) कम्प्यूटर कपल डिश स्कैच
(C) चार्ज कपलड डेविसेज (D) कॉम्पैक्ट कपलड डिश स्कैच
(E) इनमें से कोई नहीं।
224. NAFED राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का सम्बन्ध किससे नहीं है?
- (A) उर्वरकों तथा अन्य आगतों को कृषकों को उपलब्ध कराना
(B) कृषि उत्पादों के निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना
(C) देश में आपातकालीन सुरक्षा हेतु सुरक्षित भण्डार का निर्माण
(D) उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त क्षेत्रों से अभाव क्षेत्रों की ओर भेजना
(E) इनमें से कोई नहीं।



225. मुद्रा स्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है?
 (A) सरकारी व्यय में कटौती द्वारा
 (B) बचत के बजट द्वारा
 (C) प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के द्वारा
 (D) उपर्युक्त तीनों उपायों द्वारा
 (E) इनमें से कोई नहीं।
226. केन्द्र सरकार द्वारा गठित रस्तोगी समिति निम्नलिखित में से किस कर से सम्बन्धित है?
 (A) आय कर (B) निगम कर
 (C) उत्पाद शुल्क (D) सेवा कर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
227. अगस्त 2010 में निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है?
 (A) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (B) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
 (C) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर (D) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
228. 'फोकस प्रोडक्ट स्कीम' भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस नीति में शामिल है?
 (A) मौद्रिक एवं साख नीति (B) विदेश व्यापार नीति
 (C) पर्यावरण संरक्षण नीति (D) रोजगार नीति
 (E) इनमें से कोई नहीं।
229. 'सेबी' (SEBI) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत वर्तमान में 'रिटेल इन्वेस्टर्स' के लिए किसी सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है?
 (A) 50 हजार रूपए (B) 1.00 लाख रूपए
 (C) 2.00 लाख रूपए (D) 5.00 लाख रूपए
 (E) इनमें से कोई नहीं।
230. निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक में अगस्त 2010 में हुआ है?
 (A) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (B) बैंक ऑफ राजस्थान
 (C) कर्नाटक बैंक लि. (D) बैंक ऑफ मथुरा लि.
 (E) इनमें से कोई नहीं।
231. निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है?
 (A) 1 जुलाई (B) 11 जुलाई
 (C) 1 सितम्बर (D) 11 सितम्बर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
232. निजी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों में से सबसे बड़ी नियोजता कम्पनी कौनसी है?
 (A) हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि. (B) टीसीएस
 (C) रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि. (D) आईटीसी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
233. भारत के नए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष है:
 (A) 1993-94 (B) 1999-2000
 (C) 2000-01 (D) 2004-05
 (E) इनमें से कोई नहीं।
234. 'यूलिप्स' (ULIPs) को बीमा उत्पाद स्वीकार करने के सम्बन्ध में एक अध्यादेश सरकार ने जून 2010 में जारी किया था। इसके चलते अब 'यूलिप्स' योजनाओं का विनियमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा?
 (A) केवल 'इरडा' (IRDA) द्वारा
 (B) केवल 'सेबी' (SEBI) द्वारा
 (C) 'इरडा' व 'सेबी' दोनों द्वारा संयुक्त रूप से
 (D) इसे 'इरडा' व 'सेबी' दोनों के दायरे से बाहर रखा गया है
 (E) इनमें से कोई नहीं।
235. निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है?
 (A) एम. वी. कामथ (B) एस. बैंकटरमणन
 (C) डॉ. सी. रंगराजन (D) डॉ. मनमोहन सिंह
 (E) इनमें से कोई नहीं।
236. ब्रिटेन के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड (RBS) के भारत स्थित रिटेल बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किस विदेशी बैंक द्वारा किया गया है?
 (A) सिटी बैंक (B) स्टैन चार्ट
 (C) ग्रिडलेज (D) एच. एस. बी. सी.
 (E) इनमें से कोई नहीं।
237. निम्नलिखित में से कौनसा भारत के मनी-मार्केट का हिस्सा नहीं है?
 (A) बिल मार्केट (B) कॉल मनी मार्केट
 (C) बैंक (D) इंडियन गोल्ड काउन्सिल
 (E) इनमें से कोई नहीं।
238. भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौनसी सुविधा नहीं देते हैं?
 (A) बचत बैंक योजना
 (B) म्यूचुअल फण्डों का खुदरा लेनदेन
 (C) स्टाम्प पेपर (न्यायिक) की बिक्री
 (D) डिमांड ड्राफ्ट जारी करना
 (E) इनमें से कोई नहीं।
239. देश में चलनिधि की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निम्नलिखित में से कौन/से उपाय किए हैं?
 1. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात में कमी
 2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
 3. बाजार में अतिरिक्त करेंसी नोटों की आपूर्ति
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) 1, 2 व 3 सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।
240. निम्नलिखित में से कौनसी सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था नहीं है?
 (A) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
 (B) नाबार्ड
 (C) राष्ट्रीय आवास बैंक
 (D) ICICI बैंक
 (E) इनमें से कोई नहीं।
241. 'ULIP' शब्द हाल में समाचारों में था इसका पूर्ण रूप क्या है?
 (A) Universal Life & Investment Plan
 (B) Unit Loan & Insurance Plan
 (C) Universal Loan & Investment Plan
 (D) Unit Linked Insurance Plan
 (E) इनमें से कोई नहीं।
242. बहुत बार हम यह पढ़ते हैं कि कोई कॉर्पोरेट इकाई अपना पूँजी आधार बढ़ाने की प्रक्रिया में है। किसी कम्पनी को अपना पूँजीगत आधार मजबूत करने के लिए धन क्यों जुटाना पड़ता है?
 1. अपनी विस्तार योजनाओं का वित्तीयन करना।
 2. अपनी विशाखीकरण योजनाओं का वित्तीयन करना।



3. अपने ऋणों और उधारों को चुकाना।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 3 (D) केवल 1 व 2
 (E) इनमें से कोई नहीं।
243. गरीबों या बच्चों के बीच लोकप्रिय 'लघु बचत बैंक' का रूप निम्नलिखित में से कौन सा था?
 (A) कोर बैंकिंग (B) क्रेडिट बैंकिंग
 (C) डेबिट बैंकिंग (D) पिगी बैंकिंग
 (E) इनमें से कोई नहीं।
244. निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की सूक्ष्म वित्त की संकल्पना का प्रवर्तक माना जाता है?
 (A) भारत (B) बांग्लादेश
 (C) दक्षिण अफ्रीका (D) US
 (E) इनमें से कोई नहीं।
245. निम्नलिखित में से किस दर से बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं?
 (A) बैंक दर (B) CRR
 (C) SLR (D) रेपो दर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
246. भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) कब खुला?
 (A) 1972 में (B) 1980 में
 (C) 1975 में (D) 1969 में
 (E) इनमें से कोई नहीं।
247. नाबार्ड (NABARD) का मुख्य कार्य है:
 (A) कृषकों को ऋण देना
 (B) कृषि अनुसंधान
 (C) कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना
 (D) कृषि का विकास करना
 (E) इनमें से कोई नहीं।
248. नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है?
 (A) मुम्बई (B) कोलकाता
 (C) हैदराबाद (D) जयपुर
 (E) इनमें से कोई नहीं।
249. बहुत बार हम वित्तीय समाचार पत्रों में 'कोर सेक्टर' के कार्य निष्पादन के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौनसा अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में शामिल नहीं है?
 (A) कोयला (B) ऑटो क्षेत्र
 (C) स्टील (D) सीमेंट
 (E) इनमें से कोई नहीं।
250. 'माइक्रो क्रेडिट' का क्या अर्थ है?
 1. असंगठित क्षेत्र के लोगों को कम राशि के ऋण।
 2. स्वयं सहायता समूहों को ऋण।
 3. मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों को 50 लाख रूपए से 5 करोड़ रूपए तक की ऋण राशि।
 (A) केवल 1 (B) केवल 2
 (C) केवल 1 व 2 (D) 1, 2 व 3 सभी
 (E) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर माला (Answer Key)

1-C	37-C	73-D	109-D	145-A	181-B	217-C
2-D	38-A	74-C	110-B	146-D	182-A	218-C
3-B	39-A	75-C	111-D	147-B	183-D	219-E
4-D	40-C	76-D	112-B	148-D	184-C	220-B
5-A	41-D	77-D	113-C	149-D	185-D	221-C
6-D	42-C	78-B	114-C	150-D	186-A	222-C
7-B	43-D	79-D	115-D	151-B	187-C	223-C
8-C	44-B	80-D	116-D	152-A	188-A	224-C
9-D	45-B	81-B	117-D	153-B	189-C	225-D
10-C	46-B	82-D	118-D	154-C	190-C	226-D
11-D	47-B	83-D	119-B	155-A	191-A	227-C
12-C	48-C	84-D	120-C	156-D	192-C	228-B
13-B	49-A	85-C	121-C	157-C	193-A	229-B
14-B	50-C	86-A	122-D	158-C	194-A	230-B
15-D	51-D	87-D	123-A	159-D	195-A	231-C
16-C	52-B	88-A	124-A	160-D	196-D	232-D
17-D	53-A	89-A	125-D	161-C	197-B	233-D
18-C	54-D	90-A	126-D	162-D	198-D	234-A
19-D	55-B	91-D	127-A	163-C	199-D	235-A
20-A	56-B	92-B	128-B	164-E	200-B	236-D
21-B	57-B	93-C	129-D	165-D	201-A	237-D
22-A	58-E	94-D	130-A	166-A	202-C	238-D
23-B	59-A	95-D	131-A	167-A	203-B	239-A
24-B	60-D	96-C	132-B	168-B	204-C	240-D
25-B	61-D	97-D	133-C	169-B	205-A	141-D
26-D	62-B	98-D	134-A	170-D	206-A	242-A
27-C	63-C	99-C	135-B	171-D	207-A	243-D
28-D	64-C	100-A	136-B	172-D	208-A	244-B
29-D	65-A	101-D	137-A	173-D	209-A	245-D
30-B	66-B	102-C	138-A	174-D	210-C	246-C
31-C	67-D	103-C	139-A	175-D	211-B	247-C
32-B	68-B	104-B	140-D	176-A	212-A	248-A
33-B	69-B	105-D	141-C	177-A	213-C	249-B
34-A	70-D	106-C	142-A	178-D	214-A	250-C
35-D	71-C	107-D	143-C	179-D	215-C	
36-A	72-D	108-B	144-A	180-A	216-A	

